राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 07] पन्द्रहवीं विधान सभा के सातवें सत्र का तेईसवां दिवस [संख्या: 10

गुरुवार,

03 मार्च 2022

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्री संयम लोढ़ा।

गौ सैस से एकत्रित राशि

146. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में विगत तीन वर्षों में गौ सैस के रूप में कितनी राशि एकत्रित हुई? उक्त एकत्रित राशि में से कितना-कितना व्यय किस-किस वर्ष में किस-किस कार्य पर किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गौशाला विकास और बायोगैस सहभागिता योजना में विगत तीन वर्षों में कितनी धनराशि व्यय की गयी? वर्षवार एवं जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): (1) प्रदेश में राज्य सरकार को स्टाम्प ड्यूटी पर अधिभार से वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 (31.01.2022 तक) प्राप्त राजस्व राशि 970 करोड़ 94 लाख 74 हजार तथा मदिरा की बिक्री पर वैट पर अधिभार से वर्ष 2019-20 से 2021-22 (31.01.2022 तक) प्राप्त राजस्व राशि 1205 करोड़ 10 लाख 72 हजार रुपये है। अधिभार से प्राप्त कुल राशि 2176 करोड़ 05 लाख 46 हजार रुपये है।

गौ सैस से प्राप्त कुल राशि में से विभिन्न मदों में किये गये व्यय का मदवार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) गौशाला विकास और बायोगैस सहभागिता योजना में विगत तीन वर्षों में व्यय की गई राशि का वर्षवार एवं जिलेवार विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने आपके माध्यम से जो जानकारी उपलब्ध करवायी है, गौशाला विकास कार्य पर तीन साल में मात्र 5 करोड़ 74 लाख रुपये और गौशाला बायोगैस सहभागिता योजना में तीन साल में मात्र 20 लाख रुपये ही खर्च किये हैं। आपके पास 526 करोड़ रुपये इस हैड में बचे हुए हैं, तो मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि गौशाला स्वावलम्बन योजना जो वित्त विभाग को बनाकर भेजी गयी, जिसमें पंचवर्षीय योजना थी, पहले साल में आपको पचास गौशाला लेनी थी, जिस पर 40 करोड़ रुपये खर्च था, दूसरे पर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, वित्त मंत्री से वित्त से सम्बन्धित प्रश्न पूछें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जो गौशाला स्वावलम्बन योजना आपको गोपालन विभाग ने पंचवर्षीय बनाकर भेजी, उसको आपने एक पैसा नहीं दिया तो उसकी स्वीकृति के सम्बन्ध में आप क्या राय रखते हैं?

दूसरा, 1 करोड़ 39 लाख गोवंश है, उसमें से मात्र 10 लाख 61 हजार गोवंश को ही आप गौशालाओं के माध्यम से लाभान्वित कर रहे हैं। जो बढ़िया सांड हैं, उनके जरिये जो अच्छी बछड़ियां पैदा करने के लिए कृत्रिम गर्भाधान का कार्यक्रम था, एन.सी.डी.एफ. (नेशनल को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन) के माध्यम से जो भ्रूण प्रत्यारोपण स्कीम चलती थी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इसमें भारत सरकार ने पैसा देना बन्द कर दिया तो भ्रूण प्रत्यारोपण स्कीम में क्या आप धन देने का इरादा रखते हैं?

तीसरा, यूरिया और डी.ए.पी. के विकल्प के रूप में गोबर और गौ-मूत्र के जरिये जैविक खाद बनायी जा सकती है। उसके लिए जो प्रस्ताव गोपालन विभाग द्वारा वित्त विभाग को भेजे हुए हैं, उनकी स्वीकृति के सम्बन्ध में आप क्या विचार रखते हैं?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपके द्वारा उठाये गये प्रश्नों का इस प्रश्न से कोई ताल्लुक नहीं है।

दूसरी बात, आपने यह कहा कि योजना बनाकर आपको भेज रखी है, तो उस पर विचार चल रहा है।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

अब जहां तक सवाल इस बात का है कि आपने यह कहा कि 20 लाख रुपये सिर्फ आपने गंगानगर में बायो गैस पर खर्च किये हैं, तो कोई दूसरा प्रस्ताव नहीं आया क्योंकि इसकी जो पात्रता है, वह पात्रता यह है कि 50 परसेंट पैसा वह खुद खर्च करेंगे और 50 परसेंट सरकार देगी।

दूसरी बात, आपने यह कहा कि एक करोड़ समथिंग, जितनी भी आपने यह फीगर बतायी, उतना है तो मोटी बात यह है कि 180 दिन का पैसा दिया जाता है और पहली बार अप्रैल में दिया जाता है और फिर दूसरी बार सितम्बर में दिया जाता है। बाकी पैसा जैसे बड़ा पशु है तो 40 रुपये पर-पशु और छोटा पशु है तो 20 रुपये पर-पशु दिया जाता है। इसके अलावा और कुछ नहीं है।

इसके अलावा, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आपने यह कहा कि विकास के लिए सिर्फ पांच करोड़ रुपया खर्च किया है, निश्चित तौर पर पांच करोड़ रुपया ही खर्च किया है क्योंकि कोई दूसरे प्रस्ताव ही नहीं हैं। हमारे पास तो जो प्रस्ताव गोपालन विभाग से आते हैं, उन प्रस्तावों के अनुसार वह पैसा रिलीज किया जाता है।

श्री अध्यक्ष: कटारियाजी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक पूरक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो पूरक प्रश्न अलाउ करिये।

श्री अध्यक्ष: तीन प्रश्न एक साथ पूछ लिये तो पूरक प्रश्न क्या बचेगा?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अगर उत्तर में विरोधाभास है तो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज आप बोलें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह जो सैस लगाया गया है, यह पूरे गौ-वंश के संवर्धन के लिए लगाया गया है या खाली गौशालाओं में रहने वाली गायों के लिए लगाया गया है? आपने जो भी उत्तर दिया है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछ रहे हैं या एक्सप्लेन कर रहे हैं?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैंने जो पूछा है, उसका जवाब नहीं दिया है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आप फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं इस चीज को। माननीय मंत्रीजी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अब यह सुनिये आप। सरचार्ज किस-किस काम में आता है, आपका सवाल यही था कि सिर्फ इसी पर लगाया है या इसी काम में आता है या किसी दूसरे काम में भी आता है? प्रत्येक ब्लाक में नन्दीशाला बनाने पर 111 करोड़ रुपये खर्च होगा, यह एक बात। दूसरी, पंजीकृत गौशालाओं में विद्युत कनेक्शन घरेलू दर पर देने और उसकी आधी राशि राज्य सरकार वहन करेगी, उस पर खर्च होता है। तीसरी बात यह है कि गौवंश के भरण-पोषण हेतु सहायता दी जाती है। चौथी बात यह है कि आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए सहायता दी जाती है। गौशाला को स्वावलंबी बनाने हेतु बायोगैस जन सहभागिता योजना और बायोगैस संयंत्र बनाने के लिए सहायता दी जाती है। गौ-संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016 के अन्तर्गत एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 180 दिवस की सहायता राशि दो चरणों में गौशालाओं के गौवंश के भरण-पोषण के लिए दी जाती है, उसके लिए यह दी जाती है।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारियाजी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, 1 करोड़ 39 लाख ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज बैठें। रिकार्ड नहीं होगा। प्लीज। रिकार्ड नहीं होगा। माननीय सदस्य, यह रिकार्ड नहीं होगा। माननीय कटारियाजी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अध्यक्ष: हां, मेरा अधिकार है, आप बैठें। मेरा अधिकार है, आप बैठें। प्लीज बैठें। I am on legs. आप बैठें। आप बैठें, प्लीज। रिकार्ड नहीं होगा। Don't behave like this. प्लीज, बैठें। I will name you. बैठें आप। You can't impose, Mr. Lodha. माननीय कटारियाजी। आप नहीं तो ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अध्यक्ष: Should I name you? मैं आपको नेम करूं क्या? Don't set a wrong precedent. Please be seated. माननीय

(श्री अध्यक्ष)
कटारियाजी। यह बिलकुल गलत बात है। सीनियर लीडर इस तरह का बिहैवियर करते हैं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह चिन्ता पूरे सदन के हर माननीय सदस्य की है। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि प्रश्न जिस प्रकार का है और जिस प्रकार का उत्तर है, उससे कोई भी चीज स्पष्ट नहीं हो रही है।

इस सरकार के पास विभिन्न प्रकार के सैस लगाने के बाद 2,176 करोड़ रुपये की आमदनी हुई। अब इन्होंने जो प्रश्न के उत्तर में दिया कि परिशिष्ट-क पर है। ईमानदारी से आप इसको देखो तो एक घंटे तक आप देखोगे तब तो आप इस विषय को पकड़ पाओगे कि मदवार खर्चा क्या हुआ? इन्होंने बहुत चतुराई से हरेक जिले का अलग-अलग करके आंकड़ों में फंसा दिया और फंसाने के बाद यह जो लास्ट के योग का कागज दिया है, उसमें इन्होंने गौशाला विकास कार्य के लिए 5 करोड़ 74 हजार रुपये दिये हैं। गौशाला बायोगैस की सहभागिता के लिए इन्होंने 20 लाख रुपया दिया है। इन दोनों का महायोग, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें, प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): तो इसमें से मैं पढ़ रहा हूं कि जो कुछ भी इसमें फिगर दिया है और वह महायोग है 594, इसका मतलब पांच करोड़ रुपये। अब इस फिगर को कैसे पढ़ें और कैसे समझें और एक जिला कहां खतम हो रहा है, उसका महायोग कहां है और दूसरा जिला कहां शुरू हो रहा है इस टेबल में? एक मिनट में मैं आपसे यह प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रश्न का जो भाग है, इसमें इन्होंने बहुत स्पष्ट यह लिखा है और गौ सैस से प्राप्त कुल राशि में से विभिन्न मदों में किये गये व्यय का मदवार एवं वर्षवार विवरण पूछा है, यह नहीं पूछा जिलेवार।

इन्होंने सारे आंकड़े जिलेवार देकर फंसा दिया कि दो घंटे तक उन आंकड़ों को देखते रहो। मैं यह सोचता हूं कि यह प्रश्न जिस भावना से पूछा, उसमें यह स्पष्ट नहीं हो रहा है और जितनी आपके पास आमदनी हुई, उसमें आपने खर्च नहीं किया है इसलिए आपसे यह विनम्र प्रार्थना है कि इसको किसी न किसी और रूप में लें। राजस्थान की जनता इसके बारे में चिन्तित है कि इतना हमने पैसा दे दिया, यह सरकार के खजाने में पड़ा है, उसके रिटर्न में हमको इस दृष्टि से कोई सहयोग और सहायता नहीं मिली है, यह चिन्ता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह अलग ढंग से आप लेकर आयें, इस पर चर्चा कर लेंगे। अगला प्रश्न, श्री रामलाल शर्मा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक बात का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने 2018 में मदिरा के ऊपर 20 परसेंट का सैस लगाया, उसके लिए आपकी सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद। क्योंकि होता क्या है कि मदिरा खरीदने वाला 100 रुपये का वैट देगा, तो उससे जो सैस मिलेगा, वह सैस गायों के चारे पर जायेगा। इसलिए मदिरा पीने वाला भी चाहे गायों को चारा नहीं डालता हो, लेकिन इस चक्कर में गायों को चारा डाल देगा। पंडित के कहने पर भी नहीं डालते हैं कई बार। इसलिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि मदिरा पर आपने लगाया, यह बहुत अच्छा किया।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। रामलाल शर्मा।

जयपुर के तृतीय श्रेणी संस्कृत शिक्षकों के पेंशन प्रकरण

147. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला जयपुर में विगत दो वर्षों में विभाग के अधीन कितने तृतीय श्रेणी शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त शिक्षकों में से किस-किस की पेंशन अब तक जारी नहीं की गई हैं? सेवानिवृत्त शिक्षकों के नाम व कारण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान के आदेश क्रमांक:-निसशि/संस्था-2,34/प.ग्रीष्वाकाश/15(10)2015/2017/18903-19410 दिनांक 02.06.2017 द्वारा कतिपय शिक्षकों की सेवा की गणना उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि से करते हुए समस्त परिलाभ प्रदान किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं? यदि हां, तो उक्त लम्बित प्रकरणों का निस्तारण कब तक कर दिया जाएगा? आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

संस्कृत शिक्षा मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) जिला जयपुर में विगत 2 वर्षों में संस्कृत शिक्षा विभाग के अधीन 22 तृतीय श्रेणी शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त शिक्षकों में से 01 तृतीय श्रेणी शिक्षिका श्रीमती लक्ष्मी सोनी, राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, बन्धा बस्ती, वार्ड नं. 67,

(संस्कृत शिक्षा मंत्री)

जयपुर से दिनांक 30.06.2021 को सेवानिवृत्त हुई थी। उनका ग्रीष्मावकाश वेतन आहरित करने के सम्बन्ध में पेंशन विभाग द्वारा लगाये गये आक्षेप की पूर्ति की जाकर संकुल प्रभारी (कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण वितरण अधिकारी) द्वारा पेंशन प्रकरण पेंशन विभाग को भिजवाया जा चुका है।

(3) जी हां। संकुल प्रभारी (कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण वितरण अधिकारी) द्वारा नियमानुसार परीक्षण करवाकर आक्षेपों की पूर्ति पश्चात् पेंशन प्रकरण निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर दिया है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण एवं प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि 01 जनवरी से लेकर 30 जून के मध्य जिन भी कर्मचारी का पदस्थापन होता है उनकी री-जॉइनिंग कराने का काम सरकार 01 जुलाई को करवाती है। आपने वह काम करवाया नहीं। यह चले गये न्यायालय में। न्यायालय ने आदेश दे दिया कि इनके पदस्थापन से ही इनको सारे परिलाभ दिये जाएं। आपके डायरेक्टर ने भी 02.06.2017 को आदेश जारी कर दिये कि इनको परिलाभ का लाभ दिया जाए। ये लाभ लेने के बाद सेवानिवृत्त हो गये। सेवानिवृत्ति के बाद इनका पेंशन विभाग कह रहा है कि नहीं, वह सरकार का आदेश था। जब तक वित्त विभाग से अप्रूवल नहीं लेकर आओगे तब तक हम आपकी पेंशन शुरू नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें माननीय सदस्य।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): मेरा मूल प्रश्न यही है कि इनकी जो रिकवरी निकाली जा रही है और रिकवरी जमा करवाकर पेंशन का लाभ दिया जा रहा है तो क्या इन कर्मचारियों की रिकवरी बन्द करने का काम करेंगे?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जयपुर के अलावा राजस्थान के तमाम जिलों में 31 दिसम्बर के बाद में जो नियुक्ति हुई है, उसमें गर्मियों की छुट्टियों की सेवा की गणना की जा रही है, लेकिन जयपुर में किसी कारण से, कोई आदेश कम्युनिकेशन गैप के कारण नहीं हुआ था। इसके कारण से यह हुआ है। इसको ठीक करवा दिया जायेगा। लक्ष्मी सोनी का भी पीपीओ 02 मार्च, 2022 को जारी किया जा चुका है। इसकी कापी आप मेरे से ले लेना। इसमें जो इन्होंने ग्रीष्मावकाश को सम्मिलित नहीं किया है, इसके लिए अलग से निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष: आपका परपज साल्व हो गया, फिर क्या है?

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): बस एक मिनट। इनकी रिकवरी का पैसा जो जमा है, वह कब तक वापस लौटा दोगे?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): मैंने कहा कि पीपीओ नम्बर 1164152(R) 02 मार्च को जारी कर दिया गया है और ग्रीष्मावकाश के सेवा की गणना का मामला जो है, इसके बारे एसीएस आज ही उनको निर्देश देकर....

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, उनका रिकवरी के सम्बन्ध में प्रश्न है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): रिकवरी के बारे में भी, जब यह आदेश चला जायेगा कि ग्रीष्मावकाश की सेवा की गणना की जा रही है तो उसमें उनको वापस मिल जायेगा पैसा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गिरधारीलाल।

श्रीडूंगरगढ़ शहर में गन्दे पानी की निकासी

148. श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि श्रीडूंगरगढ़ शहर के ताल मैदान के पास दो कच्चे जोहड़ों में जमा गंदा पानी कालू रोड स्थित वन विभाग की भूमि में विसर्जित किया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त कार्य हेतु प्रयुक्त पाइप लाइन की लम्बाई व जनरेटर पम्प की संख्या कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) श्रीडूंगरगढ़ नगरपालिका में दिसम्बर, 2019 से अब तक गंदे पानी की निकासी पर कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त नगरपालिका में गंदे पानी की निकासी हेतु जारी राशि में अनियमितता व गबन करने पर संबंधित अधिकारियों व संवेदकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त कस्बे में गंदे पानी की निकासी हेतु कोई स्थायी समाधान करने का विचार कर रही है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) जी हां। नगरपालिका क्षेत्र का गन्दा पानी कस्बे की पश्चिम दिशा की ओर स्थित कच्चा व पक्का जोहड़ में एकत्रित होता है, जिसे आबादी क्षेत्र से लगभग 03 कि.मी. दूर कालू रोड स्थित वन विभाग की भूमि पर छोड़ा जा रहा है। उक्त

(स्वायत्त शासन मंत्री)

कार्य में 03 बूस्टर पम्प सैट एवं 01 जनरेटर लगाये गये हैं। पाइप लाइन की लम्बाई लगभग 3 कि.मी. है।

(2) नगरपालिका श्रीडूंगरगढ़ द्वारा कच्चे व पक्के जोहड़ से पानी निकासी पर दिसम्बर, 2019 से लेकर अब तक राशि 49 लाख 30 हजार 723 रुपये व्यय की गई है।

(3) जी नहीं। नगरपालिका श्रीडूंगरगढ़ में गंदे पानी की निकासी हेतु जारी सरकारी राशि में अनियमितता/गबन की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(4) नगरपालिका श्रीडूंगरगढ़ में पक्के जोहड पर 10 एमएलडी का एसटीपी बनाने हेतु ड्राफ्ट डीपीआर तैयार करवायी जा रही है, जिसका तकनीकी परीक्षण करवाया जाकर वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रेषित की जावेगी।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न-1 का जवाब 3 किलोमीटर, 1 जनरेटर और 3 बूस्टर, मान लिया वह सही है। खण्ड-2 नगरपालिका क्षेत्र में 49 लाख 30 हजार 723 रुपये व्यय हुए, वह मान लिया।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछो। मान लिया। यह सब आ चुका है इसमें।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): यही पूछ रहा हूं। दिया है, उन्हीं का पूछ रहा हूं। खण्ड3 के बारे में माननीय मंत्रीजी ने जवाब दिया कि गन्दे पानी की निकासी के लिए अनियमितता के बारे में कोई शिकायत नहीं पायी गयी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन सालों से वहां एक जनरेटर लगा हुआ है। तीन किलोमीटर पाइप लाइन बिछी हुई है। तीन साल से एक बूंद भी पानी वहां वन विभाग में गया नहीं है। तीन साल से तीन किलोमीटर पाइप लाइन गयी है, वहां जनरेटर भी चला है।

श्री अध्यक्ष: नहीं गया होगा। किसी ने शिकायत की है?

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): शिकायत नहीं की।

श्री अध्यक्ष: आपने प्रश्न ही यही पूछा है।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): एक्चुअल में पानी क्यों नहीं गया, यह बतायें।

श्री अध्यक्ष: हां, प्रश्न यह पूछें।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): तीन जनरेटर लगे हुए हैं तो पानी नहीं जाने का कारण बतायें।

श्री अध्यक्ष: बिलकुल ठीक है, माननीय सदस्य। माननीय मंत्रीजी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य स्वयं कबूल कर चुके हैं कि तीन बूस्टर लगे हुए हैं और पानी बाकायदा कालू रोड पर छोड़ा जा रहा है। फिर कैसे छोड़ा जा रहा है?

श्री अध्यक्ष: वह कह रहे हैं कि वहां पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। तीन साल हो गये हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप कह रहे हैं कि पानी नहीं छोड़ा गया?

श्री अध्यक्ष: हां, तीन साल हो गये।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप इसी में हां भर रहे हैं तो फिर जवाब ठीक है।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): पानी जा नहीं रहा है। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं फिर आपको निवेदन कर रहा हूं कि कोई भी शिकायत हमें अनियमितता या गबन के बाबत प्राप्त नहीं हुई है। सवाल यह है आपका।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, शिकायत नहीं पहुंच पाती है, आम आदमी नहीं कर पाता इसीलिए सदन में यह प्रश्न मैंने उठाया है। लगातार जनरेटर लगे हुए हैं, तीन साल तक वह पानी क्यों नहीं बाहर निकला, इसकी जांच करवाई जाए।

श्री अध्यक्ष: बिलकुल ठीक है। माननीय मंत्रीजी, इनका कहने का मतलब यह है कि तीन साल से इस व्यवस्था के बाद पानी की निकासी नहीं हो रही है, इसकी जांच करवायी जाए। यह कह रहे हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अत्यन्त जागरूक विधायक हैं। ये भी दे सकते थे इस बात की शिकायत कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में इस प्रकार का है।

श्री अध्यक्ष: अब बोल दिया उन्होंने।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अब दे देना, उसकी जांच करवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष: आप बैठें माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा। नीचे बैठें आप। अगला प्रश्न। श्री समाराम गरासिया।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): 000

पिण्डवाड़ा-आबू में लगाये गये पेड़

149. श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू में वर्ष 2020-21 में कितने पेड़ लगाये गये तथा उक्त में से कितने पेड़ जीवित बचे हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

वन मंत्री (श्री हेमाराम चौधरी): विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू में वर्ष 2020-21 में विभाग द्वारा 1.10 लाख पौधे लगाये गये तथा उक्त में से जीवित पौधों की संख्या 1.064 लाख है।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि आपने जांच कौनसे डीएफओ, अधिकारी से करवायी? वहां तीन डीएफओ लगते हैं, आबूरोड, सिरोही और वन्य जीव अभयारण्य, माउण्ट आबू। इस प्रकार की असत्य बात पेड़ पौधों के लिए ठीक नहीं है। पानी की व्यवस्था होती है, क्या इसको आप सत्पापित करवायेंगे?

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): लगाने के बाद में इसकी जांच होती है और जांच के आधार पर ही यह आपको बताया गया कि इतने पौधे लगाये गये और इतने पौधे जीवित हैं। अगर आपकी कोई पर्टिकुलर शिकायत है कि कहीं पर किसी जगह पौधे लगाये हैं और उसमें जीवित पौधों की संख्या जो उन्होंने बतायी, उसमें कोई अन्तर है तथा आप इससे सन्तुष्ट नहीं हैं, तो आप मुझे लिखित में दे दें, मैं उसकी जांच करवा लूंगा।

श्री अध्यक्ष: कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं यह पहली बार मुझे विधान सभा में ऐसी आश्चर्यजनक उपलब्धि देखने को मिली है। अपन अपने घर पर भी लगायें, खेत पर भी लगायें, तब भी इतनी उपलब्धि 1.10 लाख पौधे लगाये थे, उसमें से 1.064 लाख पौधे जीवित हैं। यह बहुत कम अन्तर है। यह तो शायद अपने देश का चमत्कार होगा कि इतने पेड़ जीवित रह गये। मंत्री महोदय, मेरी आपसे शिकायत इतनी है कि इस विभाग का इस प्रश्न के आधार पर पोस्टमार्टम करिए कि वास्तव में इस प्रकार का फर्जी उत्तर बनाकर विधान सभा के स्तर पर रखने की

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हिम्मत कर जाते हैं। इसके बारे में जरूर आपको कोई न कोई कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, प्लीज। गलत परम्परा है, बैठे-बैठे बोल रहे हैं। मंत्रीजी, आप जवाब दें।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पौधे जो लगाये गये, उनमें जीवितों की संख्या जो बतायी है, इससे आप सन्तुष्ट नहीं हैं कि इतने पौधे जीवित नहीं हैं। अगर इस प्रकार की बात है तो आप मुझे लिखित में दे दें, मैं उच्च अधिकारियों की टीम गठित करके उसकी जांच करवा दूंगा। यह बात सही है, यह कोई जरूरी नहीं है कि जो उन्होंने जवाब दिया कि इतने पौधे जीवित नहीं है, वहां मौके पर नहीं हैं तो दूसरी एक टीम गठित करके जांच दल बनाकर वहां मौके पर भेजकर जांच करवा देंगे ताकि दूध-का-दूध और पानी-का-पानी हो सके। कोई गलती करेगा तो वह सज़ा भुगतेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 150

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री हमीर सिंह भायल।

बाड़मेर सेण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक द्वारा बीजों की खरीद

151. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा किसानों को खरीफ फसल हेतु बीज वितरण विभाग के जरिये किया जाता है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बाड़मेर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक द्वारा इस वर्ष निजी फर्म से बीज खरीदकर किसानों को ग्राम सेवा सहकारी समिति के मार्फत वितरण किया गया है? यदि हां, तो उक्त बीज कौनसी फर्म से प्रति बैग कितने रुपये में क्रय किये गये एवं कौन-कौनसी ग्राम सेवा सहकारी समिति को वितरण हेतु दिये गये? किसानों से प्रति बैग कितनी राशि वसूल की गई व उक्त बीज ब्राण्डेड कम्पनी से क्रय किये गये अथवा स्थानीय कम्पनी से? विवरण दस्तावेजों सहित सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): (1) जी हां। सरकार द्वारा किसानों को खरीफ फसल हेतु बीज वितरण किया जाता है। राज्य में खरीफ 2021 में विभिन्न फसलों के अनुदानित दर पर वितरित उन्नत/प्रमाणित बीजों का विवरण परिशिष्ट-1 एवं मिनीकिट वितरण का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। बाड़मेर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, बाड़मेर द्वारा निजी फर्म से बीज खरीदकर ग्राम सेवा सहकारी समितियों को वितरण नहीं किया गया है तथा बैंक द्वारा समितियों को बीज खरीदने हेतु कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी में आया कि खरीफ सीजन के बीज का रबी के समय में वितरण किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें अधिकारियों ने खरीफ का बीज रबी में क्यों वितरित किया? उसमें बैग की कोस्ट 250 से 550 रुपये तक ली गयी इससे वहां का पूरा अख़बार भरा पड़ा है। वहां की स्थानीय निजी फर्म है। मंत्रीजी खरीफ का बीज रबी के मौसम में वितरित किया गया, उनके खिलाफ कुछ कार्यवाही करेंगे?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अगर आप लिखित में इस प्रकार की कोई शिकायत करेंगे तो उसकी पूर्ण रूप से जांच कराकर..(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह सदस्य कोम्पीटेंट नहीं है? मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। आपको जवाब नहीं सुनना है। वह खड़े होकर जवाब दे रहे हैं, अपन बीच-बीच में बोल रहे हैं। अपन क्या परम्परा डालना चाहते हैं?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): अगर आपके पास इस प्रकार की शिकायत है, आपने प्रश्न तो पूछा, लेकिन शिकायत मेरे तक नहीं पहुंचाई। अगर आप शिकायत पहुंचाएंगे तो उसकी जांच कराकर जो गलती करेगा, वह सज़ा पाएगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछा है निजी फर्म का और प्रश्न पूछ रहे हैं दूसरा सप्लीमेंट्री। प्रश्न ठीक ढंग से करोगे तो ही उत्तर ठीक ढंग से आएगा। अगला प्रश्न। श्री सतीश पूनियां।

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को मुआवजा

152. श्री सतीश पूनियां (आमेर): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में माह दिसम्बर, 2019 से जनवरी, 2022 तक तेज सर्दी, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, मावठ व पाला पड़ने से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है? यदि हां, तो क्या प्रभावित क्षेत्रों के किसानों की फसलों के नुकसान का आकलन करवाया गया है? यदि हां, तो जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त आकलन के पश्चात् प्रभावित किसानों को किस-किस प्रकार की क्या-क्या राहत दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सभी जिलों के किसानों को मौसम की सही जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई विशेष कार्ययोजना बनाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री (श्री गोविंद राम): (1) जी हां। माह दिसम्बर, 2019 से जनवरी, 2022 की अवधि में रबी फसल वर्ष 2019-20, जायद फसल वर्ष 2020, खरीफ फसल वर्ष 2020, रबी फसल 2020-21, खरीफ फसल वर्ष 2021 तथा रबी फसल 2021-22 में अब तक प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर ओलावृष्टि से हुए फसल खराबे तथा खरीफ फसल वर्ष 2021 में बाढ़ से हुए फसल खराबे के क्षेत्र की जिलेवार सूचना परिशिष्ट-"अ", "ब" एवं "स" पर संलग्न है।

वर्तमान में रबी फसल 2021-22 (संवत् 2078) की गिरदावरी का कार्य प्रक्रियाधीन है।

(2) कृषकों की फसलों में 33 प्रतिशत या इससे अधिक खराबा पाये जाने पर कृषकों को भारत सरकार के एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स के अनुसार कृषि आदान-अनुदान राशि का भुगतान किया जाता है। प्रभावित कृषकों को उपलब्ध कराये गये कृषि आदान-अनुदान राशि का जिलेवार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट-"अ", "ब" एवं "स" पर संलग्न है।

(3) कृषि विभाग द्वारा समय-समय पर विभागीय प्रशिक्षणों के माध्यम से किसानों को मौसम में हो रहे परिवर्तनों के संबंध में सूचना प्रदान की जाती है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम

(आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री)

से किसानों को समय-समय पर प्रेषित किया जाता है। मौसम विभाग से प्राप्त होने वाली जानकारी को भी समय-समय पर जिलों को भिजवाया जाता है।

(सूचना एवं विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यह वर्तमान में रबी की फसल में 2021 और 2022 की गिरदावरी का काम चल रहा है, इसे कब तक पूरा करेंगे और प्रभावित किसानों को कब तक यह मुआवजे की राशि प्रदान कर देंगे?

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2021-22 के आर्डर जारी कर दिये गये हैं और इसकी जो गिरदावरी है, वह प्रक्रिया में है और इसकी जब पूरी प्रक्रिया हो जाएगी तो फिर इसका भुगतान कर दिया जाएगा।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विशेष कार्य योजना की बात की थी मौसम की सही जानकारी के लिये, उसमें मेरा तात्पर्य था कि आजकल नई तकनीकी और नवाचार, इसमें सरकार ने कोई इनिशिएटिव लिया है क्या कि कृषकों को पहले से आपदा की कोई जानकारी आ जाए, मौसम के बारे में ठीक जानकारी पहुंच जाए? आजकल बहुत सारी नई तकनीक आ गयी हैं। इस बारे में सरकार की कोई ऐसी योजना है क्या?

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के अधिकारी यहां जयपुर में बैठते हैं और वे हमारे कृषि विभाग के अधिकारियों को जानकारी देते हैं और वे जिले के जो कृषि उपनिदेशक हैं, उनको जानकारी देते हैं। वे नीचे जो कृषि पर्यवेक्षक हैं, उनको जानकारी देते हैं और वे किसानों के व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं। उससे वहां के कृषि पर्यवेक्षक पूरे क्षेत्र में किसानों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जानकारी देते हैं।

श्री अध्यक्ष: कोई नवाचार कर रहे हैं क्या? वह पूछ रहे हैं। यह तो आपने बता दिया। कोई नवाचार कर रहे हैं क्या?

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): इसमें नवाचार करेंगे। इस सम्बन्ध में मीटिंग करके, जानकारी करके नवाचार की भी कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अविनाश।

जैतारण में बसों का ठहराव

153. श्री अविनाश (जैतारण): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री अविनाश)

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में राजस्थान राज्य पथ परिवहन की बसें सेन्दड़ा, निमाज, जैतारण शहर में पिछले लम्बे समय से अन्दर नहीं आकर बाईपास से जाने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पूर्व में उक्त शिकायतों पर कार्यवाही करते हुए रोडवेज बसों को सेन्दड़ा, निमाज व जैतारण के अन्दर आने के लिए निर्देशित किया गया था? यदि हां, तो उक्त आदेश की सुनिश्चितता कब व किस प्रकार की जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार पूर्व में जारी उक्त आदेश की पालना नहीं करने वाले रोडवेज बसों के वाहन चालकों व परिचालकों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, परिवहन (श्री बृजेन्द्र सिंह ओला): (1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण के उक्त तीनों ही स्थान सेन्दड़ा, निमाज व जैतारण शहर मुख्य मार्ग से अन्दर की ओर स्थित हैं, जिस कारणवश लम्बी दूरी एवं वातानुकूलित वाहनों का संचालन बाईपास से होकर ही किया जाता है। अन्दर होकर संचालन किये जाने पर लम्बी दूरी की वाहनों के यात्रियों द्वारा आपत्ति की जाती है।

इसके अतिरिक्त शेष सेवाएं सेन्दड़ा, निमाज एवं जैतारण शहर के अन्दर होकर संचालित की जा रही हैं।

(2) जी हां। सेन्दड़ा, निमाज, जैतारण शहर के बस स्टैण्ड पर लम्बी दूरी एवं वातानुकूलित वाहन, जिनका ठहराव निर्धारित नहीं है, उनके अतिरिक्त निगम की अन्य वाहनों के ठहराव किये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया हुआ है। सम्बन्धित आदेश की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

उक्त आदेशों की तत्समय ही पालना सुनिश्चित की जाती है। आदेशों की पालना नहीं किये जाने पर सम्बन्धित कार्मिक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(3) जी हां। खण्ड-2 में वर्णित निर्देशों की अवहेलना करने वाले सम्बन्धित कार्मिकों के विरुद्ध तत्समय नियमानुसार कार्यवाही की गई है, जिसका विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। (व्यवधान)

(प्रति एवं विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, और कोई जगह भी है। हां पक्ष में भी है, ना पक्ष में भी है।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो माननीय मंत्रीजी ने मुझे उत्तर भेजा है, मैं इसलिए निवेदन करूंगा कि सेन्दड़ा, निमाज और जैतारण मेरे विधान सभा क्षेत्र के सबसे बड़े कस्बे हैं। आबादी के हिसाब से निमाज की आबादी 30 हजार, सेन्दड़ा की आबादी 8 से 9 हजार और जैतारण की आबादी भी लगभग 25 से 30 हजार है। आपने इस उत्तर में लिखा है कि अन्दर होकर संचालित किये जाने पर लम्बी दूरी के वाहनों के यात्रियों द्वारा आपत्ति की जाती है। यहां पीछे आपने उत्तर भी दिया है। 2 किलोमीटर की दूरी पर बाईपास है। ब्यावर डिपो, जोधपुर डिपो की बसें 2018 से पहले आ रही थीं, लेकिन जबसे यह सरकार बनी है तब से इन बसों का अन्दर होकर ठहराव बन्द कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, आपने उत्तर में दिया है कि आपने उनके ऊपर पैनल्टी लगाई है, लेकिन इतने आदेश करने के बावजूद इन 3 सालों में वातानुकूलित बसों के अलावा, दूसरी कोई रोडवेज बस इन 3 स्थानों पर नहीं आ रही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। प्रश्न।

श्री अविनाश (जैतारण): मंत्री महोदय, मेरा निवेदन है कि आपने शास्ति तो लगा दी, लेकिन क्या आप ऐसा कोई निर्देश देंगे कि इन 3 कस्बों के अन्दर से होकर रोडवेज बसें निकलें।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, परिवहन): अध्यक्ष महोदय, परिवहन निगम में 32 बसें ऐसी हैं जो सेन्दड़ा होकर नहीं जाती हैं। उनको इजाजत दे रखी है। वह डीलक्स, स्टार लाइन और द्रुतगामी बसें हैं। इसके अलावा 88 बसें सेन्दड़ा के अन्दर होकर जाती हैं। 56 बसें निमाज और जैतारण के अन्दर से जाती हैं। जिन व्यक्तियों ने, कर्मचारियों ने आदेशों की पालना नहीं की है, ऐसे 200 कर्मचारियों के विरुद्ध हमने कार्यवाही की है।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल गलत जानकारी आपको अधिकारियों ने दी है। आपने जो सूची दी, आज की तारीख में उसमें से 80 परसेंट बसें सेन्दड़ा, निमाज और जैतारण शहरों के अन्दर से नहीं जा रही हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार आपके अधिकारियों को मेरे वहां भेज दें। मैं गांव वालों के साथ बैठकर आपकी मीटिंग करवा दूंगा।

(श्री अविनाश)

उससे पता लग जाएगा कि आपकी वास्तविकता क्या है? मेरा तो सिर्फ इतना निवेदन है कि जैतारण, निमाज और सेन्दड़ा के लिए रोडवेज बसों को आप सख्ती से निर्देशित कर दें।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, परिवहन): माननीय अध्यक्ष जी, 88 बसें जो सेन्दड़ा होकर जाती हैं, उनकी सूची मेरे पास है। 56 बसें जो निमाज और जैतारण होकर जाती हैं, उनकी सूची मेरे पास है। आप कहें तो पढ़ दूं। काफी समय लगेगा। आपको दे दूंगा। 32 बसों को निगम प्रशासन ने सेन्दड़ा के बाहर से जाने की परमिशन दे रखी है। 12 बसों को जैतारण के लिये और 18 बसों को निमाज के लिये निगम प्रशासन ने परमिशन दे रखी है। इसके अलावा जो लिस्ट मैं आपको दूं, इसमें से कोई भी बस अगर अन्दर होकर नहीं जाती है तो मैं संबंधित अधिकारियों को कहूंगा और वे आपसे सम्पर्क करेंगे। आप उनको सूची दे दें कि यह बसें नहीं जा रही हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री धर्मेन्द्र कुमार।

पीलीबंगा में खेल स्टेडियम की स्थापना

154. श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार खेलों को बढ़ावा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में कहां-कहां खेल स्टेडियम हैं व कहां-कहां खेल स्टेडियम बनाया जाना प्रस्तावित है?

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के कस्बा रावतसर एवं गोलूवाला में खेल स्टेडियम निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में जहां खेल स्टेडियम नहीं है, वहां भूमि आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल (श्री अशोक): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में क्रीड़ा परिषद्/खेल विभाग के नाम से कोई भूमि आबंटित नहीं है। बजट उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर स्टेडियम निर्माण का विचार किया जाता है। वर्तमान मे ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल)

(2) जी हां। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। बजट उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर स्टेडियम निर्माण का विचार किया जाता है।

ग्राम पंचायत स्तर पर चरणबद्ध रूप से खेल मैदान विकसित करने के लिये समन्वित स्टेडियम विकास कार्यक्रम 2015 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर प्रचलित At Least One Outdoor Game का मैदान बनाये जाने का प्रावधान है, जिससे स्थानीय स्तर पर मनरेगा योजना के तहत जिला परिषद् के माध्यम से बनाये जा सकते हैं।

वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 61 के अनुसार मेजर ध्यानचन्द स्टेडियम योजना के तहत चरणबद्ध रूप से राज्य के प्रत्येक ब्लाक में खेल स्टेडियमों के विकास कार्य करवाये जाने हेतु विधायक सांसद निधि/जन प्रतिनिधि/जन सहयोग/सीएसआर से प्राप्त राशि के बराबर राशि मैचिंग ग्राण्ट के रूप में राज्य सरकार द्वारा अधिकतम राशि 25 लाख दी जायेगी।

(3) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है। खेल विभाग द्वारा भूमि आबंटन की कार्यवाही नहीं की जाती है।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि मेजर ध्यानचन्द स्टेडियम योजना के लिये आपने दिनांक 26.04.2021 को पत्र लिखा और 50 परसेंट राशि का उल्लेख किया था लेकिन अब आपने 25 लाख की राशि दर्शायी है।

आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या एसडीएम, तहसील और पंचायत हैडक्वार्टर पर स्टेडियम बनाने की मंशा है? क्रीड़ा परिषद् या खेल विभाग कोई जगह चिह्नित करेगा या अलाट करेगा?

नम्बर 2, पीलीबंगा में गांधी स्टेडियम जो कि पूर्ण रूप से बना हुआ है, क्या खेल विभाग उसकी तरफ ध्यान देगा? क्या उसको अधिग्रहण करके उसका विकास करेगा?

नम्बर 3, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रावतसर व गोलूवाला में सरकारी स्कूलों में काफी जगह पड़ी हुई है। वहां स्टेडियम बन सकता है। क्या स्टेडियम बनाने की सरकार मंशा रखती है?

अध्यक्ष महोदय, वहां अच्छे खिलाड़ी हैं। जगह भी खूब पड़ी है। मेरी विधान सभा क्षेत्र में सरकारी स्तर पर आज तक एक भी स्टेडियम नहीं बना है। मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय इसमें कुछ घोषणा करेंगे।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि मैंने पूर्व में भी उत्तर दिया है कि खेल विभाग भूमि आबंटन नहीं करता है। अगर शिक्षा विभाग का मैदान है तो वह उसका मैदान है। यदि नगरपालिका का मैदान है तो वह नगरपालिका का होगा।

आपने मेजर ध्यानचन्द स्टेडियम की बात की कि पूर्व में जो बजट घोषणा थी, वह थी कि मैचिंग ग्राण्ट के बराबर पैसा दिया जायेगा। आपकी बात बिलकुल सही है कि पूर्व में जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी तो मैचिंग ग्राण्ट के बराबर देने की घोषणा ही हुई थी। बाद में वित्त विभाग को क्या समस्या हुई, मुझे पता नहीं, उसको 25 लाख तक सीमित कर दिया गया। लेकिन इसके अलावा जो माननीय विधायकगण प्रपोजल 25 लाख से ऊपर के भेज रहे हैं, हमने कई प्रपोजल उसके ऊपर के भी पास किये हैं। ऐसा नहीं कि 25 लाख की सीमा ही तय हो गयी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह योजना हम 2020-21 के सत्र में लाये थे जब खेल के ऊपर एक बड़ी चर्चा हुई। तकरीबन हर सदस्य ने कहा कि हमको मौका दो, हम 50 लाख दे देंगे, हम 01 करोड़ दे देंगे और विभाग भी लगाये। इस पर हमने यह योजना बना दी लेकिन उसके बाद बहुत सारे सदस्य सवाल तो लगा देते हैं लेकिन पैसे की चिट्ठी भेजते नहीं हैं। मेरा एक निवेदन है कि जितना गुड़, शक्कर आप डाल दोगे, उतनी मीठी चाय हम आपको बनाकर दे देंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री राजेन्द्र राठौड़।

बिजली की खरीद

155. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय ने 25 वर्ष पूर्व किये हुए विद्युत विक्रय करार को रद्द किये जाने की छूट दी है? यदि हां, तो इस दायरे में प्रदेश में कितने निजी विद्युत उत्पादन व नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के संयंत्र आते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि माह जुलाई, अगस्त व सितम्बर, 2021 में बिजली एक्सचेंज से 16 से 20 रुपये प्रति यूनिट की दर से 3 से 5 करोड़ यूनिट बिजली प्रतिदिन खरीदनी पड़ी? यदि हां, तो उक्त तीन माह में कुल कितनी राशि की विद्युत क्रय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(3) जनवरी, 2020 से जनवरी, 2021 के मध्य अडानी पावर, राजवेस्ट एनर्जी, कालीसिंध पावर से कुल कितनी बिजली किस-किस दर पर खरीदी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री भंवर सिंह भाटी): (1) जी हां। केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय के आदेश दिनांक 22.03.2021 के द्वारा अनुबन्ध की वैधता समाप्त होने या विद्युत संयंत्र संचालन के 25 वर्ष पूर्ण होने पर राज्य को आवण्टित क्षमता को त्यागने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं। इसके दायरे में निजी विद्युत उत्पादन संयंत्र नहीं आते हैं।

इस क्रम में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के 252 मेगावाट के 5 संयंत्र हैं, जिनसे प्राप्त बिजली की दर अधिक होने के कारण राजस्थान डिस्काम ने इन प्लांटों से आबंटित क्षमता को त्यागने का निर्णय किया, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

I. अन्ता गैस - 83.07 मेगावाट

II. औरिया गैस - 61.03 मेगावाट

III. दादरी गैस - 77 मेगावाट

IV. ऊंचाहार थर्मल पॉवर प्लांट - 20 मेगावाट

V. फरक्का थर्मल पावर प्लांट - 11.04 मेगावाट

उक्त प्लांटों से राज्य को आबंटित क्षमता को त्यागने हेतु केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय एवं नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन को पत्र लिखा जा चुका है।

(2) जी नहीं। यह कथन पूर्ण रूप से सही नहीं है। केवल माह अगस्त, 2021 के कुछ दिनों में 15 मिनट्स के कुछ ही ब्लाक्स में 16 रुपये से अधिक की विद्युत क्रय की गयी थी, जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है। साथ ही माह जुलाई, अगस्त, सितम्बर 2021 में एक्सचेंज से क्रय की गई बिजली की मात्रा और औसत दर का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(3) जनवरी, 2020 से जनवरी, 2021 के मध्य अडानी पावर, राजवेस्ट एनर्जी, कालीसिन्ध पावर से बिजली खरीद का विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय, आपने खण्ड-2 में यह तो स्वीकार कर लिया कि आपने अगस्त माह में 3 करोड़ 87 लाख यूनिट बिजली 17 रुपये 87 पैसे में खरीदी। इसी में आपने परिशिष्ट 'अ' के अन्दर दूसरी तालिका दी है। उसमें आपने लिखा है कि 6 रुपये 23 पैसे में 77 करोड़ 70 लाख यूनिट 484 करोड़ की खरीदी। एक ही महीने में दोनों खरीद का आपने उल्लेख किया है। अगस्त का महीना ऐसा नहीं होता कि जिसमें पीक आवर्स हों। आपने यह महंगी बिजली क्यों खरीदी?

दूसरा, मुझे ये बतायें कि इंस्टाल्ड कैपेसिटी के बारे में आपका प्रगति प्रतिवेदन कहता है कि 23384 मेगावाट है। आपकी वेबसाइट से मैंने निकाला, मैक्सिमम आपका लोड फैक्टर अगस्त में 12211 मेगावाट रहा था। जब अपने पास बिजली थी तो इतनी महंगी बिजली क्यों खरीदी? दोनों बता दें आप मुझे।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय उप नेता महोदय, प्रतिपक्ष ने बताया है, अगस्त माह में कोल माइंस एरिया में ज्यादा बारिश की वजह से कोल खानों में पानी भर जाने से कोयले का उत्पादन काफी कम हुआ। देश में उस समय कोयले की कमी हो गयी। वर्ष 2021 अगस्त में बारिश नहीं होने की वजह से किसानों की राजस्थान में पावर की डिमांड उससे बढ़ी। इससे पावर एक्सचेंज में भी रेटें बढ़ीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग की पूर्ति हेतु बिजली की पूर्ति करना हमारा ध्येय था। अगस्त व अक्टूबर में भी बिजली पर्याप्त नहीं मिलने से कई बार विद्युत की कटौती भी करनी पड़ी थी, लेकिन ओवरआल बारिश की वजह से कोल की सप्लाई और दूसरे कारणों से हमें बिजली के प्रोडक्शन में दिक्कत आ रही थी। उस समय ओपन एक्सचेंज से हम बिजली खरीदते हैं और उस समय हमने ये बिजली खरीदी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, खण्ड-3 में आपने राजवेस्ट, अडानी पावर प्रोजेक्ट और कालीसिन्ध, इन तीनों प्राइवेट फर्म्स से बिजली खरीदने की तालिका दी है। 2020-21 में अडानी की जो तालिका आपने प्रस्तुत की है उसमें 3 रुपये 92 पैसे से लेकर 8 रुपये 20 पैसे प्रति यूनिट तक आप बिजली खरीद रहे हो। इसी तरह से कालीसिन्ध में 4 रुपये 58 पैसे से लेकर 8 रुपये 99 पैसे तक खरीद रहे हो। इन दोनों के साथ आपका पीपीए है। क्या कारण है कि 8 रुपये 20 पैसे और

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

8 रुपये 99 पैसे में आप इन प्राइवेट फर्म्स से आप बिजली खरीद रहे हो? जरा यह आप मुझे बतायें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको आश्चर्य होगा, क्या यह सही नहीं है कि आपने 2021 में 13793 करोड़ रुपये की बिजली क्रय की है? यह सबसे बड़ा स्कैंडल है। जब हम सरप्लस स्टेट हैं, और सरप्लस स्टेट के अन्दर 13,793 करोड़ रुपये की बिजली खरीदना, मैं समझता हूं कि इस पर सवालिया निशान है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि इस पर आप आधे घण्टे की चर्चा रखवा दें। (व्यवधान)

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अभी जो बात उठायी है, अप्रैल, 2020 में कोविड के चलते हुए डिमांड भी कम थी इसके कारण से अडानी की जो यूनिट है उसको ब्रेकडाउन अर्थात् बन्द करा दी गयी थी जिससे वेरिएबल कोस्ट जो होती है वो तो हम जितनी बिजली लें उतनी हमें देनी पड़ती है लेकिन जो फिक्स्ड कोस्ट होती है वो चाहे प्लांट चले या नहीं चले, वो हमको देनी पड़ती है तो बिजली कम है तो भी पूरी यूनिट को हमने खड़ा रखा। कालीसिन्ध पावर की यदि हम बात करें तो इस प्लांट को चलाया नहीं क्योंकि मई और जून में हमारा बिजली का उत्पादन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे उप नेता प्रतिपक्ष को कहना चाहूंगा कि आपने जो बात उठायी है, बिजली की खरीद का हमारा जो माध्यम है, हमारे पास मिनिस्ट्री आफ सेंट्रल पावर के भी निर्देश हैं कि सस्ती से सस्ती, कम से कम रेट पर जहां से बिजली मिलती है, वहां से हमें बिजली खरीदनी चाहिए। हमारे जो प्लांट कम रेट पर, मिनिमम रेट पर बिजली का प्रोडक्शन करते हैं, पहले हम उन प्लांट्स को चलाते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान में बिजली के लिए कोयले की चाहे हमारे पास कमी रही लेकिन उसके बावजूद राजस्थान के किसानों, राजस्थान के आम कंज्यूमर को गुणवत्ता के साथ, पूरे वोल्टेज के साथ बिजली दे सकें, इस सोच के साथ हमने काम किया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, समझने में या तो अपने आप में सक्षम नहीं पा रहे हैं या आप समझा नहीं पा रहे हैं कि एक ही महीने में यह जो अडानी वाला ग्रुप है 8 रुपये 20 पैसे में बिजली बेचता है, जबकि आपका राजवेस्ट उसी महीने में आपको 4 रुपये 65

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पैसे में दे रहा है। उसी तरह से आपका जो तीसरा है कालीसिन्ध, वह भी आपको उसी समय में दे रहा है 8 रुपये 99 पैसे में, तो अलग-अलग समय में एक ही महीने में इन तीन अलग-अलग कंपनियों की अलग-अलग रेट के आधार पर आपको खरीदने की क्या आवश्यकता पड़ गयी? यह समझ में नहीं आ रहा है।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें निवेदन यह है कि जो फिक्स्ड कोस्ट और वेरिएबल कोस्ट का अन्तर रहता है, फिक्स कोस्ट हमें ऐसे तमाम प्लांट्स को चलाने के लिए देनी पड़ती है और वेरिएबल कोस्ट जो रनिंग प्लांट हमारे चलते हैं उसमें हमें देनी पड़ती है। हमने इन प्लांट्स से अप्रैल में बिजली की रेट्स के बारे में जो कहा है 8.20 रुपये तो इसमें उस समय की जो परिस्थितियां थीं, उस समय कोविड का समय भी था, उस समय हमारे पास कोल की उपलब्धता, बिजली की उपलब्धता और तमाम तकनीकी कारणों को ध्यान में रखते हुए हमने यह निर्णय लिया था। इस सम्बन्ध में मैं यही कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप इसको अलग ढंग से लेकर आयें, इस प्रश्न से इसका उतना अधिक नहीं आयेगा, इस पर चर्चा करने के लिए अलग ढंग से लायें।

अगला प्रश्न। श्री शंकर सिंह रावत।

टाटगढ़ उपखण्ड मुख्यालय पर महाविद्यालय की स्थापना

156. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रत्येक उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गयी थी? यदि हां, तो विगत दो वर्षों में प्रदेश में किन-किन स्थानों पर राजकीय महाविद्यालय खोले गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के टाटगढ़ उपखण्ड में राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री राजेन्द्र सिंह यादव): (1) बजट घोषणा वर्ष 2019-20 के अनुसार प्रदेश में महाविद्यालय से वंचित रहे उपखण्ड मुख्यालयों पर सम्भावनाओं के परीक्षण हेतु नई नीति लाकर चरणबद्ध तरीके

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

से महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गयी थी। पिछले 2 वर्षों में उच्च शिक्षा विभाग में विभिन्न स्थानों पर खोले गये राजकीय महाविद्यालयों का विवरण परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में वर्तमान में सहशिक्षा का राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर संचालित है।

वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के टाटगढ़ उपखण्ड में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आप स्वीकार कर रहे हैं कि 2019-20 के बजट में आपने घोषणा की है। उस घोषणा के अनुसार ब्यावर से टाटगढ़ 100 किलोमीटर दूर है। टाटगढ़ उपखण्ड अलग है तो उपखण्ड में आपकी घोषणाओं के अनुसार राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखते हैं या नहीं?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पिछले तीन वर्षों में 122 नये महाविद्यालय खोले हैं, 33 कन्या महाविद्यालयों की अभी घोषणा की है। 6 उपखण्ड ऐसे हैं जिनमें अभी तक कोई महाविद्यालय नहीं हैं, वहां पर चरणबद्ध तरीके से ले रहे हैं, उसमें आपका टाटगढ़ भी है।

श्री अध्यक्ष: आपके 'हां' ही भर ली, फिर क्या रह गया?

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): ब्यावर का नम्बर चरणबद्ध में आयेगा कि नहीं आयेगा, इतना-सा बता दो।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): आपके ब्यावर में कन्या महाविद्यालय भी दिया ही है न अभी।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती कृष्णा पूनियाँ।

सादुलपुर में एसओजी चौकी में रिक्त पद

157. श्रीमती कृष्णा पूनियाँ (सादुलपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में एसओजी चौकी स्थापित है? यदि हां, तो उक्त में कितने पद स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती कृष्णा पूनियाॅ)

(2) उक्त चौकी में कितने पद रिक्त हैं व उक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): (1) जी हां। सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र में राजगढ, जिला चूरू में राज्य सरकार के स्वीकृति आदेश संख्या 10/2021-22 दिनांक 27.04.2021 के तहत एसओजी चौकी स्वीकृत की गई है, जिसमें 1 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 1 पुलिस निरीक्षक, 1 उप निरीक्षक पुलिस, 1 हैड कांस्टेबल, 1 कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल चालक, इस प्रकार से कुल मिलाकर 9 पद स्वीकृत किये गये हैं।

(2) उक्त राजगढ़ एस.ओ.जी. चौकी में पुलिस निरीक्षक कार्यरत है और शेष 8 पदों में से 1 एडिशनल एसपी और 5 कांस्टेबल्स के पद वहां पर भर दिये गये हैं, पदस्थापित कर दिये गये हैं।

श्रीमती कृष्णा पूनियाॅ (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने लास्ट में क्या कहा, मैं नहीं समझ पायी। 8 पद प्रक्रियाधीन हैं, तो गृह विभाग का एक आर्डर मेरे पास है। मेरे पास जो आंसर आया है, उसमें है कि 8 पद रिक्त हैं और गृह विभाग का एक आर्डर है जिसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसओजी, राजगढ़ में पदस्थापित कर दिया गया है। तो या तो ये आदेश गलत हैं साहब या फिर आंसर गलत है। इस पर मैं प्रतिक्रिया चाहूंगी और पदस्थापन कब तक कर लिया जायेगा? यह भी मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय विधायक महोदया, वहां सिर्फ एक सीआई के लेवल का अधिकारी पदस्थापित था, लेकिन यह निश्चित तौर पर बात सही है कि आपके प्रश्न लगाने के बाद दिनांक 01.03.2022 को एक एडिशनल एसपी की पोस्टिंग कर दी गयी है और दिनांक 02.03.2022 को पांच कान्स्टेबल्स को पदस्थापित कर दिया गया है।

श्रीमती कृष्णा पूनियाॅ (सादुलपुर): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी, बाकी रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह जो चौकी स्थापित की गयी थी, वह नकली नोट, मादक

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

पदार्थों की तस्करी और गैर कानूनी संगठनों की गतिविधियों के सम्बन्ध में की गयी थी, लेकिन चौकी स्थापित करने से लेकर आज तक वहां पर कोई भी केस नहीं हुआ। जैसे-जैसे जरूरत पड़ेगी, वैसे-वैसे वहां पर पदस्थापन कर दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री पब्बाराम।

पंचायत मुख्यालय के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

158. श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार जिन पंचायत मुख्यालयों पर विद्यालय नहीं हैं, वहां नये प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक?

(2) क्या सरकार सभी पंचायत मुख्यालयों पर स्थित विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

शिक्षा मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) जी हां। माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022-23 में प्राथमिक विद्यालयों से वंचित ग्राम पंचायतों पर प्राथमिकता से नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की घोषणा के तहत समस्त जिला शिक्षाधिकारियों से प्रस्ताव चाहे गये हैं। प्रस्ताव नियमानुसार प्राप्त होने पर वित्तीय प्रावधानान्तर्गत स्थानीय मांग एवं निर्धारित मानदण्डों के आधार पर नवीन विद्यालय खोले जाने की कार्रवाई की जा सकेगी।

(2) जी हां। माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022-23 में ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नत करने की घोषणा के तहत समस्त जिला शिक्षाधिकारियों से प्रस्ताव चाहे गये हैं। प्रस्ताव नियमानुसार प्राप्त होने पर, वित्तीय प्रावधानान्तर्गत, स्थानीय मांग एवं निर्धारित मानदण्डों के आधार पर क्रमोन्नति की कार्रवाई की जा सकेगी।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि खण्ड-1 व 2 में कहा गया कि जिला शिक्षा अधिकारी से प्रस्ताव मांग लिये गये हैं, तो यह प्रक्रिया पूरी होकर विद्यालय कब तक क्रमोन्नत हो जायेंगे? क्या सरकार UDISE की शर्तें पूरी कर रही है

(श्री पब्बाराम)

और कोई उच्च प्राथमिक विद्यालय या प्राथमिक विद्यालय, जो पंचायत हैडक्वार्टर पर नहीं भी है, क्या सरकार उन विद्यालयों के क्रमोन्नयन का विचार रखती है?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, केवल 104 नयी पंचायतें बनी हैं, वहां पर प्राथमिक शालाएं नहीं हैं। मैंने प्रस्ताव मांग लिये हैं। जैसे ही प्रस्ताव आयेंगे, हम नये सत्र से पहले-पहले वहां स्कूल खोलने का प्रयास करेंगे।

श्री पब्बाराम (फलौदी): मेरा प्रश्न यह भी था कि क्या सरकार UDISE की शर्तें पूरी कर रही है और जो विद्यालय हैडक्वार्टर पर नहीं हैं, क्या आप उन्हें समग्र रूप से क्रमोन्नत करेंगे?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किये, उनमें 28(1) और 28(2) बिन्दु हैं, उनमें साफ लिखा है कि जिन पंचायत मुख्यालयों पर पांचवीं तक के स्कूल नहीं हैं, वहां खोले जायेंगे। जिन प्राथमिक शालाओं को क्रमोन्नत करना है, उनके प्रस्ताव प्राप्त होते ही हम कार्रवाई कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री संदीप शर्मा।

श्री पब्बाराम (फलौदी): सर, मेरा एक ही प्रश्न है और।

श्री अध्यक्ष: नहीं, माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा।

श्री पब्बाराम (फलौदी): 000

श्री अध्यक्ष: प्लीज, माननीय सदस्य।

कोटा में यू आई टी द्वारा विकास कार्य

159. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा शहर में यूआईटी द्वारा जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2021 तक किन-किन सड़कों पर कब-कब डामरीकरण व सुदृढ़ीकरण के कार्य करवाये गये तथा उक्त पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त शहर में उक्त अवधि में यूआईटी द्वारा पार्कों के सौन्दर्यीकरण व विकास हेतु किस-किस कार्य में कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री संदीप शर्मा)

(3) उक्त शहर में उक्त अवधि में यूआईटी द्वारा किन-किन मार्गों पर सीसी रोड का निर्माण किया गया तथा उक्त पर कितनी राशि व्यय की गयी? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) कोटा शहर में यूआईटी द्वारा जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2021 तक डामरीकरण व सुदृढ़ीकरण पर कुल राशि 114 करोड़ 77 लाख 31 हजार रुपये व्यय किये गये। जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2021 तक सड़कों के डामरीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्यों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) कोटा यूआईटी द्वारा जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2021 तक पार्कों के सौन्दर्यीकरण व विकास पर कोटा (उत्तर) विधान सभा क्षेत्र में 9 करोड़ 47 लाख 15 हजार रुपये, कोटा दक्षिण विधान सभा क्षेत्र में 12 करोड़ 48 लाख 96 हजार रुपये एवं लाडपुरा विधान सभा क्षेत्र में 9 करोड़ 59 लाख 7 हजार रुपये व्यय किये गये। जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2021 तक पार्कों के सौन्दर्यीकरण एवं विकास कार्यों का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) कोटा यूआईटी द्वारा जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2021 तक सीसी सड़क निर्माण कार्य पर कोटा (उत्तर) विधान सभा क्षेत्र में 41 करोड़ 21 लाख 37 हजार रुपये, कोटा दक्षिण विधान सभा क्षेत्र में 40 करोड़ 96 लाख 76 हजार रुपये एवं लाडपुरा विधान सभा क्षेत्र में 11 करोड़ 66 लाख 17 हजार रुपये व्यय किये गये। जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक कराये गये सीसी रोड निर्माण कार्यों का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष जी, उल्लेखित उत्तर में आधे से भी अधिक कार्य 2019 से पूर्व की सरकार ने कराये थे, उनका वर्णन आपने किया है। हकीकत माननीय मंत्री महोदय खुद जानते हैं। पूरा शहर खुदा पडा है। सड़कें गड्ढों से अटी पड़ी हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय मंत्री महोदय बताएं कि कब तक इन सड़कों का कार्य प्रारम्भ करा देंगे? किस-किस विभाग से करायेंगे? कितने मद में करायेंगे? कितने समय में पूर्ण करा देंगे? साथ ही, वे संवेदक,

(श्री संदीप शर्मा)

जो लाइबिलिटी पीरियड में उन कार्यों को सही नहीं कर पाये और सड़कें खराब हुईं, उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई सरकार द्वारा की गयी है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप भाषण दे रहे हैं। प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। प्रश्न पूछें पिन-पाइंट।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): वही पूछा है साहब, संवेदक के खिलाफ क्या कार्रवाई की? दूसरा प्रश्न यह है कि यूआईटी नगर निगम के द्वारा नयी सड़कें बनायी जाती हैं और जैसे ही वे सड़कें बन जाती हैं...

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछ रहे हैं या एक्सप्लेन कर रहे हैं?

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): जैसे ही सड़कें बन जाती हैं, पीएचईडी, आरयूआईडीपी और ये सब इनको खोद देते हैं। क्या प्रशासनिक स्तर पर को-ऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी और यदि बनी थी...

श्री अध्यक्ष: फिर आप प्रश्न नहीं कर रहे हैं। मैं अलाउ नहीं करूंगा माननीय। आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि प्रश्न पूछ रहे हैं?

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): जो को-आर्डिनेशन कमेटी बनी थी, क्या उसकी प्रगति बैठक या समीक्षा की जानकारी मंत्री महोदय को है? यदि नहीं है, तो क्या मंत्री महोदय उस कमेटी को मानिटरिंग हेतु पाबन्द करेंगे और विभाग में जिस तरह...

श्री अध्यक्ष: आप भाषण दे रहे हैं पूरा। अगला प्रश्न बुलवा लूं मैं? प्रश्न का उत्तर ही नहीं चाहते हैं आप।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, एक तो वही पुरानी बात कह दी इन्होंने कि साहब, सड़कें खुदी हुई हैं। मेरी आपको राय यह है कि अपने रेजीडेंस से लेकर बिरला हाउस तक ही जाना छोड़ें, पूरा शहर घूमें आप। आपको पता लग जायेगा, कहां पर सड़कें खुदी हुई हैं कहां नहीं।

दूसरी बात जो आपने कही, कुल-मिलाकर बात यह थी कि आइन्दा क्या होगा, तो 190 करोड़ रुपये के वर्क आर्डर जारी हो चुके हैं, जिनमें कोटा (दक्षिण), कोटा (उत्तर) और लाडपुरा, तीनों विधान सभा क्षेत्रों को कवर किया गया है। इसके अलावा भी कम से कम 80 करोड़ रुपये का एक वर्क आर्डर और जारी हुआ है। आपने कहा, को-आर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है कि नहीं तो वह आज से ही नहीं, बरसों से बनी हुई है और वह आज भी कार्यरत है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

मार्बल खनन इकाइयों को पर्यावरण सहमति

160. श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में मार्बल खनन इकाइयों को पर्यावरण सहमति देने के प्रावधानों में वर्तमान एवं विगत तीन वर्षों में क्या-क्या परिवर्तन किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पूर्व में मार्बल खनन की लघु इकाइयों को पहले जिला स्तरीय पर्यावरण स्वागत निर्धारण प्राधिकरण के द्वारा पर्यावरण अनुमति प्रदान की जाती थी? यह प्रक्रिया कब व क्यों बन्द की गयी?

(3) मार्बल खनन की लघु इकाइयों को पर्यावरण अनुमति लेने में सुगमता प्रदान करने और जिला स्तर पर ही अनुमति प्रक्रिया पूर्ण करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पर्यावरण मंत्री (श्री हेमाराम चौधरी): (1) राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) से प्राप्त सूचनानुसार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 14 सितम्बर, 2006 में प्रकाशित पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 एवं समय-समय पर हुए संशोधनों के अन्तर्गत संलग्न शिड्यूल में वर्णित क्रिया-कलापों के लिए पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता प्रतिपादित की गयी है। इसमें खनन कार्य भी शामिल है। मार्बल खनन इकाइयों के लिए पृथक से कोई प्रावधान नहीं है।

विगत तीन वर्षों में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विशिष्टत: खनन कार्य से सम्बन्धित अधिसूचनाएं दिनांक 29.11.2019, दिनांक 28.03.2020 एवं दिनांक 13.07.2021 राजपत्र में प्रकाशित की गयी हैं, जो कि परिशिष्ट-अ, अ(1) एवं अ(2) पर संलग्न है।

(2) जी हां राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) से प्राप्त सूचनानुसार पूर्व में मार्बल खनन की बी 2 श्रेणी की खनन इकाइयों को जिलास्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (DEIAA) के द्वारा पर्यावरण अनुमति प्रदान की जाती थी। तत्पश्चात् माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (केन्द्रीय), नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. सं. 186/2016 सत्येन्द्र पाण्डेय बनाम एम.ओ.ई.एफ. और सी.सी. एवं अन्य तथा ओ.ए. सं. 520/2016,

(पर्यावरण मंत्री)

विक्रांत तॉगड़ वी/एस.यू.ओ.आई. एवं अन्य में दिनांक 13.09.2018 और दिनांक 11.12.2018 के आदेशों के द्वारा जिलास्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (DEIAA) की विधिमान्यता पर रोक लगा दी गयी है।

(3) राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) से प्राप्त सूचनानुसार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2016 के अन्तर्गत पर्यावरण अनुमति उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा गठित प्राधिकरण द्वारा ही प्रदान की जाती है। अत: मार्बल खनन की लघु इकाइयों को पर्यावरण अनुमति लेने में सुगमता प्रदान करने और जिला स्तर पर ही अनुमति प्रक्रिया पूर्ण करने के सम्बन्ध में निर्णय भारत सरकार द्वारा ही किया जाना सम्भव है।

(अधिसूचनाएं पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अध्यक्ष महोदय, मैं डायरेक्टली अपना सप्लीमेंटरी क्वेश्चन पूछना चाहूंगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आपका उत्तर पढ़ा हुआ मान लिया।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): विगत तीन वर्षों में राज्य सरकार ने लघु खनन उद्यमियों को पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त करने में आ रही समस्याओं का निवारण करने के लिये क्या केन्द्र सरकार को कोई ज्ञापन या प्रस्ताव भेजा है? यदि हां, तो उन प्रस्तावों की क्या स्थिति है और स्टेट लेवल कमेटी के पास पर्यावरण पर कितनी एनओसी पेंडिंग है?

अध्यक्ष महोदय, क्या मैं एक और प्रश्न साथ में ही पूछ लूं?

श्री अध्यक्ष: अच्छा, माननीय सदस्य, एक और पूछ लें।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या राज्यस्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा सम्भाग स्तर पर कैम्प कार्यालय लगाकर लघु खनन उद्यमियों को पर्यावरणीय अनुमति के आवेदनों पर विचार करने में किसी प्रकार की विधिक बाधा है? अगर नहीं, तो सम्भाग स्तर पर कैम्प कार्यालय से कार्य करने पर केन्द्र सरकार ने कोई स्पष्ट प्रतिबन्ध लगा रखा है? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार लघु खनन उद्योग के लिये सम्भाग स्तर पर कैम्प कार्यालय लगाकर पर्यावरणीय अनुमति में सुगमता प्रदान करने का विचार रखती है?

(समय: 12.00 बजे)

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के उत्तर में सारी जानकारी विस्तार से दे दी है, फिर भी मैं माननीय सदस्या के ध्यान में लाना चाहूंगा कि सरकार के राजपत्र दिनांक 14 सितम्बर, 2006 में प्रकाशित पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 एवं समय-समय पर हुए संशोधन के अन्तर्गत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता प्रतिपादित की गयी, इसमें खनन कार्य भी शामिल है, यह आपने पूछा है। गत तीन वर्षों में भारत सरकार द्वारा विशिष्ट कार्य से सम्बन्धित अधिसूचनाएं जारी कीं जिनकी तीन अधिसूचनाएं राजपत्र में प्रकाशित हुई हैं जो आपको दे दी गयी हैं। मार्बल खनन की 'बी' श्रेणी की खनन इकाइयों को जिला स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण के द्वारा पर्यावरण अनुमति प्रदान की जाती थी। तत्पश्चात् माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली द्वारा ओए संख्या 186/2016 सत्येन्द्र पाण्डेय बनाम एमओईएफ और सीसी एवं अन्य तथा ओए नम्बर 520/2016 विक्रान्त तोगड़ वी/ एसयूओआई एवं अन्य में दिनांक 13.09.2018 और दिनांक 11.12.2018 के आदेशों के द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण की विधि मान्यता पर रोक लगा दी गई है। वर्तमान में 'बी' श्रेणी की खनन इकाइयों को पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अन्तर्गत वन, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा ही उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है। आपने जो भारत सरकार को पत्र लिखने की बात कही है, यह मैंने आपको बताया है कि ये निर्णय हैं और इन निर्णयों के अन्तर्गत भारत सरकार के ये निर्देश हैं, गजट नोटिफिकेशन है और इसमें राज्य सरकार के स्तर पर कुछ होना नहीं है। ये जो निर्णय हैं, यह ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश से ही यह फैसला हुआ है। इसलिए जो ईसी जारी की जाती है वह पूरी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही जारी की जाती है। जब तक पूरी प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है तो ईसी जारी नहीं की जा सकती है। आपने सम्भाग स्तर का कहा कि यह सम्भाग स्तर पर किया जाए तो यह आज से पहले सम्भाग स्तर पर इस प्रकार का हुआ नहीं है मैं अधिकारियों से चर्चा करूंगा कि अगर सम्भव हुआ तो सम्भागीय स्तर पर भी....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): पर सम्भागीय स्तर पर मीटिंग कराओ चाहे जिला स्तर पर मीटिंग कराओ, जो प्रक्रिया है वह तो सारी पूरी करानी है, पर आजकल सारा ऑनलाइन हो रहा है और ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी हो जायेगी तो ईसी जारी हो जायेगी। वैसे आपकी भावना से मैं सहमत हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित व समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें।)

सन्देश

राज्यपाल महोदय का कृतज्ञता ज्ञापन

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण पर दिनांक 15 फरवरी, 2022 को सदन द्वारा पारित धन्यवाद प्रस्ताव के उत्तर में निम्न संदेश राज्यपाल महोदय से प्राप्त हुआ है:-

"अ.शा. पत्र क्रमांक - प.17(5)राभ/2016/190

दिनांक 24 फरवरी, 2022

प्रिय अध्यक्ष महोदय,

आपका अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक एफ.10(1)सदन/विस/2019-22/4289 दिनांक 15 फरवरी, 2022 प्राप्त हुआ। माननीय सदस्यों द्वारा प्रकट कृतज्ञता के लिए मैं उनका आभारी हूं। आपसे निवेदन है कि आप कृपया मेरे आभार को माननीय सदस्यों को पहुंचाने का कष्ट करें।

सादर,

सदभावी,

ह.

(कलराज मिश्र)"

अनुपस्थिति-अनुमति

बाबु लाल, श्री, सदस्य, को 25 फरवरी 2022 से सत्रांत तक

मुझे सदन को सूचित करना है कि बाबु लाल (झाड़ोल), सदस्य, विधान सभा ने अपनी शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 25 फरवरी, 2022 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसींद हुरड़ा के गुलाबपुरा स्थित फैड इकाई बन्द होने के कारण श्रमिकों को अन्य विभागों में समायोजित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के अन्तर्गत विशिष्ट लहसुन मण्डी छीपाबड़ौद परिसर से लगती हुई भूमि खसरा नम्बर 42 को आबंटित नहीं किये जाने से किसानों को ही रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(3) श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या', सदस्य की ओर से चित्तौड़गढ़ जिले की तहसील डूंगला के ग्राम पंचायत करताना में करसाना बोहेड़ा मार्ग पर अरनिया पुलिया के पास स्थित प्राचीन हिन्दू धार्मिक स्थल को अवैध बताकर ध्वस्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री रामप्रताप कासनियां, सदस्य की ओर से वर्ष 2018 से 2021 तक किसानों को फसल बीमा क्लेम राशि नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से प्रदेश में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानान्तरण नहीं होने से अध्यपकों में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

(6) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में लाभार्थियों के अनुदान राशि में हुई अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री ज्ञानचंद पारख, सदस्य; श्री अविनाश, सदस्य; श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सदस्य; श्री जोराराम कुमावत, सदस्य एवं श्रीमती शोभा चौहान, सदस्य की ओर से सम्पूर्ण पाली जिले में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्रीमती इन्दिरा देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में राजमार्ग पर मेड़ता सिटी से जसनगर के मध्य स्थित क्षतिग्रस्त सड़क पर भी टोल वसूले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(9) श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाली के युवाओं को मूल निवास प्रमाण पत्र जारी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री हरेन्द्र निनामा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र घाटोल में किसानों की खातेदारी जमीन का आबंटन खनिज विभाग के लिए किये जाने से किसानों में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

(11) श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से प्रदेश में गैर राजकीय चिकित्सा संस्थानों द्वारा अधिक फीस लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से प्रदेश के टोल प्लाजाओं पर टोलकर्मियों द्वारा जनता के साथ मनमाने ढंग से हो रही लूट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(13) श्री पुखराज एवं श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से बाड़मेर जिले के गिड़ा थाना क्षेत्र में आरटीआई कार्यकर्ता अमराराम गोदारा पर जानलेवा हमला किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(14) श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र उदयपुर में जिला परिषद् द्वारा विधायक कोष का कार्य समय पर नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(15) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से माननीय राज्यपाल की घोषणा के बावजूद अजमेर के महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय में तीन वर्ष के बाद भी संविधान पार्क की क्रियान्विति नहीं होने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री पुखराज, श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री फूल सिंह मीणा एवं श्री वासुदेव देवनानी को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री ज्ञानचंद पारख, सदस्य की ओर से पाली जिले में डीएमआईसी आने के बाद भू-रूपान्तरण पर लगी रोक से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री धर्मनारायण जोशी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मावली में उदयसागर बांध से हिन्दुस्तान जिंक द्वारा करार से अधिक पानी लेने व मीटर से छेड़छाड़ करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्रीमती मनीषा पंवार, सदस्य की ओर से कम्युनिटी हैल्थ आफिसर की योग्यता में बीयूएमएस व बीएचएमएस को सम्मिलित कराने की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर), सदस्य की ओर से पंचायत समिति जहाजपुर की ग्राम पंचायत कुचलवाड़ा कलां एवं ऊंचा को नगरपालिका देवली के पैरीफेरी क्षेत्र से मुक्त रखे जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री अशोक डोगरा, सदस्य की ओर से जिला मुख्यालय बूंदी के जर्जर हो चुके रोडवेज बस स्टैण्ड को आधुनिक सुविधायुक्त बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से कोटा शहर में उच्च न्यायालय बैंच की स्थापना करने के सम्बन्ध में।

(7) श्री गोविन्द प्रसाद, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का किसानों को मुआवजा नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्रीमती शोभारानी कुशवाहा, सदस्य की ओर से जिला बाड़मेर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, धूड़िया मोतीसिंह ब्लाक सिणधरी में कार्यरत अध्यापिका से प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक द्वारा सामूहिक रूप से दुष्कर्म कर हत्या करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में विद्युत निगम कर्मचारियों द्वारा जब्त किये गये ट्रांसफार्मरों को नियम विरुद्ध बेचे जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री ओम प्रकाश हुड़ला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र महुवा की ग्राम

(श्री अध्यक्ष)

पंचायत गगवाना, बालाहेड़ी व टुडियाना को पंचायत समिति महुवा से जोड़ने तथा मण्डावर में पंचायत समिति कार्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री जे. पी. चन्देलिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिलानी की सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री अशोक लाहोटी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में व्याप्त गम्भीर पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री पुखराज।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

बाड़मेर की गिड़ा तहसील में आरटीआई कार्यकर्ता पर हमला

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिले की गिड़ा तहसील की सिमाणिया की ढाणी के अमराराम गोदारा, जो एक मानवाधिकार और आरटीआई कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर दिनांक 21 दिसम्बर, 2021 को साजिशकर्ताओं द्वारा, जब वे जोधपुर से घर जाने के लिए बस स्टैण्ड पर उतरे, एक अज्ञात स्कार्पियो से आठ-दस लोग आये और उनका अपहरण करके दूर-दराज झाड़ियों में ले गये। उनके साथ निर्मम तरीके से मारपीट की।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यों, सदस्य बोल रहे हैं। गलत बात।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): लोहे की रॉड से उसके दोनों पैर तोड़ दिये गये। इतना ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसका पैर तोड़ने के बाद उसके पैरों में लोहे की कीलें डाली गईं और पूरी तरह से उसके साथ मारपीट करके मरा हुआ समझकर छोड़कर चले गये। जब घरवालों को पता लगा तो बालोतरा हास्पिटल लेकर गये। बालोतरा हास्पिटल में सीरियस होने व ज्यादा मारपीट की हुई थी इसलिए उनको एमडीएम, जोधपुर रैफर किया। एमडीएम, जोधपुर के अन्दर 22 तारीख को अमराराम गोदारा के पर्चा बयान के आधार पर एफआईआर नम्बर 270 दर्ज की गई। पर्चा बयानों के अन्दर मानवाधिकार कार्यकर्ता के द्वारा 8 साजिशकर्ताओं के नाम लिखवाये गये थे, लेकिन अभी तक पुलिस ने 4 अपराधियों को ही गिरफ्तार किया है और बाकी सभी खुले घूम रहे हैं। जो सरपंच मुख्य साजिशकर्ता है, वह अभी भी खुला घूम रहा है

(श्री पुखराज)

और मानवाधिकार कार्यकर्ता को धमका रहा है, मारने की धमकी दे रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि मुख्य साजिशकर्ता सरपंच, जिसको संरक्षण प्राप्त है, पूर्व मंत्री कांग्रेस और बड़े नेता बीजेपी के, उन सभी लोगों के संरक्षण में वह घूम रहा है। उसको तुरन्त गिरफ्तार करें, जो स्कार्पियो साजिश में काम में ली गयी है, उसको सीज करें। मानवाधिकार कार्यकर्ता का मोबाइल जो वे छीनकर ले गये थे, वह भी जब्त करें। जिन पुलिस अधिकारियों ने इसमें लापरवाही की है, उनके विरुद्ध भी जांच करके कार्यवाही करें। यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गया प्लीज।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाया जाये, ये मेरी मुख्य मांग है।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय सदस्य राजेन्द्र राठौड़। माननीय सदस्य, परम्पराओं को नहीं तोड़ें। माननीय सदस्य, आपकी भावना को हमने स्थगन प्रस्ताव में अलाउ किया है। आपने प्रोटेस्ट कर लिया, प्लीज अपनी जगह पर जायें, गलत परम्परा नहीं डालें।

श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस लोमहर्षक घटना का जिक्र किया है, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मेरा निवेदन है कि राजस्थान के अन्दर आरटीआई कार्यकर्ताओं पर यह पहला हमला नहीं है। अब तक 16 हमले हो चुके हैं और एक जगदीश गोलिया नाम के आरटीआई कार्यकर्ता की कस्टोडियल डैथ भी हो गयी। 21 दिसम्बर की जिस घटना का जिक्र आपने किया।

अध्यक्ष महोदय, मैं खुद 22 दिसम्बर को जोधपुर में जाकर इस अमराराम से मिलकर आया, मारपीट हुई, अपहरण हुआ और अपहरण के पश्चात् हाथ पैर तोड़कर ईसा मसीह को जिस तरह क्रूसीफाई किया गया था, उसी तहर क्रूसीफाई किया गया था, पेशाब पिलाया गया।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा एफआईआर नम्बर 270/2021 दिनांक 22.12.2021, मंत्री महोदय, पर्चा बयान के आधार पर अमराराम ने कहा कि मैं गांव जा रहा था, मेरा अपहरण हुआ और एक स्कार्पियो में आठ आदमी थे, 6 आदमियों ने मुझे पकड़ा और मेरे हाथ-पैर बांधे और उसके बाद

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मेरे साथ मारपीट की। मेरे हाथ और पैर तोड़ने के बाद कीलों से मुझे टांगा गया। उसने नामजद एफआईआर में कहा है, वे बात कर रहे थे, नागराज, बंकाराम, मानाराम को परेशान करने का परिणाम अब तू भुगत ले।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, मेरी इतनी सी मांग है, 8 हमलावर थे, 4 षड्यंत्रकर्ता थे, सिर्फ 4 गिरफ्तारी हुई है। अध्यक्ष महोदय, यह बात सदन में इसलिए आयी वरना मैं बात ही नहीं करता कि इसी 22, 24 फरवरी को इस अमराराम को फिर धमकी दी जाती है। दोनों हाथ-पैर टूटे हुए वह आरटीआई एक्टिविस्ट राजस्थान की राजधानी में आता है, मारा-मारा फिरता है और अपने एडिशनल डीजीपी रवि प्रकाश को गुहार लगाकर जाता है। पुलिस ने सिर्फ, उसको जो धमकी दुबारा दी, उसने एफआईआर में भी कहा कि मुझ पर हमला करने से पहले मुझे धमकी दी गयी, रिकार्ड दिया और दुबारा जब धमकी दी गयी तो मंत्री महोदय सिर्फ एक आदमी को पाबन्द करके छोड़ दिया जाता है।

मैं समझता हूं कि इसकी जांच आप सीआईडी-सीबी की जगह एसओजी से करवायें। हद तो तब हो गयी कि जिस शिकायत के आधार पर, अमराराम ने जो शिकायत की थी, आप अब एफआईआर दर्ज करते हो, उस शिकायत के आधार पर। इसलिए, मेरा निवेदन है, व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट की बात मुख्य मंत्री जी करते हैं। आप इसकी जांच करवायें, अमराराम को सुरक्षा दें और जो साजिशकर्ता लोग हैं, उनको गिरफ्तार करें। अभी जो 4 लोग फरार हैं, उनको गिरफ्तार करें और जिन्होंने धमकी दी है, उनको तत्काल गिरफ्तार करें। मेरा निवेदन है कि यह हमला आरटीआई कार्यकर्ता सूचना प्राप्त करने वाले लोगों पर है, यह छोटी बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष: श्री फूल सिंह मीणा।

उदयपुर जिला परिषद् में विधायक कोष के कार्य समय पर नहीं होना

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया तथा नियम, 50 के अन्तर्गत स्थगन के क्रम में बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता

(श्री फूल सिंह मीणा)

हूं कि हमारा विधायक फण्ड, जो जिला परिषद् में हम एनओसी देते हैं। जिला परिषद् से जब हमारे सामुदायिक भवन हों, पानी के हैण्डपम्प हों, चाहे कोई भी विकास का काम हो, सीसी रोड हो, इन्टर लोकिंग टाइल्स लगानी हों, इसकी एनओसी के लिए, हमको एसडीओ साहब के पास भेजते हैं तो एसडीओ साहब कहते हैं कि पहले प्रशासन की स्वीकृति लाओ और सीईओ साहब कहते हैं कि पहले हमको इसका पट्टा लाकर दो।

अध्यक्ष महोदय, ऐसी दुर्दशा हमारे विधायक फण्ड की हो रही है कि 6-6 महीने तक काम अटका रहता है। जिला कलेक्टर महोदय को कहते हैं तो वे यह कहते हैं कि बोलो कौन-सा काम करवाना है तो उस काम की एनओसी दे देते हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह मेरे पूरे सम्भाग की ही नहीं, पूरे प्रदेश की स्थिति होगी। जहां पंचायत समिति की ओर से कोई एनओसी लेनी ही नहीं पड़ती है और उसका डायरेक्ट काम हो रहा है और विधायक फण्ड के पैसों को अगर लटकाते हैं तो यह हमारे साथ में बहुत अन्याय हो रहा है और हम कैसे विकास करवायें।

अध्यक्ष महोदय, यूआईटी का सार्वजनिक पार्क है। उसमें भी हम हैण्डपम्प लगाते हैं तो ये कहते हैं कि एनओसी लेकर आओ, जबकि हम एजेंसी नगर निगम को करते हैं, फिर भी वहां एनओसी यूआईटी से मंगवाते हैं। इसलिए हमारे विधायक कोष को ढिलाई में डालकर हमारे काम में बाधा डालते हैं। इसलिए इसकी कोई न कोई ऐसी प्रक्रिया करें। जब हमारे विधायक फण्ड की सरकारी एजेन्सी कलेक्टर और सीईओ दोनों एक ही हैं। वे कहते हैं पहले मुर्गी आयी या पहले अण्डा आया, इसका क्या मतलब है? हमारी इस पीड़ा को समझकर तुरन्त प्रभाव से हमारे विधायक फण्ड को लागू करवाने का आदेश फरमायें।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री वासुदेव देवनानी जी।

अजमेर के महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय में संविधान पार्क के क्रियान्वयन का अभाव

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, महर्षि दयानन्द सरस्वती यूनिवर्सिटी के 2019 के दीक्षान्त समारोह में माननीय राज्यपाल द्वारा विश्वविद्यालय में संविधान पार्क बनाने की घोषणा की गयी,

(श्री वासुदेव देवनानी)

जिससे यहां के छात्रों, शिक्षकों को संविधान के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध हो, छात्र अवगत हो सकें, पर आज लगातार तीन वर्ष हो गये पर वह संविधान पार्क कागजों पर ही चल रहा है। यहां तक कि तत्कालीन कुलपति ने उसके लिए एक करोड़ रुपये का बजट भी तय कर दिया, जमीन का चयन भी हो गया। प्रारम्भ में तो जमीन पर आपस में मतभेद हुए, लेकिन उसके बाद प्रशासन द्वारा किया कि कणात भवन के सामने सरस्वती मन्दिर के पास पार्क बनाना तय हुआ, लेकिन इस दौरान वहां के कुलपति सस्पेंड हो गये। उसके बाद कार्यवाहक कुलपति जितने भी आते गये, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, केवल फाइल चलती रही। यहां तक कि पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति थानवी जी को चार्ज दिया। वे भी फाइलों को आगे से पीछे घुमाते रहे, लेकिन कभी भी बीओएम में इस आशय की चर्चा उन्होंने नहीं की। इस लापरवाही के कारण उसकी कॉस्ट बढ़ गयी। अब जब नये कुलपति ने जाइन किया तो इसकी कॉस्ट बढ़कर के ढाई करोड़ हो गयी। उसके कारण से ये डेढ़ करोड़ रुपये, इसके बीओएम में रखा लेकिन उसको भी आज तीन महीने हो गये, कागज अभी तक चल रहा है, लेकिन कहीं भी आगे नहीं बढ़ पाया।

अत: मेरी मांग है कि सरकार कुलपति को निर्देश दे कि यह पार्क समय रहते सही करें, नहीं तो फिर कॉस्ट बढ़ जायेगी। इसका पैसा जनता के, टैक्स से वसूला जायेगा, जनता के, सरकार के पैसे का दुरुपयोग होगा। अत: मेरी मांग है कि इसको तत्काल करें। चूंकि उदयपुर में बन चुका है, बच्चे यहां भी लाभान्वित हो सकें, बोझ भी न बढ़े और इसकी तुरन्त समय पर स्थापना भी हो सके, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानचंद पारख (अनुपस्थित)।

श्री धर्मनारायण जोशी।

उदयसागर बांध से हिन्दुस्तान जिंक द्वारा करार से अधिक पानी का उपयोग

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मावली में उदयसागर बांध से हिन्दुस्तान जिंक को करार के

(श्री धर्मनारायण जोशी)

तहत पानी दिया जाता है। दिनांक 16 सितम्बर, 2021 को मैं उदयसागर बांध पर पहुंचा। मैंने वहां देखा कि पम्पिंग स्टेशन, मीटर रूम सहित सारा परिसर हिन्दुस्तान जिंक के आधिपत्य में है। जल संसाधन विभाग का चौकीदार मौके पर मिला, जिसने बताया कि जिंक पहले जो मीटर की रीडिंग बताते हैं वो मैं विभाग के रजिस्टर में कर लेता हूं। मैंने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों व जिंक प्रबन्धन के प्रतिनिधियों को मौके पर बुलाकर पम्प हाउस में पम्प चलाकर प्रक्रिया की जानकारी ली। इस दौरान मीटर रूम में लगा मीटर स्विच से नियंत्रित होना पाया गया। मौके पर जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने पम्पिंग हाउस व मीटर रूम को सील किया व मौका पर्चा बनाया। दिनांक 17 सितम्बर, 2021 को अधिवक्ता विजय प्रकाश विप्लवी, दीपक डांगी व अशोक सिंघवी ने थाना प्रताप नगर में परिवाद संख्या क्रमांक 1541/21 दिनांक 17.09.2021 दर्ज करवाकर हिंदुस्तान जिंक के विरुद्ध पानी की चोरी व मीटर से छेड़छाड़ के मामले में कार्यवाही की मांग की। मैंने दिनांक 18 सितम्बर, 2021 को भी नियम 295 के तहत मामला उठाकर सरकार से कार्यवाही की मांग की। क्षोभ का विषय है कि विभाग ने अब तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की है। मेरी सरकार से मांग है कि सम्पूर्ण मामले की जांच हो, प्रभावी कार्यवाही की जाये और जिंक द्वारा वर्षों से जो करार से अधिक पानी लिया है उसकी पम्प हाउस के बिजली बिल को आधार बनाकर राजस्व की वसूली की जाये।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती मनीषा पंवार।

कम्युनिटी हैल्थ आफिसर की योग्यता में बीयूएमएस व बीएचएमएस का समावेश

श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि वर्तमान में केन्द्र सरकार व राज्य सरकार की सम्मिलित योजना एनएचएम के अंतर्गत कम्युनिटी हैल्थ आफिसर के पदों पर प्रदेश में भर्ती की गई है। इस पद हेतु शैक्षणिक योग्यता बीएएमएस व जीएनएम रखी गई है जो कि केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित है। इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र व जम्मू-कश्मीर राज्यों के आग्रह पर कम्युनिटी हैल्थ आफिसर की शैक्षणिक योग्यता में बीयूएमएस व बीएचएमएस को भी सम्मिलित किया गया है।

(श्रीमती मनीषा पंवार)

अतः उपरोक्त संदर्भ में निवेदन है कि कम्युनिटी हैल्थ आफिसर की योग्यता में बीयूएमएस व बीएचएमएस को सम्मिलित करने हेतु केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर आग्रह किया जाए ताकि यूनानी व होम्योपैथिक चिकित्सकों को भी रोजगार के समान अवसर प्राप्त हो सकें। अन्य चिकित्सा पद्धतियों की अपेक्षा यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सकों को पूर्व में भी रोजगार के अवसर तुलनात्मक रूप से कम प्राप्त हैं। इस सम्बन्ध में भी सम्बन्धित विभाग द्वारा ध्यान दिया जाकर रोजगार के समान अवसर उत्पन्न करने का प्रयास किया जाना आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष: श्री गोपी चन्द मीणा।

कुचलवाड़ा कलां व ऊंचा ग्राम पंचायतों की नगरपालिका देवली के पैरीफेरी क्षेत्र से मुक्ति

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि पंचायत समिति जहाजपुर की ग्राम पंचायत कुचलवाड़ा कलां एवं ग्राम पंचायत ऊंचा में निवासरत सम्पूर्ण आबादी पूर्णतया ग्रामीण परिवेश में समाहित है। उपरोक्त दोनों ग्राम पंचायतों को देवली नगरपालिका के पैरीफेरी क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने से उपरोक्त दोनों ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान तथा भारत सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं से वंचित रहना पड़ेगा।

इसके अतिरिक्त उक्त दोनों पंचायतों के अधीन गोचर/चरागाह एवं बिलानाम भूमि भी नगरपालिका के अधीन चली जाएगी जिसके परिणाम स्वरूप उक्त दोनों पंचायतों के अंतर्गत निवासरत ग्रामीणों के समक्ष आजीविका के एकमात्र साधन पशुधन को चराने की समस्या उत्पन्न होते हुए गोचर/ चरागाह एवं बिलानाम भूमि के अभाव में पशुधन के पालिका क्षेत्र में सड़कों पर विचरण करने से पशुधन एवं आम जनमानस के दुर्घटनाग्रस्त होने का भय सदैव बना रहेगा।

अतः मेरा आग्रह है कि जनहित में उपरोक्त दोनों ग्राम पंचायतों को नगरपालिका देवली के पैरीफेरी इलाके में सम्मिलित नहीं करते हुए नगरपालिका देवली के पैरीफेरी क्षेत्र से मुक्त रखे जाने का श्रम करावें।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक डोगरा (अनुपस्थित)। श्री संदीप शर्मा।

कोटा में उच्च न्यायालय की बैंच की स्थापना

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख कर राज्य सरकार का ध्यान कोटा शहर के अविलम्ब एवं लोकहित के विषय की ओर आकर्षित करता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा शहर औद्योगिक नगरी के साथ-साथ शैक्षणिक नगरी के रूप में सम्पूर्ण भारत देश में जाना जाता है और कोटा प्रदेश के बड़े शहर के रूप में जाना जाता है। कोटा में उच्च न्यायालय की बेंच नहीं होने के कारण हाड़ौती के कोटा, बूंदी, बारां व झालावाड़ की जनता को जयपुर बेंच में मुकदमों के लिए 500 किलोमीटर की लम्बी दूरी तय करके जाना पड़ता है। जयपुर उच्च न्यायालय में लम्बित प्रकरणों में से 40 प्रतिशत प्रकरण हाड़ौती संभाग के हैं परंतु सरकार द्वारा आज तक कोटा शहर में उच्च न्यायालय की बेंच की स्थापना के लिए प्रयास नहीं किए गये। सम्पूर्ण कोटा की जनता, व्यापारिक संगठनों व अभिभाषक परिषद् के पदाधिकारियों द्वारा गत 15 वर्षों से निरंतर उच्च न्यायालय की बेंच की स्थापना की मांग की जा रही है और आंदोलन किए जा रहे हैं परंतु सरकार द्वारा कोटा में उच्च न्यायालय की बेंच खोलने का प्रस्ताव आज तक भी नहीं भेजा गया, न ही सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई सार्थक प्रयास किए गये। किसी भी नागरिक का संविधान प्रदत्त अधिकार है कि उसे सस्ता, सुलभ व त्वरित न्याय मिले जो तभी सम्भव हो सकता है जब कोटा में उच्च न्यायालय की बेंच की स्थापना हो।

अतः मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा कोटा में उच्च न्यायालय की बेंच की स्थापना के लिए तुरन्त प्रस्ताव भेजकर इसकी स्थापना के लिए सरकार प्रयास करे ताकि सम्पूर्ण हाड़ौतीवासियों को त्वरित व सस्ता न्याय मिल सके।

श्री अध्यक्ष: श्री गोविन्द प्रसाद।

मनोहर थाना में ओलावृष्टि से नुकसान के लम्बित मुआवजा प्रकरण

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि माह जनवरी, 2022 में बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि के कारण विधान सभा

(श्री गोविन्द प्रसाद)

क्षेत्र मनोहर थाना के अनेकों गांवों की रबी की फसलें जैसे सरसों, धनिया, गेहूं, चना, लहसुन, मसूर आदि जैसी कई बेशकीमती फसलें बर्बाद हो गई हैं। किसानों ने बड़ी मेहनत और लगन से फसलें तैयार की थीं लेकिन प्रकृति का प्रकोप ऐसा रहा कि किसान खून के आंसू रो रहा है। इस महंगाई के जमाने में खाद बीज के दाम भी पूर्ण नहीं होंगे। मैंने मेरी विधान सभा क्षेत्र के ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों में लगातार 8 दिन तक गांव-गांव जाकर दौरा किया पर उच्च अधिकारियों को, हलका पटवारी को सूचित करने के बाद भी सही तरीके से सर्वे नहीं किया गया है। सिर्फ कार्यालयों में बैठकर खानापूर्ति कर दी गयी है। ओलावृष्टि के कारण विधान सभा की प्रभावित ग्राम पंचायतें भालता, उमरिया, बेरागढ़, गेहूंखेड़ी, सरडा, बांसखेड़ी, बोरबन्द, सरखण्डिया, दांगीपुरा, पिण्डोला, टोडरी जगन्नाथ, सेमलीहाट, खाताखेड़ी, चांदपुरा भीलान करीबन 25-30 ग्राम पंचायतों में काफी नुकसान हुआ जिनको शीघ्र मुआवजा राशि जारी की जावे। इसी के साथ उनको बीमा क्लेम की राशि भी मिले। खरीफ फसल 2021 में अत्यधिक बारिश के कारण सम्पूर्ण विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना के गांवों में अतिवृष्टि से फसलें बर्बाद हो गई थीं जिनका सर्वे आनन-फानन में आधा-अधूरा जो भी किया गया होगा उसकी मुआवजा राशि भी स्वीकृत हो गई है, लेकिन हलका पटवारी एवं उच्च अधिकारियों की लापरवाही से आज दिनांक तक किसानों के खाते में वह मुआवजा राशि नहीं डली है जिससे किसानों के जीवनयापन में संकट उत्पन्न हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, शीघ्र मुआवजा राशि डाली जावे जिससे किसानों का हित हो सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शोभारानी कुशवाह।

सिणधरी में अध्यापिका से सामूहिक दुष्कर्म

श्रीमती शोभारानी कुशवाह (धौलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि मैं सिणधरी जिला बाड़मेर में दर्ज एफआईआर संख्या 0199 दिनांक 12.12.2021 पर पुलिस द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

+++ पुत्री +++ निवासी कुम्हेरी, पुलिस थाना सेपऊ, जिला धौलपुर की निवासी थी। +++ बाड़मेर जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धूड़िया मोतीसिंह, ब्लाक सिणधरी में फरवरी, 2019 से अध्यापिका के पद पर कार्यरत थी। +++ के साथ उसके पिता +++ रहते थे। +++ ने अपने पिता को

(श्रीमती शोभारानी कुशवाहा)

बताया कि स्कूल प्रधानाध्यापक रामेश्वर प्रसाद तथा सोहनलाल अध्यापक अनावश्यक रूप से अभद्र व्यवहार तथा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मानसिक रूप से प्रताड़ित किया करते थे।

+++ 9 नवम्बर, 2021 को अकेली बाड़मेर गयी थी। +++ को अकेली देखकर प्रधानाध्यापक रामेश्वर प्रसाद तथा सोहनलाल ने दिनांक 11 दिसम्बर, 2021 को सामूहिक दुष्कर्म कर उसे फन्दे से लटका कर उसकी हत्या कर दी। +++ के पिता ने जिला अस्पताल, बाड़मेर में मेडिकल बोर्ड गठित करने की मांग की थी, लेकिन अपराधियों की पहुंच होने के कारण मेडिकल बोर्ड गठित नहीं कराया गया।

अध्यक्ष महोदय, कोतवाली, सिणधरी जिला बाड़मेर में दर्ज एफआईआर संख्या 0199 दिनांक 12.12.2021 पर पुलिस द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई। अभी 20 जनवरी, 2022 को कोटपूतली जयपुर के तीन आदमी +++ के घर आये और उनसे कहा कि सोहनलाल से गलती हो गई है, आप राजीनामा कर लो। आपको जितने रुपये चाहिये वो हम दे देंगे, नहीं तो हमारा आदमी जेल चला जायेगा। हम एक-दो महीने में जमानत करवा लेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हमने आत्महत्या लिखवा दिया है, इसलिए हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।

मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि प्रधानाध्यापक रामेश्वर प्रसाद मीणा तथा अध्यापक सोहनलाल स्वामी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धूड़िया मोतीसिंह, ब्लाक सिणधरी, जिला बाड़मेर को शीघ्र गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करवाने की कृपा करें। +++ का परिवार आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप लिखा हुआ बोलें, अलग नहीं।

श्रीमती शोभारानी कुशवाह (धौलपुर): जी। इसलिए सरकार अनुकम्पात्मक नियमों के अंतर्गत +++ के भाई को सरकारी सेवा में नियुक्ति प्रदान करने की कार्यवाही करे, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रताप सिंह। माननीय सदस्य, कोई अंकित नहीं होगा। प्रताप सिंह। आप बैठें, सुन लिया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

ट्रांसफार्मरों का नियम विरुद्ध बेचान

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में विद्युत निगम कर्मचारियों द्वारा जब्त किये गये ट्रांसफार्मरों को नियम विरुद्ध बेचे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में निवेदन है कि छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में किसानों के जब्त किये गये विद्युत ट्रांसफार्मरों को विद्युत निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा मिलीभगत कर नियम के खिलाफ जाकर अवैध तरीके से बेच दिया गया है। छबड़ा में विद्युत निगम के अधिकारियों ने बकाया वसूली के तहत किसानों के जब्त किये गये विभागीय व अवैध विद्युत ट्रांसफार्मर बेच दिये। जले हुए ट्रांसफार्मरों का सैकड़ों लीटर तेल भी कर्मचारियों द्वारा मिलीभगत कर चोरी-छिपे बेच दिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सब मंत्रियों के चेम्बर भी हैं, ऐसे नहीं।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): निगम के एमडी के निर्देश पर उक्त प्रकरण की जांच अधिशासी अभियंता, अटरू ने शुरू कर दी है। निगम के सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता द्वारा पिछले तीन माह से किसानों के बकाया बिलों की राशि वसूली की कार्यवाही की जा रही है....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप जो लिखा हुआ है वही बोल रहे हैं या क्या बोल रहे हैं?

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): लिखा हुआ ही बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: 295 वाला ही है, चैक कर लें।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 295 ही है।

...जिसमें बिल जमा नहीं कराने वाले किसानों के सिंगल फेज व थ्री फेज विद्युत ट्रांसफार्मर बड़ी संख्या में उतारे गये हैं। जांच के दौरान करीब 15 से 20 विद्युत ट्रांसफार्मर जब्त किये गये हैं। निगम के कनिष्ठ अभियंता ने विद्युत ट्रांसफार्मरों को स्टोर में जमा करने के स्थान पर अन्य कर्मचारियों के सहयोग से विद्युत ग्रिड कार्यालय से ही बेच दिये हैं जबकि अवैध ट्रांसफार्मरों से निकलने वाले तेल को भी स्टोर में जमा नहीं कराया गया। इस तरह से सैकड़ों लीटर तेल को भी कर्मचारियों ने .....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठें। आपको 295 में जो लिखा

(श्री अध्यक्ष)

हुआ है वही बोलना है, मन से नहीं बोलना है। आप अपने मन से बोले जा रहे हैं। नोट अलाउड। आपका 295 पढ़ा हुआ माना गया, आप बैठ जाएं।

(माननीय सदस्य के पढ़े माने गये विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के लिए कृपया परिशिष्ट-01 देखें।)

श्री ओम प्रकाश हुड़ला। आपका पढ़ा हुआ मान लिया। ओम प्रकाश हुड़ला।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): जो काम की बात थी वह तो छूट गई।

श्री अध्यक्ष: आपका पढ़ा हुआ मान लिया, जो लिखा हुआ है वह रिकार्ड में आ जायेगा। ओम प्रकाश हुड़ला।

गगवाना, बालाहेड़ी व टुडियाना को महवा पंचायत समिति से जोड़ना व मण्डावर में पंचायत समिति कार्यालय की स्थापना

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र महवा की ग्राम पंचायत गगवाना, बालाहेड़ी एवं टुडियाना को पंचायत समिति महवा में जोड़ने एवं मण्डावर में पंचायत समिति कार्यालय खोलने के संबंध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र महवा की ग्राम पंचायत गगवाना, बालाहेड़ी और टुडियाना पंचायत समिति महवा से मात्र 0-5 किलोमीटर दूरी पर है। भौगोलिक दृष्टि से भी इन ग्राम पंचायत के लोगों का महवा आना जाना रहता है। इन ग्राम पंचायतों का उपखण्ड कार्यालय भी महवा है और पुलिस थाना भी महवा लगता है। ऐसी परिस्थितियों में इन तीनों ग्राम पंचायतों को महवा पंचायत समिति में जोड़ना नितान्त आवश्यक है।

साथ ही अभी दौसा जिले में सम्पन्न हुए पंचायती राज चुनावों में सरपंच चुनावों में इन तीनों ग्राम पंचायतों के नागरिकों द्वारा चुनाव का बहिष्कार किया गया है। अगर उक्त तीनों ग्राम पंचायतों को पंचायत समिति महवा में नहीं जोड़ा जाता है तो इन ग्राम पंचायतों के निवासियों द्वारा भविष्य में होने वाले चुनावों का भी बहिष्कार करने की ठान रखी है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में चुनावों का बहिष्कार करना गम्भीर कारण बन सकता है। मैं मेरे क्षेत्र के नागरिकों की जन भावनाओं का आदर करते हुए उक्त तीनों ग्राम पंचायतों को महवा पंचायत समिति में जोड़ने की मांग करता हूं।

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

अत: इस अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं जनहित के मुद्दे पर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि ग्राम पंचायत गगवाना, बालाहेड़ी व टुडियाना को पंचायत समिति महवा में जोड़ने के आदेश प्रदान करें। साथ ही जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मण्डावर में पंचायत समिति कार्यालय खोलने के आदेश प्रदान करें, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जे.पी. चन्देलिया।

पिलानी की सड़कों का सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि मैंने सार्वजनिक निर्माण विभाग को पिलानी विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र की मुख्य-मुख्य सड़कों के सुदृढ़ीकरण/नवनिर्माण/नवीनीकरण के प्रस्ताव कई माह पूर्व प्रेषित कर दिये थे। आपको भी उन 40 सड़कों की सूची भेजते हुए शीघ्रातिशीघ्र इनके सुदृढ़ीकरण/नवनिर्माण/नवीनीकरण के लिये बजट आबंटित करने का निवेदन किया था। इस पर मुख्य मंत्री कार्यालय द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को मुख्य मंत्री कार्यालय के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक: मुमं/सं.स.(आर.वी)/प-1/वित्त/111071 दिनांक 26.02.2021 के द्वारा तुरंत कार्यवाही करने हेतु लिखा गया था परंतु इन 40 सड़कों में से जो 34 सड़कें बहुत बुरी स्थिति में हैं, जिनकी जनता को अत्यन्त आवश्यकता है, उनके सुदृढ़ीकरण/नवनिर्माण/नवीनीकरण के संबंध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार से विनम्र निवेदन है कि राज्य सरकार के वर्तमान बजट वर्ष 2022-23 में पिलानी विधान सभा क्षेत्र की इन शेष 34 सड़कों के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा आंकलित आवश्यक बजट राशि रुपये 29 करोड़ का प्रावधान करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर अनुगृहीत करें ताकि इस विधान सभा क्षेत्र की सड़कों व आवागमन की दुर्दशा की स्थिति को सुधारा जा सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक लाहोटी।

सांगानेर में व्याप्त पेयजल संकट

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र सांगानेर के वार्ड 65, 66, 92, 96, 97, 98, 99, 103 के क्षेत्र मदरामपुरा, मुहाना क्षेत्र, शिकारपुरा, सायपुरा, कोकावास, जोतड़ा वाला क्षेत्र,

(श्री अशोक लाहोटी)

बाजणी तलाई, गोविन्दपुरा, कालाबड़ फाटक क्षेत्र, टिब्बा टोल टैक्स क्षेत्र, माल की ढाणी, सीतापुरा गांव क्षेत्र, प्रताप नगर, भांकरोटा क्षेत्र, केशोपुरा, कमला नेहरू नगर क्षेत्र, नारायण विहार, श्रृंगारपुरा, गणपतपुरा, असरपुरा, दादूदयाल नगर, पटेल नगर, विधान सभा नगर धौलाई व आस-पास के क्षेत्र सहित सैकड़ों कालोनियों में गम्भीर पेयजल संकट उत्पन्न हो रहा है। यह पेयजल संकट नहीं अपितु मानवीय संकट भी है। लोग 30-40 वर्षों से यहां निवास कर रहे हैं। कई बार आंदोलन व धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दिये गये तथा नियमन व विकास शुल्क के नाम से हजारों करोड़ों रुपये विभाग में जमा करवाने के बावजूद भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं। अध्यक्ष महोदय, सांगानेर में पानी का स्टोरेज करके पूरे जयपुर शहर को सप्लाई दी जा रही है, जबकि सांगानेर क्षेत्र की सैकड़ों कालोनियों में पीने के पानी के लिये लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। यह कैसा न्याय है?

2018 में पूर्व भाजपा सरकार ने कई बजट स्वीकृतियां जारी कर दी थीं, जिनको वर्तमान सरकार ने आते ही जानबूझकर निरस्त कर फाइल को पिछले 3 वर्षों से दबा रखा है, जिसके कारण आज दिन तक उक्त कालोनियों में बीसलपुर का पानी उपलब्ध नहीं हो पाया। टेंडर हो रहे हैं, ऐसे स्टेटमेंट 3 वर्षों से आ रहे हैं। अब जल जीवन मिशन योजना में केन्द्र सरकार 50 प्रतिशत राशि भी दे रही है। अत: कृपया उक्त क्षेत्रों में जल्द से जल्द बीसलपुर के पानी हेतु टेंडर करवाकर सांगानेर विधान सभा के घर-घर में बीसलपुर का पानी पहुंचाकर न्याय करें।

अत: मैं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री जी का ध्यान प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के तहत आकर्षित करना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदन, श्रीमती अनिता भदेल।

समिति प्रतिवेदन

महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन (क्रम संख्या 3 से 5)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति, 2021-22 के तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम प्रतिवेदनों का उपस्थापन करती हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री अर्जुन लाल जीनगर।

याचिका समिति के प्रतिवेदन (क्रम संख्या 2 से 6)

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से याचिका समिति, 2021-22 के निम्नांकित पांच प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

1. सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित समिति को प्राप्त याचिकाओं के संबंध में याचिका समिति, 2021-22 का द्वितीय प्रतिवेदन;
2. परिवहन विभाग से संबंधित समिति को प्राप्त याचिकाओं के संबंध में याचिका समिति, 2021-22 का तृतीय प्रतिवेदन;
3. सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित समिति को प्राप्त याचिकाओं के संबंध में याचिका समिति, 2021-22 का चतुर्थ प्रतिवेदन;
4. आयुर्वेद, उच्च शिक्षा, युवा मामले एवं खेल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित समिति को प्राप्त याचिकाओं के संबंध में याचिका समिति, 2021-22 का पंचम प्रतिवेदन; एवं
5. जल संसाधन, कला संस्कृति एवं पुरातत्व, राजस्व विभाग से संबंधित समिति को प्राप्त याचिकाओं के संबंध में याचिका समिति, 2021-22 का षष्टम प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष: माननीय मुख्य मंत्री जी 5 बजे रिप्लाई देंगे। माननीय प्रतिपक्ष के नेता 4 बजे अपनी बात कहेंगे। सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि अपना टाइम इस तरह से एडजस्ट करें कि हम 4 बजे प्रतिपक्ष के नेता और 5 बजे मुख्य मंत्री जी का रिप्लाई सुन सकें।

आय-व्ययक पर चर्चा, श्री सतीश पूनियां।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2022-23 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री सतीश पूनियां (आमेर): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। बजट 2022-23 के वाद-विवाद में इस बजट की विस्तृत व्याख्या में तो मैं जाऊंगा ही, लेकिन मैं सबसे पहले व्यक्तिगत तौर पर इस बजट से आहत हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र आमेर से मुझे उपलब्धि के तौर पर आईफोन-13 दिया गया, जो मैंने वापस कर दिया।

(श्री सतीश पूनियां)

माननीय अध्यक्ष महोदय, विद्याधर नगर में कॉलेज की घोषणा हुई और गोविन्दगढ़ में भी हुई। इससे पहले के बजट में ईसरदा बांध से दौसा से लेकर सवाई माधोपुर की तमाम तहसीलों को और जयपुर की तमाम तहसीलों को जोड़ने की घोषणा हुई। जिस पाइपलाइन की डीपीआर बनी है, वह जमवारामगढ़ के रास्ते चौमूं जानी है, रास्ते का पड़ाव आमेर है। खुदवाकर लेकर जायेंगे, कैसे ले जायेंगे, भगवान जाने, लेकिन उस ईसरदा के बांध की बजट की घोषणा में भी आमेर को वंचित किया गया। हम बहुत लम्बे अर्से से राजकीय कालेज की मांग करते रहे हैं। 2013 से 2018 के कालखण्ड में आमेर विधान सभा क्षेत्र में एक हजार करोड़ से भी ज्यादा के काम हुए। सीनियर सैकण्डरी स्कूल, सड़कों का काम एवं 2017 की बीसलपुर की पेयजल योजना शहर के लिए शुरू हुई थी। वह अभी तक धीरे-धीरे रेंग रही है, उसको 2019 में पूरा होना था। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि आपने यहां पर तहसीलों की घोषणा की। हमने आपको निवेदन किया और व्यक्तिगत तौर पर भी पत्र लिखा और बजट के सुझाव भी दिये। जालसू को तहसील में क्रमोन्नत करने, चन्दवाजी को उप तहसील बनाने के लिए और इस तरह की कुछ बातों का उल्लेख और निवेदन आपकी सरकार से हमने बार-बार समय-समय पर किया है।

चूंकि आमेर जयपुर से भी पुराना शहर है, वहां पर सीएचसी है, उसको जिला अस्पताल बनाने के लिए आपसे निवेदन किया था। इसमें भी कोढ़ में खाज का काम हुआ। आपने कोरोना के कालखण्ड में आदेश दिया था, मैंने अपने विधायक कोष से 35-35 लाख की दो एम्बुलेंस दीं। आज वे एम्बुलेंस वहां पर ताले में बंद होकर खड़ी हैं। बार-बार पत्राचार के बावजूद उन एम्बुलेंसों को अभी तक पिछले एक साल से ड्राइवर नसीब नहीं हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस बजट की छाया में और इसकी पृष्ठभूमि में जो लगातार सर्वे आते हैं, उनमें इस समय राजस्थान में देश में सबसे महंगी बिजली है। पेट्रोल और डीजल पर सबसे ज्यादा टैक्स है। रेप के मामलों में राजस्थान नम्बर एक पर है। बाल तस्करी में नम्बर एक पर है। भ्रष्टाचार में नम्बर एक पर है। साइबर क्राइम में नम्बर एक पर है। डेंगू से मौतों के मामले में नम्बर एक पर है। परीक्षा में धांधली के मामले में नम्बर एक पर है। बेरोजगारी की एक जो कल रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है उसमें राजस्थान में 32 प्रतिशत बेरोजगारी दर है, जो कि हिन्दुस्तान में सर्वाधिक है। यही नहीं, बेरोजगारी के कारण सर्वाधिक आत्मदाह

(श्री सतीश पूनियां)

करने वालों में राजस्थान नम्बर एक पर है। आपने बजट तो जरूर पेश किया है, लेकिन इण्डिया टुडे ने अभी एक रिपोर्ट प्रकाशित की है कि राजस्थान में गरीबों को जो आवास मिलने थे, उस पर भी सरकार ने डाका डाला। इतना भेदभाव किया, जिनके पास कोठी है, उनको पात्र मान लिया और जो गरीब हैं, उनको अभी तक आवास नसीब नहीं हुआ। आनन्द चौधरी की इण्डिया टुडे की एक पूरी रिपोर्ट प्रकाशित हुई है।

(समय: 12.43 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, 29 नवम्बर, 2018 को एक जन घोषणा-पत्र जारी होता है, उसमें बड़े-बड़े वायदे किये जाते हैं। फिर लगातार तीन लम्बे चौड़े बजट भाषण और अभिभाषण होते हैं। अब 2022 का बजट भाषण, अब तक के इतिहास का लम्बा भाषण था, उसका रिकार्ड बना। मेजों की थपथपाहट हुई, कई बार पानी पीया गया, लेकिन जनता को पिलाने वाला जल जीवन मिशन का पानी, जो कि 2024 तक राजस्थान के 86 लाख लोगों तक पहुंचना था, उसकी रफ्तार कहती है कि वह 60 लाख लोगों तक पहुंचेगा। ये जो 26 लाख लोग बचे हैं, उनका क्या होगा, वह भगवान जाने।

बजट के बारे में कहा जा सकता है और मैं तो बचपन में देखता था कि गांव, शहर की गली में जादूगर आता था, वह पत्थर से रसगुल्ला बना देता था, कबूतर को खरगोश बना देता था और डिब्बे में बन्द आदमी को गायब कर देता था। बड़े-बड़े इश्तिहार लगते थे कि जादूगर सम्राट शंकर आ रहे हैं, इन्द्रजाल दिखायेंगे, मायाजाल दिखायेंगे। मुझे लगता है कि जादू-जादू करते-करते राजस्थान की सरकार ने अपना उप मुख्य मंत्री ही गायब कर दिया। यह राजस्थान के जादूगर की जादूगरी जरूर है।

माननीय सभापति महोदय, यह बजट प्रदेश को आत्मनिर्भरता की बजाय प्रदेश को निर्भरता की ओर ले जाने वाला है। मशहूर शायर निदा फाजली ने कहा है:-

"इतना सच बोल कि होंठों का तबस्सुम न बुझे,
रोशनी ख़त्म न कर, आगे अंधेरा होगा।"

माननीय सभापति महोदय, यह बजट इसी किस्म का है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप इनको चैम्बर में बुला लो, यहां तक आवाज आ रही है।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): चैम्बर में बुलाकर आप क्या कराना चाहते हो?

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): माननीय सदस्या आपकी ही एमएलए है।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय सभापति महोदय, अभी कर्जा लेकर ऋण चुकाया जा रहा है। लगभग डेढ़ लाख करोड़ का ऋण अब तक राजस्थान सरकार ने इस कार्यकाल में लिया है, जो इसी वर्ष बढ़कर दो लाख करोड़ हो जायेगा। प्रति परिवार 1.33 लाख की देनदारी हो जायेगी और वित्तीय वर्ष 2022-23 के अन्त तक कुल देनदारी 5 लाख करोड़ से भी आगे निकल जायेगी जिससे राजस्थान के प्रत्येक परिवार पर लगभग साढ़े तीन लाख रुपये का कर्जा होगा। अपने आपको गिरवी रखकर सुख भोगना पतन की ओर ले जाता है। माननीय सभापति महोदय, आप तो चार्वाक के दर्शन से वाकिफ हैं: 'यावज्जीवेत सुखं जीवेत, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत' यानी कर्जा लिये जाओ, भले ही घी पीओ। यह मुख्य मंत्री जी की नीयत हो सकती है, लेकिन मुख्य मंत्री जी की नीयत आगे और है। भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमं कुत:|

यानी न तो परमात्मा की चिन्ता है, न ही पुनर्जन्म की चिन्ता है। अपनी चिन्ता करो, वोटों की फसल पक्की करो। लोक-लुभावन भाषण दो और वादे करो, मर्जी आये, वह करो, लेकिन मुझे लगता है कि:- चारु लोक समतो वाक्योवाक्यं यशस्य: स: चारु वाक: जो लोक लुभावन और प्रिय लगे, वही वाक्य कहने वाला चार्वाक है। मुझे लगता है कि मुख्य मंत्री जी ने भी चार्वाक की इस सूक्ति को अपने ऊपर लिया और यह बजट पेश किया है।

सभापति महोदय, यह बजट प्रदेश को आर्थिक आपातकाल की तरफ ले जायेगा। वर्ष 2022 का फिस्कल डेफिसिट 58,211 करोड़ है, जीएसडीपी का 5.8 प्रतिशत है। महोदय, विगत का आकलन करेंगे तो 2020-2021 का बीई 47,650 हजार करोड़ था एवं आरई बढ़कर 62,015 करोड़ हो गया। आप अनुमान लगाइये कि 58,211 करोड़ है, उसका जब प्रोजेक्शन होगा तो यह 70 करोड़ से भी ज्यादा जायेगा। आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था कहां जायेगी?

सभापति महोदय, ऐसे ही रेवन्यू डेफिसिट 23,479 करोड़ होने का अनुमान है। एक तरफ घोषणाएं हैं और उन घोषणाओं में समानता नहीं है।

(श्री सतीश पूनियां)

घोषणाओं का अम्बार है और आपने करते-करते एफआरबीएम की उधार की लिमिट को भी खतम कर दिया। आप केन्द्र को बार-बार कोसते हैं, लेकिन एक तरफ आपका घाटा बढ़ रहा है और सरकार के रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। आप पानी पी-पीकर केन्द्र की सरकार को कोसते होंगे, लेकिन मैं आईना दिखाना चाहता हूं कि 2021-22 की बीई में टैक्स रेवेन्यू अनुमान के अनुसार 90 हजार 50 करोड़ था, वह आरई में घटकर 82803 करोड़, यानी 8 प्रतिशत कम हो गया। माननीय सभापति महोदय, 2 घंटे 57 मिनट के भाषण में पीठ थपथपायी और केन्द्र को कोसा, लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि केन्द्र से जो वित्तीय सहायता मिलती है, वह बीई के रूप में 40107 करोड़ अनुमानित थी, वह बढ़कर आरई में 44791 करोड़ हो गयी, यानी आपको केन्द्र से 12 प्रतिशत ज्यादा वित्तीय सहायता मिली है।

माननीय सभापति महोदय, यही नहीं, राजस्थान के निवासियों को, जन धन के 3 करोड़ खाता धारकों को 12 हजार करोड़ से भी ज्यादा का पैसा मिला है।

आपने मुद्रा योजना के जरिये, स्किल के जरिये, स्टार्ट अप के जरिये क्या किया, यह तो आप व्हाइट पेपर लाएंगे तो पता लगेगा। लेकिन प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान की जनता के नौजवानों को, 1 करोड़ 11 लाख लोगों को ऋण दिया जा चुका है। राजस्थान के 75 लाख किसानों को 10 हजार करोड़ का पी एम किसान सम्मान निधि की सहायता उनके खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है।

आप बार-बार सड़कों के निर्माण की बात करते हैं। मैं यहां धन्यवाद दूंगा, श्रद्धा से याद करूंगा माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने इस देश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से लेकर देश के हाईवेज को विकसित करने का महत्वाकांक्षी प्लान बनाया। राजस्थान में इन्हीं मोदी जी की सरकार में पिछले 7 वर्षों में 2 हजार 737 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, 15 लाख आवास का लक्ष्य था जिनमें लगभग 13 लाख आवास राजस्थान में उन आवासहीन लोगों को मिले। इसी तर्ज पर अभी 2 लाख 20 हजार इस बजट में राजस्थान के लोगों को मिलेंगे, बशर्ते राजस्थान की सरकार निरपेक्ष तरीके से उन आवासहीन लोगों को ठीक तरीके से, ठीक मापदण्ड के हिसाब से मुहैया करवाने का काम करे। 66 लाख 21 हजार लोग, राजस्थान की हमारी बहनें धुएं से मुक्ति पाकर उज्ज्वलता का

(श्री सतीश पूनियां)

आनंद ले रही हैं। किसान भाइयों को पिछले वर्षों में सवा करोड़ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिये लाभ हुआ है। मुख्य मंत्री जी का दावा है कि उन्होंने जन घोषणा पत्र की 70 प्रतिशत और बजट की 85 प्रतिशत घोषणाएं पूरी कर दी हैं, लेकिन यहां उनका जादू नहीं चला और उनकी पोल खुल गयी क्योंकि सी एम आई की रिपोर्ट के मुताबिक और पिछले दिनों जितने बच्चों ने परीक्षाएं दी हैं, उन परीक्षाओं के जरिये 65 और 70 लाख विद्यार्थी परीक्षाओं में बैठे हैं। सी एम आई की रिपोर्ट के मुताबिक, इस समय जो ताजातरीन रिपोर्ट है, 32 प्रतिशत बेरोजगारी सर्वाधिक राजस्थान में है।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी अपने आंकड़े दुरुस्त कर लें। तीन वर्षों में जोर लगाकर उन्होंने कहा है कि हमने 1 लाख से भी ज्यादा नौकरियां दी हैं और आने वाले 5 वर्षों में 3 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। क्या वह बताने की कृपा करेंगे कि जो बाकी 60 लाख लोग हैं, जो बच्चे हैं 62 -63 लाख, उनके लिए स्वरोजगार की, रोजगार की या उनके लिए किसी तरीके की कोई व्यवस्था, राजस्थान की सरकार के पास कोई रोडमेप है क्या? जो बेरोजगारी भत्ते की बात के लिए आप कहते थे, मुख्यमंत्री सम्बल योजना के मार्फत, ऐसे 6 लाख 11 हजार जो पात्र लोग थे, उनमें से केवल 4 लाख 11 हजार को दिया है। 2 लाख अभी भी इंतजार कर रहे हैं। इसमें आपने बेरियर लगा दिया जो इंटर्नशिप करेगा, ड्रेस पहनकर आयेगा, विभागों में अपनी उपस्थिति देगा, तो आपने मुख्यमंत्री सम्बल के नाम से बेरोजगारी भत्ता देने की बात तो की थी लेकिन गांव का विद्यार्थी कमरा लेकर कोचिंग करता है उस भत्ते की आस में, लेकिन आज तक उन 2 लाख लोगों को अभी भी इंतजार है। अभी 15 से ज्यादा भर्तियां लम्बित हैं, जो कोई वित्तीय और प्रशासनिक कारणों से पड़ी हुई हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ए सी एफ और वन रेंजर भर्ती, 2018; सहायक कृषि अधिकारी भर्ती, 2018; ए.ईएन. भर्ती, 2018; फूड सेफ्टी आफिसर भर्ती; वेटरनरी आफिसर भर्ती, 2019; कृषि रिसर्च आफिसर, 2020; आर.ए.एस. के जो प्री के, 1989 पुलिस उप निरीक्षक; संस्कृत शिक्षा, पटवारी, पैरा मेडिकल, जे.ई.एन., वनपाल, कृषि पर्यवेक्षक, ये तमाम भर्तियां पड़ी हैं। अभी भी आमरण अनशन पर बैठे हैं, सी.एच.ए. के लोग। पंचायत सहायक, ग्राम सहायक, फार्मासिस्ट और पुलिस के खेल कोटे के अन्तर्गत कांस्टेबल और उप निरीक्षकों की भर्ती, राजस्थान के विद्युत विभाग में, को-आपरेटिव

(श्री सतीश पूनियां)

बैंक, सहकारिता, पंचायती राज एल.डी.सी., रीट, कांस्टेबल, इनसे लेकर तमाम इस तरीके की और खासतौर पर नॉन-टी.एस.पी. के क्षेत्र में भी बेरोजगार जो वंचित हैं, उनके लिए किसी तरीके की रिलीफ, इसी तरीके से नर्स ग्रेड-सैकण्ड, ए एन एम की नई भर्तियां, संविदाकर्मियों को नियमित करने का काम, कल्ला जी यहां विराजे हुए हैं, आपकी अध्यक्षता में समिति बनी थी, अभी तक राजस्थान के बेरोजगार, वे संविदाकर्मी अभी भी सड़कों पर हैं। जो निरस्त फार्मासिस्ट भर्ती है, उसके भी ज्ञापन बराबर मिलते रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा बेरोजगार के साथ खिलवाड़ हुआ है। मैं एक बयान देख रहा था कांग्रेस के अन्तरराष्ट्रीय नेता जी का, उन्होंने कहा सूरज चाहे नहीं उगे, चन्द्रमा गायब हो जाए, हम सरकार बनाते ही किसानों का दस दिन में कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन इस भाषण के साथ-साथ ये किसान की तस्वीर है जिसने हनुमानगढ़ की कलेक्ट्री में कर्जे से तंग आकर आत्महत्या की थी। श्रीगंगानगर के ठाकरी गांव का सोहनलाल कड़ेल जिसने लाइव वीडियो जारी किया और सीधे-सीधे मुख्य मंत्री पर आरोप लगाये थे कि मेरी आत्महत्या के जिम्मेवार राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं। इसी न्योलखी गांव के बृजलाल से लेकर सुरजाराम तक, उसी पीलीबंगा के राधेश्याम तक, ये तमाम किसान, इनके परिवार राजस्थान की सरकार से पूछते हैं कि कब इनका कर्जा माफ होगा, कब इनको सहूलियत मिलेगी? लगभग 35 लाख किसान जिन पर 60 हजार करोड़ का कर्जा बाकी है। राजस्थान के कामर्शियल बैंकों का, सारा मिला लें तो राजस्थान के 60 लाख किसान हैं जो 1 लाख 20 हजार करोड़ के कर्जे की माफी की अभी भी अपनी मांग को रखते हुए सरकार से गुहार करते हैं। मुझे पता है आप जब रिप्लाई करेंगे लीपापोती करेंगे, पीठ थपथपाएंगे, मेजें थपथपाएंगे, लेकिन मैं तो सिर्फ यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप में गैरत व ईमान है तो राजस्थान के 60 लाख किसानों के 1 लाख 20 हजार करोड़ के कर्जे माफ करके उनकी जमीनें कुर्क होने से बचाने का काम भी आप करें।

माननीय सभापति महोदय, आप घोषणा करेंगे, मुझे थोड़ा आभास हो रहा है कि अब 20 हजार करोड़ की करेंगे या 23 की करेंगे, पता नहीं, लेकिन मैं संतोष कर लूंगा कि भागते भूत की लंगोटी भली, कुछ मिल जाए राजस्थान के किसानों को तो हम संतोष कर लेंगे।

(श्री सतीश पूनियां)

माननीय सभापति महोदय, किसी भी प्रदेश में निवेश भी तब आता है, नागरिक सहूलियत से तब रहता है, जब वहां की कानून व्यवस्था ठीक हो। राजस्थान में यदि एक पक्ष पर चर्चा की जाए, मैंने किसानों की, बेरोजगारों की बात तो की है, लेकिन 6 लाख 51 हजार मुकदमे आज तक राजस्थान की धरती पर दर्ज नहीं हुए हैं, पहली बार दर्ज हुए हैं। यदि इस तरीके से अपराधों की राजधानी राजस्थान बनता है तो निवेश नहीं आता है, पर्यटन को बढ़ावा नहीं मिलता है और इस पर शर्मनाक यह है कि पिछले एक वर्ष में 6 हजार 337 दुष्कर्म की, उत्पीड़न की, महिलाओं के अपराधों की घटनाएं सिर्फ इसी शासनकाल में हुई। आप कैसे थानागाजी को भूल सकते हैं? आप कैसे अलवर की निर्भया को भूल सकते हैं? वह बेटियां, वे माताएं, वे बहिनें, खून के आंसू रोकर इस राजस्थान की सरकार से न्याय मांगती हैं। क्या राजस्थान की सरकार के पास इन अपराधों पर रोक लगाने का कोई रोडमेप है?

माननीय सभापति महोदय, निवेश, पर्यटन और व्यापार, ये सब बाधित होता है यदि कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो, लेकिन कानून व्यवस्था ठीक कैसे होगी? सरकार के आने के बाद कुछ दिन बाद एक खबर छपती है कि जयपुर के किसी एक थाने से, थाने के भीतर से थानेदार की कार के टायर चोरी कर लिये जाते हैं। थानेदार की कार भी थाने में सुरक्षित नहीं तो राजस्थान की सरकार से क्या उम्मीद करें। सभापति महोदय, ऐसा रेयर होता है। होटल में मेन्यू कार्ड होता है अलग-अलग डिशेज का, लेकिन राजस्थान की इस मौजूदा सरकार में भ्रष्टाचार का मेन्यू कार्ड जारी हो गया। मुख्य मंत्री जी जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, लेकिन वही मुख्य मंत्री असहाय होते हैं कि मेरे विभाग में यदि भ्रष्टाचार है तो मैं क्या करूं? पब्लिक डोमेन में मुख्य मंत्री जी जब शिक्षकों के बीच में होते हैं, जब आप पूछते हैं कि क्या तबादलों के लिए पैसे देने पड़ते हैं तो आवाज आती है हां जी, देने पड़ते हैं। जब एक बार तसल्ली नहीं होती तो दूसरी बार पूछते हैं, क्या तबादलों के लिए पैसे देने पड़ते हैं तो दूसरी बार आवाज आती है कि हां, देने पड़ते हैं। राजस्थान में घूस है तो सब मुमकिन है। ये घूस का मेन्यू कार्ड है। इसकी सारी रेट अलग-अलग है। पुलिस की रेट अलग है, राजस्व की अलग है, खान की अलग है, पी.डब्ल्यू.डी. की, परिवहन की, नगर निगम की, नरेगा की, शिक्षा की, चिकित्सा की, आबकारी की, रसद की अलग-अलग है। माननीय सभापति महोदय, तकलीफ तो इस बात की है कि ये सच को सुनना नहीं चाह रहे हैं। आंख और कान पर परदा है।

(श्री सतीश पूनियां)

माननीय सभापति महोदय, सिलिकोसिस बहुत गम्भीर बीमारी है। उसमें व्यक्ति धीरे-धीरे मरता है। उसको भी सूदखोरों ने, घूसखोरों ने बख्शा नहीं। सिलिकोसिस की बीमारी से मजदूर की मौत हो जाती है और चूल्हा जलाने को तरसते हैं तो उसके परिवार को 3 लाख मुआवजा तब मिलता है, जब 50 हजार रुपये की रिश्वत उसका परिवार दे दे। यह मैं नहीं कह रहा, एसीबी के आफिसर ने अपने अधिकृत बयान में इस बात को स्वीकार किया है, इस मेन्यू कार्ड को स्वीकार किया है।

(समय: 13.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, मैंने आपको भर्तियों का जिक्र किया, भ्रष्टाचार का जिक्र किया। आपने शिक्षा में 6 प्रतिशत बजट की बात कही। माननीय सभापति महोदय, 32 प्रतिशत स्कूलों में बिजली नहीं है, 9 प्रतिशत स्कूलों में पीने का पानी नहीं है और केवल 30 प्रतिशत स्कूल ऐसे हैं जिनमें इंटरनेट की सुविधा है। आपने घोषणा की थी जनता क्लिनिक की, न जनता है, न डाक्टर है। पीएचसी, सीएचसी और सब-सेन्टर की मैंने एक छोटी-सी बानगी बताई थी कि मेरी पीएचसी, सीएचसी में मेरी दी हुई एम्बुलेंस पर ड्राइवर भी नहीं है, लोग इन्तजार करते हैं।

हां, एक बात जरूर है, आपने पर्यटन को उद्योग बनाने की घोषणा की, उसका मैं स्वागत करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं आमेर से आता हूं और दुनिया का हर तीसरा पर्यटक आमेर किले में आता है। वहां गाइड से पूछता है, where is 'Naathi ka Bada'? I want to visit. सिंगल विंडो अभी तक नहीं मिली। एससी, एसटी माइनोरिटी वेलफेयर पर 0.9 प्रतिशत, यह खर्चा है 0.9 प्रतिशत, 1 प्रतिशत से भी कम।

मैं अमीन खां जी का धन्यवाद दूंगा, उनका दर्द जायज है। उनका इस बात के लिये भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पूरी मजबूती के साथ यह कहा कि हिन्दू राज भी आ जाए तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। इस राज में जितनी तकलीफ है, इस राज से जो तकलीफ और असम्मान मिलता है।

सभापति महोदय, यदि दूसरे प्रदेशों से इस बजट की तुलना करेंगे, पड़ौसी प्रदेशों की हम लोग तुलना करते हैं, जिक्र करते हैं। कृषि, सड़क, परिवहन और एससी, एसटी वेलफेयर पर जो खर्चा हुआ, मध्य प्रदेश में 7.6, कर्नाटक में 6.5, हिमाचल में 6.1, राजस्थान में केवल 5 प्रतिशत। बुनियादी विकास पर राजस्थान में 3.4 प्रतिशत खर्चा होता है, हिमाचल में 9 प्रतिशत

(श्री सतीश पूनियां)

होता है, कर्नाटक में 4.8 प्रतिशत होता है, गुजरात में 4.3 प्रतिशत होता है। यहां सब जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं।

माननीय सभापति महोदय, पिछले बजट की कुछ घोषणाएं हैं। मैं सीधे-सीधे सवालों पर ही आ जाता हूं। आपने सीड मनी के रूप में 5 लाख रुपये प्रति स्टार्टअप सहायता राशि देने की बात की थी। हमारा सरकार से सवाल है कि राजस्थान में कितने स्टार्टअप शुरू हुए? इनसे कितने युवाओं को फायदा हुआ और कितनी राशि उनको दी गयी?

ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में स्मार्ट टीवी, सेटटॉप बाक्स स्थापित करने के लिये 82 करोड़ रुपये खर्च किये जाने थे, आप यह बताएंगे कि कितनी जगह हुए?

600 राजकीय विद्यालयों में कृषि संकाय खोलने की बात थी, कितने टीचर लगाये? महात्मा गांधी संस्थान, गांधी म्यूजियम और महात्मा गांधी इन्स्टीट्यूट एंड सोशल साइंस खोले जाने की बात थी, आप तो गांधी जी के साक्षात शिष्य हैं, कितनी जगह हुआ? घोषणा कब पूरी हुई? कितना काम हुआ?

फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी के लिये 400 करोड़ रुपये आबंटित हुए थे। इसकी बाउण्ड्री और बेसिक बिल्डिंग का काम हो गया हो, इसके अलावा कुछ हुआ हो तो भी बताने की कृपा करें?

वेद विद्यापीठ के लिये 25 करोड़ रुपये दिये थे, इसकी घोषणा हुई थी। इसमें कितने टीचर्स लगाये गये हैं? राजीव गांधी सेन्टर आफ एडवान्स टैक्नोलॉजी, क्योंकि इसके अलावा तो आप खोलोंगे नहीं। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इन्हीं पर खोलेंगे, खोल दिये, कोई बात नहीं। सरदार पटेल, सुभाष चन्द्र बोस, भगत सिंह पर भी खोलने चाहिये। राजीव गांधी सेन्टर आफ एडवान्स टैक्नोलॉजी के लिये 200 करोड़ रुपये आबंटित किये थे, इसकी अपडेट राजस्थान की जनता जानना चाह रही है।

1500 राजकीय विद्यालयों में नासा की मदद से एस्टेरॉयड खोजे जाने वाले थे, स्पेस एंड साइंस क्लब खोलने की बात थी। क्या गहलोत सरकार राजस्थान के ग़रीबों का इस तरीके से मजाक उड़ाती है?

मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, बड़ी मुश्किल से तो आपने नेहरू गांधी खानदान के अलावा दूसरा नाम सलेक्ट किया, उस स्टेडियम की योजना कहां

(श्री सतीश पूनियां)

तक पहुंची? कृषि पर्यवेक्षकों के एक हजार पद घोषित किये थे। किसान काम्प्लेक्स, मिनी फूड पार्क, इन सबका क्या हुआ ?

जयपुर में फिनटेक सिटी बनने वाली थी, पार्क बनने वाले थे। आपने अभी घोषणा की है कि जेएलएन मार्ग को एजुकेशन हब बनायेंगे। दुनिया में हमने शहरों को एजुकेशन हब बनते सुना था, आप एक सड़क को हब बनायेंगे, कमाल है।

5 करोड़ की लागत से बायोटेक फार्मा बिजनस इंक्यूबेशन एंड रिसर्च सेंटर बनाने थे, क्या हुआ? रूरल एरिया में कितने स्टार्टअप शुरू हुए?

आपने ट्रांसजेंडर के उत्थान के लिये, क्योंकि आप तो नई-नई बातें करते हो, कई बार लोगों को लगता है कि सारा काम राजस्थान में ही हो रहा है, आपने उस पर 10 करोड़ रुपये दिये, कम से कम उनके साथ इतना अन्याय तो मत करो, उसका ब्यौरा तो दो।

60 करोड़ की राशि से जोधपुर शहर में कल्चरल सेंटर बनने वाला था। आपका अपना ही है। 60 करोड़ की राशि से, बता दें कि हवा में, पाताल में है, आकाश में है? 100 करोड़ की लागत से धार्मिक पर्यटन सर्किट बनने वाला था। मैं जानना चाहूंगा, राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि वह कहां तक पहुंचा? टूरिस्ट काम्प्लेक्स 300 बीघा जमीन पर बनने वाला था, राजस्थान का फोक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनने वाला था।

सभापति महोदय, मुझे लगता है कि जिस तरीके से राजस्थान की सरकार ने यह बजट पेश किया है, जिस तरीके के पिछले बजट, तीन अभिभाषण, अब चौथा अभिभाषण था, चौथा बजट था, इसमें साम्यता कहीं नहीं है। घोषणाओं का अम्बार है। मुख्य मंत्री जी खूब शेरों-शायरी कर रहे थे, मेरा उनको जवाब है।

"मंजिल तो मिल ही जायेगी, भटक कर ही सही,
गुमराह तो वह हैं, जो घर से निकला ही नहीं करते।"

क्योंकि पिछले दो साल में, मुख्य मंत्री जी अपने घर से दफ्तर भी नहीं गये। यहां तालियां बजवाना, मेजें थपथपाना, बार-बार पानी पीना, उसके बाद केन्द्र को कोसना, यह काम आसान है, परन्तु राजस्थान की सात करोड़ जनता के अरमान-इच्छाएं पूरी करना नहीं है। आपको 70 वर्षों में 50 वर्ष

(श्री सतीश पूनियां)

मिले। आप पेंशन स्कीम के नाम पर खुश हो रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं, जब आपकी सरकारें थीं, आपने विचार क्यों नहीं किया? अब आपकी कुर्सी सरकने लगी, कुर्सी खिसकने लगी, उसके पाये हिलने लगे तो आपको लगता है कि कुछ पापुलिस्टिक चीज़ें पैदा की जायें। राजस्थान का किसान, राजस्थान का बेरोजगार, राजस्थान का अवाम बुनियादी सुविधाओं से लेकर, उन सब बातों का जवाब आपसे मांगता है। कानून व्यवस्था की यह स्थिति आज तक राजस्थान के इतिहास में नहीं हुई।

माननीय सभापति महोदय, आप तो सिर्फ एक काम कर देंगे तो राजस्थान की जनता, राजस्थान का नौजवान धन्य हो जायेगा। जिस ऐतिहासिक तरीके से रीट की धांधली हुई, राजस्थान के 70 लाख नौजवान, उनके सवा करोड़ से भी ज्यादा परिवार, उनके पेट पर लात पड़ी है। किसान अपनी जमीन बेचकर कोचिंग के लिये जयपुर भेजता है, दूसरे जिलों में भेजता है। उसने पेट काटकर पढ़ाई की। एक के बाद एक पेपर लीक होते चले गये। आप क्यों इन्कार करते हैं? आप तो कहते हैं, ठठेरे की बिल्ली खुड़के से नहीं डरती। सभापति महोदय, फिर सीबीआई से क्यों डरते हो? आओ न मैदान में, करिये घोषणा सीबीआई जांच की। दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। एसओजी की जांच से छोटी मछलियां फंस सकती हैं, बड़े मगरमच्छों का क्या होगा?

इस बजट में, मेरा सवाल राजस्थान की सरकार से भी रहेगा, यह निवेदन भी रहेगा कि आपमें हिम्मत, गैरत और ईमान हो तो उन लाखों बेरोजगार नौजवानों के परिवार आपको दुआ देंगे। सीबीआई की जांच आपने कमलेश प्रजापति में भी दी है, अलवर की निर्भया में भी दी हैं, विष्णु दत्त विश्नोई में भी दी है। जब बेरोजगार नौजवानों के अरमानों पर पानी फिरता है तो सीबीआई की जांच एक यथेष्ट मार्ग है। आप गांधी के अनुयायी हैं। गांधी जी सच कहते थे, सच को सुनने की, देखने की, सहन करने की हिम्मत है, आप इसलिये बचाना चाहते हैं क्योंकि राजस्थान सरकार के दो-दो मंत्री, सीधे-सीधे उन पर अंगुलियां उठती हैं। यदि यह निष्पक्ष तरीके से जांच हो जाये तो इनके नकाब भी उतर जायेंगे और भविष्य में राजस्थान में कोई भी दुस्साहस करने की हिम्मत इस तरीके से नहीं करेगा कि उन पेपर पर डाका डालेगा, नौजवानों के भविष्य पर सीधे-सीधे प्रश्न खड़ा करेगा और उनका भविष्य अंधकारमय बनायेगा। सभापति महोदय, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जगदीश चन्द्र।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, आपने बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। 23 तारीख को राजस्थान के ओजस्वी मुख्य मंत्रीजी ने जो वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया है, निश्चित तौर पर इस राज व्यवस्था को चलाने की दिशा में जो मजबूत कदम होने चाहिए वह राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने करके दिखाया है।

कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ऐसा बजट जिसमें हर क्षेत्र के डवलपमेंट की बात करना, हर क्षेत्र का ध्यान रखना, चाहे देश की, चाहे राजस्थान की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, राजस्थान की मूलभूत सुविधाओं की बात हो, मानवता की बात हो, शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, हर पहलू पर बड़े गौर से राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने ध्यान दिया है और जो बजट पेश किया है, निश्चित तौर पर इसकी सराहना करनी चाहिए।

मैं अभी-अभी भाषण सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्षजी का। बड़े विस्तार से बड़ा ज्ञानवान भाषण उन्होंने दिया और दो दिन पहले जब इस बजट पर चर्चा हो रही थी तो इस सदन में चूरू से आने वाले माननीय विधायक श्री राजेन्द्र राठौड़ भी बोल रहे थे, मैंने उनका भाषण भी सुना। बड़ा लम्बा-चौड़ा भाषण बजट पर उन्होंने दिया। मैं राठौड़ साहब से यह उम्मीद कर रहा था कि वे स्टेट के डवलपमेंट की बात करेंगे और इस बजट की प्रशंसा करेंगे। वे प्रशंसा तो करना चाह रहे थे लेकिन पोलिटिकल मजबूरी है पार्टी की, बोल सकते नहीं हैं क्योंकि ऊपर से हाईकमान का आदेश है कि आपको बजट का विरोध करना है। प्रजातंत्र में विरोध करना और सराहना करना, यह प्रजातंत्र का हिस्सा है लेकिन वास्तव में जो सही बात है और जो धरातल पर चीज उतरी है, उसकी तारीफ विपक्ष को भी करनी चाहिए, पक्ष को भी करनी चाहिए। लोग भी अगर अच्छे काम करते हैं तो लोग उसकी तारीफ करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि कोविड-19 की जो परिस्थितियां थीं उसके दौरान सरकार को आर्थिक तौर पर एवं समाज को सामाजिक तौर पर नुकसान हुआ है। दो साल के कोरोना काल के बाद जो हमें राजस्व प्राप्ति में कमी हुई उसके बावजूद भी हमने वैट में छह से सात रुपये की छूट दी। करीबन सात हजार करोड़ रुपये का नुकसान हर साल सरकार को झेलना पड़ा है। उसके बावजूद हमने हमेशा राजस्थान की जनता का ख्याल रखा है।

(श्री जगदीश चन्द्र)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि 2021-22 में करीब-करीब एक हजार करोड़ रुपये और 2022-23 में लगभग तीन हजार करोड़ रुपये की कमी केन्द्र सरकार से जो सहायता मिलनी थी, उसमें आयी है। अभी-अभी बी.जे.पी. के प्रदेश अध्यक्ष यह कह रहे थे कि 12 परसेंट हमने अलग से दिया है। मैं आपको यह याद कराना चाहूंगा कि 2020 का जो बजट था, आपकी ही सरकार की फाइनेंस मिनिस्टर ने जब बजट पेश किया कोरोना को देखते हुए तो 35 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान आपने किया था, पर पता नहीं वह पैसा कहां पर गया?

हिन्दुस्तान की जनता वैक्सीन के लिए त्राहि-त्राहि कर रही थी और वैक्सीन की व्यवस्था नहीं थी। आपने वैक्सीन को मापदंड मानकर 35 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की जबकि राजस्थान सरकार ने, आपकी तरफ से वैक्सीन का पैसा नहीं आया, हमारे एम.एल.एज. ने, हमारे मुख्य मंत्री ने 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था करके सीरम इंस्टीट्यूट को भिजवाया ताकि राजस्थान में टीकाकरण की शुरुआत हो सके और जब बेहतरीन प्रबन्धन राजस्थान सरकार का था तो वह प्रबन्धन ऐतिहासिक प्रबन्धन था, लेकिन आपकी यह मजबूरी थी, आप बोल नहीं सकते थे।

आज जिस तरीके का वातावरण देश में पैदा हो गया है, वह स्थिति भी आपके सामने है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि कोविड की वजह से सरकार ने सभी वर्गों का ख्याल रखा और करीब-करीब इस बजट में 15 हजार करोड़ रुपये की हमने राहत प्रदान करने की कोशिश की है माननीय मुख्य मंत्रीजी के माध्यम से। कोई नया कर नहीं लगाया गया। यह कितनी बड़ी बात है कि चौथा बजट सरकार का है और कोरोना के बावजूद भी डवलपमेंट के लगातार काम हो रहे हैं और एक भी पैसा टैक्स का नहीं लगाया है। कभी आप यह कल्पना कर सकते थे क्या? यह जादूगरी की जो बात कर रहे हैं तो यह तो अशोक गहलोतजी जानते हैं कि जादूगरी क्या हो सकती है। यह फाइनेंशियल मैनेजमेंट था। यह जनता के प्रति कमिटमेंट था। 70 परसेंट वादे जो जन-घोषणा पत्र में हमने इस सरकार ने किये थे, उसमें से कम से कम 80 परसेंट वादे हमने जमीनी धरातल पर उतार दिये हैं और मुझे यह लगता है कि यह 1952 के बाद में पहली सरकार है जिसने चार साल के अन्दर, मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा की थी, वे वादे पूरे किये हैं।

(श्री जगदीश चन्द्र)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस बजट में कितनी बड़ी बात है कि स्टाम्प ड्यूटी हमने नहीं बढ़ायी। जो हमारे दिव्यांग साथी हैं, जो तीन पहिया, चार पहिया स्कूटर लेते हैं, उनको टैक्स में छूट दी गयी है। सौ वर्ग गज का प्लाट जो कामर्शियल है या चाहे वह दूसरा खाली है, उस पर भी एक परसेंट के आस-पास छूट दी है। दिव्यांगजन को दस लाख रुपये तक के वाहन पर शत-प्रतिशत छूट दी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि जो पैतृक सम्पत्ति, जो गिफ्ट की बात थी, 60 साल के बुजुर्ग को, 18 साल के नौजवान को, उसका भी सरकार ने ख्याल रखा है। हमने कोई ऐसा टैक्स नहीं लगाया और हमने हर जगह कहीं न कहीं लोगों का ख्याल रखने की कोशिश की है। एमनेस्टी योजना के तहत सारे डिपार्टमेंट्स में जो एमनेस्टी योजना हम लेकर आये थे पिछली बार, और अबकी बार फिर हम लोग लेकर आये हैं। हमने उसमें वैट में कमी की है, स्टाम्प ड्यूटी में की है, एक्साइज में हमने की है, मोटर व्हीकल्स में हमने यह किया है और सैकण्ड एमनेस्टी योजना है। पिछली बार भी हमने किया था और इस साल भी हम लोग यह कर रहे हैं। यह ऐतिहासिक बात हुई राजस्थान की सरकार के लिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि पिछले दो वर्षों में सरकार ने जिस तरीके से राजस्थान की जनता को यह सम्बल प्रदान किया है, वह तारीफ के काबिल है। अब ये तारीफ करना चाहें या नहीं करना चाहें, यह इनकी मर्जी है लेकिन आम जनता इसका स्वागत कर रही है और इन्हीं की सरकार के यू.पी. के मुख्य मंत्री राजस्थान की जनता से, राजस्थान के अफसरों से यह पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसा बजट पेश किया, अशोक गहलोत साहब ने ऐसा कैसा प्रबन्ध किया। यह इनके ही मुख्य मंत्री पूछ रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि पहली दफा नरेगा का, जो शहर में इन्दिरा शहरी रोजगार गारंटी योजना की जो शुरुआत की गयी है, इससे राजस्थान की सरकार से दूसरे प्रदेशों को भी शिक्षा लेनी चाहिए और हिन्दुस्तान में इस योजना को लागू करना चाहिए। शहर के अन्दर जो रोजगार की, शहर में जो बेरोजगारों को रोजगार की दिक्कत हुई कोरोना काल के दौरान, हमारा जो रेहड़ी चालक था, वेंडर थे, हाथ से काम करने वाले दस्तकार थे, उनका ख्याल करते हुए मुख्य मंत्रीजी ने

(श्री जगदीश चन्द्र)

मानवता का एक पक्ष दिखाते हुए, शहर के अन्दर 100 दिन की रोजगार गारंटी का प्रावधान करना यह बड़ी बात ही नहीं है बल्कि यह बहुत बड़ी बात है और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस शहरी रोजगार योजना के लिए 800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

माननीय सभापति महोदय, जब वर्ष 2004-05 में यह नरेगा योजना स्टार्ट की गयी, आज मैं सदन के माध्यम से आपसे यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि तब इस देश में विपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी हुआ करते थे। जब नरेगा लोक सभा में आया तो इन्हीं की पार्टी के लोगों ने नरेगा का विरोध किया था और इन्हीं की पार्टी के नेताओं ने नरेगा को गड्ढा बताया था और आज स्थिति यह है कि नरेगा को यह बन्द तो कर नहीं सकते पर उसमें पैसा जरूर घटा दिया है। 25 परसेंट पैसा घटा दिया ताकि वह आटोमैटिक ही नरेगा बन्द हो जाये। नरेगा को सीधे बन्द तो कर नहीं सकते क्योंकि यह सेंट्रल एक्ट है, सेंट्रल एक्ट में पार्लियामेंट में आपको बिल लेकर आना पड़ेगा इसलिए उसका पैसा घटा दिया। इन्डाइरेक्ट तौर पर उनको इस बात की चिन्ता हो गयी कि नरेगा में काम करने वाले जो लोग हैं, वे इनकी पार्टी के पक्ष के लोग नहीं हैं, इनको वोट नहीं करते हैं। इस बात की चिन्ता इनको सताने लगी है इसलिए नरेगा का पैसा कम कर दिया। धीरे-धीरे पैसा कम करके यह नरेगा की योजना को बन्द करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्रीजी ने नरेगा को 125 दिन किया है। यह हमारे घोषणा पत्र में बात भी थी इसलिए हमने इसमें 125 दिन किये हैं।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि कोरोना काल के दौरान शिक्षा में जो बच्चों का नुकसान हुआ था, इस बात को भी हमारे शिक्षाविदों ने महसूस किया और मुख्य मंत्रीजी से चर्चा की। काफी बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, स्कूल बन्द थे, बच्चों का मानसिक तौर पर और सामाजिक तौर पर नुकसान हो रहा था, फिजिकल एक्टीविटीज नहीं हो पा रही थीं, उसको ध्यान में रखते हुए मुख्य मंत्रीजी ने ब्रिज कोर्स स्टार्ट करने की घोषणा की है जिसमें करीब-करीब 20 करोड़ रुपये के आस-पास हमने इसमें प्रावधान किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि आये दिन बिजली की बड़ी शिकायत रहती है कि बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि 2013 से लेकर 2018 तक का जो समय था, आप जरा अन्दाजा लगाइये कि बिजली

(श्री जगदीश चन्द्र)

बोर्ड की क्या स्थिति थी? एक लाख बीस हजार करोड़ रुपये का घाटा छोड़कर गये थे, उसकी भरपाई करने के लिए सरकार को जरूरत थी लेकिन उसके बावजूद भी मुख्य मंत्री ने मानवता के आधार पर जो 100 यूनिट बिजली खर्च करता है उसको 50 परसेंट की हमने रियायत देने की घोषणा की है, यह मुख्य मंत्रीजी का स्वागत योग्य कदम है। 100 यूनिट तक 50 यूनिट फ्री बिजली और उसके साथ-साथ ही समस्त घरेलू उपभोक्ता राजस्थान के 150 यूनिट तक तीन रुपये का अनुदान, 150 से 300 यूनिट तक दो रुपये का अनुदान देंगे और 300 यूनिट तक का उपयोग करने वाले जो उपभोक्ता हैं, उनको स्लैब के आधार पर सरकार अनुदान देगी और इस योजना में 4500 करोड़ रुपये खर्च करने का सरकार का प्रावधान है, मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा की है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि सारे देश की जनता राजस्थान का जो स्वास्थ्य सम्बन्धी प्लान है, जो मुख्य मंत्रीजी ने शुरू किया है मुख्य मंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के माध्यम से, पिछली दफा जब मुख्य मंत्रीजी ने निरोगी राजस्थान का एक संकल्प लिया था, इस सदन में ये सारे लोग बैठे हुए हैं, पक्ष के लोग भी बैठे हुए हैं और विपक्ष के लोग भी बैठे हुए हैं, निरोगी राजस्थान को साकार करने की प्राथमिकता माननीय मुख्य मंत्रीजी की थी।

पहली बार मुख्य मंत्रीजी ने नि:शुल्क जांच योजना स्टार्ट की और फ्री में दवाइयां देना प्रारम्भ किया। जब फ्री में दवा देने की बात थी तब इन्हीं की पार्टी के लोगों के द्वारा सबसे ज्यादा विरोध किया गया। इन लोगों ने राजस्थान की जनता के सामने ऐसा भ्रम फैलाया कि नकली दवाइयां आ रही हैं, टीके नकली आ रहे हैं, फलां चीज नकली आ रही है बल्कि ज्यादातर इन्हीं के लोग सरकारी अस्पताल से दवाइयां लेते थे क्योंकि योजना को तो बन्द नहीं कर सकते थे। आप भामाशाह योजना लेकर आये। भामाशाह योजना के अन्दर किस प्रकार करप्शन हुआ, इस बात को राजस्थान की जनता जानती है। यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है और आज तक भामाशाह के पैसे बकाया पड़े हुए हैं। उसका भुगतान करने की स्थिति में आप लोग नहीं थे। वह लाइबिलिटी भी हमारे ऊपर आ गयी, जिसका भुगतान हमारी सरकार कर रही है।

सभापति महोदय, आज यूनिवर्सल हैल्थ सर्विस देने वाला अग्रणी राजस्थान बन गया है और जो पांच लाख रुपये तक का बीमा था, उसको

(श्री जगदीश चन्द्र)

हमने 10 लाख किया है। कितनी बड़ी बात है। सारी की सारी बीमारी उसमें कवर हो गयी हैं। मानवता के आधार पर अगर कोई स्टेट का मुख्य मंत्री या सरकार दवाई की व्यवस्था करती है, स्वास्थ्य की व्यवस्था करती है तो इससे बड़ा पुण्य का कोई काम नहीं हो सकता। हर सरकार अपनी तरफ से करती है लेकिन पुण्य और मानवता को ध्यान में रखते हुए मुख्य मंत्रीजी के इस फैसले की तारीफ की जानी चाहिए और निश्चित तौर पर दूसरे स्टेट के लोग भी इस बात को एडॉप्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि भारत के दूसरे किसी प्रान्त के अन्दर फ्री दवाई की कोई व्यवस्था होगी। पांच लाख रुपये का बीमा दुर्घटना के लिए, परिवार के किसी भी सदस्य की अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसको भी उसमें कवर कर दिया गया है ताकि कोई दवाई के मामले में चिन्तित नहीं हो। आज आप प्राइवेट अस्पताल में जाओ, वहां पर पांच सौ रुपये तो घुसने के लगते हैं, जांच के अलग से पैसे लगते हैं। जब दवाई लेकर आयेंगे तो कम से कम 10-12-15 हजार रुपये का बिल बनकर तैयार हो जाता है। कितनी बड़ी राहत की बात है। उस गरीब आदमी की स्थिति देखो जो दो सौ रुपये की दिहाड़ी करता है। इलाज के लिए पैसे नहीं होते थे और समय से पहले संसार से चला जाता था। मुख्य मंत्रीजी ने यह बहुत पुण्य का काम किया है। सरकारें आती जाती रहती हैं। माननीय कटारियाजी हमेशा यह बात कहते थे कि भगवान के लिए रहम करो। मैं आपके लिए कह रहा हूं कि आप भगवान के लिए रहम करो। कम से कम इस बात की तो तारीफ करो। आप लोगों को भी कवर किया गया है इसके अन्दर। आपको इस बात की तारीफ करनी चाहिए कि राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी की स्वास्थ्य बीमा योजना बिलकुल प्रशंसनीय है। उसकी सबको तारीफ करनी चाहिए। आम व्यक्ति को उसका पूरा फायदा हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, इस योजना के तहत 1 करोड़ 33 लाख परिवार जुड़ सकेंगे। 9 महीने में 7 लाख 41 हजार से ज्यादा लोगों ने 930 करोड़ रुपये का कैशलेस सरकार के अस्पताल से इलाज की सुविधा प्राप्त की है। कितनी बड़ी बात है। आगामी वर्ष में 5 से 10 लाख रुपये इसमें हो जाएंगे।

सभापति महोदय, अक्टूबर, 2011 में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने नि:शुल्क दवाई की योजना शुरू की थी। सबसे बड़ी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर किसी के पास कार्ड नहीं है, उसकी व्यवस्था भी कलेक्टर के माध्यम से कर दी है। यह कलेक्टर की जिम्मेदारी है कि उसका कार्ड बनाकर

(श्री जगदीश चन्द्र)

तुरन्त उसका इलाज किया जायेगा। पहले कोई न कोई ब्यूरोक्रेटिक प्राब्लम आती थी। कार्ड नहीं होता था तो इलाज हो नहीं सकता था और अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते थे। उसकी व्यवस्था भी सरकार ने कर दी है। सरकार की मंशा है कि यह योजना पूरी तरह से लागू हो।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में पिछले दो साल के अन्दर पहली बार जो हैल्थ का इन्फ्रास्ट्रक्चर था, निरोगी राजस्थान के माध्यम से मुख्य मंत्रीजी ने यहां घोषणा की थी, उस पर सरकार काम कर रही है। हमारी सारी सीएचसी को जिला अस्पताल में कन्वर्ट किया है, पीएचसी को सीएचसी में किया, सब-सेन्टर को पीएचसी में किया। यह कितनी बड़ी बात है। जरूरत के हिसाब से पूरे राजस्थान में सरकार इस पर काम कर रही है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 15 मेडिकल कालेज के लिए 3674 बैड की क्षमता के नवीन चिकित्सालयों का निर्माण किया जायेगा। कितनी बड़ी बात है, यह साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। नर्सिंग कालेज खुल रहे हैं। पंचायत समिति स्तर पर डायलिसिस की कहीं व्यवस्था नहीं थी। डायलिसिस की व्यवस्था पंचायत समिति पर, सीएचसी पर की जा रही है ताकि गुर्दे की बीमारी के इलाज हेतु किसी को जिला अस्पताल में नहीं जाना पड़े। साधन हो, नहीं हो, इसकी क्या गारन्टी है, मानवता को ध्यान में रखते हुए पंचायत समिति स्तर पर डायलिसिस की व्यवस्था राजस्थान सरकार ने की। इसके लिए मुख्य मंत्रीजी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा।

इसके साथ-साथ डेंटल की बड़ी समस्या हो गयी थी। गांव में दातुन करना लोग भूल गये थे इसलिए डेंटल की समस्या हो गयी। उसको भी ध्यान में रखते हुए हर पीएचसी लेवल पर डेंटल डाक्टर की व्यवस्था की है, डेंटल यूनिट की व्यवस्था राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने की है।

सभापति महोदय, आये दिन बीमारियां फैल रही हैं और हर जगह इस बात की चर्चा होती है कि हर चीज में मिलावट है, हर चीज में एडल्ट्रेशन है, उसको ध्यान में रखते हुए मुख्य मंत्रीजी ने पहल करते हुए जब पहली बार मुख्य मंत्री थे, तब भी उन्होंने इस पर ध्यान दिया, 'शुद्ध के लिए युद्ध', आज उसी को आगे बढ़ाते हुए मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान के अन्दर फूड सेफ्टी लैब का काम शुरू किया है। करीब 200 नये खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की भर्ती की

(श्री जगदीश चन्द्र)

जायेगी ताकि पूरे राजस्थान में इस बात का ध्यान रखा जाए कि कहीं मिलावट तो नहीं हो रही है। यदि मिलावट हो रही है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। सरकार इसके लिए संवेदनशील है।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि 10 नयी मोबाइल सेफ्टी वैन, कितनी बड़ी बात है, हम जो शुद्ध के लिए युद्ध का काम कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए, मोबाइल वैन की व्यवस्था की है।

सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान के अन्दर नवाचार स्थापित किये। वर्ष 2018 की तुलना में 2021 में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का सरकारी स्कूलों में नामांकन 20 परसेंट बढ़ा है और 3,820 सैकण्डरी विद्यालयों का सीनियर सैकण्डरी में अपग्रेड कर दिया गया है। यह आटोमेटिकली अपग्रेड कर दिया गया है क्योंकि सरकारी स्कूलों का जो टीचिंग स्टाफ है, इन्फ्रास्ट्रक्चर है, सरकार ने उसकी तरफ ध्यान दिया। एजुकेशन आफ क्वालिटी पर ध्यान दिया गया इसलिए जिस तरीके का लगाव सरकारी स्कूलों की तरफ बढ़ा है, मुख्य मंत्रीजी का संकल्प है कि राजस्थान के सारे के सारे सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हों, इसलिए सरकार ने ध्यान दिया है। आज स्कूलों में दाखिले का परसेंटेज जो बढ़ा है, वह इसी का परिणाम है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने नया आयाम स्थापित किया है। गांवों में उसी आदमी को पढ़ा लिखा माना जाता था जिसको अंग्रेजी आती थी। जिसको अंग्रेजी नहीं आती, उसको हमारे यहां आज भी पढ़ा लिखा नहीं मानते। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की जो शुरुआत की है, वह बहुत ही प्रशंसनीय काम है। आज पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन का जमाना आ गया। हर बच्चे के हाथ में स्मार्ट फोन रहता है, पूरी दुनिया से कनेक्टिविटी उसकी रहती है। अंग्रेजी की आवश्यकता को महसूस किया गया और राजस्थान में 5 हजार की आबादी के ऊपर एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले और सरकार ने फैसला किया कि 2022-23 के बजट में एक-एक हजार स्कूल ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खोले जाएंगे और करीब 10 हजार टीचर भी हम अंग्रेजी के भर्ती कर रहे हैं ताकि स्कूलों में टीचर की कमी नहीं हो। यह सरकार का बेहतरीन काम है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि सरकार ने करीब 200 करोड़ रुपये इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किये हैं। जहां साइंस लैब बननी है, एग्रीकल्चर लैब बननी है, नये भवन बनने हैं और नये भवन की

(श्री जगदीश चन्द्र)

मरम्मत होनी है, इसके लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। 19 जिलों में 36 कन्या महाविद्यालय हमने खोलने की घोषणा इस साल की है। 123 महाविद्यालय हमने पिछले बजट में खोले थे। यह उच्च शिक्षा की तरफ बढ़ता हुआ कदम है राजस्थान सरकार का।

सभापति महोदय, हमारे नर्सिंग, मेडिकल, तकनीकी, कृषि और पशुपालन कालेज खोलने के प्रार्थना पत्र जो पैण्डिंग हैं, सरकार ने दो महीने में इनका निस्तारण करने की बात की है। निश्चित तौर पर जब नये सेन्टर्स आयेंगे तो बच्चों को इस बात का फायदा होगा और टेक्निकल एजुकेशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे।

सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि स्पोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए पहली बार सरकार ने बड़े-बड़े फैसले किए हैं। जो ओलम्पिक गेम्स के मैडल के लोग हैं, जो एशियन गेम्स के मैडल के लोग हैं या दूसरे मैडल के लोग हैं, उनको सरकारी नौकरी देने का प्रावधान किया गया है और पहली बार खेलों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना की गयी है। जैसलमेर में हैण्डबाल की, डूंगरपुर में तीरंदाजी की, राजगढ़ में कबड्डी की खेल एकेडमी बनाने की घोषणा की और गंगानगर में एथलीट एकेडमी के भवन निर्माण की भी सरकार ने घोषणा की। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि लालगढ़ में राजस्थान के सबसे ज्यादा नेशनल प्लेयर हैण्डबाल के आते हैं, मैं सरकार से विनम्र आग्रह करूंगा कि लालगढ़ में भी एक हैण्डबाल की एकेडमी खोली जाए।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ रोजगार की बात की जा रही है। अभी आमेर से आने वाले माननीय सदस्य बड़े जोर-जोर से चिल्लाकर रीट की बात कर रहे थे। मैं उनसे निवेदन करते हुए याद दिलाना चाह रहा हूं कि 2016 और 2018 को याद करें। 15 लाख बच्चे रीट में बैठे और हमने रीट की परीक्षा करवायी और जैसे ही थोड़ी शिकायत की बात आयी, मुख्य मंत्रीजी ने एक मिनट नहीं लगाया। सरकार ऐसा कोई फैसला कर सकती है क्या? बोर्ड के चेयरमैन को बर्खास्त कर दिया गया। 40-50 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किये गये और जुलाई में दुबारा से परीक्षा आयोजित करने की घोषणा मुख्य मंत्रीजी ने की है तथा 32 हजार से बढ़ाकर 62 हजार पद करने की घोषणा की गयी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह

(श्री जगदीश चन्द्र)

रहा हूं कि नरेन्द्र मोदी साहब जब देश के प्रधान मंत्री बने थे, 26 मई वह तारीख भी मुझे याद है, जब इस देश में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात थी और पांच साल में 10 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी। अभी आंकड़ा बताकर गये हैं बीजेपी के अध्यक्ष कि बेरोजगारी का आंकड़ा कितना है, यह वह बताकर गये हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि जो 32 प्रतिशत आंकड़े की बात कर रहे हैं, जिस देश के प्रधान मंत्री ने 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देने की बात की है और अभी कुछ दिन पहले केन्द्र सरकार का बजट आया तो उस बजट में 2030 तक 60 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं। प्रधान मंत्रीजी की वह 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? इनको इस बात का पता नहीं। इस बात की भी सदन में चर्चा करनी चाहिए थी इन लोगों को। जिस प्रधान मंत्री के काल के अन्दर इस देश का हाईएस्ट बेरोजगारी का आंकड़ा है, वह राजस्थान का नहीं है, बाकी के बीजेपी के सूबों का अन्दाजा लगा लीजिए, क्या है। अगर कोई जिम्मेदार है, बीजेपी की सरकार इस बात के लिये जिम्मेदार है कि आपने समय रहते इसकी व्यवस्था नहीं की।

आपका कोरोना का मैनेजमेंट ठीक नहीं था, इसकी वजह से ही यह आंकड़ा जो पेश कर रहे हो, हो सकता है, यह आंकड़ा जरा वैरिफाई कर लें कि आंकड़ा ठीक है या गलत है। जरा देख लें, उसके बाद इसकी सदन में चर्चा करनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, जितनी भर्ती हमने की है, हमने तीन साल में जितने लोग भर्ती किये हैं, इन्होंने पांच साल में भर्ती किये थे। हमने तीन साल में भर्ती किये और सरकार ने 2 लाख नौकरियां हमने तीन साल में भर्ती की हैं और आगामी वर्षों में एक लाख अतिरिक्त पदों पर हम लोग भर्ती करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि 2013 से लेकर राजस्थान के अन्दर नौकरियां निकल रही थीं। आये दिन कोर्ट का स्टे होता था। कभी हाई कोर्ट का स्टे है, कभी कैट का स्टे है, कभी किसी और बात का स्टे है। अभी भी तो सरकार चल रही है, अभी तो किसी बात का स्टे नहीं हुआ, क्योंकि उस समय आपकी मंशा ठीक नहीं थी। आपकी हर चीज को पैंडिंग करने की आदत हो गयी थी। आज बच्चों की नौकरी भी लग रही है। आज सारे क्षेत्रों में नौकरी लग रही है। कहीं पटवारी नहीं था, कहीं

(श्री जगदीश चन्द्र)

तहसीलदार नहीं थे, कहीं बाबू नहीं थे, कहीं सेक्रेटरी नहीं थे। आज सारे के सारे लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? आप खुद क्वेश्चन लगाते हैं, सरकार से पूछते हैं कि कौनसे डिपार्टमेंट में भर्ती कब तक हो जाएगी। आप अपनी अन्तरात्मा में झांककर देखिए कि आपने 2013 से लेकर 2018 में कौन-कौनसी भर्ती की थी, उसका लेखा-जोखा भी सदन के पटल पर आना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं पेयजल के मामले में आपने जल जीवन मिशन के तहत 60 लाख नल कनेक्शन देने की बात कही है। आप केन्द्र सरकार से यह तो पूछें कि मैचिंग ग्रान्ट का पैसा 90:10 का क्यों नहीं कर देती? इसके बारे में कोई चिन्ता नहीं है। डिग्गी का पैसा आपने बन्द कर दिया, नरेगा का पैसा आपने बन्द कर दिया और जल जीवन मिशन का पैसा आपने रोक दिया और आरोप लगा रहे हैं राज्य सरकार के ऊपर कि राज्य सरकार खर्च नहीं कर रही है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि राजस्थान सरकार ने 60 हजार 600 करोड़ रुपये से अधिक की लागत की परियोजनाओं को स्वीकृत किया है। 35,776 गांवों में फायदा होगा और 86 लाख 21 हजार घरों में नलों के कनेक्शन दिये जाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, जल जीवन मिशन के तहत 35 परियोजनाओं की डी.पी.आर. बनाने की घोषणा की गयी थी जिनमें से 11 परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं। आगामी वर्ष में 13 हजार 921 करोड़ की 24 परियोजनाओं का कार्य शुरू किया जाएगा। प्रदेश में 5,833 गांवों के 12 लाख 24 हजार से ज्यादा घरों को शुद्ध जल उपलब्ध होगा। यह छोटी बात थोड़े ही है। गांव-गांव में वाटर वर्क्स के काम चल रहे हैं लेकिन आप पिछले पांच साल का जरा बताएं कि पांच साल में आपने क्या किया? उसका लेखा-जोखा सदन के पटल पर रखें।

माननीय सभापति महोदय, पर्यावरण के क्षेत्र में हरियाली के लिये सरकार ने घोषणा की कि 50 लाख हैक्टेयर जमीन भी कि हम राजस्थान के क्षेत्र को हरा-भरा करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में बेरोजगारी की बात करें तो 32 प्रतिशत है। आप जरा यह तो बताएं कि आपकी सरकार के जमाने में कितना इन्वेस्टमेंट इस राजस्थान में आया? हमने इन्वेस्टमेंट के लिये सरकार में बहुत कोशिश की और इन्वेस्टमेंट राजस्थान, 2022 के तहत राजस्थान

(श्री जगदीश चन्द्र)

फाउण्डेशन के माध्यम से 2021-22 के प्रथम चरण में 24 उपखण्डों में हमने औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की थी। अब 32 उपखण्ड और नये शामिल कर रहे हैं। पचपदरा, बाड़मेर में 383 वर्ग किलोमीटर पेट्रो-कैमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन टी.सी.पी.आई.आर. में रीको के माध्यम से एक हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे और एक लाख चालीस हजार लोगों को उसमें रोजगार उपलब्ध होंगे। राजस्थान में सी.आई.एस.एफ. की तर्ज पर अलग से सिक्योरिटी फोर्स आफ इण्डस्ट्रीज का ध्यान रखेगी और दो हजार लोगों की भर्ती करने की भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है, यह स्वागत योग्य घोषणा है। इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद करना चाह रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं। लम्बे-चौड़े भाषण हो रहे थे कि राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा नहीं है, कानून एवं व्यवस्था ठीक नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं लखीमपुर खीरी को भूल गये क्या? देश के होम मिनिस्टर के लड़के पर हत्या के आरोप हैं। चार किसानों की हत्या के आरोप हैं, इसका जवाब है इन लोगों के पास में? भट्टा परसौल की घटना इनको याद है, व्यापमं की घटना याद है मध्य प्रदेश के लोगों को? शिवराज सिंह चौहान की सारी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, उसका याद है इन लोगों को? देश की स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी एम.बी.बी.एस. के गलत एडमिशन के दौरान उस पर चार्ज लगे थे, उसका जवाब है इनके पास में? माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि किसी पर पत्थर फेंकने से पहले देख लेना चाहिए कि खुद के घर शीशे के तो नहीं। पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। जरा अपने गिरहबान में झांके। इसी सरकार के, इसी पार्टी के जो आल इण्डिया के अध्यक्ष थे बंगारू लक्ष्मण, वह एक लाख रुपये की रिश्वत में पकड़े गये थे, उसकी भी चर्चा इनको करनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि राजस्थान सरकार ने एसटी., एस.सी. का ख्याल रखा। अलग से सदन में बिल पेश किया जा रहा है। पिछले दफा 100-100 करोड़ की राशि हमें दी गयी थी, अब की बार बढ़ाकर 500 करोड़ की राशि बढ़ाने की मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है, वह स्वागत योग्य घोषणा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि हमारे यहां सामान्य श्रेणी ईडब्ल्यू.एस. के लोग हैं, उनके लिये भी

(श्री जगदीश चन्द्र)

100 करोड़ का प्रावधान किया गया है ताकि उनकी भी सोशल सिक्योरिटी हो, उसकी व्यवस्था भी की गयी है।

इसके साथ-साथ, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कोरोना काल के दौरान लोग भूखे मर रहे थे। देखिए, मुख्य मंत्रीजी की संवेदना, इन्दिरा रसोई की शुरुआत की गयी थी और लोगों को आठ रुपये में खाना मिल रहा था। इनके जमाने में जो रसोई चलती थी, जिला हैडक्वार्टर के ऊपर खाना बनता था, वह बासी खाना मिलता था। हम तो बिठाकर सम्मान के साथ खाना खिला रहे हैं। राजस्थान में अतिथि को भगवान माना जाता है। हमारे इन्दिरा रसोई में जो भी खाना खाता था, उसको भगवान की तरह पूजकर खाना खिलाते हैं ताकि भूखा नहीं सोये और मुख्य मंत्रीजी का सपना भी है कि राजस्थान में कोई भी भूखा नहीं सोये। इसलिए राजस्थान में 358 से बढ़ाकर 1 हजार इन्दिरा रसोई खोलने की सरकार ने घोषणा की है, यह स्वागत योग्य है। इसमें 250 करोड़ रुपये सरकार खर्च करेगी।

माननीय सभापति महोदय, पालनहार योजना, कितनी बड़ी योजना है पालनहार योजना? विधवा, अनाथ बच्चों के लिये, इस सरकार ने 6 साल की आयु वर्ग के बच्चों को मिलने वाली राशि को 500 से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया है। इसके साथ ही 6 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की राशि को 1000 से 2500 रुपये तक कर दिया गया है। इस पर 20 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इससे 14 हजार बच्चों को फायदा होगा। यह कितनी बड़ी बात है कि बच्चों का ख्याल रखा गया है।

माननीय सभापति महोदय, खाद्य सुरक्षा की बात करूं। हमारे मुख्य मंत्रीजी की मंशा है कि पूरे राजस्थान में सब लोगों को राशन मिले, लेकिन दिल्ली सरकार ने तो पोर्टल ही बन्द कर दिया। अगर यह पांच राज्यों के चुनाव नहीं होते तो दिल्ली सरकार यह खाद्य सुरक्षा में कटौती भी करती। हमारे विपक्ष के माननीय साथी चले गये, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूं कि आप जरा देख लें कि एफ.सी.आई. में कितनी सब्सिडी है इस साल की। वह भी जरा डेटा देख लें, उसके बाद तय करें कि हमारा पोर्टल बन्द कर दिया, लेकिन मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद कि गरीबों का ख्याल रखते हुए एन.एफ.एस. से, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की पात्रता की सूची में 31 जनवरी, 2022 तक 10 लाख नये परिवार जोड़ने की घोषणा की है। यह बहुत बड़ी घोषणा है। कम से कम जो गरीब आदमी है, जिसको हाथ फैलाने में दिक्कत होती है, उसकी इज्जत और मान के लिये सरकार ने उसका ख्याल

(श्री जगदीश चन्द्र)

रखा और उसका खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने का फैसला किया गया, वह स्वागत योग्य फैसला है।

माननीय सभापति महोदय, हमारा राजस्थान का लम्बा-चौड़ा क्षेत्र है। यहां पर सड़कों की बहुत बड़ी दिक्कत थी। पिछली बजट घोषणा में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 10-10 किलोमीटर सड़क देने की बात कही थी। हर विधान सभा क्षेत्र में पांच-पांच करोड़ रुपये दिये गये, लेकिन मुख्य मंत्रीजी ने महसूस किया कि वह कम पड़ रहे हैं। सड़कें ज्यादा हैं, मिसिंग लिंक हैं, किसी के रिपेयर करने की बात है। इसमें यह सामने वाले विधायक भी शामिल हैं, मन तो इनका भी कर रहा है, जाकर मुख्य मंत्री को सड़कों के कागज दिये हैं, लेकिन मुख्य मंत्रीजी ने भेदभाव नहीं किया और पूरे राजस्थान की 200 विधान सभा क्षेत्रों के लिये दिया। चाहे वह किसी भी राजनीतिक पार्टी के हों, 200 विधान सभा क्षेत्रों के लिये मुख्य मंत्रीजी ने प्रत्येक जिले में से तीन महत्वपूर्ण सड़कों को लिया है मेजर रिपेयरिंग के लिये और उन पर 3,133 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके साथ ही प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपये की सड़कें, ग्रामीण क्षेत्रों में सात करोड़ की सड़कें और दो हजार करोड़ रुपये का इसमें प्रावधान किया है। नगर परिषद्, नगरपालिका और नगर निगम के लिये भी नगर परिषद् में 25 किलोमीटर, नगरपालिका में 15 किलोमीटर और नगर निगम में 40 किलोमीटर की जो सड़कें मेजर रिपेयरिंग की हैं, उसके लिये अलग से व्यवस्था की गयी है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसके लिये 1 हजार 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्टेट हाईवे, जो दो लेन के बनने हैं, ट्रैफिक ज्यादा हो गया तो इस बात को महसूस किया गया कि जो दो लेन के स्टेट हाईवे हैं, उन पर 1 हजार 200 करोड़ रुपये सरकार खर्च करेगी। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसमें 1200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ट्रैफिक ज्यादा हो गया, इस बात को महसूस किया गया। जो 2 लेन की स्टेट हाईवे है, उस पर 1200 करोड़ रुपये सरकार खर्च करेगी। यह सरकार की योजना है।

माननीय सभापति महोदय, कला, संस्कृति और पर्यटन की बात कर रहे थे। हमने पहली बार पर्यटन को इण्डस्ट्री का दर्जा दिया। वह राजस्थान का सोर्स आफ इनकम है। पर्यटन से सरकार की मेन इनकम है। राजस्थान को लोग पसन्द भी करते हैं।

(श्री जगदीश चन्द्र)

अभी आमेर से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे कि where is 'Nathi ka bada'? I just want to say him that go and talk to the CLP leader कि वह नाथी का बाड़ा कहां है? यह तो आप लोग बेहतर जानते हैं कि नाथी का बाड़ा कहां हो सकता है, लेकिन आपने राजस्थान की 8 करोड़ जनता का एक हफ्ते जो समय बरबाद किया, उसके लिए आपको खुद आत्म मन्थन करना चाहिए कि नाथी का बाड़ा कहां है। आप नाथी के बाड़े को ठीक से समझते। मुझे लगता है कि नाथी का बाड़ा तो माननीय राठौड़ जी के क्षेत्र में ही था। उन्हीं के ही क्षेत्र में है नाथी का बाड़ा। वह अच्छे तरीके से जानते हैं। वह डेस्टीनेशन कहां है, वह जरा अपने नेता को बता दें, ताकि इनको जाने में दिक्कत न हो।

श्री सभापति: इस नाथी के बाड़े को छोड़ें अब आप।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, सरकार की तरफ से यह भी तय किया गया, 500 करोड़ का प्रावधान किया गया था वह अब 1 हजार करोड़ की राशि कर दी। प्रत्येक जिले में 2-2 पर्यटन स्थल हम चिह्नित करेंगे ताकि लोगों को महसूस हो कि राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे कृषि बजट के बारे में निवेदन करना चाह रहा हूं। राजस्थान की लगभग दो तिहाई आबादी कृषि पर निर्भर है। स्टेट जीडीपी का 30 परसेंट खेती से आता है। सरकार ने इसका ध्यान रखा है। अलग से कृषि बजट का जो फैसला किया है, यह ऐतिहासिक है। बाकी स्टेट्स को भी इसका पालन करना चाहिए। 85 लाख परिवारों का जीवन-यापन खेती पर निर्भर है। 2 हजार करोड़ रुपये मुख्य मंत्री कृषक साथी योजना में पिछली बार तय किये गये थे। मुख्य मंत्री जी ने उसको बढ़ाकर के इस बार 5 हजार करोड़ रुपये किये हैं। 11 पाइंट, 11 मिशन का एजेण्डा कृषि को डवलप करने के लिये मुख्य मंत्री जी ने रखा है। वह एक ऐतिहासिक फैसला है।

माननीय सभापति महोदय, कृषि विकास एवं कृषकों के कल्याण हेतु कुल राशि 78,938 करोड़ 68 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। यह राशि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 5.92 परसेंट है। वर्ष 2021-22 में संशोधित अनुमानों की तुलना में 11.68 परसेंट अधिक है। कुल कृषि बजट में 46,145 करोड़ 20 लाख रुपये समेकित निधि से व्यय किये जायेंगे जो कि राज्य के एस्टिमेटेड बजट 2,94,182 करोड़ 83 लाख का 15.69 परसेंट है।

(श्री जगदीश चन्द्र)

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान किसानों का प्रदेश है। आम किसान को इस बात का अहसास होने लगा है कि किस-किस मद में कितना-कितना पैसा खर्च हो रहा है। पहले एक बजट होता था। उसमें एस्टिमेटेड पैसा दे दिया जाता था।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप वापस जाइये उधर से।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): अब की बार यह अलग से रखा गया है।

श्री सभापति: आप विराजें। एक मिनट। आप एक मिनट विराजें। माननीय सदस्य, मैं आपसे मुखातिब हूं। माननीय सदस्य गर्दन जरा ऊपर करिये। आप इधर देखें। माननीय सदस्य। मैं पूरे सदन को सम्बोधित कर रहा हूं। परम्परा यह रही है कि जब कोई वक्ता बोल रहे होते हैं तो दूसरा माननीय सदस्य उनको क्रास करके उनके सामने नहीं आता है। पहले तो वहां से वह माननीय सदस्य चले, आकर के यहां शकुन्तला रावत जी के पास बैठ गये। अब आप आ रहे हैं और सीधे आकर के यहां बैठ गये। परम्पराओं का निर्वहन करना बुरा लगता है क्या आप लोगों को? कौन सिखायेगा आप लोगों को? अब बैठे रहिये आप यहीं पर। आप सभी ध्यान रखेंगे इस बात का कि जब कोई माननीय सदस्य बोल रहा होता है तो उसको क्रास करने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत ही अत्यावश्यक काम हो तो आप या तो बाहर से आइये या उनके पीछे से आइये। बड़ा ही अजीब है कि बैठे-बैठे बोल रहे हैं, क्रास कर रहे हैं। यह कोई ओपन जगह नहीं है कि जहां आपकी जो मर्जी आये वह करें। यहां एक अनुशासन है। आगे से आप ध्यान रखेंगे। प्लीज, कोई अच्छी बात बताये तो उसको समझ भी लिया करो। जरूरी नहीं कि आप बैठे-बैठे ही बोलें। हम लोगों को भी यह सिखाया गया है तब हम यहां बैठे हैं। यहां बहुत माननीय सदस्य बैठे हुए हैं आप इनसे पूछें। वरिष्ठ सदस्य हम लोगों को सिखाते थे। न सीखने की मंशा है, न कुछ करने की मंशा है। जो मन हो वह करेंगे आप लोग? मैं इसको बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। यदि आगे से आप ऐसा करेंगे तो मुझे इसका संज्ञान लेना पड़ेगा।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, खेती के लिये पानी बहुत आवश्यक है। यदि पानी नहीं होगा तो खेती कैसे हो पायेगी? राजस्थान सरकार ने हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर जिले और जैसलमेर के

(श्री जगदीश चन्द्र)

लिये आईजीएनपी, गंग कैनाल और सरहिन्द फीडर के लिये 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। फिरोजपुर फीडर के लिए किया है ताकि किसानों के लिये 2700 क्यूसेक्स का जो बहाव है, वह पूरा हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि सरहिन्द फीडर की मरम्मत के लिये मुख्य मंत्री जी ने 425 करोड़ का प्रावधान किया है जो एक मील का पत्थर साबित होगा। इन्दिरा गांधी कैनाल में 1600 करोड़ उसकी मरम्मत के लिये, उसके अन्य कार्य करने के लिये सरकार ने रखे हैं, जिसके लिये मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि डेयरी और पशुपालन में आम आदमी का ध्यान रखते हुए मुख्य मंत्री जी ने सब्सिडी देने के लिए पहले शुरू किया था, पिछली सरकार ने बन्द कर दिया पर वापस मुख्य मंत्री जी ने 2 से 5 परसेंट किया। इसके लिये मुख्य मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कल हाउस के अन्दर यूक्रेन पर चर्चा हो रही थी। सरकार की तरफ से वक्तव्य आ रहा था। 3-3 लोग बोल रहे थे। नेता, विपक्ष ने कहा कि यूक्रेन में भारत सरकार के 4 मंत्री गये हैं, उनके बारे में भी चर्चा करनी चाहिए थी। दिसम्बर और जनवरी में पूरे यूरोप के अन्दर 28 कंट्रीज ने अपने सिटीजंस के लिये एडवाइजरी जारी कर दी थी कि आप लोग वापस आ जाओ, कभी भी लड़ाई हो सकती है, लेकिन भारत सरकार के प्रधान मंत्री यूपी के चुनाव में लगे हुए थे। देश की जनता की उनको कोई चिन्ता नहीं थी। क्यों नहीं एडवाइजरी जारी की गयी? यह सरकार का इंटेलीजेंस फेल्योर है। यह रॉ का फेल्योर है। आपको पता था कि लड़ाई हो सकती थी, युद्ध हो सकता है तो आपने क्यों नहीं एडवाइजरी जारी की? आपकी पहली एडवाइजरी 15 फरवरी को जारी हुई है। लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। हमारे बच्चे मर रहे हैं। आप बच्चों को लाने के लिये 26 तारीख को हवाई जहाज भेज रहे हो। आज तक यह नहीं मालूम कि कितने बच्चे कहां हैं। कोई पोलैण्ड में है, कोई रोमानिया के अन्दर है। विपक्ष के नेता को यह बात भी करनी चाहिए थी। यह तो कह दिया गया कि आपको उन नेताओं का नाम लेना चाहिए था। यह भारत सरकार का काम था।

मैं, आप सभी का और सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने

(श्री जगदीश चन्द्र)

सदन में चर्चा तो करायी। इस विषय पर चर्चा कराने की आवश्यकता नहीं थी। यह विदेश मंत्रालय का काम था, उनकी जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन इस तरह से सदन का समय जाया किया गया। जो यहां वक्तव्य आये थे, सरकार के खिलाफ जिन लोगों ने बोला वह ठीक नहीं था। सरकार की तरफ से जो व्यवस्था हो सकती थी, वह मुख्य मंत्री जी ने की। आज भी मुख्य मंत्री संवेदनशील हैं। सरकार के मंत्री और एमएलएज की ड्यूटी है कि वह अपने लोगों से इन टच रहें, लेकिन यह केन्द्र सरकार का फेल्योर है। यह उनको स्वीकार करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, यही फेल्योर कोरोना के दौरान हुआ। पूरी दुनिया में कोरोना की एडवाइजरी जारी हो गयी थी। आप तो गुजरात में ट्रम्प के स्वागत में लगे हुए थे। पूरे देश में आपने इण्टरनेशनल फ्लाइट्स को बन्द नहीं किया। इससे पूरे देश में कोरोना फैल गया। समय रहते हुए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने आपसे आह्‌वान किया था कि हिन्दुस्तान में कोरोना आ सकता है, लेकिन सरकार ने उस बात की परवाह नहीं की। इनको चुनाव की परवाह है। इनको चुनाव से लेना-देना है। मध्य प्रदेश की सरकार भी आपने कोरोना के दौरान गिरा दी।

अभी जिस तरह से चुनाव आयोग का फैसला हुआ था। आपने 7-7 फेजेज में चुनाव कराये हैं। आप 6-8 महीने पहले से लगे हुए थे। आपने इलेक्शन कमीशन को बंदी बनाकर 6-7 फेजेज में चुनाव करा दिये। लॉ एण्ड आर्डर की प्राब्लम पंजाब में नहीं थी क्या? एक फेज में पंजाब में चुनाव हुआ था। यूपी के अन्दर 7-7 फेजेज में चुनाव क्यों कर रहे हैं? अब कोरोना कहां चला गया? सभापति महोदय, हर चीज में सियासत नहीं होनी चाहिए। मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर भी फैसले होने चाहिए। संवैधानिक तरीके से भी फैसले होने चाहिए। यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है।

सभापति महोदय, विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर की 2-3 छोटी-छोटी मांगें हैं जो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा। हमारे यहां पानी की बहुत बड़ी समस्या है। फसलें खराब हो गयीं। खेतों में पानी नहीं था। किसान पर कर्ज चढ़ गया है। सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि या तो सरकार कर्ज माफ करे या उनका इंटरेस्ट माफ करे।

दूसरा निवेदन यह है कि भाखड़ा के क्षेत्र में पिछली सरकार ने एक भी

(श्री जगदीश चन्द्र)

खाला नहीं बनाया। पानी किसान के लिये मैन सोर्स है। भाखड़ा के खाले बनने चाहिए थे ताकि किसान अपनी व्यवस्था करे।

सभापति महोदय, यह बार-बार कानून-व्यवस्था की बात कर रहे थे। लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने माननीय मुख्य मंत्री जी पर प्रहार किया कि 8 बजे के बाद में शराब के ठेके खुले रहते हैं। आप 2018 का समय याद करो कि उत्तर भारत में गंगानगर सबसे बड़ी नशे की मण्डी थी। आपकी सरकार थी और पूरे राजस्थान में एक कहावत का चलन था, 8 पी.एम. आफ्टर नो सीएम। ये कहावत आपके राज के अन्दर थी। आज वो नशे की बात कर रहे हैं, आज वो इस तरह की बात कर रहे हैं। कोई आरोप लगाने से पहले तथ्य की बात करनी चाहिए, तथ्यहीन आरोप नहीं लगाने चाहिए। इस बात को महसूस करें कि 2013 से 2018 के दौरान राजस्थान में क्या हाल थे शराब के ठेकों के? किस तरीके से गली-गली में शराब बिक रही थी? कम से कम कंट्रोल तो किया हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने। हमने पब्लिकली उसको क्रिटिसाइज तो किया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि सरकार पर जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, इनको इस बात का मन्थन करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक सुशासन की बात है, पहली बार सैनिकों के लिए कल्याण भवन की स्थापना जयपुर में हो रही है। 20 करोड़ की लागत से बनेगा सैनिकों के लिए और यही सैनिकों का हम रैस्पेक्ट करते हैं। वो देश के लिए लड़ते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि रेवाड़ी की एक रैली में माननीय प्रधान मंत्रीजी ने वन रैंक वन पेंशन की बात की थी भूतपूर्व सैनिकों के लिए। एक तरफ तो कल्याण भवन बन रहा है सैनिकों की समस्याओं के समाधान के लिए और दूसरी तरफ वन रैंक वन पेंशन की बात करते हुए उसको भूल गये। विजय चौक पर जो शहीद स्मारक था, जो शहीद ज्योति जलती थी उसको शिफ्ट कर दिया गया। 1971 के शहीदों की याद में जो ज्योति जलती थी, उसको वार मेमोरियल में शिफ्ट कर दिया गया। एक तरफ तो वो सरकार है जो शहीदों की असत्य बात करती है और दूसरी तरफ राजस्थान की सरकार ने सैनिकों के लिए अलग से भवन का निर्माण भी किया है। यह बड़ी बात है, हम सैनिकों का पूरा सम्मान करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सातवां पे कमीशन, हमने सातवां पे कमीशन लागू करने की घोषणा की है। जो पेंशन योजना है उसका सारे देश में स्वागत हो रहा है, 01 जनवरी, 2004 से

(श्री जगदीश चन्द्र)

जो लगे हैं उनके लिए किया है, यह स्वागत योग्य कदम है। 60 लाख परिवारों को इसका फायदा होगा और माननीय मुख्य मंत्री महोदय को लोग दुआ दे रहे हैं। दुआ दे रहे हैं मुख्य मंत्रीजी को कि ऐसा फैसला किया है कि बुढ़ापे में रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों की जो दुर्दशा होती है उस दुर्दशा से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कम से कम बचाया तो है। दुआएं दे रहे हैं। इनके पास में क्रिटिसाइज करने के लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई जवाब नहीं है इस बात का। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो फैसला किया है वह बेहतरीन फैसला है।

इसके साथ-साथ हमारे जो नगरपालिका के पार्षद हैं, पंचायत समिति के डाइरेक्टर हैं, उनके मानदेय में भी 20 प्रतिशत बढ़ोतरी की है, उनकी भी इज्जत की गयी है। उनको आज तक कोई पूछता नहीं था, उनकी भी इज्जत की है माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ मीडिया है। उसकी कोई परवाह नहीं करता है। कोरोना के दौरान उन्होंने जो सेवाएं दी हैं, वो बेहतरीन हैं। अपनी जान पर खेलकर सारी चीज को बाहर लेकर आये और जनमानस को जाग्रत करने का काम किया। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 50 लाख तक की सहायता उनको प्रदान करने की घोषणा की थी वर्ष 2021-22 में, अब उसमें गैर अधिस्वीकृत पत्रकारों को भी शामिल कर लिया गया है। यह बड़ी बात है। इसके लिए धन्यवाद होना चाहिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय का।

माननीय सभापति महोदय, आपने बजट पर अपनी बात रखने का मौका दिया उस पर मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। इस बजट का मैं समर्थन करना चाहता हूं। राठौड़ साहब भी आ गये हैं। राठौड़ साहब, आपका भाषण था, आप चले गये, मैं चाहता था कि आप पर बोलूं। आपने अपने भाषण में पूरी स्टेटिस्टिक्स की बात की, आपने नाटो की बात की परसों, नाटो रशिया के खिलाफ एक आर्गेनाइजेशन है, रशिया से कोई लेना देना नहीं है, वह अमेरिका की स्ट्रेटिजी का पार्ट था। मेरा आपसे निवेदन है कि इंटरनेशल रिलेशनशिप को आप जरा ठीक से, ध्यान से देख लें और आप भी मुझे जरा समझा देना। बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिन्द।

श्री सभापति: ये आपका भाषण इनको समर्पित करके कापी इनको भिजवा देंगे। (व्यवधान) आपको ही समर्पित है ये, इसकी कापी भिजवाने की व्यवस्था करेंगे आपको। श्री नरपत सिंह राजवी।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय सभापति महोदय, लगभग 48 मिनट का भाषण सुनने के बाद नाटो और कहां-कहां पहुंचाया, लेकिन मैं मेरा भाषण सिर्फ बजट पर ही केन्द्रित रखूंगा।

माननीय सभापति महोदय, कोई भी स्टेट अपनी आर्थिक व्यवस्था के लिए आन टैक्स रेवेन्यू, नोन टैक्स रेवेन्यू, डिविजिबल पूल में से शेयर और लोन्स के आधार पर अपना वेज एंड मीन्स मेंटेन करता है। राजस्थान सरकार का अभी जो बजट पेश हुआ है, आपको याद दिलाना चाहूंगा, 2017 में एफआरबीएम पैनल बना था। उसमें स्टेट गवर्नमेंट डेट्स की 20 परसेंट की सीलिंग लगायी और सेंट्रल गवर्नमेंट पर 40 परसेंट की ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के आधार पर। वर्तमान में स्थिति अभी क्या है, इस गत बजट में 40 परसेंट जीएसडीपी, एसजीएसडीपी का डेट शेयर है। कैसे काम चलेगा? एक डेट ट्रेप में यह स्टेट फंसता जा रहा है, उसके ऊपर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। यह आरबीआई का डेटा है, हाइएस्ट जीएसडीपी रेशो 2020-21 में पंजाब का था जो 53.3 परसेंट था और दूसरे नम्बर पर राजस्थान विराजमान है जहां 42.6 परसेंट है। सीलिंग से लगभग डबल। यह बात सही है कि स्टडी इन्क्रीज 7.2 परसेंट का हुआ और 2020-21, 2021-22 में 39.8 परसेंट और वर्तमान 2022-23 में 40 परसेंट पर पहुंचने की पूरी-पूरी सम्भावना है। डेट लाइबिलिटीज 31.03.2019 तक मुख्य मंत्रीजी ने भी कई बार कहा, बहुत से वक्ताओं ने कहा, 311357 करोड़ रुपये का कर्ज बीजेपी के शासन तक हुआ। वर्तमान सरकार का यह चौथा बजट है, चार वर्षों में 220675 करोड़ का कर्ज लिया है। 31.03.2023 तक 531050 करोड़ तक लोन का भार 42 परसेंट बढ़ा है। यह कोई अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्थिति नहीं दिखाती है।

माननीय सभापति महोदय, 1991 से 1998 तक 9 वर्षों में 13000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था जब माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत मुख्य मंत्री थे। उस समय हमारे सदन के नेता पीसीसी के शायद अध्यक्ष थे और डिमांड की थी कि व्हाइट पेपर जारी करें। गत 3 वर्षों में जितनी घोषणाएं की हैं, वो ध्यान डाइवर्ट करने के लिए जरूर है, असफलता छिपाने के लिए बजट भाषण को लोक लुभावना बनाया, घोषणाएं कीं लेकिन राज्य की बिगड़ती हुई वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह सम्भव नहीं लगता। 100 गज तो नापते हैं, फाड़ते

(श्री नरपत सिंह राजवी)

सिर्फ एक गज हैं। बातें ज्यादा जोर की करते हैं लेकिन उनमें कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिखता नहीं। 2022-23 का बजट अभी 3,46,142 करोड़ का है, इसमें कर्ज का भाग 1,22,818 करोड़ का है, जो कि एक तिहाई से अधिक है, 35.5 परसेंट है। कर्ज लेकर वाल्यूम बढ़ा है, बचे हुए 2,23,364 करोड़ में से आन टैक्स रेवेन्यू 98,294 करोड़ और शेष जो राशि है उसका 50 प्रतिशत हिस्सा जीएसटी का है।

(समय: 14.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहा जा रहा है। अगर ये राशि और इतना हिस्सा नहीं मिलता, ये राशि नहीं बढ़ती तो इतना बढ़ा हुआ वाल्यूम बजट में नहीं दिखता। नॉन टैक्स रेवेन्यू 22,155 करोड़, कुल 1,20,448 करोड़ का भाग है, यह बहुत बड़ा पार्ट हो जायेगा। सैलरी में लगभग 60 हजार करोड़, पेंशन में 25,478 करोड़, इंटरेस्ट रीपेमेंट में 28,838 करोड़, 1,14,316 करोड़, ये नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर हैं।

इसके ऊपर कोई असैट निर्माण नहीं हो रहा। स्टेट का खुद का नॉन टैक्स रेवेन्यू है 1 लाख 20 हजार करोड़। स्टेट का शेयर है 39 हजार 211 करोड़ सेंटर से और ग्रांट है 45 हजार 338 करोड़। केन्द्र से 94 हजार 529 करोड़ रुपये मिले हैं, जबकि स्टेट की खुद की राजस्व प्राप्तियां और राजस्व भिन्न प्राप्तियां 1 हजार 20 लाख 448 करोड़ ही हैं। यह अगर मार्जिन हटा लें और देखें कि कितना गैप है तो स्टेट के पास कुछ रहता ही नहीं है। पूरे बजट में डिविजिबल पूल स्टेट फाइनेंस कमीशन तय करता है। पहले 28 परसेंट था। माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जब भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार के मुखिया रहे तो 32.50 परसेंट किया। अब नरेन्द्र भाई मोदी के प्रधान मंत्री बनने के बाद आज डिविजिबल पूल में 42 परसेंट राशि हमें मिल रही है।

सेंटर स्पान्सर्ड स्कीम्स कम करने के कारण केन्द्र से राशि जरूर कम हुई है। उसमें मैचिंग ग्रांट स्टेट को देना पड़ता है। हर एक बात के लिये केन्द्र को चिट्ठी लिखिये कि ये बजट से कर लेंगे। केन्द्रीय प्रोजेक्ट इसे बना लें। चाहे ईस्टर्न कैनाल का मामला हो, चाहे और किसी का, हरेक चीज केन्द्र पर ही डालनी है तो फिर 42 परसेंट डिविजिबल पूल में नहीं रह पायेगा। आपको पूरी कंट्री रन करनी है। उस आधार पर सोचें कि यह कैसे होगा।

अब इर्रिगेशन है। इर्रिगेशन में इंटर-स्टेट रिवर्स को लिंक करने की

(श्री नरपत सिंह राजवी)

बात है, शेयर्स निर्धारित करने की बात है तो स्टेट लिस्ट में से कान्करेंट लिस्ट में इस सब्जेक्ट को डालना पड़ेगा, तब जाकर इस समस्या का समाधान होगा। आज धारा 370 हटने के बाद पंजाब, अनडिवाइडेड पंजाब का पहले समझौता था, पंजाब के मुख्य मंत्री और जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर के बीच में एक समझौता साइन हुआ। एक डैम था, जिसका निर्माण पूरा नहीं हुआ था। उसका निर्माण चालू हो गया। 40 हजार क्यूसेक्स पानी हमारा उसमें से मिलेगा, जो डिविजिबल पूल में आयेगा। उसमें 52.52 परसेंट आईजीएनपी का हिस्सा है राजस्थान का। आज जितना पानी मिल रहा है, लगभग उतना ही पानी हमें और मिल जायेगा। इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करके डैम के निर्माण के साथ हम उसे यूज कर सकें, यह फीडर मेंटेनेंस हो रही है, पहली बार रिपेयर हो रहा है, दो किलोमीटर तो कच्चा ही था, लेकिन इसमें कैपेसिटी और बढ़ानी चाहिये ताकि 52.52 परसेंट आपका जो शेयर है, वह जब मिले तो आप उसे हैंडल करने की स्थिति में आ जाएं।

दु:ख के साथ कहना पड़ता है, मुख्य मंत्री जी को इसमें कम से कम एक चीज तो लिखनी चाहिये थी, करप्शन में रोज़ाना न्यूज पेपर में पढ़ते हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, लेकिन करप्शन को कर्ब करने के लिये एक्ट में आप क्या-क्या अमेंडमेंट लाना चाहते हैं? जो रेड हैंडेड पकड़ा गया है, उस कर्मचारी को डिसमिस करने के सिवाय और क्या रह जाता है? वह 20 साल मुकदमा लड़कर वापस नौकरी में भी आने की कोशिश करेगा और सारे पोस्ट-रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी लेना चाहेगा। Termination of services is the only answer. मैं सोचता था कि सदन के नेता शायद इसके लिये बिल लाते, लेकिन नहीं ला रहे हैं। पेंशन और पोस्ट-रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, ये भी हटने चाहिये थे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। छत्तरगढ़ में एक पटवारी पकड़े गये। उन्होंने सरकारी जमीनों की रजिस्ट्री करवायी। रजिस्ट्री करवाने के बाद जब एसीबी के माध्यम से पकड़े गये, एक कार्यकर्ता हमारे गये उनके पास और मिले जब कहा, यह तीन करोड़ रुपया मैंने कमाया है इसमें। सारी जिन्दगी नौकरी कर लूंगा तो तीन करोड़ रुपये नहीं कमा सकता। दो-तीन साल जेल में रह जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी अगर नीयत किसी की हो तो वास्तव में इस एक्ट में चेंज करना पड़ेगा, अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। इसमें सभी साथ देंगे, कौन मना करेगा? गबन के केसेज में, मैंने तो पंद्रह दिन पहले ही एक पत्र लिखा है, एक फाइनेंशियल एडवाइजर, उस पद के आदमी ने आईएएस के

(श्री नरपत सिंह राजवी)

द्वारा नॉट रिफंडेबल लिखे हुए में 'नॉट' को व्हाइट लाइनर से हटा दिया। एडिशनल चार्ज दूसरे पद का भी था। वह फाइल आयी। उस समय उन्होंने लेकर करोड़ों की राशि रिफंड कर दी। ऐसा अगर कोई करता है और आज भी सर्विस में है तो वह आगे भी कोई निहाल करने वाला नहीं है। सख्त कार्रवाई करनी चाहिये। मैं तो यहां भी निवेदन करना चाहूंगा कि कन्विक्शन के लिये, केस करने के लिये गवर्नमेंट की स्वीकृति की आवश्यकता भी नहीं पड़नी चाहिये।

महाराणा प्रताप के बारे में एक कमेंट किया गया। उस कमेंट का सोर्स क्या है? क्या अपने देश को आजाद रखना एक सियासी लड़ाई है? क्या महाराणा प्रताप ने सियासी लड़ाई की थी? सोर्सेज आपके जितने भी हैं, मोहम्मद गजनवी के 1022 से 1023 के बीच में, आथर हैं वी.डी. महाजन। उस किताब को पढ़ेंगे तो मीडियेवल हिस्ट्री आफ इंडिया का 7 पेजेज में मोहम्मद गजनवी के चरित्र के बारे में बताया, बहुत अच्छा चरित्र बताया। थे क्या? लुटेरे। सोर्सेज क्या हैं? चाहे आइना-ए-अकबरी हो, चाहे मुगलों के समय में जितने भी लिखे हुए हैं, तारीख-ए-फिरोजशाही, ताजुल मासिर, ये सैकड़ों बुक्स हैं। उन्हीं का ट्रांसलेशन अंग्रेजी या हिन्दी भाषा में हुआ और उसी को आधार मानकर हमने बच्चों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया और खुद ने भी पढ़ना शुरू कर दिया। उसी आधार पर कह रहे हैं, तब तो मुझे कुछ नहीं कहना, अदरवाइज यह शर्मनाक बात नहीं कहनी चाहिये थी। आत्मसम्मान से सराबोर होने वाले हर राजस्थानी पर इस प्रकार से आघात नहीं करना चाहिये था।

मुख्य मंत्री जी ने राजस्थान हार्टीकल्चर मिशन शुरू किया। एक अच्छी शुरुआत है। सब्सिडी 50 से 75 परसेंट की है, स्वागत योग्य है। इंडीविजुअल तारबन्दी पर भी अनुदान दिया। यह पहली बार हुआ है। चाहे ब्लू बुल या नीलगाय से परेशानी हो, आवारा पशुओं से परेशानी हो, उससे निजात मिलेगी।

इन्दिरा गांधी कैनाल की मरम्मत का भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया है, काम चल रहा है। पिछले साल भी चालू था, लेकिन लेवल्स का ध्यान अभी भी उतनी गम्भीरता से नहीं रखा जा रहा है। जो स्थायी मुकाम है, उससे लेवल्स अगर आप देखेंगे तो वाटर ओवरहैड कम से कम एक फुट का होना चाहिये हर मोगे का। उससे कम होगा तो किसान को नुकसान होगा। उन

(श्री नरपत सिंह राजवी)

शिकायतों के निराकरण के लिये भी कोई न कोई मैकेनिज्म डवलप करना चाहिये।

सभापति महोदय, एक और निवेदन करना चाहूंगा। आजकल प्रचलन हुआ है डीएलसी रेट से अधिक राशि में रजिस्ट्री कराने का। मुझे ध्यान है कि जयपुर में डीएलसी मीटिंग में हमने पूछा था, 27 परसेंट रजिस्ट्रीज ऐसी हुई हैं, जिन पर डीएलसी रेट से अधिक बिल्डर्स ने लिया है। एक केस में तो 9 लाख की प्रोपर्टी थी, 50 लाख में रजिस्ट्री करायी है। 80 परसेंट तक लोन उसे मिल जायेगा तो हींग लगे न फिटकरी, रंग अच्छा का अच्छा आ जायेगा उसके लिये तो, लेकिन वह एनपीए होगा तो छोड़ देगा उस प्रोपर्टी को कि आप नीलाम कर दो। बैंक का पैसा पब्लिक का है। एनपीए बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण यह बन रहा है। इसके बारे में भी मुख्य मंत्री जी को सोचना चाहिये और कोई न कोई रेमेडियल मेजर्स निकालने चाहिये।

मेडिकल एंड हैल्थ डिपार्टमेंट, हमारे पूर्व वक्ता सादुलशहर से आये हुए काफी कुछ कह रहे थे। फ्री टेस्ट्स और बढ़ाएं, यह तो अच्छा है। बहुत अच्छा कदम है गरीबों के लिये तो, लेकिन इन्फ्रास्ट्रक्चर उतना बढ़ा दिया क्या? सीएचसीज में डायलेसिस होगा, इतने नेफ्रोलोजिस्ट को आपने एम्प्लोई कर लिया क्या? क्योंकि डायलेसिस भी एक स्पेशियलिटी है, हरेक डाक्टर नहीं कर पायेगा। उतने डाक्टर्स अवेलेबल हैं क्या? सीएचसीज में अभी तक इतने अवेलेबल नहीं हैं जहां तक मेरी जानकारी है।

पी.एम. केयर से इतनी राशि मिली, बहुत इन्स्ट्रूमेंट्स मिले, आक्सीजन प्लांट्स भी मिले तो उसका कम से कम इंटरनल आडिट या ए.जी. आडिट तो करवा लें ताकि जहां-जहां पर उपयोग में नहीं आ रहे हैं उनकी जानकारी पूरी मिले।

सभापति महोदय, फ्री वैक्सीनेशन की बात आयी। वैसे तो मेडिकल एण्ड हैल्थ स्टेट सब्जैक्ट है पर प्रधान मंत्री जी को इस बजट के माध्यम से कम से कम धन्यवाद तो देना चाहिए था कि करोड़ वैक्सीनेशन राजस्थान में लगे हैं और फ्री लगे हैं। पैसे वाले तो फिर भी ले लेते हैं, रिएम्बर्सेबल जिसका है वे भी सर्विसेज अवेल कर लेते, लेकिन प्रधान मंत्री जी ने उस गरीब के बारे में सोचा है तो उनको धन्यवाद तो देने की स्थिति में आते। जितना राजनीतिकरण कैम्प्स के माध्यम से राजस्थान में हुआ है, हिन्दुस्तान के किसी भी स्टेट में नहीं हुआ। अब इसके बारे में ज्यादा तो मैं नहीं कहना चाहूंगा, इतना ही कहना चाहूंगा कि एक मैकेनिज्म ऐसा भी डवलप करें।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

अभी यूक्रेन में ज्यादातर टेक्निकल साइड के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं और हाहाकार भी मचा हुआ है। यहां पर एडमिशन कराने की जो स्थिति में नहीं है और बच्चा ब्रिलियंट है तो वह एक-एक बच्चे के 20 से 25 लाख रुपये देकर बाहर एडमिशन कराने की कोशिश करता है। इस फीस मैकेनिज्म को रेगुलेट करें। पी.जी. में अगर किसी को एडमिशन लेना है तो ढाई से तीन करोड़ रुपये की फीस लगेगी, underhand and overhand, whatever it is और उस स्थिति में यहां पर आपको पी.जी. स्टूडेंट्स की कमी रहती है। बाहर से पढ़कर आयेगा तो बाहर की कंट्रीज को लाभ मिलेगा और सैकड़ों करोड़, अरबों रुपये प्रतिवर्ष इस फीस के माध्यम से बाहर जा रहे हैं।

अब यह चिरंजीवी योजना अच्छी है, गरीब को इसका बहुत लाभ मिलेगा। गवर्नमेंट सर्विस में जितने भी हैं उनके लिए आरजीएचएस लागू की है, विधायकों के लिए भी यही की है। सभापति महोदय, आप भी विधायक हैं। जो एक्ट से आपको प्रिविलेजेज मिले हैं वे आरजीएचएस में नहीं मिल पायेंगे। वहां पर तो जो सूची है उस सूची में जो मेडिसिन है वही उस दुकान से मिल पायेगी, दूसरी नहीं मिलेगी। रिमेनिंग मेडिसिन का किस आधार पर वे रिएम्बर्श करायेंगे, यह आपकी जो स्कीम है यह अभी तक बोल नहीं रही है। इनमें जो एनोमोलीज हैं इनको दूर करना पड़ेगा नहीं तो अतिरिक्त दवाइयां जो लिखी गयी हैं, जो लिस्ट में नहीं हैं, वह नहीं मिलेंगी।

फ्री मेडिसिन की बात अभी सादुलशहर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे। 2008 में उस फाइल पर मेरा लिखा हुआ है कि अगर 15 परसेंट आप और बजट मेडिसिन के लिए दे दें तो इन्डोर पेशेंट को जेनेरिक मेडिसिन हम फ्री प्रोवाइड करा सकेंगे। उसके अतिरिक्त अगर थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन के जो एंटीबायोटिक्स हैं या जो जेनेरिक में नहीं आ रही हैं उनको बाजार से लेने की उस पेशेंट को जरूरत पड़ेगी। उसी फाइल को लेकर इन्डोर एण्ड आउटडोर दोनों को फ्री किया। हमने यहां एसएमएस हास्पिटल और मेडिकल कालेजेज में जेनेरिक मेडिसिन के टेंडर किये तो 140 परसेंट की कीमत में कमी आयी और उससे हम अधिक सेवा कर सके। चित्तौड़ और बांसवाड़ा में जेनेरिक मेडिसिन, जब मैं हैल्थ मिनिस्टर था, तब कम्पलसरी की और उसके आधार पर गरीब को लाभ मिला। उसी आधार पर आगे इसको एक्सपेरिमेंट करने के बाद पूरे राजस्थान में लागू किया लेकिन, सभापति

(श्री नरपत सिंह राजवी)

महोदय, टेस्ट कराने का अगर आप स्वयं जाकर एसएमएस में देखेंगे तो इतनी लम्बी लाइन है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप होने से पहले यह अलाउंसमेंट करना समझ से बाहर है।

प्रशासन शहरों की ओर, प्रशासन तो पूरा शहरों की ओर ही घूम रहा है। स्टेट टाइम का पट्टा हो या एन्सेस्ट्रल है, उसके वारिसों के नाम से करना हो तो दो-दो साल का समय लग जाता है। अब वह क्यों लगता है उसके कारण अलग-अलग हो सकते हैं। जहां कोई घालमेल नहीं है, प्योर एण्ड सिम्पल वही राइट, वही टाइटल जो हमारा पहले का था वह आगे पास-आन करना है तो उसको और सिम्पलिफाई करना चाहिए, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। जितना ज्यादा समय लगेगा उसमें उतनी ही भ्रष्टाचार की बू आयेगी।

(समय: 14.16 बजे)

(श्री जितेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, बजट में बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में और कहना चाहिए। एग्रीकल्चर बजट, वे 11 पाइंट्स देने के बाद में एग्रीकल्चर बजट हो गया? 100 करोड़ आपने डिग्गियों के लिए दिये हैं तो उन 100 करोड़ से कितने पॉण्ड्स बनेंगे? 15 हजार किसानों को लाभान्वित करेंगे, 15 हजार कितनी बड़ी आबादी है? सोलर के बारे में साइलेंट हैं। सोलर पम्प्स एग्रीकल्चर साइड में दिये जायें, सब्सिडी बढ़ायी भी जाये क्योंकि अधिकांश जगह तो इतना ओवर एक्सप्लायटेशन हो चुका है जहां पर ज्यादा गुंजाइश नहीं है, लेकिन जहां पर पानी उपलब्ध है वह स्टडी करके वहां पर करें तो पर-कैपिटा जो एक्सपेंडिचर लाइन ले जाने में और सर्विसेज पहुंचाने में लगता है उससे ज्यादा सस्ता सब्सिडी देकर सोलर पम्प से लाभ पहुंचाया जा सकता है। डिग्गियों का पिछले साल का और उससे पिछले साल का भी भुगतान मेरे ख्याल से इस साल फरवरी-मार्च में हुआ है और आने वाले बजट में उसका भुगतान कब होगा भगवान जाने। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री जी को सदन में प्रस्ताव के माध्यम से धन्यवाद दें कि फ्री वैक्सीनेशन किया है। उसके लिए प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दिया जाये। आपने समय दिया, इसके लिए आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री लाखन सिंह।

श्री लाखन सिंह (करौली): माननीय सभापति महोदय, बजट पर बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बारम्बार धन्यवाद देता हूं।

(श्री लाखन सिंह)

आदरणीय अशोक गहलोत जी ने 23 फरवरी, 2022 को सदन में जो बजट भाषण दिया उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ऐसा जोरदार बजट और ऐसा शानदार बजट राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने दिया है वह राजस्थान के महिला, युवा, वृद्धों, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनोरिटी, सबको ध्यान में रखकर दिया है। इस बजट के मौके पर जो राजस्थान में गरीब है और अन्तिम छोर पर बैठा है उसका भी बड़ा ध्यान रखा गया है।

इस बजट में चिकित्सा के सम्बन्ध में देखा जाये, क्योंकि मैं डांग क्षेत्र के करौली विधान सभा क्षेत्र से आता हूं और वहां पर गरीबी बहुत ज्यादा है और वहां पर 50 साल, 70 साल से आज तक कोई विकास नहीं हुआ। यह जो 15वीं विधान सभा है इस विधान सभा में इतना ज्यादा विकास हुआ है कि पिछले 50 साल एक साइड के हैं और 3 साल एक साइड के हैं।

इस बजट में चिकित्सा के रूप में देख लें, शिक्षा के रूप में देख लीजिए, बिजली के रूप में देख लीजिए। आज भी ऐसे गांव हैं, जहां बिजली नहीं है। मैं इस मौके पर धन्यवाद देता हूं आदरणीय मुख्य मंत्री जी को कि हमारे मासलपुर डांग क्षेत्र, जहां आज भी बिजली नहीं है। वहां पर 132 केवी की जो घोषणा की है, उसके लिए मैं उनको बारम्बार धन्यवाद देता हूं, क्षेत्र की जनता भी बहुत धन्यवाद दे रही है।

चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जो गांव का गरीब आदमी है, उसके पास इलाज कराने के लिए, आने-जाने के लिए पैसा नहीं है, हास्पिटल में दवाई खरीदने के लिए पैसा नहीं है। इस योजना से जो पिछले बजट में 5 लाख रुपये थी, इस बजट में 10 लाख कर दी, यह बहुत-बड़ी योजना है, इससे राजस्थान का गरीब जो अन्तिम छोर पर है वह बगैर इलाज के नहीं मरेगा। यह आदरणीय मुख्य मंत्री जी की सोच है।

मुख्य मंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा, यह जो दुघर्टना बीमा है, इसमें भी 5 लाख रुपये का बीमा है। पहली बार यह दुर्घटना बीमा किया गया है। गरीब के साथ एक्सीडेंटल कुछ हो जाता है। उस गरीब परिवार के बच्चे अगर पीछे रहते हैं तो उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए यह 5 लाख रुपये उनके लिये बहुत अच्छी योजना है और उनका जीवन चलाने के लिए, उनके बच्चों का पालन करने के लिए बहुत ही अच्छी योजना है।

(श्री लाखन सिंह)

जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत करने के लिए, इनमें काम कराने के लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 1000 उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे और नवगठित ग्राम पंचायतों पर इनको प्राथमिकता दी जायेगी। 50 उपस्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में और 100 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे।

युवाओं के लिए, रोजगार के साधन पिछली सरकार में आप लोगों ने देखे हैं, इस सरकार में भी आप लोगों ने देखे हैं। अब तक 1 लाख 25 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है और कुछ भर्तियां कर भी दी गई हैं तथा 1 लाख अतिरिक्त पदों पर भर्ती अगली बार की जायेगी। रीट की 31 हजार भर्तियां थीं, उनको कैन्सिल करके 62000 भर्तियां कर दी गयी हैं। आदरणीय मुख्य मंत्री जी का बेरोजगारों को रोजगार देने का यह एक बहुत अच्छा कदम है।

इन्दिरा रसोई इतना अच्छा साधन है कि गांव का गरीब शहर में जाता है और वह भूखा जाता है तो उसके पास होटल पर खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। अब तो वह इन्दिरा रसोई में जायेगा, कुर्सी पर बैठेगा, ताजा भोजन खायेगा, जिस तरह से कहीं होटल में खा रहा है। यह एक स्वागत योग्य कदम है। इसके 358 से 1000 केन्द्र खोलने की घोषणा की है, यह भी स्वागत योग्य कदम है। स्कूटियां 2 हजार थीं, उनको 5 हजार कर दिया गया है। काली बाई भील और देवनारायण योजना में 20 हजार से बढ़ाकर 31 कर दिया गया है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि करौली में साइबर पुलिस स्टेशन खोला गया है। मैं कहना चाह रहा हूं कि अभी 23 स्कूल सैकण्डरी से हायर सैकण्डरी किये गये हैं। ये करौली विधान सभा क्षेत्र में किये गये हैं। यह बहुत बड़ा कदम है। हमारे यहां शिक्षा का बहुत अभाव है इसलिए इससे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। जो बच्चे बाहर पढ़ने के लिए नहीं जा सकते, उनके लिए भी अपने ही गांव में सीनियर स्कूल मिलेगा। छात्राओं के लिए सीनियर स्कूल मिलेगा तो वे अपनी शिक्षा प्राप्त कर पायेंगी।

इंग्लिश मीडियम स्कूल, कभी सोचा नहीं गांव वालों ने कि हमारे गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलेगा। कभी सपने में भी नहीं सोचा, गांव वाले यह बोलते हैं। अब 5 हजार से अधिक की आबादी में सीनियर स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल वहां खुलता है तो बड़ी खुशी होती है। एक गांव का गरीब आदमी कभी शहर में नहीं जा सकता। एक लाख रुपये उसकी फीस लगती है, रहने के लिए कमरा चाहिए तो वह नहीं जा सकता। आदरणीय मुख्य मंत्री जी

(श्री लाखन सिंह)

शिक्षा के लिए इतना अच्छा इंग्लिश मीडियम का प्रावधान लेकर आये हैं, यह बहुत स्वागत योग्य है। गांव के लोग इसका बहुत ज्यादा स्वागत कर रहे हैं और आने वाले समय में इसका फल भी दिखाएंगे कांग्रेस पार्टी के लिए।

क्षेत्र में जो सड़क का प्रावधान है उसमें पिछली बार मुख्य मंत्री जी ने 5 करोड़ रुपये सड़कों के लिये दिये। इस बार देखा कि सड़कों की और आवश्यकता है तो इस बार भी 10 करोड़ रुपये सड़कों के लिए दिये हैं। यह एक स्वागत योग्य कदम है। नगर परिषद् में 25 किलोमीटर सड़क दी है, यह भी एक स्वागत योग्य कदम है।

कृषकों के लिए, मुख्य मंत्री कृषक साथी योजना थी। पहली बार मुख्य मंत्री जी के द्वारा किसानों के लिए जो कृषि बजट पेश किया गया है, इसे 2 हजार करोड़ से बढ़ाकर 5 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया। आप लोगों ने देखा है कि बिजली में भी 100 यूनिट तक कोई बिजली खर्च करेगा, उसके लिए 50 यूनिट बिजली फ्री है। डेढ़ सौ यूनिट तक 3 रुपये और 300 यूनिट तक 2 रुपये, तो यह भी एक बहुत बड़ा कदम है। जो गरीब गांव में बैठा है और उसको बिल जमा कराने में बड़ी दिक्कत होती है। जब खाने के लिए भी पैसे नहीं है तो उसके पास बिल के कहां से पैसे आयेंगे तो उसके लिए बहुत ही स्वागत योग्य कदम है।

महात्मा गांधी नरेगा योजना, बहुत पहले से बात चली आ रही है कि नरेगा योजना को सौ दिन की जगह सवा सौ दिन, डेढ़ सौ दिन कर दिया जाये, लेकिन केन्द्र सरकार ने इसको नहीं बढ़ाया। यहां से कई बार प्रस्ताव भी भेजे, लेकिन मुख्य मंत्री जी ने सौ दिन की जगह सवा सौ दिन किया है, यह एक स्वागत योग्य कदम है।

जो शहरी रोजगार योजना 100 दिन के लिए लागू की गई है, यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। शहर में भी गरीब लोग रहते हैं, जो बाहर से आकर वहां बसते हैं, मजदूरी करते हैं। उनको भी रोजगार अति आवश्यक था तो यह बहुत अच्छा कदम आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने उठाया है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि एक ईस्टर्न कैनाल की जो योजना है जिसको 13 जिलों की जीवनदायिनी कहा जाता है और इस योजना को ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया है। पूर्वी राजस्थान पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रहा है, जल स्तर नीचे चला गया है। यह इतनी बड़ी योजना है, जो 34 हजार करोड़ की है।

(श्री लाखन सिंह)

आदरणीय प्रधान मंत्री जी जब राजस्थान में आये, जयपुर और अजमेर में, उन्होंने घोषणा की थी कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया जायेगा और उसी आधार पर राजस्थान के व्यक्तियों ने एमपी के चुनाव में 25 के 25 एमपी जीताकर दिल्ली भेज दिये, लेकिन वे 25 एमपी यह नहीं कह रहे हैं कि आप जो घोषणा करके आये हैं, उस घोषणा का क्या हुआ। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि उन एमपीज को प्रधान मंत्री जी को यह याद दिलाना चाहिये कि आप घोषणा करके आये हो उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाये। जिस तरह से यहां पर पानी की बड़ी किल्लत होती जा रही है उससे आने वाले समय में जनता पलायन कर देगी।

इस मौके पर मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी को भी कहना चाहूंगा कि चम्बल का पानी जो वेस्टेज होकर जाता है और आगे जाकर समुद्र में मिल जाता है तो इसकी डीपीआर बनायी जाये। डीपीआर बनाकर मात्र 15 किलोमीटर दूर भद्रावती नदी है उसमें पानी डाल दिया जाये तो पांचना बांध में वह आ जायेगा और पांचना बांध में जब पानी आ गया तो छोटे-छोटे जो तालाब हैं जैसे पास में आगरी बांध, जगर बांध है और वह नदी में बह कर भरतपुर तक जायेगा और इधर से गंगापुर से यहां लिफ्ट करके वह माधोपुर भी चला जायेगा तो मैं यह कहना चाहूंगा कि अभी उसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं है, सिर्फ एक डीपीआर बनाकर उसकी योजना से चम्बल से पानी ला दें तो उस पानी को हम भरतपुर तक ले जायेंगे और भरतपुर ही नहीं हम उसको आगे दौसा तक भी ला सकते हैं। इस तरह की योजना और प्लानिंग है तो मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस डीपीआर की इसी सदन में घोषणा करें जिससे कि चम्बल का पानी अगर पांचना में आता है तो हमारे क्षेत्र में जो सूखापन है, जहां पर पानी नहीं है, 2000 फीट तक पानी नहीं है, लोग पलायन करने लग गये हैं तो उनका जीवन सुधर जायेगा और पीन के लिए पानी हो जायेगा। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि यह घोषणा जरूर करें।

कुछ मेरे क्षेत्र की मांग है। करौली चिकित्सालय को एक जगह शिफ्ट किया जाये। पुराना चिकित्सालय शहर में है और नया करीब दस किलोमीटर दूर है तो एक जगह नये में शिफ्ट कर दिया जाये और पुराने को सेटेलाइट में तब्दील कर दिया जाये।

(श्री लाखन सिंह)

करौली जिले की मासलपुर तहसील में भी पानी का बड़ा संकट है और वहां एक गदाखाल का नाला है जिस पर एक एनिकट बनाया जाए और उस एनिकट से जो पानी का बहाव आयेगा तो वह तालाबों में चला जायेगा जिससे उस क्षेत्र का जलस्तर भी ऊंचा हो जायेगा, इसलिए इसकी भी एक घोषणा कर दी जाये।

जिला मुख्यालय पर करौली में राजकीय अल्पसंख्यक बालिका आवासीय विद्यालय स्वीकृत किया जाये। ये मेरी कुछ मांगें हैं। ग्राम कटकल में उप तहसील व कन्या महाविद्यालय खोला जाये। यह मेरे क्षेत्र की मांग है। इस बार जो बजट दिया गया है, जिस तरह से पेंशन योजना लागू की गयी है कर्मचारियों की, आप लोगों ने देखा है वीडियो देखा है, हर गांव में हर जगह जाते हैं, लोग बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। इस बार मुख्य मंत्री जी ने बहुत अच्छा बजट दिया है। राजस्थान का बजट बहुत अच्छा आया है तो इसलिये इस बजट के लिए मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मैं ही नहीं, राजस्थान की पूरी जनता मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देती है। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: माननीय श्री नारायण सिंह देवल।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, सदन के नेता ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जो बजट पेश किया, यह सरकार का चौथा बजट है और जिस तरह से घोषणाओं के हवाई किले बना दिये केवल थोथी घोषणाओं का यह पुलिन्दा है और आंकड़ों के मकड़जाल से ज्यादा कुछ नहीं है। कांग्रेस ने चुनाव से पहले जन घोषणा पत्र में असत्य वादे किये और राजस्थान की जनता को भ्रमित करके चुनाव जीत लिये। सरकार बन गयी। आज भी इनकी जन घोषणाएं अधिकांश अधूरी पड़ी हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार हवा-हवाई चल रही है और इनके मंत्रियों को लोगों से मिलने का समय नहीं है।

सभापति महोदय, 10 जुलाई, 2019 को जब मुख्य मंत्री जी ने पहला बजट पेश किया उस बजट के बिन्दु संख्या-7 में कहा कि हम सच्चे सिद्धांतों की राजनीति करते हैं और यह भी कहा गया कि हम आम आदमी, युवा और किसानों की अपेक्षाओं को समझते हैं। क्या हुआ उन सच्चे सिद्धांतों का? क्या हुआ आपके विजन डाक्यूमेंट का? क्या हुआ आम आदमी का और क्या हुआ

(श्री नारायण सिंह देवल)

राजस्थान के युवाओं का? युवा आज अपने आपको ठगा महसूस कर रहा है। रीट की जो परीक्षा हुई जिस तरह से इससे पहले पेपर हुए सारे पेपर लीक हुए और जो मेहनती ईमानदार युवा था वह आज अपने आपको ठगा महसूस कर रहा है।

सभापति महोदय, कांग्रेस के अन्तरराष्ट्रीय नेता विधान सभा चुनाव से पहले हमारे जालौर जिला मुख्यालय के स्टेडियम में दस की ताली बजाई जैसा कि राजस्थान की जनता को एक से लगाकर दस गिनना आता नहीं और कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो किसानों का दस दिन में सम्पूर्ण ऋण माफ हो जायेगा। सभापति महोदय, 2.5 लाख किसान राजस्थान में ऋण माफी का इंतजार कर रहे हैं। 1 लाख 20 हजार करोड़ से अधिक का कर्जा राजस्थान पर है। मुख्य मंत्री जी ने आदेश दे दिया कि किसानों की जमीन कुर्क नहीं होगी। मुझे बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि रोडा एक्ट के तहत किसानों की जमीन कुर्क हो रही है। किसान आये दिन राजस्थान में आत्महत्या कर रहे हैं और कांग्रेस सरकार की फितरत में है कि कोई न कोई नया शगूफा छोड़ते हैं। अब जो हमारे नेशनलाइज्ड बैंक हैं उनके लिए कह रहे हैं कि हमने केन्द्र में एक पत्र लिखा है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब इनके अन्तरराष्ट्रीय नेता ने ऋण माफी की घोषणा की तब कोई प्रधान मंत्री जी से उन्होंने पूछा था क्या कि मैं ऋण माफी की घोषणा करूं या नहीं करूं, तो इनका यह बजट जो चौथा बजट है यह ऋण माफी की तरह ही साबित होगा।

सभापति महोदय, इन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि पांच लाख युवाओं को हम नौकरी देंगे। क्या हुआ पांच लाख नौकरियों का? मात्र तीन साल में एक लाख नौकरियां दे पाये जो मेरी समझ से परे है। अब सरकार की उलटी गिनती चालू हो गयी। इनके पास 19 महीने रहे हैं। 6 महीने पहले आचार संहिता लग जायेगी तो ये चार लाख नौकरियां कैसे पूर्ण करेंगे यह हमारी समझ से तो परे है। जो भारतीय जनता पार्टी, बेरोजगार संघ और युवाओं ने मांग की है कि रीट के नाम से चीट हुई है इसकी सीबीआई से जांच हो, तब बड़े हाथी पकड़ में आयेंगे नहीं तो ये बड़े हाथी पकड़ में नहीं आयेंगे। छोटे-छोटे लोगों को ये गिरफ्तार कर रहे हैं तो मेरी मांग है कि सीबीआई से इसकी जांच हो।

(श्री नारायण सिंह देवल)

इन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो बेरोजगारों को हम 3,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। सभापति महोदय, आज तक मात्र 3 लाख 54 हजार बेरोजगारों को भत्ता मिला है। प्रदेश में 16 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं और 13 लाख बेरोजगारों ने क्या पाप किया है जिनको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है? सीएमआई की रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे अधिक बेरोजगारी राजस्थान में है। राजस्थान में बेरोजगारी की दर 32 परसेंट है और करीब 65 लाख बेरोजगार राजस्थान में है। इनके घोषणा पत्र में था कि हमारी सरकार बनेगी तो संविदाकर्मियों को हम स्थायी कर देंगे, क्या हुआ उस वादे का? तीन लाख से ज्यादा संविदाकर्मी आज कल्ला कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। सभापति महोदय, अभी तो सब यही कह रहे हैं कि ऊपर अल्ला है और नीचे कल्ला है, चारों तरफ यही हल्ला है। राजस्थान की आम जनता के मुंह पर यह वाक्य आ गया है। बजट में संविदाकर्मियों का मानदेय 20 परसेंट बढ़ाकर उन संविदाकर्मियों के साथ बड़ा अन्याय किया है। सभापति महोदय, राजस्थान के तीन लाख संविदाकर्मी हैं, यह इस कांग्रेस सरकार को कभी माफ नहीं करेंगे। अभी भी समय है चेत जाओ, नहीं तो मिनी बस लायक भी अगले चुनाव में आप लोग आओगे नहीं। जयपुर में आये दिन धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। संविदाकर्मी आज भी जयपुर में बैठे हैं, परन्तु इस सरकार में सुनने वाला कोई नहीं है।

कोरोना के नाम पर यह सरकार बहुत पीठ थपथपा रही है। सभापति महोदय, हमारा देश बहुत बड़ा देश है। देश के प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिये कि कोरोना काल में पूरे देश में फ्री वैक्सीनेशन का काम किया। सामने जो हमारे साथी बैठे हैं, इन्होंने वैक्सीन के नाम पर भी भ्रम फैलाया। कभी तो लोगों में यह शगूफा छोड़ दिया कि इस वैक्सीन को लेने से आपकी आयु कम हो जायेगी, कभी कुछ शगूफा छोड़ा, परन्तु राजस्थान की जनता ने देश के प्रधान मंत्री जी पर विश्वास किया और आज खुशी है कि पूरे देश में फ्री वैक्सीनेशन हुआ। युवाओं का वैक्सीनेशन हो रहा है।

सभापति महोदय, इस सरकार ने घोषणा की थी कि कोरोना काल के तहत कोई सरकारी कर्मचारी कोरोना ड्यूटी कर रहा है और अगर उसकी मौत हो जाती है तो यह सरकार 50 लाख रुपये की राशि उस पीड़ित परिवार को देगी। सभापति महोदय, सदन के नेता जब रिप्लाई दें तब यह बता दें कि

(श्री नारायण सिंह देवल)

राजस्थान में जो सरकारी कर्मचारी काल कवलित हुए उनमें से कितने लोगों को यह आर्थिक मुआवजा दिया है। सभापति महोदय, रानीवाड़ा की ग्राम पंचायत सरनाउ के संविदाकर्मी पंचायत सहायक स्वर्गीय मांगीलाल विश्नोई 10 अक्टूबर, 2020 को कोरोना की ड्यूटी करते-करते काल कवलित हुए। आज एक साल चार महीने हो गये हैं, मैंने कई बार मंत्री जी से आग्रह किया, 50 लाख तो छोड़ो, एक रुपया उस परिवार को इस सरकार ने नहीं दिया है और कोरोना के नाम पर आप वाहवाही ले रहे हो। अभी चार दिन पहले मेरा एक सवाल लगा था, उसमें मंत्री जी ने जवाब दिया कि हम जो सहायता दे रहे हैं उसमें 75 परसेंट केन्द्र सरकार दे रही है और आप मात्र 25 परसेंट दे रहे हो। मैं तो आपसे कहना चाहूंगा कि इस सदन के माध्यम से प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिये कि आपने इस कोरोना काल में राजस्थान की जनता को संभाला है।

सभापति महोदय, हमारे कांग्रेस के सदस्यगण वित्तीय प्रबंधन के नाम पर बहुत बड़ी-बड़ी बातें कहते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 2003-04 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब राजस्व घाटा 3424 करोड़ था और जब 2007-08 में सरकार बदली, उस समय तक 1653 करोड़ का सरप्लस करके कांग्रेस की सरकार को सौंपा। फिर 2008-13 में कांग्रेस की सरकार बनी तो इस सरप्लस को बदलकर एक बार फिर 2500 करोड़ का राजस्व घाटा करने का काम कांग्रेस सरकार ने किया। 2003-08 में जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, बिजली कंपनी के ऊपर मात्र 15 हजार करोड़ का घाटा था। 2008-13 में कांग्रेस की सरकार आई तो उस घाटे को चार गुना बढ़ाकर 75 हजार करोड़ करने का काम इस कांग्रेस की सरकार ने किया। तीन साल में 1,25,337 करोड़ का कर्ज इस सरकार ने लिया है। सभापति महोदय, अगर ओलम्पिक खेलों में कर्जा लेने की रेस हो जाय तो मेरे हिसाब से सबसे पहले स्वर्ण पदक इस कांग्रेस की सरकार को मिलेगा। मशहूर ओलम्पियन हुसैन बोल्ट भी आपका पीछा नहीं कर सकता।

सभापति महोदय, प्रदेश में 16 लाख किसानों के कृषि कनेक्शन हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको 833 रुपये की सब्सिडी देने का काम किया। इस सरकार ने तीन साल में वह सब्सिडी बंद कर दी और जब इनको लगा कि अब हमारी उलटी गिनती चालू हो गई है तब इन्होंने इस सब्सिडी की इस बजट में घोषणा की है। सभापति महोदय, अभी तक साढ़े पांच लाख किसानों

(श्री नारायण सिंह देवल)

को कृषि की सब्सिडी मिल रही है। साढ़े दस लाख किसानों ने क्या पाप किया है जिनको यह सरकार सब्सिडी नहीं दे रही है? आज ऊर्जा विभाग पर 58 हजार करोड़ का कर्जा हो गया है और सरकार इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रही है। कृषि कनेक्शन में पिछले तीन साल में एक साल आपने पैंडेंसी नहीं निपटायी और जिन किसानों ने डिमांड नोटिस भर दिये, डेढ़-डेढ़ साल तक उनको सामान नहीं मिल रहा है। एससी वर्ग को विशेष प्राथमिकता रहती है, उनको भी छह-छह महीने से सामान नहीं मिल रहा है। बिजली कंपनी के दफ्तरों में जाये तो कभी पोल मिलते हैं, पोल है तो तार नहीं है, तार है तो इंसुलेटर नहीं है और इंसुलेटर हो तो ट्रांसफार्मर नहीं है। सभापति महोदय, पूरा राजस्थान यह जानता है कि किसानों के साथ में इन्होंने कितना बड़ा खिलवाड़ किया है। किसान का अगर ट्रांसफार्मर जल जाये तो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 72 घंटे में ट्रांसफार्मर देने की व्यवस्था की जाती थी परंतु मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस सरकार में अगर किसान का ट्रांसफार्मर जल जाये तो 25-25 दिन, महीना-महीना ट्रांसफार्मर मिलता नहीं है और अगर सब कुछ मिल भी जाय तो इनके पास बिजली नहीं है। हमारे देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली राजस्थान में मिल रही है।

अभी चुनाव से पहले ऋण माफी की घोषणा हुई। इसी तरह से सदन के नेता ने इस बजट में 22 फरवरी, 2022 तक सभी किसानों के आवेदनों पर कनेक्शन देने की घोषणा की। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा परंतु यह सरकार तीन साल में एक साल के कनेक्शन भी नहीं दे पाई तो यह 10 साल की पैंडेंसी डेढ़ साल में निपटा नहीं सकती। यह मात्र एक थोथी घोषणा साबित होगी। सभापति महोदय, सभी किसानों को कनेक्शन देने के लिये 33 केवी के सब स्टेशन चाहिये, 132 केवी के जीएसएस की आवश्यकता होगी। सभापति महोदय, वाई-फाई में तो बिजली जायेगी ही नहीं। आपके बजट की घोषणाओं का क्या हाल है ?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कन्क्लूड करें।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): बस कर ही रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि 2019-20 में और 2020-21 में 16 जिलों को दिन में बिजली देने की बात कही थी। जालौर में आज बिजली नहीं मिल रही है।

माननीय सभापति महोदय, सरकारी बैंक और सहकारी समितियों से

(श्री नारायण सिंह देवल)

काश्तकार लोन लेता था, उस काश्तकार का बीमा 10 लाख का था, उसे घटाकर सरकार ने अब 3 लाख का कर दिया है। 26 लाख किसानों के बीमा होने थे, जबकि इस सरकार ने मात्र 8 लाख किसानों का बीमा किया है। 18 लाख किसान आज भी वंचित हैं। जो काश्तकार वंचित हैं, उनकी अगर किसी दुर्घटना में मौत हो गयी तो उसे न तो क्लेम मिलेगा और न ही उसके बैंक का कर्जा चुक पायेगा। सभापति महोदय, जो 2020-21 का बजट था, वह 3118 करोड़ था, वह संशोधित अनुमान बढ़कर 4489 करोड़ हो गया। अभी जो 2022-23 का बजट है, उसे आधा कर दिया है। सभापति महोदय, डीजल और पेट्रोल की रेट सबसे ज्यादा हमारे राजस्थान में है।

अन्त में, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांगें रखूंगा। सभापति महोदय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रानीवाड़ा में ट्रोमा सेन्टर खोला जाये। सभापति महोदय, हमारे यहां एमडी और स्मैक की बहुत नशावृत्ति फैल रही है, इसलिये सांकड़ पुलिस चौकी को थाना बनाया जाये। सभापति महोदय, मेरे यहां पर माइनिंग एरिये में एक रोड है, रानीवाड़ा-मेड़ा-ताबीदर-चाटवाड़ा, माइनिंग डिपार्टमेंट उनसे पैसे भी लेता है। इस बजट में इसकी घोषणा करें ताकि लोगों को फायदा हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री रफीक खान।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, आपने मुझे 2022-23 के बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, बजट इतना अच्छा था, इतना इंस्पायरिंग था कि हर आदमी के मन में भी यह आ गया कि बजट के लिए भी दो शब्द लिख दिये जाएं। मैंने बजट के लिए दो पंक्तियां लिखी हैं-

‘आ लिख दूं कुछ बजट के बारे में,
गरीब किसान, युवा, बेरोजगार, हर खास-ओ-आम का ख्वाब लिख दूं,
विपक्ष के हर उलझे हुए सवाल का जवाब लिख दूं,
आ लिख दूं कुछ तेरे बारे में, आ लिख दूं कुछ बजट के बारे में।
असर तो इतने हैं कि किताब लिख दूं,
मुख्य मंत्री का बजट तो ऐसा है कि लाजवाब लिख दूं।।'

मुख्य मंत्री जी ने 2022-23 का ऐसा बजट यहां पर प्रस्तुत किया

(श्री रफीक खान)

और किसी भी वर्ग को निराश नहीं किया। हर वर्ग को कुछ न कुछ देने की कोशिश की है। एक बजट केन्द्र सरकार ने भी पेश किया है। केन्द्र सरकार ने बजट पेश किया है, वह बिना कोई एसेट बनाने वाला, दिशाहीन, बेरोजगारों का नाम नहीं, गरीब का नाम नहीं, किसान का नाम नहीं, ऐसा बजट केन्द्र सरकार ने प्रस्तुत किया है। यहां पर ऐसा बजट प्रस्तुत किया, जिसमें आप बजट पर खर्चा कर रहे हो तो राजस्थान स्टेट को कुछ न कुछ दे रहे हो। मेडिकल कालेज दे रहे हो, स्कूल दे रहे हो, बिल्डिंग दे रहे हो, इन्फ्रास्ट्रक्चर दे रहे हो, सड़क दे रहे हो। सारी मूलभूत सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान सरकार ने यह बजट यहां पर प्रस्तुत किया है।

मैं आपको 2004 से 2014 के 10 साल मनमोहन सिंह जी की समय की याद दिलाना चाहूंगा। जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधान मंत्री थे तो देश की आजादी से लेकर आज तक अगर हिन्दुस्तान की सम्पत्ति में, आम आदमी की सम्पत्ति में अगर किसी समय में ग्रोथ हुई तो 2004 से लेकर 2014 के बीच में हुई। हर आदमी की सम्पत्ति में ग्रोथ हुई। व्यापार ऐसे बढ़े कि पान वाले के पास पैसा, ठेले वाले के पास पैसा, दुकानदार के पास पैसा, हर आदमी के पास पैसा आया। सभापति महोदय, 2014 के बाद ऐसा ग्रहण लगा कि पैसा खतम हो गया। मुझे अच्छे से याद है कि जब 2014 में केन्द्र में कांग्रेस की सरकार पलटी तो डॉलर की वैल्यू 50 रुपये थी। उस 50 रुपये को पहुंचने में आजादी से लेकर 2014 तक 60-65 साल लगे। इन 6-7 सालों में डॉलर 76 रुपये पहुंच गया, यानी कि 50 परसेंट से भी ज्यादा की गिरावट और पूरे देश की गिरावट। पिछले कोविड के समय में देश कि इकोनॉमी कैसे बच गयी? देश की इकोनॉमी इसलिए बच गयी कि पिछले दस सालों में देश के सर्वोच्च पद पर एक इकोनॉमिस्ट बैठा था। उनकी जो फाउंडेशन रखी हुई थी, उसकी वजह से देश की इकोनॉमी बची। 2014 के बाद में जिस तरह से इकोनॉमी चरमरायी, डिमोनेटाइजेशन आया, कोविड जैसी प्रॉब्लम से देश ग्रसित हुआ। सबसे बड़ा फायदा अगर आम और गरीब आदमी को हुआ और सबसे बड़ी राहत मिली तो वह नरेगा से मिली। नरेगा प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल की एक ऐसी योजना थी, जिसको न केवल राजस्थान की इकोनॉमी ने सराहा, बल्कि पूरे हिन्दुस्तान की इकोनॉमी ने सराहा और उसी से 30 करोड़ लोगों को रोजगार मिल पाया। मेरे पास नरेगा के सर्टेन फिगर हैं, उन्हें मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं क्योंकि मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस योजना में पिछले सालों में 1

(श्री रफीक खान)

लाख 11 हजार करोड़ का खर्चा है, उसका बजट ही इन्होंने 75 हजार करोड़ कर दिया, उसको रिड्यूस कर दिया। मैं इन लोगों के ऊपर इल्जाम लगाता हूं कि ये रोजगार उपलब्ध नहीं कराना चाहते, ये रोजगार खतम करना चाहते हैं। गरीब आदमी को, आम आदमी को मारना चाहते हैं। 2020-21 में पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर करीब 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिला और कामगारों की संख्या, वर्किंग डेज की संख्या और मैन डेज की संख्या 30 करोड़ थी। राजस्थान में बीजेपी के राज में पिछले पांच सालों में 5 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए, जबकि जब से हम सरकार में आये हैं हमने तीन सालों में 10 हजार करोड़ रुपये का खर्चा किया और आम आदमी को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने की कोशिश की है। पिछले पांच सालों में कार्य दिवसों की संख्या 25 हजार करोड़ थी, अब के तीन सालों में यह संख्या 46 हजार करोड़ पहुंच चुकी है।

सभापति महोदय, आज बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। हमें अन्दाजा था, मनमोहन सिंह जी बहुत दूरदर्शी थे, सोनिया गांधी जी बहुत दूरदर्शी थीं। उनको अन्दाजा था कि इसको एक्ट बना दो ताकि ये आगे कभी कुछ कर नहीं पायें। इन्होंने नरेगा के ऊपर बहुत भाषण दिये, लेकिन सात साल हो गये, उसे खतम नहीं कर पाये। इन्होंने उसको रिड्यूस करने की कोशिश तो की, लेकिन खतम नहीं कर पाये। इसकी शुरुआत राजस्थान में हुई और इसकी जरूरत को समझते हुए मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि 100 दिन को बढ़ाकर 125 दिन कर दिये। इससे आम जनता को, आम आदमी को और गरीब को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। न केवल 100 से 125 दिन कर दिये, जबकि आज सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि बेरोजगार शहरों में भी बहुत हैं, शहरों में आदमी रोजगार के लिए जूझ रहा है। जिस तरह की केन्द्र की नीतियां हैं, डिमोनेटाइजेशन के बाद में रोजगार खतम हो गये। अभी मैं सुन रहा था। लोक सभा में एक सदस्य बोल रहे थे, वे कह रहे थे कि 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के जॉब छूट गये। इस डिमोनेटाइजेशन और कोविड के अन्दर 2 करोड़ लोगों के जॉब छूट गये, जो कि अलग-अलग सेक्टर में काम करते थे। आटोमोबाइल सेक्टर में, इन्फ्रास्ट्रक्चर में, हर जगह जॉब की कमी आ गयी और इतने लोग बेरोजगार हो गये। इस बात को ध्यान में रखते हुए शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री ने इस बार किया, इसके लिए मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस योजना से न केवल रूरल एरिया में फायदा, बल्कि शहरों में भी फायदा होगा।

(श्री रफीक खान)

सभापति महोदय, जब यह बजट आया तो बजट के बाद हम सब लोग अपने-अपने घर गये। रास्ते में देखा कि सरकारी कर्मचारी डीजे लगाकर डांस कर रहे हैं। मुख्य मंत्री जी ने यहां पर ऐसा मास्टर स्ट्रोक दिया। हम एक बार एसेम्बली आ जाते हैं तो हम पूरी जिंदगी पेंशन के हकदार हो जाते हैं। जिस आदमी ने अपने जीवन के 30-35 साल सरकार के काम में दे दिया, उसको पेंशन नहीं मिलती है, पेंशन मिलती है तो दो-तीन या पांच हजार रुपये मिलती है। एक ऐसा काम कर दिया कि उनको अगले वर्ष से पेंशन चालू हो जायेगी। मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि पूरे राजस्थान के सरकारी कर्मचारी धन्यवाद दे रहे हैं। इस बात का सेलिब्रेशन एक फेस्टिवल की तरह, एक कार्निवल की तरह, सरकारी कर्मचारी ने डिपार्टमेंट में मनाया है। जब से बजट दिया गया है, तब से लेकर आज तक हर विभाग में हर कर्मचारी इस बात को फेस्टिवल की तरह मना रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों की पेंशन का एक बहुत बड़ा काम, जो कि बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था, मुख्य मंत्री जी ने किया, मैं उसके लिए दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं।

बीजेपी के विधायकों में भी चर्चा हो गयी कि ये तो मास्टर स्ट्रोक डाल दिया आपने, अब हमारी सरकार नहीं बननी। ये ही लोग बाहर आकर बातें कर रहे थे।

(समय: 15.00 बजे)

सभापति महोदय, कोविड के समय में बहुत अरसे से एक मांग चली आ रही थी कि ऐसे समय में जब लॉकडाउन रहा, दो महीने आदमी घर में बंद रहा, जॉबलैस हो गये तो बिजली का पैसा कम होना चाहिए। दो महीने का रिलीफ मांग रहे थे। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्य मंत्री जी को कि खाली दो महीने की ही रिलीफ नहीं दी, मुख्य मंत्री जी ने दो महीने की जगह हर आदमी को, हर बिल के अन्दर 50 यूनिट फ्री कर दी, 2 रुपये की सब्सिडी कर दी 100 यूनिट तक और 150 यूनिट तक 300 रुपये की सब्सिडी कर दी। मैंने केलकुलेट कराया तो 500 से लेकर 750 रुपये हर आदमी को बिजली के बिल में रिलीफ मिलने वाला है।

बहुत सारी बातें हमारे साथी यहां अभी बोल रहे थे। पेंशन योजना की खिलाफत नहीं कर सके। बिजली के बारे में कोई नहीं बोला। 10-10 करोड़ की सड़कें कोई कांग्रेस के विधायकों को नहीं मिली हैं, 10-10 करोड़ की सड़कें

(श्री रफीक खान)

इनको भी मिली हैं। पूरे 200 विधान सभा क्षेत्रों में 10-10 करोड़ रुपये मुख्य मंत्री जी ने सड़कों के लिए दे दिये, ताकि पूरे राजस्थान का विकास हो सके। इनसे इस बात पर भी कोई शुकराने का लफ्ज नहीं निकला। मैं यह कहता हूं कि ये 10-10 करोड़ की सड़कें भी इनसे शिफ्ट कर लेनी चाहिए। जो धन्यवाद दे उन्हीं को 10-10 करोड़ की सड़कें दो। मोबाइल लौटाए, 10-10 करोड़ की सड़कें भी लौटा दो आप।

एजुकेशन का मसला हो तो एजुकेशन के अन्दर तो मुख्य मंत्री जी ने कमाल कर दिया। पिछले साल 150 स्कूलें अनाउंस की महात्मा गांधी के 150वें जन्म दिवस पर और उनकी कामयाबी, उनकी रिक्वायरमेंट और उनकी जरूरत को देखते हुए, वे स्कूलें इतनी सक्सेसफुल गयीं, वह मॉडल इतना सक्सेसफुल गया कि लोगों ने अपने बच्चे प्राइवेट बड़ी-बड़ी स्कूलों से ट्रांसफर करके सरकारी स्कूलों में डाल दिए। पहली बार ऐसा हुआ कि लोगों ने सिफारिशें करायीं। लोगों ने कहा कि हमारे बच्चों को महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवा दो। एक स्कूल में जब एडमिशन होने लगे तो 60 बच्चों की वैकेंसी है और एप्लीकेशन आ रही हैं चार हजार, एप्लीकेशन आ रही हैं पांच हजार। मुख्य मंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया और इस बजट में घोषणा की कि हम 2 हजार स्कूलें इस आने वाले साल में खोलेंगे। दो हजार स्कूलें और दस हजार इंग्लिश मीडियम स्कूलों के शिक्षक भी भर्ती किए जाएंगे।

मैं धन्यवाद दूंगा कि मुख्य मंत्री जी को कि इससे न केवल रोजगार का डवलपमेंट होगा, बल्कि एक नये एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत होगी। यह कह सकते हैं कि राजस्थान में शिक्षा के अन्दर अगर मील का पत्थर साबित होगा तो ये महात्मा गांधी स्कूलें होंगी जो इस टेन्योर में शुरू हुई हैं। तीन साल के कार्य के अन्दर अगर सबसे स्वर्णिम अक्षरों में किसी चीज का नाम लिखा जाएगा, जिसके परिणाम दूरगामी आएंगे, जो एक इन्फ्रास्ट्रक्चर की, इसकी नींव रखने का काम करेगी तो ये महात्मा गांधी स्कूलें करेंगी। मैं पूरे सदन के साथियों को कहना चाहता हूं कि सबको आगे होकर इस प्रयास में शामिल होना चाहिए। अपने अच्छे से अच्छे स्कूल को इंग्लिश मीडियम स्कूल जिसमें स्पेस हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल में कन्वर्ट कराएं ताकि पूरे समाज को फायदा मिल सके। इसमें कोई राजनीति नहीं है। इसमें कोई बीजेपी का विधायक नहीं है, इसमें कोई कांग्रेस का विधायक नहीं है, इसके अन्दर पूरे प्रदेश के विकास की बात है। हर बच्चे को शिक्षा मिले, हर बच्चे को इंग्लिश

(श्री रफीक खान)

मीडियम की शिक्षा मिले, ऐसी सोच के साथ में मुख्य मंत्री जी ने एक बहुत जबरदस्त बजट प्रस्तुत किया।

माननीय सभापति महोदय, एक मुद्दा मैं बीच में ले लेता हूं, बाद में क्या पता आप समय दें या न दें। आज सुबह मैं और हमारे उद्योग मंत्री जी यूक्रेन से आए हुए कुछ स्टूडेंट्स को लेने गये। 8 एम.बी.बी.एस. के स्टूडेंट्स थे जिनको सरकार ने वहां से किसी तरीके से साधन उपलब्ध कराकर, मैं फिर से धन्यवाद दूंगा और पूरे सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने उन सबको न केवल वहां से लाकर, बल्कि सकुशल घर पहुंचाने का जिम्मा हम लोगों को दिया। उनके लिए गाड़ियां अरेंज कीं और उन सबको सकुशल घर भेजा गया। करीब 1000 बच्चे राजस्थान के ऐसे हैं, जो यूक्रेन में फंसे हुए थे। काफी कुछ बच्चे आ चुके हैं, और बच्चे आने के प्रोसेस में हैं। तीन मंत्रियों को दिल्ली डेप्यूट कर दिया गया है। केन्द्र सरकार ने अपने मंत्रियों को भेजा हुआ है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है। उप नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं, मैं अपील करना चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट यूक्रेन में हैं न केवल उनको लाया जाए, बल्कि उनका प्रबन्ध किया जाए। उनको हिन्दुस्तान के अन्दर एजुकेशन दी जाए। जो कोर्सेज उनके रह गये हैं, उन कोर्सेज को पूरा और उनके लिए सीटें बढ़ाई जाएं, उनके लिए मेडिकल कालेजेज खोले जाएं। उनको फिर से दोबारा विदेश में नहीं जाना पड़े, इस बात का संज्ञान लें और हम सब मिलकर ये काम करें। हम सब यह सोचें कि ऐसी पालिसी बने कि जितने स्टूडेंट्स वहां से आ रहे हैं, कोई थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, कोई सैकण्ड ईयर का स्टूडेंट है, किसी की फैमिली के 50 लाख खर्च हो चुके हैं, किसी के 20 लाख खर्च हो चुके हैं, किसी की खर्चा करने की अब और स्थिति नहीं है इसलिए हम सबको मिलकर इसका संज्ञान लेना चाहिए। बीजेपी के नेताओं को मैं कहना चाहता हूं कि हमारे साथ चिट्ठियां लिखें, केन्द्र सरकार को रिक्वेस्ट करें कि इन सबको हिन्दुस्तान में जगह मिले, इनको सीटें मिले, इनके लिए सीटों का एनहांसमेंट हो, इनके लिए अगर अलग से कालेज खोलने पड़े तो उसकी भी घोषणा जल्दी से जल्दी हो ताकि इन लोगों को फायदा मिल सके और दोबारा ऐसी नौबत न आए कि इनको बाहर जाकर एजुकेशन लेनी पड़े।

सभापति महोदय, हैल्थ का मामला, हैल्थ के सैक्टर में जितना काम राजस्थान में हुआ है उतना काम शायद ही कहीं हुआ हो। हम जयपुर के

(श्री रफीक खान)

विधायक, खासतौर से मैं जब भी यहां इस सदन में सामने देखता हूं, तो मेरे को सामने जयपुर का एक भी विधायक नजर नहीं आता। ऐसा लगता है कि वे कुछ बातों को लेकर सीरियस नहीं हैं। एक भी आदमी प्रतिपक्ष का यहां जयपुर का नजर नहीं आता। जयपुर में जब कोविड का मसला चल रहा था तो ये उस सिनेरियो से भी नदारद थे। जैसे यहां से नदारद हैं, ऐसे ही वहां से भी नदारद थे। कोविड का मैनेजमेंट और मुख्य मंत्री जी की कार्यशैली, आर.यू.एच.एस., जो एक हास्पिटल बंद की कगार पर था, बीजेपी के राज में उस हास्पिटल को कोई नहीं पूछ रहा था, पिछले टेन्योर में उसमें एक पेशेंट की ओ.पी.डी. नहीं। क्यों? क्योंकि वह मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने बनाई थी, लेकिन उस हास्पिटल को कोविड केयर स्पेशियलिटी हास्पिटल में तब्दील किया गया। जहां कैपेसिटी 350 मरीजों की थी, वहां 1500 पेशेंट को एट ए टाइम भर्ती किया गया और इलाज किया गया। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्य मंत्री जी को। ये टी.वी. कैमरे पर दो आदमी वेटिंग में बैठे हैं, उनकी फोटो दिखाते रहे, इन्होंने ये शाबासी नहीं दी कि 350 बैडेड हास्पिटल को 1500 बैडेड हास्पिटल में तब्दील कर दिया और हर आदमी को इलाज मिला।

सभापति महोदय, निकटवर्ती राज्य जहां इनकी सरकारें हैं हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, वहां से हजारों पेशंट ने यहां आकर जान बचाई। हमारे मुख्य मंत्री जी ने ये नहीं कहा कि हम भेदभाव करेंगे, उन्होंने कहा जो आदमी हास्पिटल में आ गया उसको इलाज कराकर भेजेंगे राजस्थान से। मुझे खुशी है कि चाहे कोविड का मसला हो, चाहे क्वारंटाइन का मसला हो, चाहे रेमडेसिविर उपलब्ध कराने का मसला हो, चाहे टोसिलिजुमैब उपलब्ध कराने का मसला हो और उसके बाद में एक ब्लैक फंगस और आ गया था, सभापति महोदय, आप तो डाक्टर हैं, स्वयं जानते हैं, वह 60 इंजेक्शन लगते थे, एंफोटेरिसिन। एंफोटेरिसिन का मसला हो, हर आदमी को, मैंने यूपी के बहुत सारे पेशेंट्स को एंफोटेरिसिन के इंजेक्शन जयपुर में फ्री आफ कोस्ट उपलब्ध करवाए। कोविड प्रबन्धन के नाम पर जैसा राजस्थान में काम हुआ और स्पेशियली जयपुर के एस.एम.एस. हास्पिटल और आर.यू.एच.एस. में काम हुआ, ऐसा काम शायद ही पूरी दुनिया में कहीं हुआ हो।

उसके बाद में वैक्सीनेशन का दौर आ गया। वैक्सीनेशन का दौर आ गया, वैक्सीनेशन में कोविड के सेंटर खोले गये। मैंने खुद ने आदर्श नगर विधान सभा क्षेत्र में कोविड केयर सेंटर खोला और मुख्य मंत्री जी के आशीर्वाद

(श्री रफीक खान)

से पूरे सदन में मैं यह कह सकता हूं कि पूरे हिन्दुस्तान की पहले नंबर की साइट बनी जिसमें 2 लाख से ज्यादा अगर एक स्पॉट पर वैक्सीनेशन किया गया तो हमारे आदर्श नगर में कोविड केयर सेंटर पर किया गया। धन्यवाद जिने देना है, बिनै ही देवो, मोदी जी तो पूरे देश में बैठे हैं, पचास-पचास कोन लग्या सका, लोगां म्हे जोड़ हो गया इंजेक्शन लगाने वास्ते, थारे एम.एल.ए. की भी रिक्वेस्ट म्हारै कन ही आयी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कन्क्लूड कीजिए।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): इन्होंने मुझको याद दिला दी इसलिए दो बात बोलनी पड़ेगी अब। टीके आज से लेकर के, आजादी से लेकर के अब तक कांग्रेस सरकार लगाती रही है। कभी बाबा बनकर फोटो नहीं छपाई टीकों के कार्ड के ऊपर। जब से आदमी पैदा होता है और बड़ा होता है तब तक टीके लगते आये हैं, पहली बार टीके नहीं लगे हैं लेकिन कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर्स ने और कांग्रेस के नेताओं ने अपनी फोटो नहीं डाली उसके ऊपर। आप लोग टीके बाद में लगा रहे हैं और एडवटाईजमेंट कर रहे हैं। जान बचाने का एडवटाईजमेंट कर रहे हैं। हमने जान बचाने को प्रायोरिटी समझा और उसी का नतीजा है कि आज आप और हम बिना मास्क के इस सदन के अंदर बैठे हैं।

यह अशोक गहलोत जी का एफर्ट है और उन्हीं का काम है कि आज हम असेम्बली में बिना मास्क के बैठे हैं।

श्री सभापति: माननीय, कन्क्लूड करें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): माननीय सभापति महोदय, किसानों के लिये अलग बजट है। किसानों के लिये अलग बजट प्रस्तुत किया, एक एग्जाम्पल सैट किया। यह किसान-किसान करते रहे। उस पर भी दो लाइन लिखी है, वह सुननी बहुत जरूरी हैं।

"एक वह है जो रौंदते हैं, किसानों पर मोटर कार,

एक राजस्थान के जननायक, जो देते हैं किसानों

को अलग से बजट का उपहार।"

ऐसे मुख्य मंत्री ने, इस सोच के साथ बजट दिया। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, जो बजट दिया है, उसकी कह रहा हूं।

(श्री रफीक खान)

"मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा,
इस सियाह समुन्द्र से नूर निकलेगा।"

मैं आपको यह बताना चाहता हूं। किसानों का अलग से बजट प्रस्तुत किया। इसके अन्दर बहुत सारी घोषणाएं की। मैं पूरी पर डिटेल में जाऊंगा तो (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) आप मेरा समय यहीं पूरा कर दोगे। प्रशासन शहरों की ओर, प्रशासन गांवों की ओर। सभापति महोदय, 10 लाख से ज्यादा के पट्टे रूरल एरिया में बांटे जा चुके हैं। करीब 2 लाख लोगों को शहरी एरिया में पट्टे दिये जा चुके हैं। पिछले 50 सालों में यह काम, जब-जब कांग्रेस की सरकार आयी है, उन्होंने ही किया है। इन्होंने कभी पट्टे देने का काम नहीं किया। अगर राजस्थान में आवास देने का काम किसी मुख्य मंत्री ने किया, तो उस मुख्य मंत्री का नाम अशोक गहलोत है।

श्री सभापति: माननीय, कन्क्लूड करें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): यूडीएच मंत्रालय और अशोक गहलोत जी के संयुक्त प्रयासों से।

सभापति महोदय, एक चीज रीट पर और बोलूंगा। आप दो मिनट का और देना। रीट पर इन्होंने बहुत हल्ला किया। बहुत सारी बातें बोलीं। अब वह यहां से उठकर चले गये। जब इनका खुद का केस था, तब तो सीबीआई गड़बड़ थी, तब सीबीआई की जांच ठीक नहीं थी, तब यह इल्जाम लगा रहे थे कि सीबीआई से जांच मत कराओ। सभापति महोदय, मैं हाई कोर्ट का एक डिसीजन पढ़ना चाहता हूं। लम्बी बात नहीं करता हूं। जब रीट पर बात आयी इन्होंने सदन में खूब हल्ला किया। इन्होंने यह कहा कि डेढ़ घण्टे की चर्चा करा दो। हमारे चार आदमियों को सस्पेंड कर दिया, उनको बहाल कर दो। सब बात मान ली, फिर कह रहे हैं कि हम सदन नहीं चलने देंगे। सदन का सारा समय खराब किया। एबीवीपी ने अपील की, हाई कोर्ट में मुकदमा किया, उसके डिसीजन की दो लाइन मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं - “as of now we don’t see any reason to disturb outgoing investigation in the hands of SOG.”

(समय: 15.12 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

यह हाई कोर्ट कह रही है। हाई कोर्ट पर भी भरोसा नहीं कर रहे हो।

(श्री रफीक खान)

हाई कोर्ट कह रही है कि एसओजी के हाथ में जो जांच है, उसको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है तो किन कर्मचारियों को बचाना चाह रहे हो भाई? किसके लिये एलीगेशन लगा रहे हो? पूरा सदन बोला, एक-एक आदमी ने कहा कि एसओजी जांच बहुत ठीक कर रही है, फिर चेंज किस बात की? जब हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, फिर बार-बार। मण्डावा से आने वाली विधायक ने उनके लिये कहा, उनकी दो लाइन..

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में समाप्त करें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): "उड़ गई तेरे होठों की लाली, वह किसी दिल की मलिका बन गयी, और तू कहता रहा दुल्हन काली।" सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री कन्हैया लाल चौधरी।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, 2013 में जब चुनाव आया तो कांग्रेस अपना घोषणा पत्र लेकर आती है और उसमें वादा करती है कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, बेरोजगारों को भत्ता देंगे, जितने भी संविदाकर्मी हैं उनको हम परमानेंट करेंगे। वादा किया कि हम बिजली की घरेलू दरें बिलकुल नहीं बढ़ाएंगे। आज यह चौथा बजट पेश हो रहा है। 2019-20 के बजट से लेकर, 2020-21, 2022-23 के बजट तक, इस चौथे बजट के अन्दर किसान, बेरोजगार, संविदाकर्मी, सब इस बजट में देख रहे थे कि वादा पूरा होगा। राजस्थान के किसान, सब इस वक्त निराशा में हैं। आखिरी बजट आयेगा। सबको पता है कि 2013 के अन्दर, जिस तरह से इन्होंने बजट पेश किया था, चुनावी बजट में इन्होंने लगभग 300 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की घोषणा की थी। लगभग 70 कालेज की घोषणा की थी। इन्होंने चुनाव तक न तो एक-एक लाख रुपये किसी पीएचसी पर बजट दिया, न कालेजों में एक लेक्चरर लगाया, न कोई खोली। जब हमारी सरकार दिसम्बर, 2013 में आयी, हमने वह पूरे 300 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये। 70 कालेज बनाये, उनकी बिल्डिंग भी बनायी। यह वादे तो पूरे नहीं कर रहे, नई-नई घोषणाएं करते जा रहे हैं। इन्होंने लगभग 150 के आस-पास कालेज खोले। किसी के अन्दर बिल्डिंग नहीं है, लेक्चरर नहीं हैं। पुराने लेक्चरर, जिनको हमारी सरकार ने दूसरे कालेजेज में लगाया था, उनको भी यह तोड-तोड़कर दूसरी जगह लगाने का काम कर रहे हैं।

(श्री कन्हैया लाल)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं, आप चुनावी बजट देते हो, इसको पूरा करने का काम करें। आप लोगों ने पहला बजट पेश किया था, घोषणा की थी कि हम विकास पथ बनाएंगे, हर ग्राम पंचायत में विकास पथ बनाएंगे। हमारी पिछली सरकार ने हर ग्राम पंचायत पर गौरव पथ बनाया। उसकी नकल करते हुए आपने घोषणा तो कर दी। यह चौथा बजट है, अभी तक आप लोगों ने हर विधान सभा क्षेत्र में, एक ग्राम पंचायत में 50 लाख रुपये का काम कराया? एक विकास पथ नहीं बनाया।

इसी तरह से आपने घोषणा की, सभी विधायक, अभी चर्चा कर रहे थे, कि 10-10 करोड़ रुपये आपको रोड के लिये दिये हैं। मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार में हर विधायक को, हर विधान सभा क्षेत्र में लगभग 100-100 किलोमीटर की मिसिंग सड़कें बनाकर दीं। आप देखेंगे, इन्होंने पिछले बजट में केवल 10 किलोमीटर की सड़क दी। लोगों को उम्मीद थी, सभी विधायकों को उम्मीद थी कि इस बार हमें कम से कम 10 करोड़ रुपये की मिसिंग लिंक की सड़कें देंगे। जब पता लगा कि वह 3 करोड़ रुपये आपको मिसिंग लिंक के लिये दिये हैं, उससे ज्यादा से ज्यादा 7-8 किलोमीटर बनेगी। यानी चौथे बजट तक, आप केवल 16-17 किलोमीटर मिसिंग लिंक की सड़कें बनाना चाह रहे हो। कहते हैं कि हमने 7 करोड़ रुपये आपको मेंटीनेंस के लिये दे दिये। आप लोगों ने, पिछले चार साल के अन्दर, जो पुराने गड्ढे थे वह ही नहीं भर पाये। रूटीन के अन्दर केन्द्र से पैसा आता है, वह पैसा ही आप पूरा नहीं लगा पा रहे और कहते हैं 7 करोड़ रुपये अलग से मेंटिनेंस के दे दिये।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में टोडारायसिंह से बटुण्डा रोड है, उसमें 21 करोड़ रुपये का बजट था। आज भी वह माइनिंग डिपार्टमेंट में सैंक्शन है, आधा-अधूरा पड़ा है, उसके अन्दर अभी भी बजट नहीं दे पा रहे हैं।

इसी के साथ-साथ आरएसआरडीसी से हमारे पूर्व मुख्य मंत्री जी ने डिग्गी कल्याण जी के विकास के लिये 60 करोड़ रुपये सैंक्शन किये, 60 करोड़ में से अब तक केवल 30 करोड़ रुपये लगाये हैं। 30 करोड़ रुपये का आप बजट दें तो वह विकास पूरा हो। धार्मिक नगरी है, राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के लोग वहां जाते हैं। मन्दिर में तो हम दे ही नहीं सकते, पैसे कैसे देंगे?

(श्री कन्हैया लाल)

आप लोगों ने वादा किया था कि हम बिजली की दरें नहीं बढाएंगे। सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम ही बिजली की दर बढ़ाने का किया। जो बिजली का बिल पहले गरीब आदमी के लिये हजार रुपये का आता था, आज कम से कम 2 हजार रुपये का आ रहा है। समय पर बिजली नहीं मिल रही। जब कोई ट्रांसफार्मर जल जाता है तो कम से कम 15 दिन से पहले ट्रांसफार्मर नहीं लगा पा रहे। लगाते हैं तो इतनी घटिया क्वालिटी का लगाते हैं कि लगाने के 10-15 दिन बाद ही वह जल जाता है।

आप लोगों ने वादा किया कि एक साल के अन्दर, एग्रीकल्चर के कनेक्शन बाकी हैं उनको करके देंगे। एग्रीकल्चर कनेक्शन की यह स्थिति है कि जिन्होंने डिमाण्ड जमा करा दी, दो-दो साल तक आप उन लोगों को कनेक्शन नहीं दे पा रहे हो। विशेषकर, एससी, एसटी समाज के आप देते हो, 6 महीने तक कहीं पोल लगा दिया तो तार नहीं मिल रहे, तार मिल गये तो ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा। जितने पैसे नहीं बनते, उससे ज्यादा तो चक्कर लगाने में लगते हैं। किसान उम्मीद में बैठ जाता है कि मेरे खेत में, पानी पिलाने के लिये बिजली आयेगी तो डीजल का पैसा बचेगा।

स्थायी शुल्क ले लीजिये, आपने हर चीज में बढ़ाने का काम किया। इस बजट में लोगों को उम्मीद थी कि नया कृषि बजट आयेगा किसानों का बहुत भला होगा। किसानों का भला करने के लिये, किसानों की आमदनी डबल करने के लिये, हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी योजना लेकर आये। किसान सम्मान निधि हो, एमएसपी बढ़ाने का काम किया हो, या जिस तरह से तीन कानून लेकर आये। आप लोगों ने अफवाह फैलाकर, काला कानून बताकर, उन कानूनों को रद्द करवाया। किसानों को आस थी कि नये कृषि बजट में हमें कुछ बड़ी चीज मिलेगी पर जब बजट देखा तो इसमें कोई भी ऐसी योजना नहीं मिली जिससे किसानों का कोई भला होने वाला हो।

लोगों को यह उम्मीद थी कि कम से कम हमारा किसानों का कर्जा माफ होगा या हमें अलग से जो छह हजार रुपये मिल रहे हैं उसको बढ़ाकर जिस तरह से मध्यप्रदेश के अन्दर चार हजार रुपये अलग से देते हैं तो यहां भी किसान सम्मान निधि में चार हजार रुपये जोड़कर दस हजार रुपये करेंगे तो किसानों को काफी उम्मीद थी, पर जब बजट को देखा तो इसमें कुछ भी नहीं मिला।

पुरानी डिग्गी का काम हो या चाहे फार्म पॉण्ड हो या चाहे ग्रीन हाउस

(श्री कन्हैया लाल)

हो, इन सब पर जो सब्सिडी थी, वह भी आप लोगों ने इसको बढ़ाने का काम नहीं किया और जो पहले मिल रही थी, वह ही है।

जहां तक मेडिकल की बात करें तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से ये अभी कह रहे थे कि कोरोना काल में हमने यह वैक्सीन लगायी है, हमने सब जगह लगायी। आजादी के बाद के अन्दर पहली बार किसी ने समय पर पूरे विश्व के अन्दर को-वैक्सीन और कोविशील्ड बनाने का जो काम किया, वह भारत सरकार के देश के प्रधान मंत्री मोदीजी की बदौलत है कि आज पूरे भारत की जनता चैन से बैठी हुई है। उन्होंने लगभग 300 करोड़ टीके लगाने का जो काम किया वह आज दिन तक किसी ने नहीं किया। उससे पहले वैक्सीन भी बाहर से आती थी, दूसरे देशों से आती थी तो वह वैक्सीन समय पर नहीं आ पाती थी। मैं यह धन्यवाद देना चाहता हूं देश के प्रधान मंत्रीजी को।

जिस तरीके से मेडिकल के अन्दर सब लोगों को यह उम्मीद थी कि हमारे क्षेत्र के अन्दर भी मेडिकल के अन्दर सबका भला होगा, सबके साथ होगा पर यह चौथा बजट है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मेरे मालपुरा विधान सभा क्षेत्र के अन्दर वहां पर ट्रोमा हास्पिटल के लिए हमारी मांग थी। बराबर के जो मंत्री केकड़ी से रघु शर्माजी आते थे, अब परसादी लालजी भाई साहब यहां पर विराजे हुए हैं। वहां पर दो स्टेट हाईवे निकलते हैं, एक सांगानेर से माण्डल जाता है और एक दूदू से छान जाता है। वहां पर रोजाना आये दिन कुछ न कुछ एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। लोगों को यह उम्मीद थी कि यहां पर हमारा ट्रोमा हास्पिटल में क्रमोन्नत हो जाये तो लोगों का एक्सीडेंट्स में समय पर इलाज हो जाये। मैं आपसे मांग करना चाहता हूं कि वह भी करें।

इसके साथ-साथ, पिछले तीन साल में मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर न तो कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला, न कोई उप स्वास्थ्य केन्द्र खोला तो इस बजट के अन्दर मेरे पारली, उनियारा, मोर, इन जगह पर अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलेंगे तो आपकी काफी मदद होगी। एग्रीकल्चर के साथ-साथ बेरोजगारों जो संविदा पर लगे हुए थे, वे भी उम्मीद कर रहे हैं कि हमें भी इस बजट के अन्दर परमानेंट करेंगे।

राजस्व विभाग की मैं बात करूं तो अभी सब लोग प्रशंसा कर रहे थे कि हमने प्रशासन गांवों के संग अभियान में काफी लोगों का भला किया। जिस तरह से गांवों के अन्दर गरीब आदमी को 275 रुपये में पट्टा देने का

(श्री कन्हैया लाल)

काम पूर्ववर्ती सरकार ने किया, पट्टा सब दे रहे हैं बाकी वहां पर जब तहसीलदार जा रहा है, वहां पर पटवारी जा रहा है, वहां पर एस.डी.एम. बैठ रहा है। अगर उस गरीब आदमी का रजिस्ट्रेशन साथ के साथ उसी कैम्प में हो जाता है तो उस गरीब आदमी के दो हजार रुपये पट्टे के जो रजिस्ट्रेशन के लगते हैं, वह बचते, वह गरीब आदमी जाता है, उसका पट्टा तो बन जाता है बाकी उसको ज्ञान नहीं रहता है और वह ले जाकर रख देता है और छह महीने तक अगर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो वह पट्टा निरस्त हो जाता है। यह सारी चीजें उसमें लेकर चलते।

इसके साथ-साथ पिछले चार साल से मैं यह मांग कर रहा हूं कि मेरे मालपुरा विधान सभा क्षेत्र के अन्दर आजादी के बाद में सैटलमेंट नहीं हुआ है। जितने भी पुराने नक्शे थे वह सारे फटे पुराने हैं, उनका अगर सैटलमेंट समय पर हो जाता तो अच्छा रहता। न तो मालपुरा तहसील में है, न मेरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है और जयपुर के अन्दर, वहां सब जगह पर वह नक्शे कहीं न कहीं या तो गुम हैं या वह जले हुए हैं। उसकी वजह से किसान रोजाना कानूनी लड़ाई के लिए कोर्ट में फंसे रहते हैं और जो प्रभावशाली व्यक्ति है, वह कहीं न कहीं से अपने पैसे के बलबूते पर नक्शा कहीं से निकालकर ले आता है और वह गरीब आदमी का हक ले लेता है तो यह अगर हो जाये तो काफी भला होगा।

मैं गृह विभाग की बात करूं तो पिछले बजट के अन्दर मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा की थी कि हर थाने के अन्दर हम स्वागत कक्ष खोलेंगे पर आज दिन तक किसी भी थाने के अन्दर स्वागत कक्ष नहीं खोला गया। एस.पी. हमारे ऊपर यह प्रेशर बनाता है और यह कहता है कि आप लोगों का पिछले दो साल तक विधायक मद के अन्दर पैसा भी नहीं मिला और जो मिला वह पूरा का पूरा हमने कोरोना के अन्दर दिया। वह यह प्रेशर बनाता है कि अगर आपको हमसे काम करवाना है या आपके कहने से एस.आई. आपका कहना मानेगा तो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में अपनी बात को समाप्त करें।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): सबसे पहले आपके बजट से 20-20 लाख रुपये देकर आप स्वागत कक्ष बनाओ। जब आपके पास पैसे ही नहीं हैं, आप बजट में क्यों प्रावधान करते हो कि हम हर थाने के अन्दर स्वागत कक्ष

(श्री कन्हैया लाल)

बनाएंगे? वह वापस वहीं पर आ गये। सभी विधायक इससे दु:खी हैं तो अगर आप कोई घोषणा करते हो तो उसको पूरा करें।

गौशाला के लिए अभी विधान सभा में क्वेश्चन आया था कि हम नन्दी गौशाला हर जिले के अन्दर खोलेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: बैठे-बैठे वार्ता न करें।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): बाकी जब 600 करोड़ रुपये का बजट पड़ा है, आज तक कोई नहीं खुला। जिले से लेकर आपने घोषणा की कि हम उपखण्ड स्तर तक खोलेंगे तो अभी तक तो जिले के अन्दर एक भी नन्दी गौशाला नहीं खुली है और बात करते हो कि हमारे पास खूब बजट पड़ा है।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत केन्द्र सरकार ने काफी बजट दिया है, सारी चीज दी है। हम सब यह बात करते हैं कि गांवों का विकास हो, गांवों के अन्दर नालियां हो, गांवों के अन्दर लाइटिंग हो, वहां पर पार्क हो, यह सारी चीजें हो, वहां पर कचरा परिवहन भी हो। इस बजट के अन्दर यह प्रावधान करते या यह ऐसी कोई योजना बनाते। पंचायती राज मंत्री और मुख्य मंत्रीजी उस कचरे का परिवहन करने का कोई प्रावधान करते क्योंकि अब जिस तरह से हमारे देश के प्रधान मंत्रीजी ने जल जीवन मिशन योजना चालू की, उसके तहत हर घर के अन्दर जब पानी पहुंचेगा और वहां पर पानी जायेगा और अगर उन नालियों की प्रोपर सफाई नहीं होगी तो वह पूरा का पूरा उस रोड पर आयेगा और उसकी वजह से हम जितनी भी रोड्स का निर्माण करेंगे, वापस वह नष्ट होंगी।

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इस बजट के अन्दर जब आज हमारे मुख्य मंत्रीजी जो रिप्लाई दें तो उसके अन्दर यह भी प्रावधान लेकर आयें कि कचरा परिवहन की कोई ऐसी व्यवस्था हो, ऐसा कोई सिस्टम डवलप करें जिससे उसका काम हो सके।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): इसके साथ-साथ मैं पेयजल मिशन की बात करूं तो पेयजल में जल जीवन मिशन के अन्दर आज ही हमारे देश के प्रधान मंत्रीजी दुनिया भर के पैसे दे रहे हैं पर तय समय के अन्दर यह लोग उस काम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अगर 50 परसेंट के लिए यह कहते हैं कि साहब, हम 50 परसेंट पैसा दे रहे हैं पर आज भी जो पुरानी लाइनों के अन्दर ही वह घर-घर कनेक्शन करने का काम कर रहे हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट में मैं मेरे क्षेत्र की दो-तीन मांगें हैं, मैं यह कहना चाहता हूं कि बजट घोषणा पत्र में एक घोषणा भी की थी। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री हरीश चौधरी।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): बीसलपुर को हम देवली से जोड़ेंगे, वह भी अभी तक नहीं किया। इसके साथ मालपुरा के अन्दर पी.जी. कालेज क्रमोन्नत किया जाये। पी.एच.सी. किया जाये, ट्रोमा हास्पिटल किया जाये। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सहयोग करें। समाप्त करें।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि यह मेरा विधायक के तौर पर मेडन स्पीच है और आपने मुझे बोलने की इजाजत दी। मेरे से पूर्व कई विधायकों ने इस बजट के सन्दर्भ में चर्चा करते हुए मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दिया और मैं भी व्यक्तिगत तौर पर इस ऐतिहासिक बजट के लिए मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी को धन्यवाद देना चाहता हूं पर क्या यह बजट मुख्य मंत्रीजी का है, क्या यह बजट सरकार का है, क्या यह बजट राजनीतिक पार्टी का जिससे मुख्य मंत्रीजी आते हैं उसका है या क्या यह बजट उस विचारधारा का है जिससे मुख्य मंत्रीजी और यह सरकार बनी है? मेरा व्यक्तिगत यह मानना है कि यह उस विचारधारा का बजट है जो मुख्य मंत्रीजी ने इस सदन में प्रस्तुत किया है। वह विचारधारा क्या है? यह विचारधारा साम्यवाद की विचारधारा है। आर्थिक तौर के ऊपर कई विचारधारा हैं। मुख्य तौर के ऊपर हम लोग जिस विचारधारा की चर्चा करते हैं उसमें पूंजीवाद की और साम्यवाद की भी चर्चा करते हैं। एडम स्मिथ ने पूंजीवाद के सन्दर्भ में जब अपनी विचारधारा दुनिया के सामने रखी तो उसके पीछे भी उनका एक विचार था, सोच था, एक रोड-मैप था जिसके माध्यम से सरकारें और समाज आगे बढ़े, जिससे समाज का उत्थान हो।

साम्यवाद विचारधारा के जनक कार्ल मार्क्स थे। हम लोगों को विरासत के अन्दर नेहरूजी की विचारधारा मिली। हमारे विपक्ष में बैठे हुए

(श्री हरीश चौधरी)

मित्रों को जो पहले पूंजीवाद की पैरवी करते थे आज दुर्भाग्य से इनके ऐसे हालात बने हुए हैं कि यह अपने मुख से आर्थिक पाइंट के ऊपर कुछ बोल ही नहीं सकते।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें। आपस में बोले नहीं।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): इसके पीछे जो पृष्ठभूमि है, वह पृष्ठभूमि यह है कि आज देश के अन्दर crony capitalism के माध्यम से जो फैसले हो रहे हैं, दुनिया के कोई भी विचारक ने उसके पक्ष में कोई तर्क नहीं दिया। आज हमारे देश का यह दुर्भाग्य है, दिखने में तो हमको एक व्यक्ति दिखता है, एक पद पर बैठे हुए व्यक्ति दिखते हैं प्रधान मंत्री के तौर पर, पर जहां वह फैसले होते हैं, उनके पीछे ताकतें किनकी हैं? उनके पीछे ताकतें हैं देश के चंद बड़े पूंजीपतियों की। जो बजट लगातार केन्द्र की तरफ से आ रहा है वह उन पूंजीपति, crony capitalism ताकतों का है और आगे से केन्द्र सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदीजी का बजट है।

आज ऐसी स्थिति शायद दुनिया के इतिहास के अन्दर कभी किसी दल की नहीं रही होगी जैसी आज हम लोगों के मित्र विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी की है। उसके ऊपर कुछ अपनी बात भी जाहिर नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास कोई तर्क नहीं है। ये क्रॉनी-कैपिटलिज्म के सन्दर्भ में वह क्या कर रहे हैं? सिर्फ मेजें थपथपा रहे हैं। लोग सिर्फ प्रोपेगण्डा कर रहे हैं उनके माध्यम से। हम लोग कैसे राजनीतिक ताकत के माध्यम से अपना सर्वाइवल करें, यह इनको भी पता है, अच्छी तरह से पता है सभापति महोदय।

आज राजस्थान का बजट मुख्य मंत्रीजी ने दिया है। वेलफेयर स्टेट के लिए दिया है। हर वर्ग के लिए दिया है। आर्थिक ताकत चन्द लोगों के लिए, हर वर्ग के लिए देने का काम किया है। उस आर्थिक ताकत के स्टेकहोल्डर मजदूर नहीं, किसान नहीं, नौजवान नहीं, छोटे व्यापारी नहीं, उद्योगपति नहीं हैं। उनकी आर्थिक ताकत का उपयोग उन्हीं के लिए किया है इस बजट के माध्यम से। मैं तहेदिल से धन्यवाद देना चाहता हूं इस ऐतिहासिक बजट के लिए। यह काम बड़े लोग, उन बड़ी ताकतों से बनी हुई सरकारें नहीं कर सकतीं क्योंकि वह जो ताकत हम लोगों की है, उस ताकत का उपयोग चन्द बड़े पूंजीपतियों के लिए ही फैसले करते हैं और बजट उन लोगों के लिए ही है। लगातार 7-8 बजट जो दिये गये केन्द्र में, उन पूंजीपतियों के सन्दर्भ में ही थे। आज सिर्फ बोलने के लिए यह बात कह रहे

(श्री हरीश चौधरी)

हैं। हकीकत इन लोगों को भी पता है। इसलिए आर्थिक फ्रंट के ऊपर ये चर्चा नहीं करते हैं। इस सदन में भी ये चर्चा नहीं करेंगे, पार्लियामेंट में भी चर्चा नहीं करेंगे, मीडिया के माध्यम से भी चर्चा नहीं करेंगे और समाज में दूसरी जगह भी चर्चा नहीं करेंगे।

सभापति महोदय, बदलते हुए मैंने मेरे साथियों को देखा है। मेरे वोकल एक साथी हैं, डंकल के लिए बड़े आन्दोलन करके बड़ी-बड़ी बातें करते थे, जब वह विपक्ष में हुआ करते थे। कल्याण सिंहजी कालवी के जब सहयोगी थे वह और आज इस क्रोनी-कैपिटलिज्म के युग के अन्दर उनकी बात में इतनी बड़ी तब्दीली, शायद कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। यह सफर किस लक्ष्य के लिए? वह इकलौता लक्ष्य है, सत्ता प्राप्ति। भावनाओं के आधार पर कोई भी समाज, कोई भी देश आगे बढ़ सकता है? सिर्फ विवाद ही विवाद, सकारात्मक सुझाव, जो सही है उसे सही और जो गलत है, उसको गलत बोलेंगे। इस समाज को बांटना है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। यह भारत नहीं है, भारत और भारत की विचारधारा नहीं है। हर क्षेत्र के अन्दर नई परिभाषा। इतिहास के सन्दर्भ में एक अलग पक्ष और अलग इन्टरप्रिटेशन। यह पृष्ठभूमि जो आज देश के अन्दर है, इन हालातों में एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी बजट राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने दिया और हर वर्ग के लिए दिया। कोशिश इन्होंने बहुत की कि पूरा का पूरा कन्ट्रोल इस इकोनॉमी का, उन मित्रों को, जो पूंजीपति मित्र हैं, क्रॉनी-कैपिटलिस्ट, उनको दिया जाए। वह अलग बात है कि देश के किसान जागरूक थे, देश के किसान एकजुट थे। कृषि क्षेत्र की 45 प्रतिशत आर्थिक ताकत थी, उसको देने का भी प्रयास किया क्या? लम्बा चौड़ा तर्क सदन के अन्दर और सदन के बाहर, सरकार और मीडिया तो इन लोगों की है, वह कृषि बिल को भी देश के किसानों की ताकत से इनको वापस लेना पड़ा। 700 किसानों की शहादत के बाद, आज हम सबका नैतिक दायित्व बनता है कि देश किस दिशा में जा रहा है। हम लोग भविष्य की बातें करते हैं, अगली पीढ़ी की और हम लोग अपनी राजनीतिक विचाराधारा को छोड़ कर सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के माध्यम से राजनीतिक फैसले करेंगे, सरकार में बैठे हुए फैसले करेंगे तो आने वाली पीढ़ी हम लोगों को माफ नहीं करेगी। पूरे देश और दुनिया ने देखा कि किस तरह से प्रोपेगण्डा इन लोगों ने किया। किन-किन संस्थाओं का दुरुपयोग इन लोगों ने किया। आज इन लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि देश से माफी मांगें।

(श्री हरीश चौधरी)

सभापति महोदय, जिन संस्थाओं के माध्यम से व्यक्ति को बैठा कर एजी पैरा के बारे में लम्बी-चौड़ी बातें ये करते हैं। सीएजी के अन्दर विनोद रायजी को बैठा कर, विवाद करके राजनीतिक तौर पर उस विवाद के माध्यम से देश के अन्दर वातावरण बनाया टू जी का। यही नहीं, बड़े पूंजीपतियों से संचालित मीडिया के अन्दर कितने शून्य लगाये कि इतना घोटाला देश के अन्दर हुआ। सभापति महोदय, क्या आज इनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि देश को जवाब दें कि जिस टू जी के सन्दर्भ में ये बात कर रहे थे, आज उसको नजरअन्दाज क्यों कर रहे हैं। क्या यह कायरता नहीं है? क्या यह दोहरा चरित्र नहीं है?

आज सैन्य शक्ति जो हमारे देश की है, हम लोग सेनाओं को हर तरह से अलग रखते हैं और ऊंचा रखते हैं। उसके शीर्ष नेतृत्व पर बैठकर वन रैंक वन पेंशन जैसी बातों का विवाद करके आज वही व्यक्ति राजनीतिक दल का चोला पहनकर जब वहां बैठता है तो पूरा देश अच्छी तरह से देखता है कि वीके सिंहजी, आप जब उस समय उस पद पर बैठे हुए थे, पवित्र वह पद था, उसके साथ आपने न्याय नहीं किया। रिटायरमेंट बैनिफिट लेने के लिए, राजनीतिक पद के माध्यम से कुछ प्राप्त करने के लिए उन्होंने कार्य किया। इतिहास कभी माफ नहीं करेगा।

देश में समाजों के अन्दर ऐसे दौर आते हैं। आज ये रोजगार की बात कर रहे हैं। क्या इन लोगों का नैतिक अधिकार है रोजगार के बारे में राजस्थान की पवित्र विधान सभा के अन्दर खड़े होकर बोलें? ये आंकडे हैं। देश के 84 प्रतिशत लोगों को पिछले एक साल के अन्दर 2022 में जो उनकी आमदनी थी, वह घटी। सिर्फ बढ़ी किसकी? बढ़ी उन्हीं पूंजीपतियों की। कितना गुना बढ़ी? क्या इस सदन के माध्यम से माफी नहीं मांगनी चाहिए कि दो तरह का हिन्दुस्तान बनाने में आप जो योगदान कर रहे हो, आने वाला इतिहास इनको माफ नहीं करेगा। आज हम लोगों की स्थिति क्या हो गई, इसकी एक बार तो चर्चा करते। ग्लोबल हंगर इन्डेक्स के अन्दर देश का स्थान क्या है? पिछले साल और इस साल उसके अन्दर हमारा स्थान क्या है? सभापति महोदय, 2021 में 94वां स्थान था। आज दुर्भाग्य से हम लोगों का वह स्थान 104 हो गया। ये हंसी उड़ाते हैं। ये अशोक गहलोत जी की हंसी उड़ाते थे अकाल के समय में। ये विवाद करते थे कि अकाल के समय राजस्थान के लोग भूखे हैं, मौत हो गयी उनकी। उस वक्त भी अशोक गहलोत जी ने राजस्थान को

(श्री हरीश चौधरी)

विश्वास दिलाया कि भूखा मरेगा नहीं, भूखा किसी को सोने भी नहीं दूंगा। ऐतिहासिक अकाल का प्रबन्धन राजस्थान में किया था इन लोगों को पता नहीं है? आगे बैठे ये लोग हैं जो पारिवारिक पृष्ठभूमि से आये हैं और मालिक इन पर मेहरबान है, इसलिए इन लोगों को अकाल का नहीं पता। हम लोगों के परिवार को अकाल का पता है। अनाज नहीं मिलना, हम लोगों के परिवार को पता है। पानी के लिए अपना जीवन लगाना, यह हम लोगों को पता है। तन पर कपड़ा नहीं, हम लोगों को पता है। छत नहीं है, यह हम लोगों को पता है। उस अकाल के अन्दर बेहतरीन प्रबन्धन किया गया। कोरोना के वक्त में भी राजस्थान की सरकार ने किसी व्यक्ति को भूखा नहीं रहने दिया। मैं तहेदिल से धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान की सरकार को, राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी को कि कोरोना का बेहतरीन प्रबन्धन किया।

हमारी पूर्व मुख्य मंत्री, आदरणीय वसुन्धरा राजे जी ने बजट भाषण के तत्काल बाद बाहर जाकर कहा कि यह नीति का बजट नहीं है, राजनीति का बजट है। वसुन्धरा राजे जी, आपको यह नीति नहीं लगती, क्योंकि आपको उन अडानी और अम्बानी के पक्ष में किये हुए फैसले ही नीति लगती है। राजस्थान के आम-अवाम के लिये जो बजट है, वह आपको राजनीति लगती है। हर जगह आप परिभाषा बदल रहे हो, पर नीति और राजनीति की परिभाषा भी बदलने का आप प्रयास कर रहे हो, राजस्थान की जनता इतनी भोली नहीं है कि वह अहसास नहीं करे कि यह नीति का बजट है कि राजनीति का बजट है।

हमारे एक विद्वान मित्र कह रहे थे कि राजस्व घाटा बढ़ा। मैं विनम्रता से उन विद्वान मित्र को पूछना चाहता हूं कि राजस्व घाटा किस पृष्ठभूमि में बढ़ा? आज राजस्थान के साथ में क्या अन्याय केन्द्र सरकार कर रही है, राजनीतिक दलगत विचारधारा से उठकर राजस्थान के साथ खड़े रहने का वक्त नहीं है? हां, सबकी ख्वाहिश रहती है कि आज इस पद पर हैं, कल उस पद पर जाने की और परसों उस पद पर जाने की सबकी ख्वाहिश रहती है। बहुत कम ऐसे सौभाग्यशाली रहते हैं, जो ख्वाहिश रखते हैं, वह ख्वाहिश पूरी होती है। उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में, मैं भी हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अशोक गहलोत जी को कि जब मैंने मेरी मंशा उनके सामने प्रकट की कि यह सोने का पिंजरा, मंत्री पद से मुझे स्वतन्त्र करके विधायक के तौर पर राजस्थान के अन्दर आप अवसर दो तो वह अवसर मुझे दिया। आज मैं

(श्री हरीश चौधरी)

इस सदन के माध्यम से उनको तहेदिल से धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, शांत रहें।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): माननीय सभापति महोदय, यह राजस्व घाटा किस पृष्ठभूमि के अन्दर बढ़ा? जो जी.एस.टी. के माध्यम से हम लोगों को, राजस्थान को मिल रहा था, वह नहीं मिल रहा। इसके बावजूद भी राजनीतिक मजबूरी के कारण, एक व्यक्ति के महिमामण्डन करने की मजबूरी के कारण हम उसका दोष राजस्थान के ऊपर दे रहे हैं। हमारे खुद की मातृभूमि से महत्वपूर्ण कोई भी चीज नहीं है, उसको बदनाम नहीं करें।

आज जो सैस का खेल हो रहा है, एडिशनल एक्साइज का खेल हो रहा है, मैं मेरे मित्रों को कहना चाहता हूं कि यह आप जो मौन ले रहे हैं इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। यह सैस और एडिशनल एक्साइज के माध्यम से राजस्थान के साथ जो अन्याय हो रहा है, आप मौन हों और उस अन्याय के साथ में हो, इतिहास आप लोगों को माफ नहीं करेगा। यह हक और अधिकार हमारा है, यह पैसा सरकारों का नहीं है। यह केन्द्र सरकार का पैसा नहीं है, यह पैसा राजस्थान की जनता का है। टैक्स के रूप में कलेक्ट करने का अधिकार सरकारों के पास होता है। उस पैसे की ताकत जनता की होती है और उस पैसे का सैस और एडिशनल एक्साइज के तौर पर हमारे से लूट हो और उस लूट का दुरुपयोग उन पूंजीपतियों के लिये हो, माननीय सभापति महोदय, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ और नहीं हो सकता। जो व्यक्ति सच्चाई के लिये बोलता है, आने वाले समय के लिये बोलता है, उनकी यह पूंजीपति मित्रों की ताकत से हंसी उड़ाते हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे देश के अन्दर कोविड के सन्दर्भ में हमारे नेता राहुल गांधीजी ने बोला तो इनके पूंजीपति क्रॉनी-कैपिटलिज्म के माध्यम से इनकी संस्थाएं, जिसमें मीडिया भी शामिल है, हंसी उड़ायी। फिर किन परिस्थितियों से वह देश के अन्दर निकला, क्या इनको माफी नहीं मांगनी चाहिए?

जी.एस.टी. के सन्दर्भ में उन्होंने आगाह किया, मोनेटाइजेशन के समय उन्होंने आगाह किया। आज देश के अन्दर जो डिप्लोमैटिक हालात बने हुए हैं, माननीय सभापति महोदय, चाइना और रशिया के माध्यम से हमारे देश की परिस्थिति चारों तरफ से क्या हुई है? हमारे पड़ोसी अब हमारे मित्र

(श्री हरीश चौधरी)

नहीं रहे हैं। अन्धा व्यक्ति भी आकलन करेगा तो उसको भी अच्छी तरह से पता है कि आज श्रीलंका कहां खड़ा है, आज पाकिस्तान कहां खड़ा है, आज अफगानिस्तान कहां खड़ा है, आज नेपाल कहां खड़ा है? उसके बावजूद भी एक व्यक्ति की महिमा मण्डन करने के कारण आज शान्त और चुप हैं। यूक्रेन तो एक शुरुआत है। माननीय सभापति महोदय, आने वाले समय के अन्दर क्या हालात बनेंगे और हम लोग मौन रहेंगे तो यह राष्ट्रवाद के लिये सिर्फ बात करना ही असली राष्ट्रवाद नहीं है। जो कोई भी बोल रहा है, उसकी बात को शान्त करना, जो व्यक्ति उन बड़े पूंजीपतियों के सामने भूमि अधिग्रहण के सन्दर्भ में, किसानों के साथ भट्टा पारसौल की पदयात्रा करके, जो वह ताकत भूमि अधिग्रहण की सरकार और सरकार के माध्यम से पूंजीपतियों की हुआ करती थी, वह कृषि बिल के माध्यम से बदलाव करते हुए वह ताकत वापस किसानों को दी। भूमि अधिग्रहण के बाद में, कृषि बिल के सन्दर्भ में भी यही स्थिति थी।

माननीय सभापति महोदय, समय कम है, इसलिए मैं सीधा इस बजट पर आता हूं। ऐतिहासिक फैसला हुआ और देश में इस फैसले की शुरुआत, जहां का मैं प्रभारी हूं उस पंजाब स्टेट से हुई। वहां के मुख्य मंत्री, चरणजीत सिंह चन्नी ने बिजली के सन्दर्भ में ऐतिहासिक फैसले लिये। यहां बातें करना अलग बात है, पर हमारे मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने जो प्रथम 50 यूनिट के अन्दर जो टैरिफ पहले 3.50 रुपये हुआ करता था, उसको फ्री कर दिया। क्या यह नीति है या राजनीति है? यह सवाल पूरे राजस्थान के सामने है। प्रथम 50 यूनिट तक सबके लिये फ्री, 51 यूनिट से 150 यूनिट तक जो 6.50 रुपये प्रति यूनिट थी, उसके ऊपर तीन रुपये की सब्सिडी और 151 से 300 यूनिट तक की 7.35 पैसे में दो रुपये की सब्सिडी दी है, वह हर वर्ग के लिये उन्होंने राहत प्रदान की। आज यह पूरी दुनिया के अन्दर जब कभी भी, यह लोग तो बड़े माहिर हैं, इनके पास तो बड़ी-बड़ी कम्पनीज हैं, सर्वे भी कराते हैं, हर चुनावों में सर्वे करवाते हैं, छोटे-बड़े सबमें, सबसे बड़े दो मुद्दे क्या आते हैं? कहीं भी दो मुद्दे आते हैं पूरी दुनिया के अन्दर एक तो इंफ्लेशन, महंगाई और दूसरा एम्प्लायमेंट। आज इंफ्लेशन के अन्दर जो सबसे बड़ी राहत राजस्थान की सरकार ने दिया है, मैं उनको तहेहिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, अशोक गहलोत जी को तहेदिल से धन्यवाद देना चाहता हूं।

(श्री हरीश चौधरी)

पुरानी पेंशन के लिये कल मैं सदन के अन्दर सुन रहा था। इस सदन में तो कम से कम असत्य नहीं बोलो। सदन के अन्दर यह बात कर रहे थे कि पुरानी पेंशन पर रोक कांग्रेस, यूपीए के अंदर लगी। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ पढ़कर आओ इस पुरानी पेंशन के सन्दर्भ में। माननीय सभापति महोदय, बोलने के लिये बहुत कुछ है, हमारे मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने खुद ने एक एडिटोरियल लिखकर अपना पूरा पक्ष उसके माध्यम से पूरी दुनिया के सामने रखा, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं।

इन लोगों की बात मुझे समझ में नहीं आती है। किसानों को कृषि बिल नहीं चाहिए था। जोर-जबरदस्ती किसानों के लिये कृषि बिल लाये। कर्मचारियों को पेंशन नहीं चाहिए, जोर-जबरदस्ती करके कि यह कर्मचारियों के हित में है। इनकी सोच किसी की समझ से परे है। दूध के सन्दर्भ में जो पांच रुपये सब्सिडी दी, उसका तहेदिल से मैं समर्थन करता हूं। तारबन्दी के लिये, बड़े-बड़े लोगों के लिये तो जो उनके फार्म हाउस हैं, छह-छह, आठ-आठ, दस-दस फीट की दीवारें होती हैं, अन्दर कोई जानवर क्या, इंसान भी नहीं घुस सकता, पर आज जो किसानों के हालात बने हुए हैं आवारा पशुओं के माध्यम से, यह आवारा पशु किसके कारण हैं? यह आवारा पशु हमारी गलत आर्थिक नीतियों के कारण हैं। हम लोग जिन्दाबाद बहुत बोल लेते हैं, पर उनके सन्दर्भ में जब गलत नीतियां होती हैं, जब हम उन पशुओं को आवारा की श्रेणी के अन्दर छोड़ते हैं, उस सन्दर्भ में राहत पहुंचायी जा रही है।

कृषि यंत्र के लिये 60 हजार किसानों को अनुदान मिल रहा है। एक लाख किसानों को सोलर पम्प की 60 प्रतिशत तक सब्सिडी मिल रही है। 25 लाख किसानों की सम्पूर्ण कर्ज माफी की थी।

माननीय सभापति महोदय, बार-बार यह जन घोषणा-पत्र की बात करते हैं। हां, जन घोषणा-पत्र बनाने वाला व्यक्ति आज आपके सामने खड़ा है। मैं हरीश चौधरी, यह जन घोषणा-पत्र मेनीफेस्टो कमेटी के चेयरमैन के तौर पर मैंने यह जन घोषणा-पत्र बनाया। आप यह बात करते हो कि 70 प्रतिशत काम जन घोषणा-पत्र के अनुसार नहीं हुआ। क्या-क्या शब्दों का आप प्रयोग करते हैं? नकल, कर्मचारियों के सन्दर्भ में क्या-क्या बातें करते हैं? इस जन घोषणा-पत्र के अन्तर्गत 70 प्रतिशत ही नहीं, उससे ज्यादा फैसले राजस्थान सरकार के हुए हैं। यह मैं इस सदन के माध्यम से इस देश और दुनिया को बताना चाहता हूं।

(श्री हरीश चौधरी)

सभापति महोदय, समय कम है। इस रिफाइनरी का भी बहुत बड़ा इतिहास है। रिफाइनरी बनाने की मांग की गई। हमारे पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी का बाड़मेर और रामसर दौरा था। मैं उस वक्त सांसद था। तर्क के आधार पर पर मैंने भी उनसे निवेदन किया। उस वक्त के तत्कालीन पेट्रोलियम मिनिस्टर के अपने तर्क थे। उस तर्क के आधार पर उन्होंने वह बात स्वीकार नहीं की लेकिन हम लोगों ने लगातार उस बात की पैरवी की और आखिर में बाड़मेर के अन्दर वह रिफाइनरी लगी। मेरे विधान सभा क्षेत्र बायतू के अन्दर आज रिफाइनरी के सन्दर्भ में जो फैसला लिया गया, उसके लिये मैं तहेदिल से धन्यवाद देना चाहता हूं।

किसान से इन लोगों को पता नहीं क्या एलर्जी है। वोट के वक्त तो किसान, किसान और विवाद के वक्त कुछ नहीं। आज कृषि बजट से शुरुआत हुई है किसानों के लिये तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। उसमें यह बात कह रहे हैं कि 11 मिशन हैं। किसान के सन्दर्भ में 11 मिशन हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों? उन बड़े पूंजीपतियों के लिए 3-3 लाख करोड़ की टैक्स माफी, तब आप लोग कुछ नहीं बोलते हो। मैं तहेदिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कृषि बजट और उसके माध्यम से इन 11 मिशनों के लिये।

टूरिज्म के अन्दर जो इण्डस्ट्री का दर्जा दिया गया है, वह भी एक ऐतिहासिक फैसला है। मैं इसके लिए तहेदिल से राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मेरे एक मित्र जमीन की कुर्की के लिये बोल रहे थे। शायद ही कोई दूसरा प्रदेश हो सकता है, राजस्थान सरकार ने 5 एकड़ तक की जमीन को कुर्क नहीं करने का इस सदन से बिल पारित कराकर, कानून बनाकर महामहिम राज्यपाल के पास भेजा। हमारे विपक्षी मित्र राज्यपाल महोदय के पास उसको वापस लौटाने के लिए, कानून बनाने की जगह उस पर विवाद कर रहे हैं। उस विवाद के पीछे क्या कारण हैं? यह इनकी सोच है क्योंकि उसमें किसी अडानी, अम्बानी का फायदा नहीं हो रहा है। उसके अन्दर राजस्थान के आम किसान का फायदा हो रहा है। मेरा हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि हम लोग एक सर्वदलीय डेलीगेशन लेकर चाहे राज्यपाल के पास हो, चाहे केन्द्र सरकार के पास हो, यह 5 एकड़ जमीन की कुर्की के सन्दर्भ में जायें। आप उनके लिये सिर्फ बातें नहीं करो, आप उनके लिये 5 एकड़ जमीन के सन्दर्भ में बात करें।

सभापति महोदय, पेट्रोल, डीजल के बारे में यह बात कर रहे हैं।

(श्री हरीश चौधरी)

इनकी मोरल अथोरिटी है कि यह पेट्रोल, डीजल के बारे में बात करें? इन्होंने देश के सामने किस तरह की बात रखी है? प्रधान मंत्री जी ने खुद यह बोला कि आपके प्रधान मंत्री भाग्यशाली हैं इसलिए अन्तरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की दरें कम हो गयी हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो आज अन्तरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड आयल की दरें हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भाग्य से इसको आज भी जोड़कर रखेंगे या नहीं रखेंगे? अन्तरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड आयल की रेट 100 डालर से ज्यादा हो गयी है। आज उसको भाग्य से जोड़ेंगे या किसी और से जोड़ेंगे, इस बात का भी जिक्र जरूर करना।

सभापति महोदय, सैस और एडिशनल एक्साइज के माध्यम से राजस्थान के हितों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसी के कारण राजस्थान सरकार ने अपने टैक्स बढ़ाये हैं। टैक्स बढ़ाने के पीछे कारण क्या हैं? उसकी जिम्मेदारी इन लोगों को लेनी चाहिए। उसमें भी यह कह रहे हैं कि गंगानगर में कितने हैं, जयपुर में कितने हैं? सबको पता है कि गंगानगर में कितने हैं और जयपुर में कितने हैं। लेकिन उसका कारण क्या है? उसका कारण केन्द्र सरकार के सैस और एडिशनल एक्साइज हैं। उसके पीछे सोच और विचारधारा क्या है? वह क्रोनी-कैपिटलिज्म है। रिलायंस को ज्यादा से ज्यादा फायदा इस पेट्रोलियम इण्डस्ट्री से कैसे मिले, उसके कारण यह निर्णय किये गये।

सभापति महोदय, जेएसडब्ल्यू, जो उनके प्रमोटर्स हैं, जो उनके आनर हैं, वह किनके खास हैं? आज पूरी दुनिया अच्छी तरह से जानती है, मैं वापस उस बात की याद दिलाऊं। पाकिस्तान के अन्दर हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी को वहां उस वक्त के तत्कालीन प्रधान मंत्री से मिलने के लिये कौन लेकर गये? किस कारण लेकर गये? उसकी चर्चा भी इस सदन के अन्दर आपने जेएसडब्ल्यू के सन्दर्भ में की। इस जेएसडब्ल्यू के अन्दर भूमि अधिग्रहण के वक्त जब इनकी सरकार थी, 20 और 25 हजार बीघे के हिसाब से जमीन का कम्पनसेशन दिया। जब यहां हेमाराम चौधरी राजस्व मंत्री थे और अशोक गहलोत जी मुख्य मंत्री थे तो 3 और साढ़े 3 लाख रुपये के हिसाब से उन किसानों को भूमि के बदले मुआवजा मिला। कौन किसके साथ था? यही आंकड़े बाड़मेर से लेकर पाकिस्तान यात्रा और दिल्ली में जो फैसले हो रहे हैं, वह सब दुनिया अच्छी तरह से जानती है।

आप सिर्फ बोलने के लिये बोल रहे हो। अगर करना है तो आपके पास

(श्री हरीश चौधरी)

कई ताकत हैं। अपनी ताकत से उस जेएसडब्ल्यू का जो करना है, जो दूसरी जगह आप लोग करते हो, वह कर सकते हो। सिर्फ बातें करने के लिये जेएसडब्ल्यू की बात नहीं करो, यह मेरा निवेदन है।

सभापति महोदय, इन लोगों से बराबरी नहीं हो सकती है। बराबरी नहीं हो सके तो बदनामी शुरू कर दो लेकिन बदनामी से बदनाम हो सकते हैं, नाकाम नहीं हो सकते। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में बेहतरीन बजट के सामने बराबरी करनी है तो केन्द्र सरकार के बजट के रूप में देश की जनता ने आपको अवसर दिया है। उस बजट के अन्दर बराबरी करो। सिर्फ बदनाम करने के लिये आरोप-प्रत्यारोप नहीं करें। आरोप-प्रत्यारोप की जो संस्कृति इन्होंने शुरू की है वह हमारे समाज के लिये बहुत घातक है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन में निवेदन करना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस के अन्दर किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। प्रधान-मन्त्री फसल बीमा की हम लोग चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा के विज्ञापन हम लोग देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से हमें कितना नुकसान हो रहा है? बाड़मेर जिले में खरीफ 2018 के अंदर 335 करोड़ का कम्पनसेशन, जो हमारा हक और अधिकार था, वह राजस्थान सरकार ने टाटा एआईए बीमा कम्पनी के माध्यम से हमको दिलाने का फैसला किया। जब वह दिल्ली के कृषि मंत्रालय में गयी तो वह फैसला उलट दिया गया।

(समय: 15.56 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

मेरे कामरेड मित्र यहां बोल रहे थे। उनकी संख्या कम है इसलिए आवाज नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने किसानों के फसल बीमा के सन्दर्भ में अपनी बात रखी। मेरा भी मन हुआ कि वेल के अन्दर जाऊं। लेकिन यह दलीय व्यवस्थाएं हैं, उनमें हम लोगों की भी सीमाएं होती हैं। व्यक्तिगत तौर पर मैंने उनको धन्यवाद दिया।

अध्यक्ष महोदय, पैमाने बदले जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विद इन टू मिनट्स, वाइंड अप। प्लीज।

श्री हरीश चौधरी (बायतु): अध्यक्ष महोदय, मैं अभी कर लेता हूं।

श्री अध्यक्ष: टू मिनट्स, वाइंड अप।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): अध्यक्ष महोदय, 60:40 के माध्यम से जो क्राप कटिंग और मौसम के आधार पर था, उसको बदलकर 40:30:30 किया। उसमें ग्रीन इंडेक्स को भी शामिल किया है। उससे हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। यह कोई भी ग्रामीण पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति अच्छी तरह से जान सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि हम लोग हमारी खुद की स्टेट इंश्योरेंस कम्पनी खोलकर उसके माध्यम से राजस्थान के किसानों को फसल बीमा दिलायेंगे। यह पहली बार नहीं हो रहा है। गुजरात तथा दूसरे प्रदेशों के अन्दर भी स्टेट इंश्योरेंस कम्पनीज के माध्यम से कर रहे हैं जिससे लोगों को न्याय मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हाउसिंग बोर्ड के अन्दर हमारे मंत्री शान्ती धारीवाल जी को चेयरमैन बनाया। इस बात को आगे बढ़ाया कि इस बोर्ड के माध्यम से क्या कुछ होता है और क्या कुछ हो रहा है। मैंने राजस्व मंत्री के तौर पर खुद भी निवेदन किया था कि रेवेन्यू बोर्ड की जगह दूसरी व्यवस्था करो जिससे आम अवाम को न्याय मिल सके, केसेज में न्याय मिल सके। पोल्यूशन बोर्ड हो, इंडस्ट्री में रीको हो, रेवेन्यू बोर्ड हो, यह फैसला जो मुख्य मंत्री जी ने किया है, इस फैसले को आगे बढ़ाते हुए बोर्ड के माध्यम से भी करें।

अध्यक्ष महोदय, पेयजल हम लोगों के लिये सबसे बड़ी चुनौती है। पेयजल में 90 प्रतिशत सब्सिडी केन्द्र सरकार सेन्ट्रल स्पोंसर्ड स्कीम के तहत हमें देती थी।

(समय: 16.00 बजे)

डीपीएपी के अन्दर, डीडीपी में, एनआरडीडब्ल्यूपी के अन्दर सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम्स के अन्दर, आज जब जेजेएम के माध्यम से हम लोगों को, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, पूरे सदन को निवेदन है कि इस सत्र के अन्दर हम इस बारे में चर्चा करें, जो अन्याय राजस्थान के साथ हो रहा है, डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर हो रहा है, आज टिली एरिया के अन्दर उनको उतना ही मिल रहा है लेकिन हमको डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट के अन्दर नहीं मिल रहा है। 5 प्रतिशत हम लोगों को देना पड़ता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह पीड़ा 15 हजार रुपये प्रत्येक हाउसहोल्ड को देना पड़ रहा है। ये तो मैं आज वापस धन्यवाद देता हूं आदरणीय अशोक गहलोत जी को कि जेजेएम में जो फाइनेंशियल प्रोविजन राज्य सरकार की तरफ से हुआ है उसके कारण से जेजेएम के अन्दर हम लोगों को राहत मिलती है।

(श्री हरीश चौधरी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। ये गोमाता के बारे में बहुत बोलते हैं।

श्री अध्यक्ष: I said, Four O'clock is Four O'clock. Please wind up within five minutes.

श्री हरीश चौधरी (बायतू): माननीय अध्यक्ष महोदय, गोमाता के माध्यम से ये बातें बहुत करते हैं। जेजेएम के अन्दर इन्होंने प्रोविजन रखा है, सिर्फ मनुष्य के लिए इन्होंने रखा है, पशु के लिए नहीं रखा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केवल नारों तक गोमाता नहीं रखें, फैसलों के वक्त भी रखो जैसे अशोक गहलोत जी फैसलों के वक्त भी, जो गाय के सन्दर्भ में इन्होंने जो फैसला किया वैसा फैसला करो। हां, नारे और राजनीतिक माइलेज के लिए तो आप कोई बात कर सकते हो।

श्री अध्यक्ष: I am extremely sorry, माननीय सदस्य।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): चुनाव के अन्दर योगी आदित्यनाथ को भी जाति बताने की मजबूरी हुई।

श्री अध्यक्ष: Please wind up.

श्री हरीश चौधरी (बायतू): माननीय अध्यक्ष महोदय, साधु की कोई जाति नहीं होती है। चुनावी माइलेज लेने के लिए उनको भी अपनी जाति बतानी पड़ी। इसलिए चुनाव के वक्त ही जय गोमाता मत करो, फैसलों के वक्त भी जय गोमाता करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया। जितना समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: Please, don't commend it. I don't want to listen this.

श्री हरीश चौधरी (बायतू): धन्यवाद।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बजट पर मैं राजस्थान की जनता की तरफ से हकीकतों को लाने का प्रयास करूंगा। मैं सोचता हूं कि बजट हर राज्य के विकास का एक मेरुदण्ड बनता है। इसी बात को ध्यान में रखकर अब तक जनता ने क्या दिया और हमने उसका क्या उपयोग किया, यही वास्तव में बजट की सबसे बड़ी सैंक्टिटी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कि जिस तौर तरीके से हमने अबकी बार बजट बनाया है, मेरे हिसाब से, मैं कोई बहुत अर्थशास्त्री तो नहीं हूं लेकिन अगर इन आंकड़ों को देखा जाये, एनेलेसिस किया जाय तो यह धरती पर दुनिया की कोई ताकत नहीं उतार सकती, यह गुलाब चन्द कटारिया आज इस सदन में कह रहा है। पढ़ने और सुनने से हर आदमी को अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा लेकिन इसकी जब तह में जाते हैं तो इस अच्छाई को जमीन पर कैसे लाओगे, वैसे ही लाना होगा, जैसे इन्दिरा गांधी आयी है नई रोशनी लायी है, इन्दिराजी आयेंगी, गरीबी मिटायेंगी। ये 1971 के नारे हैं। अब 50 साल में गरीबी मिट गयी देश की? आज तो बहुत देश धनवान हो गया? वैसी ही दुर्गति इसकी होगी। आपने एक और नारा लगाया कि देश की एकता और अखण्डता के लिये कांग्रेस को वोट दो, देश को तोड़ा किसने? देश में देशद्रोही पैदा किसने किये? यहां बम पटकने वाले लोग कौन लाया? इसके बारे में भी ऐसा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा का ऐसा ही पिछली बार में कहा। आज भी मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं कि एक, दो, तीन, चार, नौ, दस, कर्जे माफ हो गये? एक लाख से अधिक लोगों की जमीनें कुर्क हो गयीं कुर्क। ऐसा क्यों करो जो हमसे सम्भव नहीं होता है? उतना ही बोलो जितना सम्भव हो सकता है। आपने कहा कि संविदा के सब लोगों को हम पक्का कर देंगे, कर दिया न? वो नारा तो बाहर था, चलो वहां का हिसाब कभी और करेंगे। आपने इस प्रकार की बातें कहकर जनता को गुमराह किया। सब बेरोजगारों को 3500 रुपये प्रति माह मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ा-सा आपका ध्यान ईमानदारी से इस ओर ले जाना चाहता हूं कि इन आंकड़ों को देखने का प्रयास कीजिये। बड़े-बड़े विद्वान लोग हैं आपके साथ, मैं तो विद्वान नहीं हूं। ये जो राजस्व प्राप्तियां हैं, ये राजस्व प्राप्तियां 2015-16 में 1 लाख 285 करोड़ रुपये थीं। 2016-17 में बनी 1 लाख 9 हजार, 2017-18 में बनी 1 लाख 27 हजार, 2018-19 में बनी 1 लाख 37 हजार, उसके बाद 2019-20 में यह आयी है 1 लाख 40 हजार। आपके इन आंकड़ों को देखने से यह तो समझ में आता है कि हर साल वृद्धि है रेवेन्यू रिसीट में, वो एक सामान्य स्तर के हिसाब से ही चल रही है, कोई एकदम चमत्कार नहीं हुआ है, पर आप चमत्कार करने वाली ताकत हो। आपने देखा होगा कि आपने 2019-20 में बीई लिया था, वो लिया था 1 लाख 64 हजार करोड़, आपके एक्चुअल हो गया 1 लाख 40 हजार

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

करोड़, मतलब अब तक तो सोचते थे उसके करीब पहुंचते थे, कभी-कभी कोई दो-तीन हजार घटता था, सीधा का सीधा आपके 1 लाख 64 हजार का आपने अनुमान किया और 1 लाख 40 हजार आया। सीधा का सीधा 23 हजार 890 करोड़ रुपये का रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, 2019-20 में। फिर आपके 2020-21 में कोरोना के कारण थोड़ा बहुत कह सकते हैं 1 लाख 73 हजार करोड़ माना, आप एक्चुअल में आ गये 1 लाख 34 हजार करोड़ पर, 1 लाख 73 हजार करोड़ सोचा और 1 लाख 34 हजार करोड़ पर आ गये। अब आपने 2021-22 का जो बीई लिया उसमें आपने 1 लाख 84 हजार करोड़ माना, अभी रिवाइज एस्टीमेट किया तो आपने 1 लाख 89 हजार करोड़ माना।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक कह रहा हूं कि जो कुछ मैं समझ पाया हूं दिसम्बर तक अभी राजस्थान की रिसीट हुई है 1 लाख 16 हजार करोड़ रुपये। अब मैं आपसे थोड़ा विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। अबकी बार तो आपने तो पूरा ही कमाल कर दिया। पिछली आपकी जो रेवेन्यू रिसीट 2020-21 में एक्चुअल आयी है वो 1 लाख 34 हजार करोड़ आई है। अबकी बार आप अपना रेवेन्यू रिसीट ले गये सीधा 2 लाख 14 हजार करोड़ रुपये। क्या यह वृद्धि सम्भव है? क्या यह वृद्धि की जा सकती है? वर्तमान सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वर्ष 2022-23 में अनुमान बहुत ही गलत तरीके से, लोक लुभाने के उद्देश्य से लगाये गये हैं जो कि वास्तविकता से परे हैं। प्रथमत: यह है कि सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में मांगों की अनुसूची पृष्ठ 1 पर पढ़ें। समेकित निधि के तहत राजस्व प्राप्तियों के वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2 लाख 14 हजार 977 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होने का अनुमान दर्शाया है। यह कदम ही कपोल कल्पित है। मैं आज नहीं कह रहा हूं, मेरी इस बात को आने वाला कल साबित करेगा कि यह कपोल कल्पित है या नहीं है या यह कहूं कि यह जादूगर की जादूगरी है तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हकीकत तो यह है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अभी मैंने आपको जो बताया था, राजस्व प्राप्तियां 1 लाख 34 हजार 307 करोड़ रुपये ही रही थी, इस हेतु चालू वित्तीय वर्ष में अनुमान 2021-22 से 1 लाख 84 हजार 330 करोड़ रुपया बताया गया, जिसे बढ़ाकर 1 लाख 89 हजार करोड़ रुपये किया गया। ये अनुमान वास्तविकता से एकदम परे हैं। अत: सरकार से मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि चालू वित्तीय वर्ष जो अभी चल रहा है जिसमें आपने 1 लाख 89 हजार करोड़ आरई इसका लिया है। उसका जो मैंने फिगर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

देखा है दिसम्बर, 2021 तक जो आपकी रेवेन्यू रिसीट हुई वह आपके 1 लाख 16 हजार 185 करोड़ रुपये हुई। आपका जनवरी का महीना भी आ गया, आपके साथ विद्वान लोग बैठे हैं, मुझे यही बता दें कि 31 जनवरी के दिन राजस्थान का रेवेन्यू रिसीट क्या था? अब बचे हुए दो महीनों में हम क्या चमत्कार करेंगे कि अपनी इस रेवेन्यू रिसीट को पूरी कर लेंगे? 2022 तक कितनी राजस्व प्राप्तियां हो चुकी हैं, वो कृपया सदन पटल पर रखें। कृपया यह भी स्पष्ट करें कि दो बाकी के माह में शेष रही प्राप्तियां प्राप्त हो जायेंगी? यदि नहीं तो साफ है कि सरकार ने ये अनुमान केवल वाहवाही लूटने के लिए प्रदर्शित किया है और यह यहीं तक ही सीमित नहीं रहते हुए आगामी वित्तीय वर्ष में 2022-23 के बजट अनुमानों में इन प्राप्तियों की राशि को बढ़ाकर 2 लाख 14 हजार 977 करोड़ रुपये किया है। इससे तो यह जाहिर होता है कि वर्ष 2020-21 में जो एक्चुअल आपके पास आ गया था उससे आप लगभग 80 हजार करोड़ रुपये रेवेन्यू रिसीट बढ़ाओगे। 80 हजार करोड़ रुपये रेवेन्यू रिसीट्स बढ़ायेंगे, यह चमत्कार है। 2014 से लेकर अब तक इतने बजट मैंने देखे हैं, उनमें कहीं मुझे दिखाई दिया नहीं। आपके यहां टैक्स में छोड़ रहे हैं आप। यह भी छूट मिल रही है, वह भी छूट मिल रही है तो फिर ऊपर से आमदनियां पड़ेंगी, जिसके कारण से थैला भरेंगे। मतलब कुछ समझ में ही नहीं आता, क्या कहना चाहते हैं। नजर डाली जाये तो किसी को भी राजस्व प्राप्ति में इतनी वृद्धि कभी भी नहीं हुई, फिर न जाने गहलोत सरकार ने किस चमत्कार की उम्मीद से यह अनुमान लगाया है। ये आंकड़े वास्तव में सदन को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं हैं।

इसी प्रकार बजट अनुमान में प्राप्तियों की तुलना में हकीकत में राजस्व प्राप्तियां कम होने से राजस्व घाटा, जो कि सरकार ने वर्तमान में बजट प्रस्तुत किया है, वह राजस्व घाटा आपने माना है 23 हजार 488 करोड़। मैं 80 हजार करोड़ का डिफरेंस मान रहा हूं। 80 हजार करोड़ के रेवेन्यू रिसीट्स आप करेंगे और ये जब नहीं होंगी तो आपका यह जो कर्जा है, इसे सपोर्ट में लेने के लिये जो आप यहां आंकड़े दे रहे हैं 23 हजार करोड़ रुपये का घाटा रहेगा, वह कई गुना बढ़ेगा, जो आगे दिखेगा। इससे एक बात और जाहिर होती है कि जब सरकार इतना राजस्व हासिल ही नहीं कर सकेगी तो साफ ही जाहिर है कि व्यय करने के लिये भी सरकार के पास इतनी कम धनराशि उपलब्ध होगी, जिससे आवश्यक चीजों को छोड़कर कई विकास कार्यों में भी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सरकार को मजबूरन कटौती करनी पड़ेगी और परिणामत: कई सारी योजनाएं धूल चाटती नजर आयेंगी।

यह वाकया रिकार्ड हो जाये। मैं रहूं, न रहूं तो भी आने वाली पीढ़ी उसे पढ़े। कई जगह तो ऐसी स्थिति हो जायेगी, जैसे- घर में नहीं है दाने और बुढ़िया चली भुनाने।।

कई सारी योजनाओं का मात्र शिलान्यास, मेरे शब्दों को समझ लेना, केवल और केवल शिलान्यास करके राजस्थान की जनता को धोखा देने के अलावा इस बजट में आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकेंगे। यह मैं दावे के साथ कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, ये जो पूंजीगत प्राप्तियां आपने अनुमानित की हैं, उन्हें प्राप्त करने का 2019-20 का जो बीई था, वह 69 हजार करोड़ था। आपने पूंजीगत सपोर्ट लेकर 4 हजार 474 करोड़ बढ़ाकर इस पूंजीगत प्राप्ति को 73 हजार करोड़ किया। यहां आपको सपोर्ट करने के लिये 4 हजार और अधिक लेना पड़ा। बहुत कमाल है। मैं सोचता हूं कि राजस्थान की जनता को गुमराह करने का काम मत करिये कृपा करके। सारी सेंसेटिविटी खतम हो जायेगी।

आपने 2020-21 में जो बीई सोची है प्राप्ति की, वह है 52 हजार 360 करोड़ रुपये। आपकी एक्चुअल पहुंच गयी है 1 लाख 703 करोड़ रुपये। इसका मतलब आपने यह कहां से एडजस्ट किया, 48 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्जा, जो आपने नहीं दिखाया, वह आपने लेकर इस बजट को पार करने का प्रयास किया है। इसी तरह से आप देखेंगे कि 2021-22 में आप 66 हजार 501 करोड़ रुपये बीई में लेकर आये कि हमें पूंजीगत प्राप्तियां होंगी, लेकिन पूंजीगत प्राप्तियां आरई में हुईं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस फिगर को विशेष रूप से देखें, 1 लाख 29 हजार 667 करोड़ रुपये। बजट को सपोर्ट करने के लिये आप पूंजीगत प्राप्तियां, मतलब कर्जा जिस प्रकार से ले रहे हैं, वह लगभग होगा 63 हजार 195 करोड़ रुपये। कर्जे से लेकर जो रेवेन्यू रिसीट्स में कमी पड़ी, यह आप उसकी पूर्ति कर रहे हैं। अबकी बार फिर आपने हवाई किला बनाया है। आपकी बीई 2021-22 में थी 66 हजार करोड़, आप अबकी बार बीई में चले गये 1 लाख 31 हजार 324 करोड़ रुपये। क्या बनाना चाह रहे हैं? मैं सोचता हूं कि 2021-22 का जो बजट अनुमान था, उसकी तुलना में 2022-23 का बजट अनुमान 64 हजार 823 करोड़ रुपये का अधिक रखा, मतलब यह सीधा

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

का सीधा पूंजीगत प्राप्तियां। कर्जा लेकर अपने बजट को एडजस्ट करने के लिये यह आपने इसमें रखा है।

इसी तरह से पूंजीगत व्यय, जो विकास के लिये सबसे बड़ा मापदण्ड है, क्योंकि रेवेन्यू रिसीट्स और व्यय तो हमारा लगभग बराबर-सा हो जाता है। कभी-कभी और भी पूंजीगत घाटा हमें होता है। मान लें, नहीं भी हुआ घाटा तो भी अब यह जो पूंजीगत व्यय आपने सोचा था 2019-20 में, बीई में 19 हजार 472 करोड़ रुपये से हम विकास कार्य करेंगे। एक्चुअल में आप विकास कितना कर पाये, 14 हजार 718 करोड़ का। इसका मतलब जितना आपने सोचा था, ये भाटे लगे के लगे क्यों रह जाते हैं, ये इस कारण से रह जाते हैं कि उसको बजटरी सपोर्ट नहीं मिलता है। उसके कारण से वह काम आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि पैसा नहीं होता। आपने 4 हजार 754 करोड़ रुपये विकास कार्य में कटौती कर दी। यह आपका 2019-20 का अकाउंट बताता है।

अब 2020-21 का अकाउंट। आपने माना था 21 हजार 618 करोड़ के हम विकास कार्य करेंगे। किया कितना है, 15 हजार 270 करोड़ रुपये। इसका मतलब इसमें जो विकास पर खर्च होना चाहिये 6 हजार 348 करोड़ रुपये, विकास में कम खर्च करके, जो काम जहां अटका, यह पांच-पांच साल, सात-सात साल योजनाएं क्यों चलती हैं, इस कारण से चलती है कि हम लोगों को खुश करने के लिये और ताली पिटाने के लिये, यह भी मिल जायेगा, वह भी मिल जायेगा। मिलेगा कहां से, जेब में होगा तो मिलेगा। यह आपकी दशा है। अभी आपने क्या कमाल किया? आपने 2021-22 में बीई बनायी थी 24 हजार 215 करोड़ की और अभी रिवाइज्ड एस्टीमेट में आप आये हैं 24 से सीधे 28 हजार करोड़ रुपये पर। वास्तव में मैंने दिसम्बर तक का जो आंकड़ा ढूंढा है, अभी तक आपका जो खर्चा हुआ, वह 16 हजार 518 करोड़ रुपये हुआ है। इसका मतलब इतना पैसा खर्च करके विकास को 9 महीने लगे, अब आप 3 महीने में चमत्कार करके 8 हजार करोड़ रुपये खर्च करके विकास का काम पूरा कर लेंगे? यह वास्तव में जनता के साथ ठगाई का धन्धा हो रहा है।

इसी तरह से अबकी बार आप बजट अनुमान में सीधे के सीधे कह रहे हैं कि 34 हजार करोड़ के हम विकास कार्य करेंगे। कहां से करेंगे? पहले से ही डाउन से डाउन जा रहे हैं। यह जो 43 परसेंट विकास का पैसा आप खर्च करने का बढ़ा रहे हैं, यह आपके पास उपलब्ध नहीं होगा, यह मेरी गारंटी है। मैं

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आपको सही ढंग से कह रहा हूं। आप इसे समझना चाहें तो समझें और न समझना चाहें तो आपकी इच्छा।

जो आपका बजट था, वह रेवेन्यू और पूंजीगत, दोनों मिलाकर 2019-20 का बीई बनाया था 2 लाख 33 हजार करोड़ का। एक्चुअल में कितना खर्च हुआ, 2 लाख 13 हजार करोड़, अर्थात् आप अपने बजट को सब कुछ, पैसा उधार लेने के बाद भी 19 हजार 416 करोड़ रुपये कम खर्च कर पाये। इसके बाद आपने 2020-21 का बीई लिया और 2 लाख 25 हजार करोड़ का बजट रखा यहां हाउस में। आपने इसको अभी पूरा जो किया है, वह है 2 लाख 35 हजार। इसका मतलब आपने 9 हजार 247 करोड़ रुपये और अधिक कर्ज लेकर बजट को इस 2020-21 में पूरा किया। अब आपका 2021-22 का बजट है 2 लाख 50 हजार करोड़ रुपये का। आरई में वह कितना चला गया, 2 लाख 50 हजार का बजट आपने यहां रखकर थपथपवाया, वह बजट आरई में पहुंच गया। सभी बन्धुओ, समझने की कोशिश करें, 3 लाख 19 हजार करोड़ रुपये आरई में आ गये हैं। 2 लाख 50 हजार करोड़ सोचा था बजट और वह आ गया है 3 लाख 19 हजार 128 करोड़ रुपये। अब यह पैसा कहां से आयेगा? या तो कर्जे में से निकलेगा। बीई में 2 लाख 50 हजार करोड़ से शुरू किया आपने 2021-22 का बजट। अभी आप सीधा 3 लाख 46 हजार करोड़ पर जा रहे हैं। यह आयेगा कहां से पैसा? केवल और केवल आंकड़ों के एडजस्टमेंट के आधार पर लोगों को झुनझुना पकड़ाकर नचाएं तो आपकी इच्छा। कोई दिक्कत नहीं, हमें तो कोई परेशानी नहीं है। पर मैं यह कह रहा हूं कि यह जो आपका 2021-22 का बीई था, उससे सीधा ही 94 हजार 470 करोड़ रुपये का अधिक बजट इस साल आप पेश कर रहे हैं, जो 3 लाख 46 हजार करोड़ तक जा रहा है। अब यह आपका जो व्यय है न, वह बता रहा है कि व्यय में आपने जो 2019-20 में सोचा था, 2 लाख 10 हजार करोड़ रुपये खर्च करेंगे वह हुआ 1.91 ही, 19,288 करोड़ रुपये आप व्यय नहीं कर पाये, कम खर्च किये।

इसी तरह से आपने 2020-21 में 2 लाख 7 हजार 368 करोड़ रुपये का सोचा था, उसकी जगह 1.93 लाख करोड़ ही आप खर्च कर पाये, इसका मतलब 13,789 करोड़ रुपये आप खर्च ही नहीं कर पाये। अब आप जो खर्चे में आ रहे हो वह 2.32 लाख करोड़ में आ रहे हो, 2.53 लाख करोड़ आपने आर.ई. माना है, वास्तव में होगा नहीं और अभी जो आपने बी.ई. सीधी बढ़ायी है वह आप 2.73 लाख करोड़ पर आ गये हो। आपका जो एक्चुअल 2020-21

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

में आया था वह 1.93 लाख करोड़ है और अभी आप 2.73 लाख करोड़ पर जा रहे हो। अब यह जो आपकी 40 हजार करोड़ की वृद्धि आ रही है, यह बजट कैसे, कहां से आयेगा, किस तरह से आयेगा? समझाने का प्रयास करें तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा।

सबसे बड़ी आमदनी होती है वह कर से होती है। अब कर में आपकी क्या स्थिति आयी है? 2019-20 में आपने सोचा था कि हम 1 लाख 18 हजार कर वसूल करेंगे, यह बी.ई. में आया और एक्चुअल में हुआ कितना? केवल 95 हजार करोड़। इसका मतलब 22,910 करोड़ रुपया वसूल करना जो आपका काम है, आपने आखिर अपना अकाउंट मिलाया होगा कि हमको यहां-यहां से इतना-इतना पैसा इस कर में मिलेगा और उसके आधार पर बजट बनाया और उसकी स्थिति यह हो गयी है कि केवल और केवल आप 22,910 करोड़ रुपया वसूल नहीं कर पाये जो आपने अनुमान लगाया।

इसी तरह से 2020-21 में आपने सोचा है कि हमको 1 लाख 23 हजार करोड़ रुपये का कर आयेगा। आया कितना? वही 95 हजार करोड़ पहले भी 2019-20 में वही 95 हजार करोड़ आया और इसमें भी एक्चुअल कितना आया? 95 हजार करोड़ ही आया। इसी तरह से आप 2021-22 में गये थे कि 1 लाख 30 हजार करोड़ हमको मिलेगा और आप अभी आर.ई. में 1.27 लाख करोड़ पर आये हो। मैंने जो हिसाब निकाला वह 31 दिसम्बर का ही आंकड़ा मुझे मिल पाया और केवल और केवल 80 हजार करोड़ का आप कर पाये हो। इसका मतलब जितना पैसा आपको मिलना चाहिए था, 1.30 लाख करोड़ माना वह भी 50 हजार करोड़ रुपये आज की तारीख में ज्यादा है। अब आप सीधे ही 2022-23 में आ गये और 2022-23 में सोचा क्या कि हमारे पास इतने पैसे आ जायेंगे, इतने पैसे आ जायेंगे कि सब जगह भाटे लगा देंगे और वह 1 लाख 47 हजार 504 करोड़ रुपया हमको मिलेगा। मिलेगा कहां से? कोई आधार तो बताओ, बढ़ोतरी भी हो सकती है 5-10 हजार करोड़ की, पर जब आप सब प्रकार की छूट दे रहे हो और आपने कहा कि हमने 1,500 करोड़ रुपये की टैक्स में छूट दी है तो फिर यह कहां से आयेगा, यह समझ में आने वाला नहीं है।

अ-कर राजस्व, इस अ-कर राजस्व में भी आपने 2019-20 में 19 हजार करोड़ सोचा था और मिला केवल 15 हजार करोड़। इसका मतलब आपको 2 हजार 400 करोड़ रुपया अ-कर में भी कम मिला। इसी तरह से

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आप 2021-22 में आये तो 19 हजार 595 करोड़ सोचा था, आपको मिला 13 हजार 600 करोड़, 5 हजार 942 करोड़ रुपया कम मिला। अब आप 2021-22 में आये तो आपने सीधा ही 17 हजार करोड़ का सोचा और आर.ई. आपने बैठे-बैठे ही बना दी वह 18 हजार करोड़ की बना दी और एक्चुअल में आपके पास 31 दिसम्बर के दिन तक जो अ-कर पैसा आया है वह 11 हजार 640 करोड़ रुपया आया है। कहां से क्या करोगे आप? आर.ई. और बी.ई. में, अभी हमारे पास समय कितना बचा है और सीधा ही अ-कर माना 22 हजार करोड़। अभी तक तो आप 13 हजार करोड़ रुपये वसूल कर पाये और उसकी जगह सीधा का सीधा 22 हजार करोड़ रुपया अ-कर आ जायेगा तो आयेगा कहां से?

केन्द्रीय कर में, बार-बार हरेक कोई भाषण देता है तो सबने एक सोच लिया, हम सब लोगों के दिमाग पर राजनीति का चश्मा चढ़ गया है और हकीकत को समझना नहीं चाहते हैं। केवल उठे और गालियां ठोकीं। केन्द्रीय सरकार से सहायता, यह मैंने फिगर नहीं बनाया, आपने जो डाक्यूमेंट दिये उसी आधार पर पढ़ रहा हूं। 2019-20 में सोचा, वह सोचा कि 26 हजार करोड़ मिलेगा, उसकी जगह आपको 29 हजार करोड़ मिला। 26 हजार करोड़ आपने अनुमान किया था उसमें 29 हजार करोड़ मिले। 2020-21 में जरूर आपने 29 हजार करोड़ माना और उसमें आपको कम पैसा आया, 24 हजार करोड़ ही आया और यहां आपको 5097 करोड़ का कम केन्द्रीय करों से मिला। अभी आप जो 2021-22 में जा रहे हो तो आपने सोचा है कि 36 हजार करोड़ मिलेगा और अभी आपने आर.ई. में स्वयं ने माना है 43 हजार करोड़ रुपया। इसका मतलब पैसा बढ़ रहा है केन्द्रीय करों में। इसका मतलब इसमें 24 हजार 332 की सीधी बढ़ोतरी हुई है। अब आपने जो अगले साल का माना है अगर आपको कोई अनुमान ही नहीं होता तो आप यह केन्द्रीय करों में हिस्सा आपको मिलने वाला हो 45 हजार 317 करोड़ तो यह कहां से मिलने वाला है? यह आंकड़ा भी इसी तरह से निकाला होगा या उनके कुछ आंकड़े देखकर मिलाया होगा। मैं सोचता हूं कि वास्तव में आपका अकाउंट बनाने वाला कोई न कोई बहुत होशियार आदमी है और आपने जिस तरह से कहा होगा तो उसने बनाया होगा क्योंकि जब मालिक खुश तो दुनिया खुश और मालिक नाराज तो कहां रहेंगे।

अब आप देखो कि क्या दुर्गति हो रही है। सामाजिक सेवाओं पर जो व्यय है, सामाजिक सेवा का मतलब शिक्षा, चिकित्सा, ये सारे हैड आते हैं, इस पर आपने 2019-20 में जो सोचा था वह 84 हजार 815 करोड़ रुपये खर्च होंगे और केवल 73 हजार 802 खर्च हुए। 11 हजार करोड़ रुपया जो आपने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सामाजिक सेवा पर सोचा था उसमें कम खर्च हुआ। इसका मतलब वे पत्थर वहीं के वहीं चिपके रह गये, क्योंकि आपने सोचा था कि पैसा आयेगा पर आया नहीं। इसी तरह से आपने 2021-22 में सोचा कि 85 हजार करोड़ रुपया हमको मिलेगा, पर आपको एक्चुअल मिला है 81 हजार 651 करोड़ रुपया, तो आपको 4,102 करोड़ रुपया कम मिला।

अब आपने अपना सीधा सामाजिक सेवाओं पर जो 2021-22 में खर्चा बताया है वह 99 हजार 244 करोड़ रुपया और अभी आर.ई. में आप आये हो, उसमें इस 99 हजार को ही बढ़ाकर आपने 1 लाख 3 हजार करोड़ रुपये का माना है। जबकि आपका अभी, मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, इन विद्वान लोगों से कह रहा हूं कि इस प्रकार के आंकड़े बनाकर राजस्थान की जनता को ठगने का धन्धा मत करो। यह जो दिसम्बर अभी गया है, यह जो 2021 का एंड हुआ है, उस समय तक आपकी आमदनी हुई है, वह जो आपने 99 हजार करोड़ सोचा था और 103 आर.ई. कर दिया, उसमें केवल आपके पास आया 52 हजार 588 करोड़ रुपया। जितना आपने सोचा उसका आधा भी नहीं आया तो यह क्या जादू होगा तीन महीने में और कहां से आने वाला है यह पैसा?

इसी तरह से आपने अबकी बार और छलांग लगायी और 2022-23 में यह जो सामाजिक सेवा पर आप खर्चा कर रहे हैं उसमें पुराना आपका जो लेटेस्ट आंकड़ा है वह 81 हजार करोड़ का है और आप सीधा बढ़कर 111, 1 लाख 11 हजार करोड़ रुपया हम सामाजिक सेवा पर खर्च करेंगे, यह कहां से करोगे? कहां से आयेगा? कोई गणित तो बतायेगा, कोई जोड़-बाकी तो कहेगा या नहीं कहेगा?

इसी तरह से आपने लिखा कि आर्थिक सेवाओं पर जो व्यय है, आर्थिक सेवा का मतलब जिस कृषि के बारे में आपने खूब थपथपाया, उसका तो आगे बोलूंगा लेकिन कृषि भी उसमें से एक है। उस कृषि का आपने पिछली बार 66 हजार 603 सोचा था और खर्च हुआ 60 हजार, 5,852 करोड़ रुपया कम खर्च हुआ 2019-20 में। फिर आपने 2020-21 में सोचा कि 58 हजार 900 करेंगे, 51 हजार ही कर पाये और 7,544 करोड़ रुपया आर्थिक सेवाओं में कम खर्च किया। आप बी.ई. में आये 64 हजार 644 पर, अभी आपने आर.ई. बढ़ाकर 80 हजार करोड़ रुपये कर दिया। जो है उसकी भी तो आपको प्राप्ति नहीं हो रही है। अभी मैंने जो आंकड़ा निकाला है उसमें 31 दिसम्बर के दिन तक आपकी आर्थिक सेवाओं पर जो खर्चा हुआ, वह 41 हजार 145 करोड़ रुपया खर्च हुआ है तो तीन महीने में आप 41 हजार से 80 हजार कर दोगे?

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

क्या जादू होने वाला है कि 41 हजार को 3 महीने जनवरी, फरवरी और मार्च में बराबर 40 हजार करोड़ रुपये और आर्थिक सेवाओं पर खर्च करके इस सबको उठा लोगे? अबकी बार 2022-23 में आपने बड़ा कमाल किया है। आपने जो आर.ई. मानी है वह आपने 91 हजार करोड़ रुपये की मानी है। अभी तो 41 हजार करोड़ पर अटके हुए हो इस दिसम्बर में और अब आप अगले साल की अप्रैल में कह रहे हो कि हम 91 हजार करोड़ रुपया आर्थिक सेवाओं पर खर्च करेंगे तो कहां से आयेगा? कोई बजट को समझा तो सके कि पैसा कहां से आयेगा, कहां जायेगा, तब तो कुछ समझने की कोशिश करें।

यह जो आपने कृषि-कृषि, जिसके लिए बहुत तालियां पिटवायीं, उसके लिए तो आगे और बोलूंगा पर कृषि की दृष्टि से यह जो आर्थिक सेवाओं की विभिन्न मदों में राजस्व व्यय है यह आपने 2019-20 में 9 हजार 744 करोड़ सोचा, उसकी जगह आपका 10 हजार करोड़ हुआ, अर्थात् आपने 571 करोड़ रुपया ज्यादा खर्च किया। इसी तरह से 2020-21 में आपने 11 हजार 182 सोचा 12 हजार 50 हुआ, इसमें भी आपका 864 रुपया ज्यादा हुआ। अब आप 2021-22 में बीई में आये हैं, उसमें 11 हजार 287 सोचा, अभी आरई में 12 हजार 965 कर दिया। अब इसको आप सीधा एक तरह से, जो आप आरई में आये थे। उसमें 12 हजार 965 आपने माना। अब आपका बजट है 12 हजार 761, इसका मतलब 200 करोड़ रुपया कम होने के बाद भी बजट किसानो को समर्पित है। 200 करोड़ रुपया कम खर्च करके भी बजट किसानों को समर्पित है। इस प्रकार की बात कहना मैं सोचता हूं, इन आंकड़ों से तो कम से कम आप प्रमाणित नहीं कर सकते हैं।

अब कृषि सम्बन्धी जो कार्य होते हैं, जिनमें पूंजीगत व्यय होकर के विकास के काम होते हैं। उसमें आपकी स्थिति क्या है 2019-20 में? आपने सोचा 341 करोड़ खर्च करेंगे, खर्च कर पाये केवल 206 करोड़, कहां कट लगता है, पूंजीगत से ही विकास की आधारशिला रखी जाती है। उसमें से आपका 135 करोड़ रुपया कम खर्च हुआ, रखा तो केवल 341 करोड़, उस 341 करोड़ में से भी 135 करोड़ रुपया कम खर्च हुआ, फिर भी विकास हो रहा है।

फिर, आपने 2020-21 में 259 करोड़ सोचा और इसमें आपका बढ़ा है, 145 करोड़ ज्यादा खर्च किया। 2021-22 में आपने 521 सोचा, अभी आप बता रहे हो 640 करोड़, इसमें भी आपका बढ़ा। आप इससे सीधे बीई में 833 करोड़ पर जा रहे हो। मतलब, ये जिस प्रकार से आंकड़े बनाये हैं किसी ने भी,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)
मैं सोचता हूं आपकी भावना का आदर करते हुए उसने कहीं न कहीं जोड़-बाकी बिठाने की कोशिश की होगी। बाकी, यह पैसा कहीं आ नहीं सकता, ऐसा मेरा विश्वास है।

अभी आपका कृषि बजट जो है, यह आपका सारा कृषि को समर्पित है, इसको आगे और बताऊंगा। इस कृषि बजट में आपने 35 घोषणाएं की थीं, कितनी 35 और अमाउण्ट कितना उन 35 घोषणाओं में, 43 हजार 701 करोड़ रुपया खर्च होगा। उधर मैंने बताया आपको, 200 करोड़ रुपया आप अपने बजट में ही मान रहे हो कि हमको पिछली आरई से इस बार हम जो आरई में आ रहे हैं, उसमें से बजट घट रहा है, किसी में पूंजीगत व्यय आपने 833 करोड़ रुपये का प्रावधान किया, कितना 833 करोड़ रुपया और उधर में आपका सारा मिलाकर के आर्थिक सेवाओं में और पूंजीगत व्यय मद में कुल बजट प्रावधान 19 हजार 218 करोड़ का है जिसमें ग्राम विकास, ये सब योजनाएं हैं। टोटल आर्थिक विकास में आपका बजट जो बता रहा है, वो खर्च होने वाला 19 हजार 218 करोड़ रुपया तो आप यह कृषि को, मैंने अभी आपको फिगर बताया इतने हजार करोड़ की जो आपने घोषणा की है। इन घोषणाओं की पूर्ति कहां से होगी? यह चमत्कार वास्तव में कोई न कोई जादूगरी दिखती है, बाकी तो बहुत असम्भव है।

जल जीवन मिशन को लेकर जो भी उठे, ठोके, जो भी उठे, ठोके। आपने 44-45 साल तक राज किया। क्या यह समस्या आपसे हल नहीं हो रही? आप नहीं सोच सकते थे कि राजस्थान में पानी लाने के लिए एक आदमी को लगाये रखना पड़ता था? ये बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य को नहीं मालूम था? इतने सालों तक दिल्ली में राज करने के बाद उस समस्या का निदान आप नहीं कर सके और देश का प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी आने के बाद जल जीवन मिशन सैकण्ड टाइम में, उसने कहा नहीं। मैं प्रत्येक घर को नल की टोंटी से पानी दूंगा, इसकी योजना बना रहा हूं और आपको पैसा दे रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको पैसा नहीं दे रहा है, पर आपकी जेब में कुछ है ही नहीं, उसमें मिलाकर खर्च करने के लिए इसलिए अटके हुए हो। दोष किसका है और जवाब किसको दे रहे हो। इस योजना को केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, क्योंकि पहले आप इसमें 90:10, 90:10 करते थे। अब उन्होंने कहा नहीं-नहीं बराबरी का हिस्सा है, अगर खर्च करना चाहो तो करो। अपनी जेब से भी कुछ गांठ का गोपीचन्द खोओगे तो सही जगह लगेगा, नहीं तो आओ और कहोगे, कोई पाइप खा रहा, कोई क्या खा रहा है। आपने और मैंने इस राजस्थान की विधान सभा में कई बार देखा है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वर्ष 2024 तक प्रदेश में 1 करोड़ 1 लाख कनेक्शन होने थे। 1 करोड़ 1 लाख 32 हजार 274 घरों को कनेक्शन देने की आपकी ये सारी योजना है। पहले साल इसमें आपने लक्ष्य क्या रखा था 2020-21 में, थोड़ा-सा आंकड़ों की माननीय मुख्य मंत्री जी मानिटरिंग करो। उसमें देखो कि डिपार्टमेन्ट क्या कर रहा है और ये अधिकारी क्या कर रहे हैं। 20 लाख 77 हजार कनेक्शन करने का आपने लक्ष्य रखा था 2020-21 में, लगे कितने? 7.84 लाख, मतलब 20 लाख का लक्ष्य रखा और उसमें से कनेक्शन हुए राजस्थान में 7 लाख 84 हजार। 2021-22 का और बताता हूं। आपने 2021-22 में लक्ष्य क्या रखा, 30 लाख परिवारों का। जा-जाकर भाटे सब जगह लगा आये, तुम्हारे गांव में नल कनेक्शन आ रहा है, नल कनेक्शन कहां से आ रहा है, पानी नहीं है तो नल कहां से आ रहा है? जिस योजना को सपोर्ट करने के लिए जो पैसा चाहिए और खर्च करना चाहिए वह अगर आप खर्च नहीं करोगे, 30 लाख परिवारों को दोगे जनवरी 2022 तक, मैंने ये अभी जनवरी, 2022 तक का निकाला। इसमें केवल और केवल 30 लाख में से 4 लाख 31 हजार कनेक्शन हुए हैं। डिपार्टमेन्ट के अधिकारी से पूछ लीजिए, फिगर गलत तो नहीं बता रहा कहीं, ताकि कम से कम मुझे मेरी सच्चाई का पता लगे। ये मैं आपको बता रहा हूं, जनवरी के एण्ड तक, जो कनेक्शन आपने किये हैं। आपने 30 लाख में से 4 लाख 31 हजार कनेक्शन लगाये हैं। ये तो आपकी जिन्दगी में नहीं लगने हैं, यदि इस तरह से चला तो।

अब आप वित्तीय सपोर्ट देखो। ऐसा नहीं है केन्द्र सरकार ने, आप बार-बार उठकर जो पत्थर फेंकते हो न, इसके कारण से माथे पर जब लगता है तो दर्द तो होता है कि देने के बाद भी इस प्रकार की भाषा बोलते हैं, कुछ तो कम से कम रहम करना चाहिए।

आपको 2019-20 में, 2020-21 में और 2021-22 में सब मिलाकर तीन सालों में केन्द्र सरकार ने जो पैसा अलाट किया है, वह 13 हजार 982 करोड़ रुपया है, कितना? 13 हजार 982 करोड़ रुपया आपको आबंटन किया कि इस जल जीवन मिशन को आप जल्दी से आगे बढ़ाओ। आप खर्च कितना कर पाये? आप खर्च कर पाये केवल 2 हजार 452 करोड़ रुपया। उन्होंने 13 हजार करोड़ रुपये का अलाटमेंट किया। आप केवल 2 हजार 452 करोड़ रुपया

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

खर्च कर पाये तीन साल में। आपकी प्राप्ति क्या रही है 18 प्रतिशत, कितनी प्राप्ति रही, 18 प्रतिशत। राज्य सरकार पर्याप्त बजट होने के बाद भी बार-बार 90:10, 90:10, केवल आप ही उनके नजदीक हो, बाकी हिन्दुस्तान की जनता उनके नजदीकी नहीं है? वे जिस कुर्सी पर बैठे हैं, उनको सबके साथ न्याय करना पड़ेगा। आपके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन निकालेंगे क्या? अगर देश के सब लोग स्वीकार करके योजना का लाभ ले रहे हैं, कई राज्यों ने इसमें बहुत अच्छी प्रगति की है, हमने प्रगति नहीं की।

अब आपका ये असंतुलन भी और देखो, आप मानिटरिंग करो, प्रभु। यह जो बाड़मेर मरुस्थल जिला है, यह जो 18 परसेंट आपकी उपलब्धि बता रहे हैं, यह राजस्थान की 18 परसेंट, इसमें भी बाड़मेर की क्या है, बाड़मेर की 10 प्रतिशत। जैसलमेर की उपलब्धि क्या है, 4.24 प्रतिशत। जो जिले तकलीफ में हैं, जिसके लिए इतने जोर से भाषण दिया, उस जिले की दशा देखकर के भी उनको थोड़ी चिन्ता करनी चाहिए कि हमारा तो कम से कम ठीक कर लें।

आपको ये जनजाति बहुल का बताता हूं। पैसा होते हुए भी प्रतापगढ़ में अभी तक इन तीन सालों में 8.6 प्रतिशत नल कनेक्शन हुए हैं डूंगरपूर में 10.8 हुए हैं बांसवाड़ा में 7.9 हुए हैं और उदयपुर में 14 प्रतिशत। यह तो पैसों का क्षेत्रीय संतुलन भी नहीं हो रहा है। आपको इस प्रकार से इस योजना में कुल 43 हजार 323 गांवों को लाभान्वित करना है और अभी तक 977 गांव केवल इससे लाभान्वित हुए हैं। यह प्रगति आपकी है।

मैं सोचता हूं कि इसको क्या कहें और आपने और हमने सबने एक नीतिगत फैसला किया था कि आंगनबाड़ी केन्द्र और स्कूल, ये कम से कम 100 प्रतिशत पानी की इस योजना से जुड़ जायें, लेकिन उसमें भी आपकी उपलब्धि नहीं आयी। आपने देखा होगा कि हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु जैसे में शत-प्रतिशत सभी संस्थाओं को नल के कनेक्शन से जोड़ दिया। राजस्थान की प्रगति अभी केवल और केवल 50 परसेंट है जबकि 100 प्रतिशत स्कूल और आंगनबाड़ी को जोड़ लेना था, उसे भी आप नहीं जोड़ पाये।

अब जिस पेंशन योजना के बारे में, मैं भी अगर पेंशन प्राप्त करता हूं तो आपकी बात की तारीफ करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि, पुरानी पेंशन योजना में मतलब जो कर्मचारी है, उसको देना कम पड़ता था, लेना ज्यादा होता था। इसलिए हर व्यक्ति उस पेंशन योजना को पसन्द करता है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इसमें किसी को कोई एतराज नहीं है। मैं सोचता हूं चाहे आप हो या मैं हूं लेकिन मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं। पहले क्या होता था कटौती में, कर्मचारी के जीपीएफ में जमा होता था जिस पर उसको निश्चित ब्याज देय होता था। जो भी जीपीएफ में जमा होता था उस पर ब्याज मिलता था। पूरे सेवा काल में की गई समस्त कटौती मय ब्याज कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर उसे वापस मिलती थी। अंतिम आहरित जो भी उसकी लास्ट पे-ग्रेड होती थी, उसके पचास परसेंट की उसको पेंशन मिलती थी और समय-समय पर उसमें और भी बढ़ोतरी होती थी। पुरानी पेंशन व्यवस्था के अन्तर्गत जीपीएफ खाते में जमा राशि का पूरे सेवा काल में अगर वह लेना चाहता था तो 75 प्रतिशत एडवांस भी वो अपनी शादी-ब्याह किसी भी समय परिवार के लिए ले सकता था। नयी पेंशन योजना में क्या है, जो भी कर्मचारी होगा उसको लगेगा, कर्मचारी द्वारा मूल वेतन महंगाई भत्ते का दस प्रतिशत स्वयं कटाता है और दस प्रतिशत राज्य सरकार उसमें मैचिंग ग्रान्ट मिलाती है और यह पीएफआरडीए अकाउंट में जाकर के जमा हो जाता है। पूरे सेवा काल में एकत्रित फंड स्वयं का प्लस राज्य का योगदान, इसका साठ प्रतिशत, उसको उसमें 75 प्रतिशत तक का पैसा निकालने का अधिकार था, इसमें केवल उसको साठ प्रतिशत पैसा निकालने का अधिकार है। शेष चालीस प्रतिशत फंड जो बचता है वह बीस सालों की क़िस्तों के रूप में उसको पेन्शन में मिलता है। नवीन पेंशन व्यवस्था के अन्तर्गत पेंशन फंड में से पूरे सेवा काल में तीन बार केवल पैसे निकाल सकता है उसकी लिमिट बांधी हुई है। चलो समझ में आता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं थोड़ा-सा अनजान आदमी हूं। यह जो मेरे पास आंकड़े हैं, जो आपने मुझे बजट एट ए ग्लांस और जो डाक्यूमेंट दिया है, आज की तारीख में जो पेंशन लागू है उस पेंशन योजना के आधार पर भी आपको कितना पैसा पेंशन का देना पड़ेगा कर्मचारी को, वह मैं बता रहा हूं। 2004 की पेंशन स्कीम बदल जाने के बाद भी जो पुराने लोग रिटायर हो रहे हैं, उनको कितनी पेंशन देनी पड़ेगी, तो 2023-24 में आपको 33 हजार करोड़ देनी पड़ेगी। इसी तरह से बढ़ते-बढ़ते जो आपका 2032-33 आयेगा तो 2032-33 में भी पुराने लोगों को, नयों को नहीं, पुराने लोगों को 40,201 करोड़ रुपये आपको पेंशन देनी होगी।

अब आप नयी पेंशन पर आ जायें, जो आपने पुरानी पेंशन को रिवाइज की। प्रदेश सरकार यदि कर्मचारी की पुरानी पेंशन योजना बहाल करती है तो उसे हर महीने में जो मैंने केलकुलेशन किया, हो सकता है मेरे आंकड़े

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कुछ कम-ज्यादा हों तो आप उसे ठीक कर लेना, हर माह करीब 344 करोड़ रुपये की बचत होगी। इनको क्या होगा, अप्रैल से ही क्योंकि इन्होंने पुरानी पेंशन योजना को रिवाइज कर दिया, इसका मतलब इस समय जो परसेंटेज दस कट रहा था और दस आप मिला रहे थे उसके कारण से आपकी 344 करोड़ रुपये प्रति महीना इसमें बचत होगी। अगर यह बारह महीने और बारह साल तक क्योंकि रिटायरमेंट तो 2032 के बाद आयेगा, पहले तो आ नहीं सकता, उस समय तक आप इस खाते में उन 49,536 करोड़ रुपये बचाकर के रखोगे। समझने का प्रयास करना। यह अगर आपने लागू कर दी तो हर महीने अब ये जो अप्रैल, 2022 आ रहा है यहां से लेकर के जब तक वो रिटायर होगा 12 साल बाद मानूं मैं 2032 में तब तक राज्य सरकार को 49,536 करोड़ रुपये की बचत होगी और 2035 तक राज्य सरकार के कोष में जायेगी। 01 अप्रैल, 2004 से जिन लोगों को आपने नयी पेन्शन से जोड़ा है उन कर्मचारियों का अब तक अगर 2 हजार करोड़ रुपये भी मानें तो लगभग चालीस हजार करोड़ रुपये आज की तारीख में 2004 से लेकर 2021 तक 17 साल का पैसा सरकारी खजाने में जमा है। अब मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आप दो घोषणा कर दो। एक तो आप यह कह दो कि 1 अप्रैल, 2022 के बाद अब कर्मचारी का दस प्रतिशत पैसा नहीं कटेगा, जैसे पुरानी स्कीम में कटता था उसी हिसाब से कटेगा ताकि एक मुक्ति मिल जाये। यह आप कह देना, बोलो तब और एक यह कह देना कि यह जो 17 साल के पैसे हैं उसके और सरकार के दोनों के कटे हुए तो कम से कम उसका जो पैसा है उसको जीपीएफ का मानते हुए उसके खाते में ट्रांसफर कर दो ताकि उस कर्मचारी को पुरानी पेंशन का लाभ पूरा का पूरा मिल जाए। कर देना घोषणा और उसके बाद मैं सोचता हूं कि इस योजना को लागू करो। न तो 2032 में आप रहोगे न मैं रहूंगा, रोने वाला रोयेगा। कोई हिसाब तो लगाया नहीं कि पैसा कितना देना पड़ेगा। कृपा करके आप इन विद्वान साथियों से इतना कह दो कि जिस दिन 2032 में रिटायरमेंट इन लोगों का पुरानी पेंशन से होगा तो जो आपने 40 हजार करोड़ रुपये सोचा था वह इसको मिला करके कितने हजार करोड़ रुपये राजस्थान की जनता अपने टैक्स से देगी, इसके बारे में भी स्पष्ट होना चाहिए कि वास्तव में हम क्या कर रहे हैं। अब आपने भर्तियों के बारे में बहुत ही ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलें। बीच में नहीं बोलें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं सोचता हूं कि भर्तियों के

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बारे में हर बच्चा बहुत आशान्वित रहता है। जिन्दगी में यही सबसे बड़ा उसका जीवन का खुशहाली का समय होता है लेकिन ...

श्री अध्यक्ष: कटारिया साहब, 15 मिनट बचे हैं। 5 बजे मुख्य मंत्री जी बोलेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): कोशिश करूंगा।

मैं सोचता हूं कि आपने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि पांच लाख लोगों को नौकरी मिलेगी फिर उसके बाद आपने 2019-20 में कहा 74,500 को मिलेगी, फिर आपने 2020-21 में कहा 53 हजार को मिलेगी, फिर उसके बाद 2021-22 में कहा कि 52 हजार लोगों को मिलेगी और इस साल आपने घोषणा की है कि एक लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। चलो एक लाख को अलग रखते हैं अभी। अभी तो जो 1.80 लाख है, उस 1.80 लाख में ईमानदारी से आपके यहां जो भी बैठे हों, उनको कहना, मुझे इस 1.80 लाख में से जो आपने बिलकुल केटेगरीवाइज किसमें कितने पद भरेंगे, उसमें से कितने भरे हैं वह रिप्लाई में दे देना, मेरा मन संतुष्ट हो जाएगा। आपने 1.80 लाख, जिसकी आपने बजट में घोषणा की उसमें से कितने लोगों को नौकरी पर चढ़ा दिया, तब तो आपकी बात समझ में आयेगी। दुर्भाग्य है उस बच्चे का कि हमारे यहां जो स्थिति अब राजस्थान में बनी है न इन नकलचियों के गिरोह से, उससे सारे बच्चों के भविष्य पर अंधकार छा गया और वह गरीब बच्चा, जो बड़ी मुश्किल से अपने मां-बाप का खेत गिरवी रखकर पढ़ता है उस बच्चे को अंधकार में डाला है। कभी पेपर लीक हो जाते हैं उससे आउट हो जाता है, कभी आपकी परीक्षा कोर्ट में जाकर चिपक जाती है इसलिये रुक जाता है, कभी और किसी न किसी संकट में आ जाते हो और यह भर्तियां हो नहीं पाती हैं। कृपा करके आप इस पर मेहरबानी करो उस बच्चे के लिए जो नौकरी आप निकालते हो उसकी इतनी परफेक्ट व्यवस्था करो कि कम से कम ये नकलची और चोर गिरोह बाहर हो ताकि उस बच्चे को किसी प्रकार से आप बचा सको, इतनी तो कृपा करो कम से कम।

अब आपकी मुख्यमंत्री सम्बल योजना, आपने कहा था कि हर बच्चे को या तो नौकरी मिलेगी या भत्ता मिलेगा। बच्चों ने वोट दिया। वो तीन नारे आपके हैं न, आपको कोई बहुत ज्यादा राजस्थान में नहीं, पचास हजार वोट ही ज्यादा मिला है, ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है। आपके और हमारे बीच में वोटरों का अन्तर केवल पचास हजार का है और 52 हजार पोलिंग स्टेशन

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लेकिन इसके कारण से जो भी हुआ, कोई बात नहीं आपने जैसा बनाया, सरकार बनाने का जो तौर-तरीका अपनाया, मैं सोचता हूं कि आपने कहा था कि हम इनको इतना पैसा देंगे, फिर आपने कैप लगा दी कि कितने बच्चों को देंगे, एक लाख साठ हजार को ही देंगे। कैप लगाने की जरूरत क्या है, जबकि एम्प्लायमेंट में 16 लाख बच्चे तो रजिस्टर्ड हैं। राजस्थान बेरोजगारी की दृष्टि से आज ही आया है, पहले तो हम दूसरे स्थान पर मानते थे हरियाणा के बाद लेकिन आज राजस्थान बेरोजगारी की दृष्टि से हिन्दुस्तान का पहला राज्य बनने का दुर्भाग्य बना है।

(समय: 16.48 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

मैं सोचता हूं कि यह जो एक लाख साठ हजार है, आपने इस बार इस कैप को थोड़ा बढ़ाया है और कैप को आपने दो लाख कर दिया। अब 80-85 हजार को तो वसुन्धरा जी के टाइम पर बेरोजगारी भत्ता मिलता था, फिर भी आपने उसको किया, पर उसके साथ शर्तें क्या जोड़ दीं, उन शर्तों को जोड़कर उन बच्चों को दूर हटाना आपका मकसद हो तो मैं नहीं कह सकता हूं। आपने किया कि तीन माह का कौशल प्रशिक्षण लेना पड़ेगा एक तो, फिर क्या है कि आपको किसी न किसी दफ्तर में जाकर नौकरी करनी पड़ेगी। अब वह चार हजार की नौकरी करने जायेगा और स्कूटर में पेट्रोल डालेगा तो वह ज्यादा जल जायेगा। कौन मूर्ख होगा जो गांठ का पेट्रोल डालकर के वहां नौकरी करने जायेगा। क्यों झुनझुना बजाते हो? इस तरह से बच्चों को क्यों गुमराह करने का प्रयास करते हो?

मैं सोचता हूं जन घोषणा पत्र को आप छोड़ें जो कुछ भी आप और कोई लोग बोलेंगे, अब यह जो नरेगा, नरेगा, नरेगा मैं समझ नहीं पाया। आपने क्या कहा कि हम अब शहरों में शुरू करेंगे और शब्द इतना चतुराई से लिखा है मैं समझ नहीं पाया हूं। मैं शब्दों को समझना चाहता हूं आपसे भी कि आपने कहा था कि इस योजना के माध्यम से आगामी वर्ष में, अब आप यहां 2022-23 लिख देते न आगामी वर्ष और कौन सा है। यह बजट ही 2022-23 का है तो आगामी वर्ष क्या है, क्या 2023-24 वाला है, स्पष्ट कर देना। आगामी वर्ष है या इसी वर्ष से आप लागू करोगे, यह चक्कर देने का काम मत करो। आगामी वर्ष बहुत चतुराई से शब्द निकाला है। बहुत चतुराई से शब्द निकाला है, बहुत धन्यवाद आपके बजट बनाने वाले को कि आपको क्या खुश करने का प्रयास किया है। उसमें आगे लिखा है ग्रामीण क्षेत्र में 125 दिन का

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मिलेगा, उसमें भी यही लिखा है 100 दिवस के रोजगार को राज्य सरकार के खर्चे पर बढ़ाते हुए 125 दिन की घोषणा करता हूं और इसमें भी लिखा आगामी वर्ष। अब यह आगामी वर्ष कौनसा है? न आप रहोगे, न मैं रहूंगा, आगामी वर्ष है। यहां लिख दो, मेरी गलती हुई हो तो आप बोल जाना 2022-23, मुझे कोई एतराज नहीं।

श्री सभापति: कृपया शांत रहें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): महात्मा गांधी नरेगा योजना, जिसके नाम से आप मारे जा रहे हो कि यह कर दिया, वह कर दिया। आपकी स्थिति मैं थोड़ा सा बताता हूं। इसका सारा पैसा केन्द्र सरकार से मिलता है। अकुशल श्रमिकों की मजदूरी भुगतान की सम्पूर्ण राशि केन्द्र सरकार देती है। अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों की मजदूरी तथा सामग्री पर व्यय राशि का 75 परसेंट पैसा केन्द्र देता है। मिठाइयां कोई बनाये, परोसो आप। मैं लाया हूं, मैं लाया हूं। कम से कम सच्चाई तो बताओ कि हो क्या रहा है। आप क्या खर्चा करते हो, वह भी बताता हूं। अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों की मजदूरी भुगतान व सामग्री व्यय पर 25 परसेंट राज्य करता है। रोजगार की मांग करने पर, अगर आप समय पर रोजगार नहीं दे सको तो जो फाइन लगता है, वह आपको देना पड़ता है। राजस्थान रोजगार परिषद् के मैं आंकड़े देख रहा था। हमारे यहां 2020-21 में 1 करोड़ 12 लाख लोगों के कार्ड बने थे। उसमें से 75 लाख का कार्य नियोजन हुआ। 2021-22 में 1 करोड़ 20 लाख बने, उसमें से केवल और केवल अभी तक 63 लाख को रोजगार से जोड़ सके।

आगे चलें, प्रति परिवार उपलब्ध कराये गये औसत रोजगार दिवस। माल फोकट का फिर भी कितनी सफलता है, वह देखो। आपको 2020-21 में औसत 61 दिवस मिला और 2021-22 में केवल और केवल 42 दिन का रोजगार मिला है। आपको 100 दिन का तो दे रखा है, उसको पूरा नहीं कर रहे हो और बजाओ ताली 125, कमाल ही करते हो। 100 दिन का कार्य कितने लोगों को मिला है? जो आपकी सीमा में है, जो आप कर सकते हो, 100 दिवस में आपने 2020-21 में केवल और केवल 1 लाख 23 हजार लोगों को काम दिया है। मतलब एक तरह से आपके पास 1 करोड़ 12 लाख के तो कार्ड बने हुए हैं और आप 1 लाख 12 हजार लोगों को रोजगार दे पाये। अबकी बार केवल 2 लाख 57 हजार लोगों को 100 दिन का रोजगार दे पाये। जो आपकी लिमिट है, उसको तो कृपा करके कम से कम पूरी करो।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(समय: 16.52 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

इसमें भौतिक प्रगति देखकर आपको आश्चर्य लगेगा। मैं सोचता हूं कि भौतिक प्रगति में प्रति परिवार रोजगार का औसत 2018-19 में 57 दिन का था। 2019-20 में 53 दिन का, 2020-21 में 61 दिन और 2021-22 में केवल 47 दिन का औसत रोजगार आया है। कुल परिवार काम में लगे हैं जो लाखों में हैं, वे केवल 51 हजार, 55 हजार, 75 हजार और 63 हजार हैं।

मुख्य मंत्री जी, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, उच्च शिक्षा में आपके कालेजों के कारण से ग्रामीण बच्चे को अपनी जिंदगी बनाने के लिये एक अच्छा अवसर मिला है। आज कम से कम ग्रामीण बच्चियां भी इन कालेजों में आकर अपने आपको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन इनकी हालत पर शायद कोई मानिटरिंग नहीं करता है। या तो हम खोलते हैं तब बजट को तो ध्यान में रखते नहीं, केवल झुनझुना पकड़ा देते हैं। उसका कोई सपोर्टिंग पैसा नहीं है और इसलिए आपने 123 नये महाविद्यालय खोले हैं। 17 महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर किया। अधिकांश महाविद्यालयों में भवन की स्वीकृति नहीं हुई। 13 महाविद्यालयों के लिये अभी तक जमीन ही तय नहीं हो पा रही है। 40 ऐसे महाविद्यालय हैं जिनके भवन निर्माण के लिये बजट का आबंटन ही नहीं किया। 2019 से लेकर अब तक जिन महाविद्यालयों में बजट आबंटन किया, उनमें एक भी बिल्डिंग कम्पलीट होकर बच्चों को उपलब्ध नहीं कराई है, आप सोच सकते हो क्या है। रिक्त पदों की स्थिति देखकर तो ऐसा लगता है कि हम बच्चे का भविष्य बनाना चाहते हैं या बच्चे के भविष्य से खेलना चाहते हैं। मैं सोचता हूं कि मैं 20 किलोमीटर दूर जाकर कालेज में पढ़ लूंगा, अगर स्टाफ मिलेगा तो मेरी परसेंटेज ठीक बनेगी, अगर वहां स्टाफ नहीं होगा तो मेरी परसेंटेज नहीं बनेगी। मैं आपको केवल दो फिगर दे रहा हूं, वैसे तो मेरे पास सारे ही हैं। प्राचार्य के 292 में से 208 खाली हैं। सहायक प्राचार्य में 6,962 में से 2,792 खाली हैं, मतलब 40 परसेंट। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पुस्तकालय की कुल 274 पोस्टें स्वीकृत हैं, उसमें से 247 खाली हैं। क्या कालेज चल रहा है, क्या वहां की लाइब्रेरी चल रही है, कौन देख रहा है? पिओन देख रहा होगा। 539 प्रयोगशाला सहायक हैं, उनमें से 455 खाली हैं, इसका मतलब 85 परसेंट आपकी पोस्टें खाली हैं।

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी, please windup within four minutes. We have already decided it.

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): विश्वविद्यालय की भी ऐसी स्थिति है। मेडिकल कालेज के बारे में थपथपाया, हमने 23 मेडिकल कालेज खोले, गांठ के गोपीचन्द 45 साल तक क्या किया? 45 साल तक सरकार चलाई है तब 60 मेडिकल कालेज राजस्थान को मिले। अब प्रधान मंत्री मेडिकल कालेज देते हैं तो ईमानदारी से उसके बारे में भी तो दो शब्द बोल दो। अगर वह यह योजना बनाकर हर जिले को मेडिकल कालेज नहीं देते तो क्या राजस्थान में यह सब मेडिकल कालेज मिल जाते? मैं सोचता हूं कि इसके बारे में भी कम से कम कुछ सच्चाई बतानी चाहिये।

मुख्य मंत्री जी, एक बात मैं आपको बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, इस रीट परीक्षा में जिस प्रकार का घालमेल हुआ है, अगर आपके मन में कहीं गांधी जिन्दा है तो मेरी हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है। इस स्कैंडल के आधार पर उस व्यक्ति तक पहुंचो, जिस व्यक्ति ने इस प्रकार का केवल और केवल शिक्षा संकुल की जिम्मेदारी, बाकी सब जगह पर प्रशासन ने किया, पुलिस ने किया। यहीं क्या विशेषता थी कि जिसके कारण यह जिम्मेदारी इन प्राइवेट लोगों को मिली? उनमें से कुछ गिरफ्तार भी हुए हैं, कुछ अभी भी भागे हुए हैं। यह मीणा तो प्राइवेट कालेज चलाता है, उसका कालेज सेंटर है और वहां से डबल लाक की चाबी से काटकर पेपर निकालकर ले जाता है। इसका मतलब उसको लगाने वाला भी दोषी है या नहीं है? क्यों लगाया? केवल वो ही दोषी नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा, जब तक आप इस दोषी को नहीं पकड़ोगे तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा।

बिजली कंपनियां, बिजली कंपनियां। हमने 2000 में बिजली कंपनियां इसलिए बनाईं कि व्यवस्था सुधरेगी, लेकिन बिजली कंपनियां निरन्तर घाटे में चल रही हैं। हमने 2015-16 में...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्यसूची पूर्ण होने तक बढ़ा दिया जाय।

(स्वीकृत)

श्री अध्यक्ष: सदन का समय बढ़ाया जाता है।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2022-23 पर सामान्य वाद-विवाद

माननीय कटारिया साहब, 5 मिनट।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मेरा जहां रह जायेगा, मैं वहां एंड कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष: पांच बजे तक, दो मिनट बाकी हैं, आप बोलिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): कोई दिक्कत नहीं है। मैं आगे आ जाता हूं, छोड़ो।

डीजल-पेट्रोल, डीजल-पेट्रोल, वैट की तरफ भी देखो, आपने कितना वेट बढ़ाया? 06.07.2019 को पेट्रोल पर 04 परसेंट वैट बढ़ाया, 22.03.2020 को 04 परसेंट बढ़ाया, फिर 16.04.2020 को 02 परसेंट बढ़ाया, फिर 08.05.2020 को 02 परसेंट बढ़ाया और अभी आपने माइनस किया 02 परसेंट, मतलब हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा। एक्साइज है, लेकिन वह सारे प्रदेश के लिये है, केवल अपने अकेले के लिये नहीं है। जिस प्रकार से वैट पेट्रोल और डीजल में बढ़ा रहे हो, बाकी राज्यों में क्या है? दिल्ली जो हमारे पड़ोस में है, वहां पेट्रोल पर है 19 परसेंट और डीजल पर 16 परसेंट है, गुजरात में 13 परसेंट और 14 परसेंट, हरियाणा में 18 परसेंट, 16 परसेंट, मध्यप्रदेश में 29 परसेंट, 19 परसेंट और उसके बाद उत्तर प्रदेश में 19 परसेंट और 17 परसेंट। यह जो पड़ोस के राज्य हैं, मेरे गुजरात में 09 से लेकर 11 रुपया कम लगता है तो मेरे उस एरिये के पेट्रोल पम्प चलेंगे क्या? उनकी सेल होगी? सेल नहीं होगी तो घूम कर थोड़ा बहुत नुकसान तो हमारी रेवेन्यू में आयेगा या नहीं आयेगा? मैं सोचता हूं कि ज्यादा मत करो लेकिन कम से कम उस एरिये के बराबर और बाकी राज्यों के बराबर करने का प्रयास करो तो यह चोरी रुकेगी।

अब आपने क्या कमाल किया है, हमारे सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य कल कह रहे थे कि सरकार तो नहीं गिरी। हां, सरकार तो नहीं गिरी लेकिन आपने नियम और संविधान को कोने में घुसेड़ा न। 200 विधायकों में से 30 आप बना सकते हो। आपने उनमें से 20 विधायक और उनके परिवारजनों को, 60 लोगों को एडजस्ट किया। तीन निर्दलीयों को आपने झुनझुना पकड़ाया। 14 को यह झुनझुना पकड़ाकर आप सरकार जरूर टिका दोगे लेकिन राजस्थान की जनता की टांट टूट जायेगी।

(समय: 17.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, एक मिनट में समाप्त करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप दो मिनट दें। मैं अन्तिम बात कहकर अपनी बात खतम करता हूं। मैं आपसे दो चीजों के बारे में विशेष कहना चाहता हूं। जैसा मैं समझ पाया या मेरे से समझने में गलती हुई हो तो माफ करना, आपने कहा कि राज्य का कर भार सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में कितना है। मैं सोचता हूं कि यह निरन्तर बढ़ रहा है और 2021-22 में 39 प्रतिशत हुआ और इस बार 40 प्रतिशत से भी अधिक होने की उम्मीद है।

एक और विषय पर कहकर मैं अपनी बात खतम करता हूं। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी बात पर ध्यान देना। मैं जो कुछ कह रहा हूं कि इस बजट का सबसे बड़ा कहीं कंटेंट है तो वह इस जगह पर है। कृपा करके इन विद्वान लोगों को पूछना कि 'Budget at a Glance' का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि पृष्ठ संख्या 5 पर रुपया आता है, का विवरण दर्शाया गया है। इसके आन्तरिक और केन्द्रीय ऋणों का पुनर्भुगतान के लिए 21 परसेंट, यह कभी भी आज दिन तक नहीं हुआ। सारे पुराने बजट के आंकड़े मेरे पास हैं। इसमें अगर कभी बढ़ोतरी भी हुई है तो वह केवल और केवल 7 या 8 परसेंट होती है। यह पहली बार है कि आपने इन आन्तरिक और केन्द्रीय ऋणों से 21 परसेंट लेकर आप इस बजट को सपोर्ट कर रहे हैं, यह बात बिलकुल भी जंचने लायक नहीं है। इसी तरह से आपने आन्तरिक उधार, शुद्ध सार्वजनिक लेखा, यह ऋण वाला जो कोष्ठक है, आप अधिक से अधिक 26 से लेकर 28 परसेंट तक ले सके, पर आपका यह रुपये आते हैं 37.92 परसेंट, यानी कि आप 38 परसेंट पैसा उधार लेकर इस बजट को सपोर्ट करें, यह न आज होगा और न ही कल होगा। यह राजस्थान की जनता के साथ छलावा होगा और उस छलावे का परिणाम राजस्थान और आप दोनों भुगतेंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय मुख्य मंत्री जी।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बजट की डिबेट पर नेता प्रतिपक्ष सहित हमारे कुल 95 साथियों ने भाग लिया है और मुझे खुशी है कि अच्छी डिबेट हुई और सबने अपनी बात कही। यह कायदा भी होता है कि जब हम बजट पेश करते हैं तो माननीय सदस्य अपनी बात रखते हैं। मैं पक्ष और विपक्ष के सभी साथियों को विश्वास दिलाऊंगा कि आपके जो भी सुझाव आये हैं, उस पर हम लोग पूरी तरह से प्रोसेस करवा रहे हैं। क्या-क्या सुझाव हैं, इसमें क्या-क्या हल हो सकते हैं, उन्हें हल करेंगे। मैं समझता हूं कि जो

(श्री अशोक गहलोत)

बजट पेश किया गया, उसके ऊपर राजस्थान और राजस्थान के बाहर भी चर्चा हो रही है। आप दुनिया के अन्दर तो छोड़िये, चर्चा राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश के अन्दर हो रही है।

मैं माननीय कटारिया साहब को कहना चाहूंगा कि अध्यक्ष महोदय ने आपको हिंट दिया था कि 45 मिनट हो चुके हैं, तब तक आप खाली आंकड़े पढ़ते जा रहे थे। आंकड़े तो कोई भी खड़ा होकर पढ़ सकता है। पिछली बार भी आपने ऐसा ही किया था। हमारे ऊपर खूब कटाक्ष किया, ताली ताली बजाते कि होता कुछ नहीं। होता कुछ नहीं तो फिर राजस्थान में 85 परसेंट बजट लागू कैसे हो गया? क्या आपके पास जवाब है? जो हमारा मैनिफेस्टो था, उसको हमने 70 परसेंट पूरा कर दिया। आपको जानकर खुशी होगी कि अभी 500 घोषणाएं हुई होंगी, उनमें से जो 60 घोषणाएं इम्पोर्टेंट हैं, उनमें स्वीकृतियां जारी करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

यह मेरा नौवां बजट है। हर बजट में अपन आमने-सामने बैठते हैं। आप आंकड़ों का खेल खेलते हैं। जो पांच साल पहले हुए वे आंकड़े भी ले आते हो। यह डिबेट है, जो बजट पेश किया गया है, उसमें क्या कमियां हैं, क्या खामियां और आप क्या सुझाव देना चाहते हैं, इस पर बात करने की बजाय आप प्रदेशवासियों को गुमराह, मैं नहीं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं, यह मैं आपको कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष महोदय पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी हैं। आपने उनको बनाया है, इसलिए आंकड़े तो स्वाभाविक ही जुबान पर या किताबों में होते हैं, उसी पर पूरा खेल होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष और माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि जब इनको मालूम है कि देश के अन्दर कोई राज्य सरकार बिना केन्द्र सरकार की अनुमति के एक रुपया भी लोन नहीं ले सकती। कान्स्टीट्यूशन के अन्तर्गत जो एफआरबीएम एक्ट बनाया गया है, वह आपके ही शासन में 2005 में यहां एडाप्ट किया गया। उसके अन्तर्गत भारत सरकार की परमिशन से ही कोई राज्य सरकार कर्जा ले सकती है, जो कि आपको मालूम है। भारत सरकार के भी पैमाने हैं। आप बार-बार बोल रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू सरप्लस, किसी राज्य के जो तमाम आंकड़े हैं, जीडीपी ग्रोथ कितनी हुई है? टैक्स का और नॉन टैक्स का कलेक्शन कितना हो रहा है, उसके आधार पर यदि एफआरबीएम एक्ट के अन्तर्गत यदि भारत सरकार परमिट करती है

(श्री अशोक गहलोत)

तो आप लोन ले सकते हैं। इसके ये मायने भी हुए कि परमिट ही वे करते हैं तो सब पैरामीटर देखकर करते हैं। इसका मतलब मैंने जो बजट पेश किया वह पैरामीटर के आधार पर ही किया, उसके आधार पर ही 5 परसेंट, पहले 3 परसेंट था, कुछ शर्तों के साथ कोरोना काल में उन्होंने राज्यों को 5 परसेंट तक की छूट दी। मुझे खुशी है कि हमने वे शर्तें पूरी कीं, हमने लगभग 5 परसेंट कर्ज उठाया।

अध्यक्ष महोदय, इसमें आंकड़ों में जाने की जरूरत क्या है? काम की बात करो, काम की बात नहीं होती है। एक साल, दो साल, पांच साल के आंकड़े, उनका क्या मतलब है? वे तो आंकड़े हैं, गलत हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब आपकी सरकार थी तब भी वही अधिकारी थे और अब भी वही अधिकारी बनाते हैं, तो जरूरत क्या है कि हम उन पर बहस की बातें कर रहे हैं। हम क्या-क्या कमियां हैं, उस पर खुलकर बहस करें या करते और अब भी करने का मौका आयेगा। हमें सुझाव दीजिये, हमें आपकी तरफ से आश्वासन दीजिये कि राजस्थान की जितनी भी समस्याएं हैं, जो केन्द्र से ताल्लुक रखती हैं, चाहे वह ईआरसीपी की योजना हो, कई बार हम कहते हैं कि प्रधान मंत्री वादा नहीं निभा रहे, वह बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, आपकी सरकार ने बनायी है, हम तो उसे आगे ले जाना चाहते हैं, मगर मदद नहीं मिल पा रही है।

जेजेएम की बात की, पहाड़ी इलाकों में और नोर्थ ईस्ट के एरिये में 90:10 परसेंट मिलता है। हमारे यहां पर आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। कागज तो आपने सबसे बंटवा दिये, 45 साल में क्या किया। आपने मोदी जी से प्रेरणा ले रखी है, वे 70 साल की बात करते हैं, आप 45 साल की बात करते हो। आज यहां जो कुछ बैठे हैं, जिस रूप में बैठे हैं। आजादी के बाद यहां पर क्या था? राजस्थान में 13 मेगावाट बिजली बनती थी और वह भी जनरेटर से। केवल राजा-महाराजाओं के महलों में टिमटिमाती थी। आज राजस्थान और देश के अन्दर क्या नहीं है? साइंस में, टेक्नोलॉजी में, कृषि में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में, आप बताइये कि क्या नहीं हुआ है। फिर भी सुनना पड़ता है कि 45 साल में क्या किया। यह जुमला हम कम जानते हैं।

मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि सदन में जो घोषणाएं रह गयी हैं जो फीडबैक मिला, उसके आधार पर मैं बाद में बोलूंगा। अभी तो मैं सदन को इस पर विश्वास दिलाऊंगा, पक्ष-विपक्ष के तमाम साथियों को, प्रदेशवासियों को

(श्री अशोक गहलोत)

कि आप निश्चिंत रहें। बजट पेश किया है, आप तो करीब 15-20 बार बोल गये कि कैसे लागू होगा, पैसा कहां से आयेगा। मैं आपका आभारी हूं कि जो चिन्ता मुझे और मेरे साथियों को करनी चाहिये थी, वह चिन्ता आप कर रहे थे। पैसा कहां से आयेगा, यह लागू कैसे होगा, लागू हो ही नहीं सकता, असम्भव है, यह चिन्ता तो हमें करनी चाहिये। हम सरकार में हैं, हमने बजट पेश किया है। वह चिन्ता भी आप कर रहे हैं। इसलिए मैं जरूरी समझता हूं और आपको भी, तमाम सदन के साथियों को भी और प्रदेशवासियों को भी मैं कहता हूं कि निश्चिंत रहें, बजट सोच-समझकर बनाया गया है, मेहनत की गयी है। 45 हजार सुझाव आए हैं हमारे पास, 45 हजार सुझाव आए हैं। हमने पब्लिक से भी सुझाव मांगे थे। अलग-अलग वर्गों से भी हमने बातचीत की है, एन.जी.ओ. से की, व्यापारियों से की, उद्‌यमियों से की, एक्टिविस्ट से की, धर्मगुरुओं से की। जिससे भी सुझाव आए, छात्रों से, नौजवानों से, बेरोजगारों से, कर्मचारी संगठनों से तब जाकर ये अमृत के रूप में निकला है बजट। अमृत के रूप में निकला है। मंथन हुआ है, समुद्र मंथन की तरह मंथन हुआ है तब जाकर यह बजट पेश हुआ है इस हाउस के अन्दर, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मैं कहना चाहता हूं।

ये हमारे बजट आपकी ऐसी दुर्गति कर देते हैं कि हमारा बजट आता है, आप बोल नहीं पाते हो और पीछे से छिपकर बाहर जाते हो अपने घरों में, ये स्थिति बनती है आपकी। इस बार हिम्मत दिखाई आप लोगों ने। माननीय सदस्य जो आमेर से आते हैं, काली वधू को ब्यूटी पार्लर ले गये और दिखा दिया, यह बजट पर कटाक्ष है। यह बजट पर टिप्पणी थी आपकी क्योंकि कहने के लिए आपके पास कुछ बचा ही नहीं था तो हमारे माननीय सदस्य क्या करते? कुछ तो कटाक्ष करते। परंतु मुझे खुशी है कि उन्होंने अपनी गलती को माना और माफी मांगी प्रदेशवासियों से। अच्छी बात है। अच्छी बात भी है कि आपने कम से कम माफी मांगी। हमारे नौजवान साथी हैं, कम से कम कुछ कहने को मिला, नहीं तो कुछ तो कहना ही था क्योंकि अध्यक्ष भी हैं पार्टी के।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बार-बार मैं देखता हूं कि माननीय नेता, प्रतिपक्ष हमेशा कहते हैं कि केन्द्र सरकार देती है, हम उसका जिक्र नहीं करते। जिक्र तो मैं क्या करूंगा, जिक्र तो स्वत: ही होगा। जब पैसा आता है या आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो शिकायत हमारी बनी रहेगी और

(श्री अशोक गहलोत)

कांस्टीट्यूशन में लिखा हुआ है फाइनेंस कमीशन बनेंगे। फाइनेंस कमीशन तय करेगा कितना हिस्सा राज्यों को मिले। माननीय अध्यक्ष महोदय, फाइनेंस कमीशन जो 14वां था उसे डिवीजिबल पूल बना दिया कि ये पैसा इस प्रकार से राज्यों में जाएगा। पेट्रोल-डीजल हो, चाहे वह टैक्स-रेवेन्यू हो, जितनी रेवेन्यू हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है इस बात का कि वह पैसा आ नहीं रहा है। वह पैसा नहीं आ रहा है और 41 परसेंट देना था हमें उसकी बजाय 30 परसेंट के आसपास पैसा मुश्किल से मिल रहा है। इसीलिए इस बार भी हमें पैसा कम मिलेगा। जो पैसा हमें मिलना चाहिए था, 27 लाख 57 हजार 820 करोड़ की रेवेन्यू रिसीट थी टैक्स की और 41 परसेंट होता है 11 लाख 30 हजार 706 करोड़, राज्यों के लिए और राजस्थान का हिस्सा होता है 6.026 परसेंट मतलब 68 हजार 136 करोड़, ये हमें मिलना ही था। इसमें कोई अहसान वाली बात नहीं है। चाहे सरकार यू.पी.ए. की हो, चाहे एन.डी.ए. की हो, कोई भी पार्टी की हो, ये तो देना ही पड़ेगा क्योंकि ये फाइनेंस कमीशन की रिकमंडेशंस हैं। हमारा हिस्सा 68 हजार 136 करोड़ में से कितना रखा है इन्होंने अभी बजट में? 49 हजार 211 करोड़ रखा। मतलब 19 हजार करोड़ रुपये हमें कम दे रहे हैं। बताइए, क्यों दे रहे हैं कम हमें? जी.एस.टी. टाइम पर देते नहीं हैं। पिछली बार भी 15 हजार करोड़ कम कर दिया हमारा। 15 हजार करोड़ कम कर दिया। इस प्रकार से जो हालात हैं, बाकी तो कई शिकायतें हमारी और भी हो सकती हैं परंतु जो हालात हैं उसमें जो 32 परसेंट था पहले, फाइनेंस कमीशन, 14वें फाइनेंस कमीशन ने उसको कर दिया 41 परसेंट राज्यों के लिए।

मैंने शायद पहले भी कहा था सारी हमारी योजनाएं बदल दीं। जो 90:10 थी या 80:20 थी या 60:40 थी, उसको अब मैं क्या कहूं, लम्बी लिस्ट है मेरे पास में, उन तमाम अधिकांश योजनाओं को 40:60 कर दी या 50:50 कर दी। इसके कारण से जो बढ़ोतरी होनी थी, वह खतम हो गयी, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। बाकी तो बहुत कुछ किया, जब से गवर्नमेंट आयी है, एन.डी.ए. की तरफ से हमारे जो प्लान थे, जो अनाउंसमेंट थे, रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा रेल लाइन का था, गंगापुर-सरमथुरा-गंगापुर वाया करौली रेल लाइन का था, नसीराबाद से सवाई माधोपुर रेल लाइन का था, मेमू कोच फैक्ट्री, अध्यक्ष महोदय, आपने ही सैंक्शन की थी,

(श्री अशोक गहलोत)

शिलान्यास हो गया था भीलवाड़ा के अन्दर, गायब हो गयी। कई प्रस्ताव हमारे थे, उन पर कोई सुनने वाला ही नहीं है। चर्चा भी नहीं होती है उनकी तो। ये जो स्थितियां बनी हैं, मैं समझता हूं कि उसमें, फिर ऐसे-ऐसे निर्णय कर रही है कि भारत सरकार बैंकों में पैसे जमा करवा रही है। पहले हमारे जो फंड होते थे संचित निधि होती है, कंसोलिडेटेड फंड, उसमें पैसा आता था, लिक्विडिटी रहती थी सरकार के पास, वह कम हो गयी, बंद हो गयी। इस प्रकार के हालात चल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से बजट पेश किया गया है और जो सारी स्कीम्स लागू कर रखी हैं हमने, उसमें हमने कोई कमी नहीं आने दी है और इसलिए जिस प्रकार से ग्रोथ हुई है जीडी.पी. की, आप देखिए 2018-19 बीजेपी शासन में 9 लाख 11 हजार 634 करोड़ रुपये थी, वह अब 2021-22 में 11 लाख 96 हजार 137 करोड़ की हो गयी। वर्ष 2022-23 में जो अनुमान हमने पेश किया है वह 13 लाख 34 हजार 310 करोड़ का होगा। एक तरफ तो मोदी सरकार 5 ट्रिलियन डालर इकोनोमी की बात करती थी, वह तो सपना रहेगा, होने वाला नहीं है परंतु हम 15 लाख करोड़ तक ले जाएंगे इकोनोमी को, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमने तय किया है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे चूरू से आने वाले उप नेता, आप तो 5-6 या 7 बार बन गये हैं, मंत्री भी रहे हैं, भैरोंसिंह जी की पूरी ट्रेनिंग ली हुई है आपकी, आपने कैसे कह दिया कि सरकार ओवरड्राफ्ट में चली गयी? आप तो जानते हैं ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है जबकि मैं कहना चाहूंगा हमारी सरकार आने के बाद में एक बार भी ओवरड्राफ्ट में नहीं गयी है, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। एक बार भी नहीं गयी। आपने ऐसा फैलाया, बोलने की अदा तो है ही आप में, बोलने की कारीगरी आपमें पूरी है, कैसे प्रभावित करो, किस प्रकार से शब्दों का चयन करो। कह दिया आपने ओ.डी. में चली गयी। बताइए आप, एक बार भी ओवरड्राफ्ट में नहीं गयी है। वेज एंड मीन्स से पैसा ड्रा करते हैं। आर.बी.आई. खुद कहती है कि राज्यों को चाहिए कम ब्याज लगेगा और आप उसमें पैसा विदड्रा कर रहे हैं, वह ड्रा होता रहता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने जो पेश की है जितनी भी, वह तमाम हालात जो बने हुए हैं देश के अन्दर, प्रदेश के अन्दर कोरोना के बावजूद भी जिस रूप में हमने कोई कमी नहीं रखी है काम करने के अन्दर, आप सबका

(श्री अशोक गहलोत)

मैंने सहयोग लिया था, पक्ष-विपक्ष का। 21 घंटे मैंने वीडियो कांफ्रेंसिंग की है। 550 मैंने वी.सी. की है, गवर्नेंस के लिए भी और कोरोना के लिए भी। प्रयास किया गया इसमें राजनीति नहीं हो। जब जिन्दगी और मौत का सवाल हो तो वहां राजनीति किस बात की? मानवीय दृष्टिकोण से हमने कोशिश की कि हम सब लोग मिलकर चलें और उसी कारण से पूरे देश के अन्दर, विदेश के अन्दर राजस्थान में भीलवाड़ा मॉडल की आज भी चर्चा होती है। जो पैकेज हमने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो बाद में कहा 50 हजार रुपये दो, उसके पहले मैंने पैकेज दे दिया। आर्फन बच्चों को 5 लाख रुपये 18 साल पर, एक लाख रुपये तत्काल और 2,500 रुपये उनके लिए वजीफा प्रतिमाह। विधवाओं के लिए भी हमने एक लाख रुपया दिया तत्काल और वजीफा दिया 1,500 रुपये का। इस प्रकार हमने शानदार पैकेज दिया है। 50 हजार रुपये के अलावा हमने दिया है। इस प्रकार से हमने कोई कमी नहीं आने दी है।

अध्यक्ष महोदय, यह जो फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं, मैं शार्ट में अगर कहूं तो इतना ही कह सकता हूं कि इन सब पैरामीटर में भारत सरकार से अगर हम कम्पेयर कर रहे हैं तो उनके पैरामीटर से राजस्थान पीछे नहीं है, आगे है उनसे, यह मैं निवेदन कहना चाहता हूं।

फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य 2022-23 में भारत सरकार ने जो रखा है, वह लक्ष्य, 6.4 का रखा है, हमने 5.8 परसेंट का रखा है। परन्तु रेवेन्यू डेफिसिट 2020-21 के अन्दर हमारा 4.34 परसेंट रहा, भारत सरकार का 7.3 परसेंट रहा है। फिस्कल डेफिसिट हमारा 5.86, उनका 9.2 परसेंट रहा है। रेवेन्यू डेफिसिट का जो लक्ष्य 2022-23 के अन्दर था वह हमारा 1.7 है, 3.8 परसेंट इनका है हमारा आधे से भी कम है। इस प्रकार से, राजस्थान सरकार ने प्रयास किया है कि कोरोना के बावजूद भी रेवेन्यू बढ़े। रेवेन्यू बढ़ी भी है। अब रेवेन्यू राज्यों की भी और केन्द्र की भी बढ़ने लग गयी है, देश के अन्दर। यह देश के अन्दर शुभ संकेत है। देश की इकोनोमी के लिये शुभ संकेत है कि हम जल्दी ही तीसरी लहर समाप्त होते-होते ही हम गाड़ी पटरी पर लाने में कामयाब हो रहे हैं। राज्यों की भी, केन्द्र की भी, आर्थिक स्थिति आगे बढ़ती जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, मोदी जी ने अभी अनेक मदों में कमी की, उस पर भी ध्यान देना चाहूंगा। उन्होंने सब्सिडी कम कर दी। एक तरफ किसान वाली बात हो रही थी। एमएसपी खरीद में 5 हजार रुपये कम कर दिये। फर्टिलाइजर सब्सिडी में 24.9 परसेंट की कमी कर दी। फसल बीमा योजना में 3.1 परसेंट।

(श्री अशोक गहलोत)

फूड सब्सिडी में कटौती की है 27.8 परसेंट। पेट्रोलियम में 10.8 की कटौती। मनरेगा, नरेगा के अन्दर 25.5 परसेंट की कमी की है। मिड-डे मील में कोई बढ़ोतरी नहीं की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति है कि भारत सरकार से हमें जो मदद मिलनी चाहिये, हम अपेक्षा करते हैं, चाहे वह ईआरसीपी की योजना हो, चाहे अन्य योजनाएं हों, हमें पूरी इमदाद मिले। मध्यप्रदेश, यूपी की योजना उन्होंने अभी लागू की है, केन बेतवा नाम है। राजस्थान सरकार भी क्यों नहीं, 16 राष्ट्रीय योजनाएं बनी हुई हैं। प्रधान मंत्री जी जयपुर व अजमेर में कहकर गये, वह योजना राष्ट्र हित में लागू करने में क्या दिक्कत है? दो महीने पहले, जब यूपी के चुनाव आ रहे थे, मध्यप्रदेश और यूपी की 40 हजार करोड़ की योजना है, भारत सरकार ने स्वीकार कर ली। हम बार-बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, योजना आपने बनाई है, उसको हम पूरा करना चाहते हैं। तेरह ज़िले की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। नेता, प्रतिपक्ष और आपकी पार्टी के अध्यक्ष से रिक्वेस्ट करूंगा कि राजस्थान की जनता ने आपको 25 एमपी दिये हैं पर वहां ईआरसीपी के बारे में कोई बोल ही नहीं रहा है। मंत्री आपके मित्र है, जोधपुर से ही हैं, इस विभाग के हैं, उनको कोई चिन्ता ही नहीं है। क्या वह प्रधान मंत्री जी को यह नहीं कह सकते कि राजस्थान का मामला है? 16 योजनाएं, पहले से राष्ट्रीय स्तर की परियोजना बनी हुई है तो इसमें हमें दिक्कत क्या आ रही है? क्या प्रधान मंत्री उनकी बात नहीं सुनेगे? वह कहे ही नहीं तो क्या होगा? मैं समझता हूं कि इसे हमें सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि राजस्थान का हित है, उसमें पक्ष और विपक्ष मिलकर, केन्द्र सरकार पर कड़ा दवाब ड़ालें, जिससे हमें उसका लाभ मिल सके।

अभी हमने क्या किया है, मैंने घोषणा भी की थी कि हम इसको देरी से और कीमतें बढ़ जायेंगी, जैसा मैने कहा, आप पिछली बार हाउस में नहीं थे। मैंने कहा कि लगभग 37 हजार करोड़ की रिफाइनरी की योजना थी, आपकी पिछली सरकार ने उसको रोक दिया। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम भारत सरकार के अन्डर में आता है, उन्होंने परवाह नहीं की, इस कारण से वह योजना डिले हो गयी। आज वह 37 हजार करोड़ रुपये की योजना 70 हजार करोड़ की बनने जा रही है। बताइये, इसका जिम्मेदार कौन है? आप लोग हो, आपकी पार्टी के लोग हैं जिन्होंने योजना को रोका। 26 परसेंट की भागीदारी

(श्री अशोक गहलोत)

क्यों? पानी हमारा, बिजली हमारी, तेल हमारा, भागीदारी 26 परसेंट। मैं बार-बार कह रहा हूं, भागीदारी होती ही नहीं है राज्य सरकारों की। एसबीआई कैपिटल कम्पनी है स्टेट बैंक आफ इंडिया की, उनके कहने पर हमको लेनी पड़ी 26 भागीदारी, अब वह 70 हजार करोड़ की पता नहीं कब पूरी होगी? यह स्थिति है।

हमने ईआरसीपी के लिये क्या किया, अभी मैंने कहा बजट के अन्दर, 9 हजार 600 करोड़ दिये। अगर भारत सरकार डिले करती है, हम डिले करेंगे, वह आज 40 हजार करोड़ की है, वह बढ़ते-बढ़ते पता नहीं कहां चली जायेगी। 13 ज़िलों में सिंचाई योजना दो लाख हैक्टेयर में है। पीने का पानी मिलेगा। जेजेएम की योजना तो बन गयी लेकिन छोर सिरे तक, गांव के अन्दर पानी कैसे पहुंचेगा, घर के अन्दर पानी कैसे पहुंचेगा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बार-बार यह कहते हो कि कर्जा माफ ही नहीं हुआ, पब्लिक में भी, यहां भी। अगर कर्जा माफ नहीं हुआ तो 22 लाख लोग धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? यह तो ऑनलाइन है। कोई देख सकता है कि 22 लाख लोग, कौन-कौन है वह। 14 हजार करोड़ में से 6 हजार करोड़ तो आपके वक्त के बाकी थे, वह हमने चुकाया साथ में। यह तो आंकड़े हैं। हमने लिमिट रखी ही नहीं। 9-9 लाख रुपये तक है। टोंक का आदमी है, उसके 9 लाख रुपये माफ हुए हैं। दो लाख की लिमिट हमने नहीं रखी। आपने पहले 50 हजार किया, फिर दो लाख आ रहे थे, आपकी सरकार चली गयी। हमने उसको निभाया है। बार-बार बोलते रहते हो, लोन माफ नहीं किया। एक, दो,तीन, चार। राहुल गांधी ने कहा है, तो उसी तीन दिन के अन्दर-अन्दर लोन माफ हुए हैं राजस्थान में। हम यह भी कहते हैं राष्ट्रीयकृत बैंक हैं वह अभी मान नहीं रही, आप मनवा सकते हो उनको, आप मनवाना नहीं चाहते। आप नहीं चाहते हो, क्योंकि सरकार की वाहवाही हो जाएगी। हम कहते हैं, जो एनपीए होता है इंडस्ट्रियलिस्ट का, उसके अन्दर चाहे 50 करोड़ हो या 25 करोड़ हो, लेन-देन होता है, बातचीत होती है, बारगेनिंग होती है और मामला सैटल होता है। हम कहते हैं कि ऐसे ही सैटलमेंट आप किसान के साथ कर लो। जो हमारा हिस्सा बनेगा वह स्टेट गवर्नमेंट भरेगी, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

बीजेपी के पार्लियामेंट में, जब मैम्बर पार्लियामेंट ने सवाल पूछा तो जवाब क्या दिया, आपको मालूम है? केन्द्र सरकार का किसान माफी का कोई

(श्री अशोक गहलोत)

विचार ही नहीं है। किसान कर्ज माफी से, डिफाल्टर किसानों को पैसा मिलता है, जिससे किसान जान बूझकर कर्ज नहीं चुकाते, इससे किसान बार-बार कर्ज माफी की मांग कर सकते हैं, ऐसी मांग को खारिज करना मुश्किल होता है। यह आपके पार्लियामेंट में, मंत्री जी ने जवाब दिया है।

आपकी नीति नहीं है। यूपीए गवर्नमेंट में 72 हजार करोड़ रुपये के कर्जे माफ किये थे डाक्टर मनमोहन सिंह जी ने। वह बड़े इकोनोमिस्ट थे, वर्ल्ड के माने हुए। अगर वह माफ कर सकते हैं तो मोदी के पास तो इकोनोमिक एडवाइजर भी है, वह डा. मनमोहन सिंह जी से बात कर सकते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर पूर्व प्राइम मिनिस्टर से बात करे तो क्या दिक्कत है? पूछ सकते हैं कि कैसे माफ करें, आपने कैसे माफ किया। वह बात तो कहीं है ही नहीं, जान बूझकर आप घबराये हुए रहते हो, पता नहीं अगली बार क्या होगा। इसलिये आप क्या कर रहे हो, बार-बार ऐसे मुद्दे उठाते हो जिनका कोई तर्क नहीं है, कोई तथ्य ही नहीं है। उठा रहे हैं कि राजस्थान में कर्जा माफ ही नहीं किया। राहुल गांधी जी तो कहकर चले गये। छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, सब में वादा निभाया है, यह आपके ध्यान में आना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, कहने को तो बहुत सारी बातें हैं। हमने घोषणाएं ही इतनी सारी की हैं कि उन पर बोलें उतना ही कम है। जो सुझाव आये हैं उनको तो हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमने इस योजना को, 9 हजार 600 करोड़ रुपये का प्रोवीजन रखा है। नवनेरा बांध बन रहा है, ईसरदा भी आयेगा, बीसलपुर भी आयेगा। दौसा हो, माधोपुर हो, जो भी है, उसमें जयपुर भी आता है, अजमेर भी आता है, टोंक भी आता है, करौली भी आता है, धौलपुर भी आता है, भरतपुर भी आता है, अलवर भी आता है, बड़ी योजना है। प्लीज, प्लीज, नेता, प्रतिपक्ष कहां देख रहे हो? उधर मत देखो, मेरी तरफ भी देखो। ईआरसीपी को राष्ट्रीय योजना घोषित करवाने के लिये आप लीड लो तो हमारा काम हो जायेगा, मैं निवेदन करना चाहता हूं। आपकी बात का वज़न है, आपका पार्टी में, समाज में मान-सम्मान भी है। आप बड़े दिल से बोलते हो। कैलाश मेघवाल जी, पता नहीं आपने इनको क्या घुट्टी पिला दी है। कोई आपका मैंने पेपर में पढ़ा, कोई अख़बार के अन्दर आया था कुछ, पर मेरा यह मानना है कि अगर विपक्ष के साथी तैयार हों तो हम

(श्री अशोक गहलोत)

भी आपके साथ चलने के लिए साथ तैयार हैं। आप टाइम लीजिए पी.एम. से, हम चलेंगे। जाइंट रिक्वैस्ट करेंगे कि ई.आर.सी.पी. को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर यह जो मैं आपको रिक्वैस्ट कर रहा हूं, यह एप्रोच हमारी होगी तो अवश्य ही परियोजना राष्ट्रीय परियोजना घोषित होगी और उसके बाद में हमें बनाने में आसानी हो जायेगी। 90:10 का रेश्यो होगा। अब पूरा पैसा स्टेट गवर्नमेंट भरेगी। अभी जो हमने तय किया कि रोको मत इसको। नहीं रोकने की एवज में 9 हजार 600 करोड़ रुपया अभी रखा है और आगे और लगातार रखते जायेंगे।

एक बात आपने यह कह दी थी, पता नहीं कि वह चार हजार ही घर जुड़े हैं। पता नहीं कहां से आप यह फिगर लेकर आ गये। दस लाख से ज्यादा तो कनेक्शन हो चुके हैं और काम उनका चल रहा है जे.जे.एम. के अन्दर। यह पता नहीं आप कहां से फिगर लेकर आये हैं।

साथ ही, मैं यह कहना चाहूंगा कि पिछली बार आप हाउस के अन्दर आये नहीं थे। जब अभिभाषण के ऊपर रिप्लाई हो रहा था, तब मैंने पूरा बताया था। आपने अभी यह कहा कि एक लाख 60 हजार की भर्ती की आपने कही थी। हमने यह कहा कि एक लाख भर्ती हो चुकी है, बाकी प्रोसेस के अन्दर है। एक लाख का ब्रेकअप मैं दे चुका हूं पिछली बार हाउस के अन्दर, आप नहीं थे उस दिन हाउस के अन्दर, यह मैं कहना चाहता हूं।

हमने यह कहा है कि यह पहली बार होगा राजस्थान के अन्दर कि तीन लाख भर्ती होगी, तीन लाख भर्तियां होंगी। एक लाख हो चुकी हैं, एक लाख प्रोसेस के अन्दर हैं और एक लाख का मैंने अनाउंसमेंट किया है। बजट के अन्दर किया है, वह सब होकर रहेगी। आपकी यह चिन्ता वाजिब है कि जो रीट के अन्दर हुआ, ऐसी घटना आपके वक्त में भी हुई तीन बार। केन्द्र सरकार के मंत्रालयों में हुई है। डिफेंस में हुई है। यूपी. हो, चाहे बिहार हो, चाहे गुजरात हो, सब जगह पर हुई है। जो हालात जिस तरीके से बन गये हैं, जो माहौल बन गया है उसमें लोगों में फ्रस्ट्रेशन आ रहा है युवाओं के अन्दर भी हाहाकार मचा हुआ है बेरोजगारी को लेकर और हमें चिन्ता करनी चाहिए कि यह क्यों ऐसी गैंग पैदा हो रही है पर मैं आपको यह विश्वास दिलाऊंगा कि उसको सरकार ने बहुत गम्भीरता से लिया है। उसी रूप में हम यह चाहेंगे कि आने वाले वक्त के अन्दर भविष्य में कोई ऐसी नौबत नहीं आये। हालांकि, उसके आंकड़े दिये जा रहे थे कि लाखों लोगों के 145 नम्बर आ गये 150 में

(श्री अशोक गहलोत)

से, यह सब बातें गलत थीं। जो परसों परिणाम आये हैं लेवल फर्स्ट के वह सब असत्य आंकड़े थे, लोगों को भड़काने वाले थे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह चिन्ता करना पक्ष-विपक्ष का मैं समझता हूं कि दायित्व भी है क्योंकि यह लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़ा मामला है। जो 25 लाख बच्चे थे, हमने उनके लिए सब अच्छे इंतजाम किये, सबके लिए आह्वान किया एन.जी.ओ. को, उनके सहयोग से भी हमने अच्छा इंतजाम किया, वहां रहने, खाने, पीने के लिए भी, बसें फ्री रखी उन सबके लिए पर ऐसी घटना हो गयी कि उस परीक्षा को रद्द करना पड़ा। उस बात का मुझे आज भी दु:ख है क्योंकि कई बच्चे जो हैं वे पास हो रहे थे, उनको यह दु:ख होता है कि हम पास हो रहे थे, अब पता नहीं आगे क्या होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो बजट में घोषणाएं हमारी हैं, यह तो इसकी बानगी है। चाहे वह चिरंजीवी योजना हो, मैं मांग करूंगा केन्द्र से, भारत सरकार को भी 10 लाख का बीमा करना चाहिए, नम्बर एक। हमने अस्पतालों में कैशलेस इलाज शुरू कर दिया है, कर रहे हैं। उसके लिए मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि कैशलेस इलाज होना आई.पी.डी., ओ.पी.डी. में एक बहुत बड़ी बात है। कुछ पैसे लगेंगे ही नहीं सरकारी अस्पतालों के अन्दर, वह मैंने घोषणा की है। यह तमाम जो योजना है, इसमें भारत सरकार को भी आगे आना चाहिए।

इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, आप उसकी चिन्ता कर रहे थे अभी कि यह कैसे लागू होगी? लागू होगी, यह भी लागू होगी। मैं यह चाहूंगा कि केन्द्र सरकार भी इसको अपनाये। नाम दूसरा रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। इन्दिराजी का नाम तो वे क्या रखेंगे। आप जानते हो मोदीजी को, मोदीजी तो मोदीजी ही हैं। 70 साल में क्या हुआ? कांग्रेस को हम लोग, कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे, कांग्रेस कभी मुक्त होगी नहीं, कहने वाले मुक्त हो सकते हैं, कांग्रेस तो यहां रहेगी देश के अन्दर।

मनरेगा में 25 दिन का हमने बढ़ाया है। केन्द्र सरकार को यह चाहिए कि वह पचास दिन का बढ़ाये।

पुरानी पेंशन योजना, जिसकी चर्चा पूरे देश के अन्दर है। यह आप जैसे भावुक आदमी को समझना चाहिए कि यह तो बहुत ही सेंटिमेंटल मामला है, मानवीय दृष्टिकोण का मामला है। मैंने एक आर्टिकल लिखा है, आपने पढ़ा

(श्री अशोक गहलोत)

होगा शायद। सब तो नहीं पर कोई न कोई तो पढ़ता ही है। यह मैंने बताया कि किस प्रकार से ह्यूमन राइट कमीशन यह कह रहा है कि आप इस पर विचार करो। आर्मी को पहले ही बाहर रखा हुआ था इस योजना से। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को, उनको बाहर क्यों रखा हुआ था? जुडिशियल कमीशन है, वह यह रिकमंड कर रहा है कि हम जुडिशियल में इसको लागू नहीं करेंगे तो ह्यूमन राइट कमीशन यह कह रहा है, जुडिशियल कमीशन यह कह रहा है और सी.ए.जी. जिसने इतने आब्जेक्शन लगाये हैं, 17 साल में जो जिस प्रकार की यह योजना चली, कोई नियम बनाये नहीं, कायदे नहीं हैं, पूरा पैसा जमा होगा म्युचअल फंड के अन्दर, शेयर मार्केट के अन्दर। तीस-चालीस साल बाद में किसने देखा कि उस वक्त शेयर मार्केट क्या होगा? वह जो पैसा मिलेगा रिटायरमेंट पर कर्मचारी को, उस वक्त में जो राशि जमा हुई है और उन्होंने आगे जमा करवाया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, अब आप बताइये कि म्युचअल फंड क्या है? ऊपर नीचे होता रहता है और साथ में वह ही स्थिति है जो आपका शेयर मार्केट है, उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। इतना लोगों में अविश्वास या कहना चाहिए कि लोगों को चिन्ता थी, चिन्ता सता रही थी कि हमारा क्या होगा, रिटायरमेंट पर क्या होगा? पुरानी पेंशन तो सबको मालूम है कि वह तो, उससे ही इस देश का 70 साल तक विकास हुआ है, पुरानी पेंशन से ही तो, वह प्रयोग तो आपके सामने है। पुरानी पेंशन चल रही थी, आज यहां तक देश पहुंचा है। अचानक ही पता नहीं क्या कारण रहे होंगे? हालांकि, मैंने यह लिखा है बजट के डाक्यूमेंट में भी कि हो सकता है कि कर्ज का भार बहुत बढ़ रहा था फाइनेंशियली इसलिए किया होगा, वाजपेयी की गवर्नमेंट में यह योजना लागू की गयी थी।

मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई योजना को लेकर अगर लाखों लोग चिन्तित हों इस देश के अन्दर कर्मचारी, आज मैंने यह सुना, पढ़ा तो नहीं है, हमारे राजस्थान कैडर के ही एक आई.ए.एस. आफिसर रहे हैं, वे सी.ए.जी. बन गये थे, उनका आर्टिकल भी आया है। इंडियन एक्सप्रेस में भी इसके बारे में कमेंट्स आये हैं कि यह नहीं लागू होना चाहिए था। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिस अधिकारी ने यह लिखा है, आर्टिकल लिखा है उन्होंने, मैं यह पूछना चाहता हूं उनसे भी कि अगर जब यह योजना लागू की थी 2004 के अन्दर, उस वक्त यह योजना लागू ऐसे होती कि आज के बाद में जितने भी कर्मचारी हैं पहले के भर्ती और नये भर्ती होंगे, उन सबके लिए यह लागू होगी, तब

(श्री अशोक गहलोत)

उनको यह मालूम पड़ता कि उनकी क्या स्थिति है। उस समय उनकी दस साल की सर्विस रही होगी, दस-बारह साल की तो मालूम पड़ जाता कि हमारा खुद का फ्यूचर क्या है। आप यह भेदभाव कर रहे हो। आधे कर्मचारी तो पुरानी पेंशन के, आधे कर्मचारी नई पेंशन में। क्या बीत रही होगी, कोई सोच नहीं सकता था। अगर हमने सोच-समझकर यह कदम उठाया है तो वेलकम क्यों हो रहा है उसका? इसलिए हो रहा है कि उनको एक सिक्योरिटी मिल गयी है। 2038 में कौन कहां पर रहेगा, अगर हम यह चिन्ता करेंगे तो फिर कोई फैसला ही नहीं कर पायेंगे। जो आपने अभी कहा कि उस वक्त कौन रहेगा। निर्णय करते हैं, इतिहास बनता है, इतिहास बनाना सीखना चाहिए और इतिहास वही बनाता है जो पहले वाले इतिहास को लेकर गम्भीर होता है, उनको एप्रीशिएट करता है। मोदीजी की तरह नहीं कि इन 70 सालों में कुछ नहीं हुआ है, यह 70 साल के इतिहास को आप भुला दोगे तो बांग्लादेश, पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गये हों, बांग्लादेश बन गया हो, इतना इनोवेशन हो गया हो, साइंस ने, विज्ञान ने, तकनीकी योजना में पता नहीं देश कहां तक पहुंच गया। आप इतिहास को भुलाओगे तो फिर इतिहास कभी बना नहीं पाओगे। इतिहास वही बना पाता है जो इतिहास को याद रखता है, उसको एप्रीशिएट करता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह उम्मीद करता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो पहले मांगें मुझ से की थीं, काफी मैंने उनको बजट में लेने का प्रयास किया। मैं कुछ और घोषणाएं करना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने 23 फरवरी को यह बजट प्रस्तुत किया, प्रस्तुत बजट में सभी वंचित वर्गों को सम्बल प्रदान करने के साथ-साथ प्रदेश के चहुंमुखी विकास की राह प्रशस्त की है। इसमें प्रदेश के साथसाथ सम्पूर्ण देश से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो रही हैं, किन्तु हमें अपेक्षा के अनुरूप केन्द्र सरकार का सपोर्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान कुछ ऐसे मुद्दों की ओर आकर्षित करना चाहूंगाः

केन्द्र सरकार ने 14th Finance commission जिसका मैंने आपको जिक्र कर दिया, मैं इसको नहीं पढूंगा, मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से केन्द्रीय करों में हिस्सा राशि को 32 परसेंट से बढ़ाकर 41 परसेंट करने की

(श्री अशोक गहलोत)

रिकमंडेशन की गई थी। उससे होने वाले लाभ को लगभग सभी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) में राज्यों की हिस्सा राशि बढ़ाकर समाप्त कर दिया।

इसी प्रकार बेसिक एक्साइज ड्यूटी का हिस्सा राज्यों को मिलता है, वह तो कम कर दिया और एडिशनल रूप से एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। यह हिस्सा राज्यों को नहीं मिलता है।

इसी प्रकार से मैंने आपको बताया कि 15 हजार करोड़ रुपये पिछली बार, 19 हजार करोड़ इस बार कम किये जा रहे हैं। मैंने आपको ब्रीफ किया। अध्यक्ष महोदय, दूसरी मेरी यह भी मांग है भारत सरकार से, मैं चाहूंगा कि हाउस का सपोर्ट मिले, सब लोग कहें इसको, कि जीएसटी कम्पनसेशन जो है 2022 तक है, इसको 5 साल और आगे बढ़ाना चाहिए। तब जाकर राज्यों की स्थिति ठीक हो पायेगी।

अध्यक्ष महोदय, 15वें वित्त आयोग ने राजस्थान को 2 हजार 300 करोड़ रुपये लागत के 10 विशेष प्रोजेक्ट्स दिये थे। केन्द्र सरकार इन परियोजनाओं की स्वीकृति नहीं दे रही है। यह भी हमारे लिए चिन्ता का विषय बना हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे तथा प्रदेश के 25 सांसद हमारे साथ मिल कर केन्द्र से ऐसे बिन्दुओं पर आवश्यक सहयोग दिलवाने का प्रयास करें। मैंने आपको निवेदन भी किया है। इसमें सभी पाइंट आ जायेंगे जो हमने इसके अन्दर रख छोड़े हैं।

1. अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं कुछ घोषणाएं करना चाहता हूं। राज्य के प्रत्येक जिले में मेडिकल कालेज स्थापित करने को हमने लक्ष्य बनाया। नेता प्रतिपक्ष महोदय, एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं, आप बार-बार कहते हो कि वर्तमान सरकार ने मेडिकल कालेज दे दिये। आपको जानकारी होनी चाहिए कि योजना बन गयी थी यूपीए गवर्नमेंट के वक्त में, उस वक्त यहां पर हमारी सरकार थी, तब बन गयी थी, सात कालेज सेंक्शन हो गये थे। एक कालेज हमारे उप नेता चुरा कर ले गये। सीकर का ले गये चूरू में, क्योंकि हैल्थ मिनिस्टर खुद बन गये थे। उस वक्त में योजना बन चुकी थी। आप यह मत कहो कि भारत सरकार बनाकर मेडिकल कालेज दे रही

(श्री अशोक गहलोत)

है। यह गलत बात है। 14 जिलों में तो कालेज संचालित हैं और गंगानगर, सिरोही, चित्तौड़ और धौलपुर में जल्दी कालेज शुरू हो जायेंगे।

2. अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा सेवाओं के विस्तार व आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दृष्टि से-

I. बीबीपुर, किराड़ा छोट्टा (निमलाई) (भादरा)-हनुमानगढ़ में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे।

II. उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जाना व नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित है, जो इस प्रकार है:-

उप स्वास्थ्य केन्द्र से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

अजबपुरा (बानसूर)-अलवर, उवार-भरतपुर, सिणली जागीर (बालोतरा), मोड़ का निम्बाहेड़ा (आसींद)-भीलवाड़ा, पूनरास, सड़ू छोटी (बीदासर), राजपुरा (तारानगर)-चूरू, उदपुरा-चित्तौड़गढ़, महारिया (लालसोट), देलाड़ी, चांदेरा व खेड़ी (बांदीकुई)-दौसा, कैथरी (सैपऊ)-धौलपुर, जेठाना-डूंगरपुर, मेहरवाला (टिब्बी)-हनुमानगढ़, विजयपुरा, सुमेल, बगराना, डीडावता (माधोराजपुरा)-जयपुर, राजलानी (भोपालगढ़), खोपारड़ी, ननेऊ (फलौदी)-जोधपुर, बालवाड़ा (सायला), देताखुर्द-जालौर, खेड़ी (टोड़ाभीम)-करौली, मकराना-नागौर, फुलाद (मारवाड़ जंक्शन), जीवंद कला (रानी)-पाली, उमरगढ़, छापावाली (सादुलशहर)-श्रीगंगानगर।

नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

हरपुरा, खवास (केकड़ी)-अजमेर, साहडोली (रामगढ़), न्याणा (गोविन्दगढ़)-अलवर, संतरा (गिड़ा), खिंपसर (बायतू), मांगता, शौभाला (गुड़ामालानी)-बाड़मेर, रामसिंहपुर पालकी (नगर), घाटोली तिराहा (रूपवास)-भरतपुर, जालूपुरा (बिलाड़ा)-जोधपुर, दौलतपुरा (डीडवाना), जनाणा (खींवसर), चूडियास (डेगाना), गुलर (परबतसर)-नागौर, धुरासनी (सोजत)-पाली, सारोठ, अजीतगढ़ (भीम)-राजसमंद, छाण (खण्डार)-सवाई माधोपुर, पाटिया (नयागांव)-उदयपुर, जारगा (बसेड़ी)-धौलपुर, चिखली (चौरासी)-डूंगरपुर तथा पथाना (बुहाना), सोनासर (मलसीसर), वाहिदपुरा (मण्डावा), कांकरिया (खेतड़ी)-झुन्झुनूं।

साथ ही, बहीर टोंक, कालाखोह (सिकराय)-दौसा व खीरियां (केकड़ी)-अजमेर में नवीन शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे।

(श्री अशोक गहलोत)

III. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जायेगा, जो इस प्रकार हैं-

धूंधरी (केकड़ी)-अजमेर, हरलाना (राजगढ़), माजरी (बहरोड), इटैडा (लक्ष्मणगढ़), कराना (बानसूर)-अलवर, कक्कू (नोखा)-बीकानेर, झील का बाड़ा (बयाना), ललिता मूडिया (वैर)-भरतपुर, सिद्धमुख-चूरू, राहुवास (लालसोट), बहरावण्डा (सिकराय)-दौसा, नादनपुर (बसेड़ी)-धौलपुर, धवली (शाहपुरा), आंतेला (विराटनगर), मोतीकटला-जयपुर, अलसीसर (मंडावा), सुल्ताना-झुन्झुनूं, बापीणी (लोहावट), सामराऊ (ओसियां)-जोधपुर, बूटाटी (डेगाना), खुनखुना (डीडवाना)-नागौर, तलावड़ा (गंगापुर)-सवाई माधोपुर, चला (नीम का थाना)-सीकर, सागवाड़ा (खेरवाड़ा), बंबोरा (वल्लभनगर), भबराना (सलूम्बर)-उदयपुर व दत्तवास (निवाई)-टोंक के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जायेगा। साथ ही, नावां-नागौर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण करवाया जायेगा। इसके अतिरिक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोहावट-जोधपुर में मातृ एवं शिशु रोग कल्याण केन्द्र शुरू किया जायेगा।

IV. अटरू-बारां, डेगाना-नागौर व नोहर-हनुमानगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया जायेगा।

V. जयपुर के मोतीडूंगरी रोड स्थित मोबाइल सर्जिकल यूनिट को सेटेलाइट अस्पताल के रूप में विकसित किया जायेगा।

VI. निम्बाहेड़ा-चित्तौड़गढ़ उप जिला अस्पताल को जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया जायेगा।

VII. बच्छरारा (रतनगढ़)-चूरू व बावड़ीखुर्द (फलौदी)-जोधपुर में आयुर्वेद औषधालय खोले जायेंगे।

3. माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा व खेल के अन्दर इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्री-प्राइमरी बाल वाटिकाएं आरम्भ करना प्रस्तावित है। आगामी वर्ष में प्रथम चरण में एक हजार विद्यालयों में प्री-प्राइमरी बाल वाटिकाएं आरम्भ की जायेंगी। इसमें NTT Course किये हुए अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी। इस पर 50 करोड़ रुपये वार्षिक खर्च होंगे।

4. विद्यालयों में विद्यार्थियों के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से ए.पी.जे. अब्दुल कलाम Personality Development Programme प्रारम्भ

(श्री अशोक गहलोत)

किया जायेगा। इसके अंतर्गत, शिक्षा की दृष्टि से मेधावी एवं विभिन्न सह-शैक्षणिक गतिविधियों यथा- Debate, Essay competition, साहित्यिक गतिविधियों व सांस्कृतिक लोक कलाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले एक हजार विद्यार्थियों का चयन कर उन्हें देश के अन्य राज्यों में exposure visit करवायी जायेगी तथा Exchange programme में भेजा जायेगा।

5. प्रदेश में निजी शिक्षण संस्थाओं और कोचिंग केन्द्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए उनकी समस्याओं का भी समुचित समाधान करने की दृष्टि से Private Educational Institutions Regulation and Facilitation Board का गठन किया जाना प्रस्तावित है।

6. प्रदेश में नये राजकीय महाविद्यालय खोले जायेंगे जो इस प्रकार हैं-

टांटोटी (केकड़ी)-अजमेर, टहला (थानागाजी)-अलवर, पूगल (खाजूवाला)-बीकानेर, चौरासी, रामसागड़ा-डूंगरपुर, पावटा-जयपुर, सांकड़ा (पोकरण), रामगढ़-जैसलमेर, कालन्द्री-सिरोही, हिन्दूमलकोट-श्रीगंगानगर, भचुण्डला-प्रतापगढ़, मण्डरायल (सपोटरा)-करौली, नेछवा (लक्ष्मणगढ़)-सीकर व चौथ का बरवाड़ा-सवाई माधोपुर।

7. साथ ही, दूदू-जयपुर, खींवसर-नागौर, प्रतापगढ़-अलवर, बड़ा गुढ़ा (सोजत)-पाली व फतेहपुर, श्रीमाधोपुर-सीकर में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जायेंगे।

8. राजकीय कन्या महाविद्यालय, सिरोही व नागौर तथा राजकीय महाविद्यालय-उनियारा, श्रीडूंगरगढ़-बीकानेर को स्नातक (यूजी) से स्नातकोत्तर (पीजी) में क्रमोन्नत किया जायेगा। साथ ही, राजकीय महाविद्यालय, जामडोली-जयपुर में आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए 10 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

9. प्रदेश के महाविद्यालयों में विभिन्न संकाय एवं नये विषय प्रारम्भ किये जायेंगे, जो इस प्रकार हैं:-

I. राजकीय महिला महाविद्यालय बस्सी-जयपुर, देवगढ़-राजसमंद व तिजारा-अलवर में विज्ञान संकाय;

II. राजकीय महाविद्यालय बस्सी-जयपुर में वाणिज्य संकाय;

III. राजकीय महाविद्यालय तिजारा-अलवर में कला संकाय (गृह विज्ञान);

(श्री अशोक गहलोत)

IV. राजकीय कन्या महाविद्यालय, किशनपोल-जयपुर में इतिहास, राजनीति विज्ञान, वाणिज्य एवं अर्थशास्त्र विषय; तथा

V. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय-बाड़मेर में पीजी स्तर पर Botany विषय शुरू किया जायेगा।

10. राजकीय तकनीकी व उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने एवं बढ़ाने की दृष्टि से, मैं आगामी वर्ष में Rajasthan Higher Technical Education Quality Improvement Scheme लागू करना प्रस्तावित करता हूं। इस पर 15 करोड़ रुपये का व्यय होगा। साथ ही, विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा शैक्षिक उन्नयन की परियोजनाएं प्रस्तत करने पर उन पर भी विचार कर स्वीकृति दी जा सकेगी। इस हेतु 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा।

11. खमनोर-राजसमंद, मांडण (बहरोड़)-अलवर, कामां, वैर-भरतपुर, बगरू-जयपुर व भणियाणा (पोकरण), फतेहगढ़-जैसलमेर में आईटीआई खोली जायेंगी।

12. बायतू-बाड़मेर, गुढ़ा (उदयपुरवाटी), मण्डावा-झुंझुनूं एवं किशनगढ़बास, तिजारा-अलवर में खेल स्टेडियम स्थापित किये जायेंगे। साथ ही, रतनगढ़-चूरू के खेल स्टेडियम में इंडोर स्टेडियम सहित अन्य आधारभूत सुविधायें विकसित की जायेंगी।

परिवहन

13. गत वर्ष एवं इस वर्ष के प्रारंभिक महीनों में कोविड महामारी के चलते Tour Operators को हानि हुई है। अतः Indian Association of Tour Operators (IATO) तथा Rajasthan Association of Tour Operators (RATO) से मान्यता प्राप्त Tour Operators द्वारा संचालित वातानुकूलित लग्जरी बसों को 01 अक्टूबर, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक मासिक मोटर वाहन कर में पूर्ण छूट दिये जाने की घोषणा करता हूं।

14. वर्ष 2021-22 में मैंने e-vehicles के संचालन को प्रोत्साहन देने के लिये 31 मार्च, 2022 तक ऐसे वाहनों के क्रेताओं को SGST का पुनर्भरण करने का तथा दो पहिया एवं तिपहिया ई-वाहनों पर बैट्री क्षमतानुसार क्रमशः 5 से 10 हजार तथा 10 से 20 हजार रुपये तक का एकमुश्त अनुदान दिये जाने की घोषणा की थी। अब SGST पुनर्भरण तथा एकमुश्त अनुदान की तिथि 31 मार्च, 2023 तक बढ़ाये जाने की घोषणा करता हूं।

(श्री अशोक गहलोत)

15. टैक्सी/मैक्सी, कैब के गैर-परिवहन यानों के रूप में Assignment होने पर अतिरिक्त कर नहीं लिया जाएगा।

16. बेगूं-चित्तौड़गढ़ में नवीन उप-परिवहन कार्यालय खोला जाएगा।

युवा, रोजगार एवं उद्योग:

17. युवाओं को स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिये राज्य सरकार एवं निजी क्षेत्र के संयुक्त सहयोग से रियायती मूल्य पर राज्य में आगामी वर्ष में 3 हजार 300 लघु वाणिज्यिक वाहन उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 20 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

18. हमने महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत 2021-22 में सहरिया, कथौड़ी जनजाति व राज्य के विशेष योग्यजन श्रमिकों को भी आर्थिक सम्बल प्रदान करने की दृष्टि से 100 दिवस के स्थान पर 200 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया था। इसकी निरन्तरता में आगामी वर्ष में भी इन्हें 200 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।

19. हमारे द्वारा देश-विदेश में रहने वाले प्रवासी राजस्थानियों को पुन: अपने प्रदेश की मिट्टी से जुड़ने के लिये Rajasthan Foundation के माध्यम से प्रेरित किया गया है। प्रवासी राजस्थानियों द्वारा राज्य को प्रत्येक क्षेत्र में दिये जा रहे अमूल्य योगदान के दृष्टिगत विश्व के प्रमुख देशों में चरणबद्ध रूप से Rajasthan Foundation के Chapters शुरू किये जाएंगे। आगामी वर्ष Rajasthan Foundation के कार्य को बढ़ाने के लिये 10 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे।

20. ओसियां-जोधपुर में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा।

सामाजिक सुरक्षा:

21. प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, कामगारों, रेहड़ी/ठेले वालों तथा परम्परागत व्यवसायों से जुड़े कारीगरों की दक्षता विकास एवं समग्र कल्याण हेतु Labour Welfare Board का गठन किया जाना प्रस्तावित है।

22. इन्दिरा रसोई योजना के अन्तर्गत किसी भी दानदाता द्वारा यदि नि:शुल्क अथवा सस्ती दर (Token Price) पर अपने स्वयं के खर्चे पर गरीबों हेतु खाने की व्यवस्था की जाती है तो सरकार द्वारा इन भोजनालयों के संचालन के लिये बिजली, पानी सहित नि:शुल्क भवन उपलब्ध कराया जायेगा।

23. राज्य में स्वयं सहायता समूहों के विस्तार एवं इनके सदस्यों की आय में वृद्धि किये जाने की दृष्टि से-

(श्री अशोक गहलोत)

I. 50 हजार नवीन स्वयं सहायता समूहों का गठन कर लगभग 5 लाख 50 हजार ग्रामीण महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा।

II. Revolving Fund व Community Investment Fund के रूप में 300 करोड़ रुपये तथा बैंकों से ऋण के रूप में 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी।

III. सवाई माधोपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर व दौसा जिलों में ग्रामीण हाट एवं सुविधा केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।

24. तिंवरी (ओसियां)-जोधपुर, नाथद्वारा-राजसमन्द व सवाई माधोपुर में अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास, भणियाना (पोकरण)-जैसलमेर, सेडवा-बाड़मेर में अम्बेडकर छात्रावास, बेगूं-चित्तौड़गढ़ में देवनारायण बालक छात्रावास, धौलपुर में अल्पसंख्यक बालक छात्रावास व अभे का पार (रामसर)-बाड़मेर में अल्पसंख्यक बालिका आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे।

25. राज्य के समस्त राजकीय व अनुदानित आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के साथ ही वृद्ध आश्रम, बेघर व्यक्तियों के गृह आदि में मैस भत्ते की राशि को एक समान करते हुए 2 हजार 500 रुपये प्रति विद्यार्थी/आवासी प्रतिमाह किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही मैं, राजकीय छात्रावासों में मैस व्यवस्था के विस्तार एवं सुधार हेतु आधुनिक उपकरण, डायनिंग टेबल एवं कुर्सी आदि के लिये 100 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित करता हूं।

26. जन सहभागिता योजना के तहत राज्य की वक्फ सम्पत्तियों के संरक्षण एवं विकास हेतु 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा।

आधारभूत संरचना:

27. वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्तुत करते समय मैंने प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के लिये 7 करोड़ रुपये की नोन पेचेबल/क्षतिग्रस्त तथा 3 करोड़ रुपये की मिसिंग लिंक स्वीकृत करने की घोषणा की थी। माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये फीडबैक के आधार पर अब मैं, इसे संशोधित करते हुए प्रत्येक विधान सभा के लिये 10 करोड़ रुपये की नोन पेचेबल सड़कें/मिसिंग लिंक स्वीकृत करना प्रस्तावित करता हूं।

(श्री अशोक गहलोत)

28. प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण एवं अन्य आधारभूत कार्य लगभग 1 हजार 147 करोड़ रुपये की लागत से करवाये जाना प्रस्तावित है। सडकों की सूची बहुत लम्बी है मैं इन सड़कों की सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-02 देखें)

29. प्रदेश के विभिन्न शहरों में बाईपास, सड़क व ब्रिज निर्माण कार्यों हेतु DPR बनायी जानी प्रस्तावित है, ये कार्य हैं:-

क्र.सं.	बाई पास सड़क एवं ब्रिज निर्माण कार्य (DPR)
1.	मण्डावरी (लालसोट)-दौसा में बाईपास निर्माण
2.	डीग-कुम्हेर में बाईपास का निर्माण
3.	गुढ़ा से जयपुर वाया किशोरी-सिघला-तिबारा-झिरी आंधी-रामगढ़ (SH 55) आंधी बाईपास (2.5 किलोमीटर) का निर्माण
4.	भादरा शहर-हनुमानगढ़ में रेलवे क्रोसिंग पर अण्डर ब्रिज का निर्माण
5.	मेड़ता रोड-नागौर के रेलवे फाटक (संख्या 101) पर आर.ओ.बी. का निर्माण
6.	गंगापुरसिटी-सवाई माधोपुर में आर.यू.बी. निर्माण हेतु डी.पी.आर.

30. प्रदेश के विभिन्न शहरों में ड्रेनेज, जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण सम्बन्धी विभिन्न विकास कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं, जो इस प्रकार हैं:-

I. कपिल सरोवर-कोलायत के जीर्णोद्धार, सौन्दर्यीकरण के कार्यों के साथ-साथ इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के जल उपलब्ध कराने का कार्य हाथ में लिया जाएगा। इस पर 20 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

II. सवाई माधोपुर शहर में कोतवाली के पास से राजबाग लटिया नाले के एक तरफ सुरक्षा दीवार मय सी.सी. सड़क निर्माण के साथ पार्क व वाकिंग ट्रेक का निर्माण करवाया जायेगा। साथ ही, हम्मीर सर्किल का सौन्दर्यीकरण किया जायेगा। इस पर 45 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

III. हिण्डौली-बूंदी की रामसागर झील का सौन्दर्यीकरण करते हुए साइकिल ट्रेक व पार्क का निर्माण करवाया जायेगा। इस हेतु 15 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।

IV. जोधपुर में क्रीड़ा संगम केन्द्र, गौशाला मैदान परिसर में वाक पथ

(श्री अशोक गहलोत)

एवं परिसर का 13 करोड़ 88 लाख रुपये की लागत से जीर्णोद्धार कार्य करवाया जायेगा।

V. बाड़मेर नगर परिषद् क्षेत्र में सीवरेज का कार्य करवाया जायेगा।

VI. बेगूं-चित्तौड़गढ़, सुजानगढ़-चूरू, मकराना, डीडवाना-नागौर तथा मुकुन्दगढ़-झुन्झुनूं में बारिश व गन्दे पानी की निकासी व ड्रेनेज सिस्टम हेतु DPR बनायी जायेगी।

पेयजल एवं भूजल:

31. आमजन को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु विभिन्न पेयजल योजनाओं के कार्य करवाये जायेंगे। ये लिस्ट बहुत लम्बी है, इसलिए मैं इन परियोजनाओं की सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-03 देखें)

32. मेरे द्वारा अपने पिछले कार्यकाल में वर्ष 2013-14 तथा अब वर्ष 2019-20 के बजट में बाड़मेर जिले के चौहटन, गुढ़ामालानी, धोरीमन्ना व सिणधरी के 889 गांवों तथा झुन्झुनूं जिले की उदयपुरवाटी एवं सूरजगढ़ के 921 गांवों व इनकी ढाणियों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु परियोजना लागू करने की घोषणा की गयी थी। हमने अब 4 हजार 765 करोड़ रुपये का JICA जापानी कम्पनी से ऋण लेते हुए वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। इस परियोजना की तकनीकी DPR अन्तिम चरण में है। शीघ्र ही तकनीकी स्वीकृति जारी कर आगामी वर्ष में प्राथमिकता से कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

33. वर्ष 2021-22 के बजट में कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना से सीकर जिले की तहसील धोद, सीकर, खण्डेला, दांतारामगढ़, श्रीमाधोपुर व नीम का थाना के शेष रहे 864 गांव व 13 कस्बों तथा झुन्झुनूं जिले की तहसील चिड़ावा, नवलगढ़ के 269 गांव एवं 5 कस्बों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की योजना प्रारम्भ करना प्रस्तावित किया गया था। इस परियोजना की नई BSR के अनुसार लगभग 8 हजार 780 करोड़ रुपये की संशोधित DPR अन्तिम चरण में है। जैसा मैंने पहले भी कहा था, इस परियोजना के लिये IGNP के साथ-साथ यमुना से जल उपलब्धता भी आवश्यक रहेगी, जिसके लिये हम केन्द्र सरकार के स्तर पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। आगामी वर्ष इस योजना का कार्य प्रारम्भ करने के लिये 500 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

34. मेरे द्वारा भादरा, नोहर तथा तारानगर के कुल 30 बारानी गांवों के लिये सिद्धमुख नहर व साहवा लिफ्ट कैनाल से सिंचित कर नहरी

(श्री अशोक गहलोत)

क्षेत्र में परिवर्तित करने के लिये Technical Assessment/सर्वे एवं Viability हेतु विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय कमेटी बनाये की बजट घोषणा की गयी थी। पूर्व में इस क्षेत्र में फिजिबिलिटी के कई बिन्दु सामने आये। अब विशेषज्ञों द्वारा Assess कर बतायी गयी Feasibility के आधार पर इन गांवों की सिंचाई के कार्य प्राथमिकता से हाथ में लिये जायेंगे। इस परियोजना के लिये आगामी वर्ष में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

35. समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से 31 दिसम्बर, 2021 तक के बकाया जल प्रभार शुल्क को 31 मार्च, 2022 तक एकमुश्त जमा कराये जाने पर ब्याज एवं शास्ति में शत-प्रतिशत छूट दिये जाने की घोषणा करता हूं।

36. राज्य में भू-जल के समुचित उपयोग तथा राज्य की औद्योगिक इकाइयों की सुविधा हेतु भू-जल संरक्षण एवं प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन किया जायेगा।

37. कठूमर-अलवर में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का नवीन अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय खोला जायेगा।

(समय: 18.00 बजे)

ऊर्जा

38. राज्य में विद्युत वितरण निगमों के फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिये, मैटेरियल मैनेजमेंट के लिये और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तथा अन्य कार्यों के लिए एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग (ERP) लागू करने की मैं घोषणा करता हूं। इस पर 75 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

39. ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य में वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु:-

I. शिव-बाड़मेर में 220 केवी जीएएस स्थापित किया जायेगा।

II. फुलवारा-भरतपुर व मुकाम-नोखा, दामोलाई (खाजूवाला)-बीकानेर में 132 केवी जीएसएस स्थापित किये जायेंगे।

III. सैंथली, पीपरोली (रामगढ़), सिलीबावड़ी (थानागाजी), सुरेर (राजगढ़)-अलवर व सालरिया (रानी)-पाली में 33 केवी जीएसएस स्थापित किये जायेंगे।

(श्री अशोक गहलोत)

IV. हाथोज-जयपुर, गडरा रोड (शिव), आडेल (गुढ़ामालानी)-बाड़मेर में सहायक अभियन्ता (विद्युत) व सिकराय-दौसा में अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत) के कार्यालय खोले जायेंगे।

40. राज्य में ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिये लगभग 2-2 करोड़ रुपये की लागत से प्रत्येक जिले में वन क्षेत्रों तथा समीप के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए एक-एक ईको-टूरिज्म लव-कुश वाटिका विकसित करने की घोषणा करता हूं। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर रखता हूं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-04 देखें।)

41. वर्ष 2021-22 के बजट में सीवरेज सुविधा से वंचित 50 शहरों में Faecal Sludge Treatment Plants (FSTP) स्थापित किये जाने की घोषणा की गयी थी, जिन पर तीव्र गति से कार्य प्रगतिरत है। इसी क्रम में आगामी वर्ष में 600 करोड़ रुपये की लागत से 68 शहरों में FSTPs स्थापना व सम्बन्धित कार्य किये जायेंगे। जो सूची मैं सदन के पटल पर रख रहा हूं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-05 देखें।)

42. जोधपुर के एमडीएम चिकित्सालय, उम्मेद चिकित्सालय व कमला नेहरु वक्ष एवं क्षय चिकित्सालय, उदयपुर के टीबी बड़ी चिकित्सालय, खेमराज कटारा चिकित्सालय व सुन्दर सिंह भण्डारी चिकित्सालय (अम्बा माता), अजमेर के जेएलएन चिकित्सालय व जनाना चिकित्सालय तथा झालावाड़ के एसआरजी चिकित्सालय में 27 करोड़ रुपये की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स स्थापित किये जायेंगे।

43. राज्य की ऐतिहासिक बावड़ियों में बूंदी जिले की अभयनाथ, नागर-सागर का कुण्ड, भावल्दी, मीरा गेट, मालनमासी, शुक्ल बावड़ी, बोहराजी का कुण्ड, मनोहर बावड़ी, क्लब बावड़ी, अनार कली की बावड़ी व पुलिस लाइन की बावड़ी, कोटा जिले की बड़गांव बावड़ी, खड़े गणेश जी, जयपुर जिले की पन्ना मीना का कुण्ड व गोनेर बावड़ी, दौसा जिले की झाझीरामपुरा, भद्रावती-भाण्डारेज तथा टोंक जिले की टोडारायसिंह की बावड़ियों का 20 करोड़ रुपये की लागत से पुनरुद्धार किया जायेगा।

44. राणा हम्मीर की स्मृति में सवाई माधोपुर में राणा हम्मीर पेनोरमा, अदम्य साहस व स्वाभिमान के धनी दुर्गादास राठौड़ की स्मृति में जोधपुर में वीर दुर्गादास पेनोरमा तथा गोविन्द गुरू की कर्म स्थली छाणी मगरी-डूंगरपुर में पेनोरमा के निर्माण कार्य कराये जायेंगे। इन पर 12 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।

(श्री अशोक गहलोत)

45. नई दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस राजस्थान की कला एवं संस्कृति के फेस के रूप में स्थापित हैं। विशेषकर इसकी आर्ट गैलेरी का अपना विशेष महत्व है। इसकी विरासत को दृष्टिगत रखते हुए 15 करोड़ रुपये की लागत से बीकानेर हाउस के उन्नयन एवं विकास के कार्य करवाये जायेंगे।

46. ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा करने वाले एवं गोवर्धन जी जाने वाले श्रद्धालुओं हेतु यात्री विश्राम स्थलियों सहित अन्य आधारभूत सुविधाएं विकसित की जायेंगी। साथ ही, डीग महल-भरतपुर में लाइट एवं साउंड शो की व्यवस्था की जायेगी।

47. मेरे द्वारा वर्ष 2021-22 में धार्मिक नगरी, पुष्कर के पवित्र सरोवर में बारिश के पानी के साथ गन्दगी को जाने से रोकने सम्बन्धी विभिन्न कार्यों हेतु डीपीआर बनाये जाने की घोषणा की गयी थी। जिसके तहत प्रथम चरण में लगभग 11 करोड़ रुपये की लागत से वराह घाट चौक, ब्रह्म चौक होते हुए सन्तोषी माता ढाणी स्थित Sump तक Drain का कार्य किया जायेगा।

48. जयपुर की विश्व विरासत-चारदीवारी क्षेत्र की हवेलियों, भवनों आदि के संरक्षण, रखरखाव एवं प्रबन्धन कार्य हेतु जयपुर हैरिटेज फंड बनाया जाकर आगामी वर्ष 10 करोड़ रुपये के कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं।

49. खण्डेला-सीकर में छोटा पाना एवं बड़ा पाना की छतरियां, चारोड़ा धाम तालाब परिसर, गोपीनाथ मंदिर व टिनगरिया हनुमान मन्दिर के संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण के कार्य करवाये जायेंगे।

50. कैला देवी जी मन्दिर, झील का बाड़ा (बयाना)-भरतपुर के मन्दिर परिसर एवं तालाब के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण के कार्य करवाये जायेंगे। साथ ही, भैरव जी मन्दिर-बांसवाड़ा व गोरेश्वर मन्दिर के जीर्णोद्धार व विकास कार्य भी करवाये जायेंगे। इन पर 20 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

51. विज्ञान को Night Sky Astro Tourism के माध्यम से आम जन से जोड़ने एवं इसके प्रचार हेतु राज्य के समस्त जिलों एवं जयपुर में प्रमुख 4 पर्यटक स्थलों, पार्कों एवं बीकानेर हाउस, नई दिल्ली में उच्च स्तरीय रिज्योल्यूशन के टेलिस्कोप स्थापित किये जायेंगे।

52. सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर में सुविधाओं का विस्तार करते हुए आधारभूत संरचना के विकास के साथ-साथ नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधी नगर, गुजरात का आफ कैम्पस खोला जायेगा।

(श्री अशोक गहलोत)

53. प्रदेश की कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु-

I. कैला देवी (सपोटरा)-करौली व विराटनगर-जयपुर में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोले जायेंगे।

II. बगड़ तिराया (रामगढ़)-अलवर, जसोल (पचपदरा)-बाड़मेर, सिरोही सदर-सिरोही, अलसीसर (मण्डावा), मेहाड़ा (खेतड़ी)-झुंझुनूं, माधोराजपुरा (चाकसू)-जयपुर, मामचारी (सपोटरा)-करौली एवं नासिरदा (देवली)-टोंक में नवीन पुलिस थाने खोले जायेंगे।

III. टिमेड़ा बड़ा (कुशलगढ़)-बांसवाड़ा, पीह (परबतसर)-नागौर, छाण (खण्डार)-सवाई माधोपुर, मिथोद (पीपल्दा)-कोटा व सेवर (बाड़ी)-धौलपुर में नवीन पुलिस चौकी खोली जायेंगी।

54. प्रदेश के नगरपालिका मुख्यालयों पर स्थित 150 पुलिस थानों में से 108 सीआई स्तर के पुलिस थाने हैं। आगामी वर्ष शेष रहे एसआई स्तर के 42 पुलिस थानों को भी सीआई स्तर के थानों में क्रमोन्नत किया जायेगा।

55. आम जनता को सुगम व त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के लिए आगामी वर्ष में-

I. चौहटन-बाड़मेर व घड़साना-श्रीगंगानगर में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जायेंगे।

II. नागौर में विशेष न्यायालय (पोक्सो एक्ट) खोला जायेगा।

III. ओसियां-जोधपुर में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।

IV. सीकर में एन.आई. एक्ट न्यायालय खोला जायेगा।

V. धोद-सीकर, मसूदा-अजमेर, पीपलू-टोंक, सरमथुरा-धौलपुर, बिलाड़ा-जोधपुर व सलूम्बर-उदयपुर में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जायेंगे।

56. आज प्रदेश में, आम जन को ई-मित्र के माध्यम से घर के नजदीक 500 से अधिक सेवाएं उपलब्ध करवायी जा रही हैं। इसमें विस्तार करते हुए निजी क्षेत्र की लगभग 200 अन्य जन उपयोगी सेवाएं यथा ई-कामर्स, ई-शिक्षा, कृषि क्षेत्र एवं चिकित्सा परामर्श आदि भी ई-मित्र के माध्यम से उपलब्ध करवायी जायेंगी।

(श्री अशोक गहलोत)

57. 01 जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हुए राजकीय कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर देय ग्रेच्युटी एवं अवकाशों के बदले नकद भुगतान की गणना उनके सेवानिवृत्ति के समय महंगाई भत्ते की प्रभावी दर से किया जाना प्रस्तावित करता हूं। इस पर लगभग 400 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आयेगा।

58. पिछली सरकार ने 5 अक्टूबर, 2018 को आदेश जारी कर कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल की अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में ही स्वीकृत कर उक्त अवधि को Qualifying Service हेतु अमान्य करने का निर्णय लिया था। अब मैं, कार्मिक हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसे स्वीकृत असाधारण अवकाश की अवधि को Qualifying Service के रूप में मान्यता दिया जाना प्रस्तावित करता हूं।

59. महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) के अन्तर्गत नकद लाभ उनकी स्क्रीनिंग की तिथि से देय था। इन संस्थानों के शिक्षकों की मांग को देखते हुए 01 जनवरी, 2018 एवं इसके पश्चात् देय सीएएस पदोन्नति का लाभ पात्रता की तिथि से नकद दिया जाना प्रस्तावित है।

60. प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु-

I. देचू (लोहावट)-जोधपुर व जोबनेर-जयपुर में नवीन उपखण्ड कार्यालय खोले जाने प्रस्तावित हैं।

II. फागी-जयपुर में राजस्व अपील अधिकारी (कैम्प कोर्ट) न्यायालय खोला जायेगा।

III. निर्झरना (लालसोट)-दौसा, डेह (जायल)-नागौर, तलावड़ा (गंगापुर सिटी), बरनाला (बामनवास)- सवाई माधोपुर, धोद, पाटन (नीमकाथाना)-सीकर व झल्लारा-उदयपुर उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत किया जायेगा।

IV. मिर्जापुर (अन्ता)-बारां, पांचू (नोखा), दन्तोर (खाजूवाला), जसरासर (नोखा)-बीकानेर, सुवाणा, टोंकरवाड़-भीलवाड़ा, हमीरवास बड़ा (राजगढ़)-चूरू, पिलानी-झुंझुनूं व धुंवाकलां (देवली)-टोंक में उप तहसील खोली जायेंगी।

V. मुझे माननीय सदस्यों, जन प्रतिनिधियों एवं जन सामान्य से समय-समय पर नये जिले बनाने के सम्बन्ध में ज्ञापन प्राप्त होते रहे हैं। ऐसे मांग पत्रों के साथ-साथ गुणावगुण के आधार पर आवश्यकता का आकलन कर

(श्री अशोक गहलोत)

नये जिलों के लिये 6 माह में अभिशंसा देने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन प्रस्तावित करता हूं।

61. प्रदेश में हम्मीरगढ़-भीलवाड़ा, रानीवाड़ा-जालौर, मनोहरपुर-जयपुर, बालेसर-जोधपुर एवं गुढ़ा (उदयपुरवाटी)-झुंझुनूं, सेमारी (खेरवाड़ा)-उदयपुर को नगरपालिका बनाया जायेगा। साथ ही, पोकरण-जैसलमेर नगरपालिका को चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में क्रमोन्नत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, बगड़ी (सोजत)-पाली को पंचायत समिति बनाया जायेगा।

62. राज्य के विभिन्न सेवा संवर्गों यथा पुलिस कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल, जेल प्रहरी, होम गार्ड के आरक्षी, नर्सिंग स्टाफ, आबकारी विभाग के कार्मिकों को देय मैस भत्ते की राशि में 01 अप्रैल, 2022 से 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

63. प्रदेश में गत 2 वर्षों में कोविड-19 के कारण राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा अनेक निर्वाचन योग्य सहकारी समितियों के चुनाव नहीं कराये जा सके हैं। आगामी वर्ष में ऐसी सभी निर्वाचन योग्य सहकारी समितियों में चरणबद्ध रूप से चुनाव सम्पन्न कराये जायेंगे।

64. प्रदेश में तिजारा-अलवर, शाहबाद-बारां, गुढ़ामालानी-बाड़मेर एवं सवाईमाधोपुर में कृषि महाविद्यालय खोले जायेंगे। साथ ही, जोबनेर-जयपुर, कुशलगढ़-बांसवाड़ा व श्रीडूंगरगढ़-बीकानेर में सहायक निदेशक (कृषि विस्तार) के कार्यालय खोले जायेंगे।

65. जैविक उत्पादों एवं जैविक सब्जियों के उत्पादन एवं विक्रय को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कृषकों द्वारा उत्पादित जैविक उत्पाद एवं अन्य कृषि जिंसों को क्रय कर कानफैड व सहकारी उपभोक्ता भण्डार के डिपार्टमेंटल स्टोर, डी-मार्ट स्टोर, रिलायन्स स्टोर, मेट्रो स्टोर आदि ग्रोसरी स्टोर पर विक्रय कराने की व्यवस्था की जायेगी।

66. खरपतवार वृद्धि की रोकथाम एवं फसलों की कतारों के बीच मृदा की नमी को बनाये रखने के लिए 10 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में प्लास्टिक मल्चिंग लगायी जायेगी।

67. आगामी वर्ष में महात्मा गांधी नरेगा के तहत पंचशाला योजना के अन्तर्गत पौधशाला, कार्यशाला, निर्माणशाला, पशुशाला व पोषणशाला के 50 हजार से अधिक कार्य किये जायेंगे।

(श्री अशोक गहलोत)

68. किसानों की मांग के अनुसार पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से आगामी वर्ष में 2 लाख मैट्रिक टन यूरिया एवं 1 लाख मैट्रिक टन डीएपी का अग्रिम भण्डारण किया जायेगा। इस पर 20 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

69. गीजगढ़-दौसा व रेलमगरा-राजसमन्द में कृषि उपज मण्डी खोली जायेगी। साथ ही, छतरगढ़ (खाजूवाला)-बीकानेर की गौण मण्डी को कृषि उपज मण्डी घोषित किया जायेगा।

70. परेऊ (गिड़ा)-बाड़मेर में पशु चिकित्सालय खोला जायेगा। पदमपुरा, चिड़ासन (चिड़ावा)-झुंझुनूं व आसपुर (नावां)-नागौर में पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे।

71. वेटेरिनरी शिक्षा में अधिक से अधिक छात्र प्रभावित होकर जुड़ सकें इस दृष्टि से वर्तमान में देय स्टाइपेंड 3,500 रुपये को बढ़ाकर 14,000 रुपये किये जाने की मैं घोषणा करता हूं।

72. वर्ष 1954-55 में निर्मित माधोपुर व्यास लिंक तथा माधोपुर व्यास क्रीक की विशेष रिपेयर का कार्य पंजाब सरकार के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है। इससे रावी ब्यास का अतिरिक्त पानी स्थापित क्षमता 10 हजार क्यूसेक के अनुसार इन्दिरा गांधी नहर फीडर के माध्यम से प्रदेश को प्राप्त हो सकेगा।

73. चम्बल-पांचना-जगर लिफ्ट परियोजना का कार्य हाथ में लिया जायेगा।

74. सवाई माधोपुर मुख्यालय पर नाले पर एनिकट रवांजना डूंगर का निर्माण किया जायेगा।

75. सादुलशहर-श्रीगंगानगर में पक्के खालों का निर्माण किया जायेगा।

76. डूंगरपुर में अपर घोड़ी तालाब की दायीं एवं बायीं नहरों की मरम्मत एवं अधूरी नहरों का निर्माण कार्य करवाया जायेगा।

77. दुल्हेपुरा (खण्डेला)-सीकर में डब्ल्यूएचएस के निर्माण कार्य हाथ में लिये जायेंगे।

78. जनजाति क्षेत्र के कृषकों के लिए सौर ऊर्जा आधारित सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना के माध्यम से 50 लिफ्ट सिंचाई योजनाओं से लगभग 1,500 हैक्टेयर भूमि पर 20 करोड़ रुपये की लागत से सिंचाई सुविधा विकसित की जायेगी। धन्यवाद।

(श्री अशोक गहलोत)

79. माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय सदस्यों को मैं पुन: विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जो भी सुझाव आपने दिये हैं वो और साथ में नेता प्रतिपक्ष महोदय ने जो बातें कही हैं, मैं समझता हूं कि पूरा अध्ययन करके हम लोग सीरियसली, क्या-क्या होना सम्भव है, वह पूरा करेंगे और आप निश्चिंत रहें। बजट की घोषणाएं, पैसा कहां से आयेगा, आप जानते हो कि कहां से आयेगा, आयेगा, रेवेन्यू राजस्थान की बढ़ेगी, केन्द्र देगा, सब करेंगे और काम चलायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अच्छा बजट पेश किया है, अच्छे ढंग से लागू करेंगे। आप सबकी दुआएं, शुभकामनाएं मेरे साथ रहेंगी तब लागू हो पायेगा।

ताली तो बजा दो। कुछ तो करो।

इन्हीं शब्दों के साथ में, माननीय अध्यक्ष महोदय, तमाम सदस्यों का मैं बहुत अधिक धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 04 मार्च 2022 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18:14 बजे शुक्रवार, दिनांक 04 मार्च 2022 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गयी)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

वृहद सिंचाई परियोजना से गांवों में सिंचाई सुविधा

150. श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कोटा संभाग में बहने वाली कालीसिंध व परवन दो प्रमुख नदियां है? यदि हां, तो उक्त की प्रदेश में कुल लम्बाई कितनी है तथा उक्त नदियां हाड़ौती के किस-किस जिले में होकर बहती हैं ? उक्त जिलों में इनकी लम्बाई कितनी है?

(2) क्या यह सही है कि परवन वृहद सिंचाई परियोजना से विधान सभा क्षेत्र सांगोद की तहसील कनवास के गांवों को सिंचाई व पेयजल हेतु पानी देने की योजना कालीसिंध नदी से नहीं बनाकर परवन नदी से पानी कालीसिंध नदी में डालने की योजना बनाई गई है? यदि हां, तो उक्त पर कुल कितनी राशि व्यय होगी? क्या उक्त कार्य प्रारंभ हो गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त पानी कालीसिंध नदी पर बने भंवरासा बांध के द्विवतीय चरण से प्राप्त नहीं किया जा सकता है? यदि हां, तो परवन नदी से कालीसिंध नदी में पानी लाने की क्या आवश्यकता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कोटा संभाग के अन्तर्गत बहने वाली कालीसिंध एवं परवन, प्रमुख नदियों में से हैं। कालीसिंध नदी की राज्य में कुल लंबाई 171 किमी है जो झालावाड़ जिले में 85 कि.मी. एवं कोटा जिले में 86 कि.मी. लंबाई में प्रवाहित है। परवन नदी की राज्य में कुल लंबाई 161 किमी है। यह झालावाड़ जिले में 61 कि.मी. एवं बारां जिले में 100 कि.मी. लंबाई में प्रवाहित होती है।

(2) जी हां। परवन वृहद सिंचाई परियोजना की नहर प्रणाली के द्विवतीय चरण अन्तर्गत सांगोद विधान सभा क्षेत्र की कनवास तहसील के 46 गांवों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाये जाने हेतु बायीं मुख्य नहर से कालीसिंध नदी को जोड़कर सिंचाई तंत्र विकसित किया जा रहा है, जिस पर (परवन नहर द्विवतीय चरण) राशि रुपये 781 करोड़ व्यय किया जाना

(जल संसाधन मंत्री)

प्रस्तावित है। परवन सिंचाई परियोजना से नहर प्रणाली के द्वितीय चरण का कार्य प्रारम्भ कर अब तक राशि रुपये 355.23 करोड़ का व्यय किया गया है।

(3) वर्तमान में कालीसिंध नदी पर निर्मित भंवरासा (कालीसिंध) बांध के द्वितीय चरण की परियोजना स्वीकृत नहीं है एवं इस पर भंवरासा बांध के प्रस्तावित द्वितीय चरण में पानी उपलब्धतानुसार झालावाड़ तथा कोटा जिले के 18,518 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई तंत्र विकसित किया जाना प्रस्तावित है जो परवन परियोजना के अन्तर्गत विकसित किये जा रहे कमाण्ड क्षेत्र से पृथक/अतिरिक्त है।

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

जमवारामगढ़ बांध को चंबल नदी से जोड़ने की कार्ययोजना

161. श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार की प्रदेश में नदियों को जोड़ने की कार्ययोजना है? यदि हां, तो उक्त योजना पर अब तक कितना कार्य हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जमवारामगढ़ बांध को चंबल नदी या मेज नदी से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में नदियों को जोड़ने के अन्तर्गत आधिक्य जल उपलब्धता वाले बेसिनों से कम जल उपलब्धता वाले बेसिनों में पानी हस्तानान्तरण करने के अन्तर्गत दो प्रस्तावित परियोजनाएं क्रमश: "पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना" तथा "साबरमती के अधिशेष जल को जवाई बांध पुर्नभरण योजना" अन्तर्गत कार्य हाथ में लिये गये हैं। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना अन्तर्गत नौनेरा (नवनेरा) बैराज का निर्माण कार्य स्वीकृत कर कार्य पर राशि रुपये 615.90 करोड का व्यय किया जा चुका है तथा मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2022-23 अंतर्गत नवनेरा-बीसलपुर-ईसरदा लिंक, महलपुर-बैराज एवं रामगढ़ बैराज हेतु राशि रुपये 9,600 करोड के कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं। कार्य को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से करने हेतु पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम गठित किया जाना प्रस्तावित है।

साबरमती बेसिन के अधिशेष जल को जवाई बांध पुनर्भरण हेतु उपयोग में लिये जाने की पी.एफ.आर. केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली के पास अन्तरराज्जीय परिप्रेक्ष्य में स्वीकृति हेतु लम्बित है। सिरोही एवं पाली जिले में पेयजल उपलब्ध करवाये जाने हेतु मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2022-23 अन्तर्गत कोटड़ा तहसील में दो बांधों का निर्माण राशि रुपये 1,800 करोड़ तथा इन बांधों से पाइप लाइन द्वारा जवाई बांध में पानी लाये जाने हेतु राशि रुपये 1,200 करोड के कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं।

(2) "पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना" के अन्तर्गत चंबल नदी की

(जल संसाधन मंत्री)

सहायक नदियों यथा कुन्नु, कुल, पार्वती, कालीसिंध, मेज में उपलब्ध अधिशेष जल को कम जल उपलब्धता वाले बेसिनों में अपवर्तित करने के अन्तर्गत उक्त परियोजना की डीपीआर में तृतीय चरण में रामगढ़ बांध को भरने का प्रावधान लिया गया है। उक्त परियोजना की डी.पी.आर. वर्तमान में केन्द्रीय जल आयोग में परीक्षणाधीन है। स्वीकृति एवं संसाधनों की उपलब्धतानुसार कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

किसानों के सहकारी ऋण माफ करने की कार्ययोजना

162. श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2018-19 में पूर्ववर्ती सरकार ने सहकारी बैंकों का 50 हजार तक का ऋण माफ करने की घोषणा एवं उनके माफ करने के प्रमाण पत्र किसानों को सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर से दे दिए थे एवं नये ऋण के लिए भी उक्त किसानों को योग्य मानते हुए उनको नया ऋण भी उपलब्ध करा दिया था? यदि हां, तो उनकी जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने अपने 3 वर्ष की वर्षगांठ पर 21 लाख किसानों का 15 हजार करोड़ रुपये का ऋण माफ करना बताया है? यदि हां, तो दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 से 17 दिसम्बर, 2021 तक जो ऋण माफ किया गया है, उसका जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जन-घोषणा पत्र के अनुसार 10 दिनों में ऋण माफ करने की घोषणा की पूर्णत: पालना हो गयी? यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में कितना ऋण माफ किया गया व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। 17 दिसम्बर, 2018 से लेकर 17 दिसम्बर, 2021 तक सहकारी बैंकों द्वारा की गई ऋण माफी का विवरण निम्नानुसार है:-

विवरण	**लाभान्वित कृषकों की संख्या**	**प्रदत्त माफी राशि (करोड़ में)**
राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना-2019	21,05,210	8,185.98

(सहकारिता मंत्री)

जिलेवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

राजस्थान फसली ऋण माफी योजना-2018 अंतर्गत 17 दिसम्बर, 2021 तक सहकारी बैंकों द्वारा राशि रुपये 7,568.39 करोड़ ऋण माफी की गई है। गत सरकार द्वारा राजस्थान फसली ऋण माफी योजना-2018 पेटे रुपये 2,000.00 करोड़ सहकारी बैंकों को उपलब्ध करवाये गये थे। शेष रही ऋण माफी राशि रुपये 5,568.39 करोड़ के लिए एनसीडीसी से जो ऋण लिया गया उसका चुकारा वर्तमान सरकार द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त एनसीडीसी को ब्याज की राशि 765.40 करोड़ तथा केन्द्रीय सहकारी बैंकों को समय पर ऋण माफी राशि पुनर्भरण में हुए विलम्ब अवधि हेतु 8 प्रतिशत की दर से ब्याज की राशि 611.83 करोड़ का चुकारा भी वर्तमान सरकार द्वारा किया गया।

इस प्रकार वर्तमान सरकार द्वारा कृषकों को ऋण माफी के रूप में राशि रुपये 15,131.60 करोड़ वहन की गई है।

(3) चुनाव घोषणा पत्र के अनुसार 10 दिनों में ऋण माफ करने की घोषणा के क्रम में सहकारी बैंकों के माध्यम से राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना-2019 अंतर्गत दिनांक 18.02.2022 तक प्रदत्त माफी का विवरण निम्न प्रकार है-

विवरण	**प्रदत्त माफी**	
	लाभान्वित कृषकों की संख्या	**प्रदत्त माफी राशि (करोड़ में)**
राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना-2019	21,06,043	8,193.72

राज्य सरकार द्वारा वाणिज्यिक बैंकों, अनुसूचित बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कृषकों के ऋणों की माफी हेतु Recommendation देने के लिए एक समन्वय समिति दिनांक 10.03.2019 को गठित की गई। उक्त कमेटी की बैठक दिनांक 27.03.2019 तथा दिनांक 08.08.2019 को आहूत की गई। बैठक में बाद चर्चा वाणिज्यिक बैंकों में ऋण माफी बाबत एक कन्सेप्ट पेपर तैयार कर सभी बैंकर्स को उपलब्ध कराया गया। कन्सेप्ट पेपर के अनुरूप सभी बैंकर्स के समन्वय से ऋण माफी योजना पर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में अन्य बैंकों हेतु राज्य सरकार द्वारा ओटीएस योजना के तहत ऋण माफी के प्रस्ताव दिनांक 09.11.2021 को वाणिज्यिक बैंकों, अनुसूचित

(सहकारिता मंत्री)

बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कारपोरेट कार्यालयों को भिजवाया गया तथा दिनांक 27.12.2021 को माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने एसएलबीसी की बैठक में सभी बैंकों से एसबीआई की ओटीएस योजना 90:10 के अनुरूप सरकार की ओर से प्रेषित प्रस्तावों को लागू करने का आग्रह किया। साथ ही माननीय मुख्य मंत्री राजस्थान ने प्रधान मंत्री, भारत सरकार को दिनांक 27.12.2021 को पत्र लिखकर कर्ज माफी में राज्य सरकार को सहयोग करने व राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को निर्देशित करने का अनुरोध किया। केन्द्र सरकार से सहयोग अपेक्षित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

रानीवाड़ा में ओलावृष्टि से प्रभावितों को मुआवजा

163. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि 7 जनवरी, 2022 से 27 जनवरी, 2022 तक प्रदेश के कई जिलों में ओलावृष्टि, अतिवृष्टि के कारण किसानों की अरबों रुपयों की फसलों को नुकसान हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार प्रभावित जिलों के किसानों का सर्वे, गिरदावरी करवाकर उनको उचित मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना व कब तक तथा नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की पंचायत समिति रानीवाड़ा व सरनाऊ के कई गांवों में ओलावृष्टि एवं बेमौसम बरसात से किसानों की जीरा, ईसबगोल, रायड़ा, अरण्डी, अनार आदि फसलों को नुकसान हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांवों में गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? कारण सहित सदन को अवगत करावें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 28.12.2021 एवं 10.01.2022 को ओलावृष्टि, पाला एवं शीतलहर से फसल खराबे की विशेष गिरदावरी करवाने के आदेश जारी किये गये हैं। विशेष गिरदावरी रिपोर्ट में 03 जिलों भरतपुर, जोधपुर एवं झालावाड़ में 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबे की सूचना प्राप्त हुई है।

(आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री)

33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराब होने पर राज्य आपदा मोचन निधि के नोर्म्स के अनुसार कृषि आदान-अनुदान का भुगतान करने का प्रावधान है।

भरतपुर एवं जोधपुर जिले के प्रभावित कृषकों को कृषि आदान-अनुदान भुगतान करने हेतु दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं तथा झालावाड़ जिले की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में रबी फसल की गिरदावरी का कार्य प्रक्रियाधीन है। जिलों से रिपोर्ट प्राप्त होने पर एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार कार्यवाही की जायेगी। एसडीआरएफ नोर्म्स की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जालौर जिले की किसी भी तहसील में ओलावृष्टि नही हुई है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

कठूमर में बसों का संचालन

164. श्री बाबूलाल (कठूमर): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार कठूमर-लक्ष्मणगढ़ मार्ग पर पुन: बसें संचालित करने का विचार रखती है?

(2) क्या सरकार पूर्व में संचालित महुवा से नगर वाया कठूमर तथा महुवा से लक्ष्मणगढ़ वाया कठूमर, मण्डावर से कठूमर वाया रोनीजा वाया भनोकर बसों को पुन: चलाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कठूमर-लक्ष्मणगढ़ मार्ग पर वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की संचालित बसों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**आगार**	**मार्ग मय वाया**	**समय**
1	अलवर	अलवर-भरतपुर वाया लक्ष्मणगढ़, कठूमर	13.40
2	भरतपुर	भरतपुर-अलवर वाया कठूमर	08.00
3	भरतपुर	अलवर-भरतपुर वाया कठूमर	15.00

निगम के सीमित संसाधनों के कारण वर्तमान में उक्त मार्ग पर संचालित निगम बसों के अतिरिक्त बसों का संचालन करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(राज्य मंत्री, परिवहन)

(2) महुवा से नगर वाया कठूमर मार्ग पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की 28 बसें संचालित हैं जिनका विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

महुवा से लक्ष्मणगढ़ वाया कठूमर, मण्डावर से कठूमर वाया रोनीजा, वाया भनोकर मार्ग पर निगम के सीमित संसाधनों के कारण निगम बसों का संचालन करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

उदयपुर में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के लाभार्थी

165. श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला उदयपुर में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में कुल कितने शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है? वर्ष 2018 से अब तक कितने बेरोजगारों ने नवीनीकरण करवाया व कितने प्रतीक्षा सूची में हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सलूम्बर, सराड़ा, जयसमंद, सेमारी व झल्लारा पंचायत समिति में कई बेरोजगारों को पंजीयन होने के उपरांत भी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार जन-घोषणा पत्र के अनुसार प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला उदयपुर में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में वर्तमान में कुल 3,722 शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। वर्ष 2018 से 31 दिसम्बर, 2021 तक 1,823 बेरोजगारों ने नवीनीकरण करवाया है। वर्तमान में कोई आवेदन प्रतीक्षा सूची में नहीं है। नवीन मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 मे 01 जनवरी, 2022 से नवीनीकरण की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है।

(2) जी हां। पंजीकृत सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाता, अपितु स्नातक उत्तीर्ण पात्र बेरोजगार आवेदकों को ही नियमानुसार बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सलूम्बर, सराड़ा,

(राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता)

जयसमंद, सेमारी व झल्लारा पंचायत समिति में स्नातक उत्तीर्ण पात्र बेरोजगार आवेदकों को भी नियमानुसार बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजनान्तर्गत स्नातक उत्तीर्ण एवं योजना की पात्रता रखने वाले एक समय में अधिकतम 2 लाख की सीमा तक आशार्थियों को नियमित रूप से बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। विभिन्न कारणों से बेरोजगारी भत्ता बन्द किये जाने पर लाभान्वितों की अधिकतम सीमा तथा लाभ प्राप्त कर रहे लाभान्वितों के अन्तर को शेष रहे वैरिफाई किये जा चुके आवेदनों में से वरीयता के आधार पर स्वीकृत किया जा रहा है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

(3) जी हां। राज्य सरकार के जन-घोषणा पत्र के बिन्दु संख्या 10.1 के अनुसार प्रदेश के जिला रोजगार कार्यालयों मे पंजीकृत पात्र स्नातक योग्यताधारी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नियमित रूप से दिया जा रहा है। जन घोषणा पत्र की पालना मे मुख्यमंत्री युवा संबल योजना-2019 को 1 फरवरी, 2019 से प्रारम्भ किया गया। योजनान्तर्गत स्नातक उत्तीर्ण पात्र बेरोजगार पुरुष आशार्थी को 3,000 रुपये प्रतिमाह व महिला, निःशक्तजन व ट्रांसजेण्डर आशार्थी को 3,500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया गया है। योजना में लाभान्वितों की अधिकतम संख्या एक समय मे 1,60,000 निर्धारित की गई थी।

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना-2019 को और बेहतर बनाकर रोजगारपरक बनाने हेतु कौशल प्रशिक्षण व इन्टर्नशिप से जोड़ा गया है। योजनान्तर्गत 1 जनवरी, 2022 से पुरुष आशार्थी को 4,000 रुपये प्रतिमाह व महिला, निःशक्तजन व ट्रांसजेण्डर श्रेणी के आशार्थी को 4,500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। नवीन योजना में लाभान्वितों की अधिकतम संख्या बढ़ाकर एक समय में 2 लाख कर दी गई है।

सुजानगढ़ के गांवों में थ्री फेज बिजली

166. श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा गांवों में सिंगल फेज लाइन को थ्री फेज में बदलने की कोई कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पंचायत मुख्यालयों को सिंगल फेज से थ्री फेज में बदलने

(श्री मनोज कुमार)

का कोई नियम निर्धारित है? यदि हां, तो थ्री फेज से वंचित पंचायत मुख्यालयों को कब तक सिंगल फेज से थ्री फेज में बदल दिया जायेगा?

(3) विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में कितनी ग्राम पंचायतें थ्री फेज बिजली विहीन हैं? उक्त में सरकार द्वारा कब तक थ्री फेज बिजली उपलब्ध करवा दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विभाग द्वारा गांवों में सिंगल फेज लाइन को थ्री फेज में बदलने के कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं। गांवों में थ्री फेज कनेक्शन हेतु आवेदन प्राप्त होने एवं तकनीकी आवश्यकता होने पर सिंगल फेज लाइन को थ्री फेज लाइन में बदलने की कार्यवाही की जाती है।

(2) जी नहीं।

(3) विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में कोई भी ग्राम पंचायत थ्री फेज विद्युत लाइन से वंचित नहीं है।

मालपुरा में स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना

167. श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय संचालित नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां व कब तक तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में संचालित राजकीय महाविद्यालयों में अधिकांश कार्मिकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? रिक्त पदों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में राजकीय क्षेत्र के 02 महाविद्यालय क्रमश: राजकीय महाविद्यालय, मालपुरा एवं राजकीय महाविद्यालय, टोडारायसिंह स्नातक स्तर पर संचालित हैं। वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के राजकीय महाविद्यालय, मालपुरा एवं राजकीय

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

महाविद्यालय, टोडारायसिंह को स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत करने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के राजकीय महाविद्यालय, मालपुरा एवं राजकीय महाविद्यालय, टोडारायसिंह में शैक्षणिक व अशैक्षणिक वर्ग के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण क्रमशः परिशिष्ट-01 व 02 पर संलग्न है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा सहायक आचार्यों के 918 रिक्त पदों को भरने हेतु दिनांक 22.09.2021 से दिनांक 09.10.2021 तक लिखित परीक्षा आयोजित की जा चुकी है।

उक्त महाविद्यालय में रिक्त पदों को पदोन्नति/चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर/स्थानान्तरण/अनुकम्पात्मक नियुक्ति से भरा जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ब्यावर में यातायात थाने की स्थापना

134. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए यातायात पुलिस थाना खोले जाने के प्रावधान किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला अजमेर मे किन-किन स्थानों पर यातायात पुलिस थाना स्थापित है एवं कितना-कितना स्टाफ कार्यरत है तथा ब्यावर यातायात पुलिस में कितना स्टाफ कार्यरत है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ब्यावर में बिगड़ती यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए एक यातायात पुलिस थाना खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रदेश में यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए पुलिस में यातायात शाखाएं कार्यरत हैं।

(2) अजमेर जिले में यातायात पुलिस थाना स्थापित नहीं है। यातायात व्यवस्था हेतु अजमेर में अजमेर शहर, ब्यावर, किशनगढ़, पुष्कर, नसीराबाद में यातायात शाखा खुली हुई हैं जिनमें कार्यरत स्टाफ निम्नानुसार है:-

क्रं स	स्थान	पुलिस निरीक्षक	उप निरीक्षक	सहा. उप निरीक्षक	हैड कानि.	कानि.	योग
1	अजमेर	01	01	04	25	131	158
2	ब्यावर	00	00	00	02	05	07
3	किशनगढ़	00	01	00	02	08	11
4	पुष्कर	00	00	00	02	06	08
5	नसीराबाद	00	00	00	01	02	03

(3) ब्यावर में कार्यरत यातायात शाखा द्वारा यातायात व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाया जा रहा है। इस कारण ब्यावर में यातायात पुलिस थाना खोला जाना विचाराधीन नहीं है।

चूरू के विद्यालयों के नवीन भवन

135. श्री नरेन्द्र बुड़ानिया (तारानगर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला चूरू में कितने ऐसे राजकीय उप्रावि, मावि व उमावि हैं जिनमें कक्षा-कक्षों की कमी है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र तारानगर में कितने ऐसे विद्यालय हैं जिनका सम्पूर्ण भवन क्षतिग्रस्त है? क्या सरकार उक्त भवनों का नव निर्माण करवाने की योजना रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

(3) विगत तीन वर्षों में जिला चूरू में कितने ऐसे विद्यालय हैं जिनके सम्पूर्ण भवन का निर्माण हुआ है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला चूरू के 135-राजकीय विद्यालयों में कक्षा-कक्षों की कमी है। विद्यालयवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र तारानगर में कोई भी विद्यालय भवन सम्पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त नहीं है।

(3) विगत तीन वर्षों में जिला चूरू में एक विद्यालय (राजकीय प्रवेशिका संस्कृत स्कूल, न्यामा) में समग्र शिक्षा अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में सम्पूर्ण भवन का निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ है। यह निर्माण कार्य वर्तमान में प्रगतिरत है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी।)

अनूपगढ़ में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय

136. श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूल खोले जाने की कार्ययोजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के रावला, 365 हेड, नाहरांवाली व रामसिंहपुर में भी अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूल खोले जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के

(शिक्षा मंत्री)

बिन्दु संख्या 26 के अनुसार अंग्रेजी माध्यम के राजकीय विद्यालयों की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए 5 हजार से अधिक आबादी वाले गांवों एवं कस्बों में अगले 2 वर्षों में अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय प्रारम्भ किये जा रहे हैं। इन स्कूलों की लोकप्रियता एवं इनमें प्रवेश हेतु अभिभावकों एवं विद्यार्थियों की मांग को देखते हुए आगामी वर्ष में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भी महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल और शुरू किये जाएंगे।

उक्त की पालना में विभाग को प्राप्त अन्य प्रस्तावों के साथ उक्त क्षेत्र के प्रस्ताव प्राप्त होने पर समग्र स्थिति का गुणावगुण के आधार पर आकलन किया जाकर उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों के तहत अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जा सकेंगे।

बगरू नगरपालिका में सीवर लाइन डालने की योजना

137. श्रीमती गंगा देवी (बगरू): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका, बगरू में सीवर लाइन के अभाव में घनी आबादी के प्रत्येक वार्ड में आमजन को सड़कों पर गन्दे पानी के बहाव एवं जगह-जगह सौ-फिटे गटर के गड्ढों से निकलने वाले पानी से जानमाल की क्षति एवं आबादी क्षेत्र की सुन्दरता नष्ट हो रही है? यदि हां, तो प्रत्येक वार्ड की कालोनीवार आबादी तथा वर्षा जल एवं घरों से निकलने वाले गन्दे पानी की निकासी की योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र में सीवर लाइन के लिए कोई योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कितनी लागत की एवं क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त समूचे नगरपालिका क्षेत्र बगरू के लिए सीवर लाइन स्वीकृत करते हुए सीवर लाइन डाले जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। यह आंशिक रूप से सही है। नगरपालिका, बगरू में वर्षा जल एवं घरों से निकलने वाले पानी की निकासी की कोई योजना वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है।

(2) नगरपालिका, बगरू क्षेत्र में सीवर लाइन डाले जाने की वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

(3) इस भाग का उत्तर भाग संख्या 02 के उत्तर में निहित है।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका योजना के तहत बाड़मेर में रोजगार

138. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राष्ट्रीय शहरी आजीविका योजना (NLUM) के तहत बाड़मेर नगर परिषद् क्षेत्र में विगत दो वर्षों में कितने लोगों को रोजगार दिया गया एवं कितने लोगों को व्यक्तिगत ऋण स्वीकृत किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में वर्तमान में क्या-क्या कार्य संपादित किए जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर परिषद् बाड़मेर द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना (NLUM) के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण पूर्ण नहीं होने के कारण किसी को भी रोजगार नहीं दिया गया है एवं विगत दो वर्षों में 70 व्यक्तियों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु व्यक्तिगत ऋण स्वीकृत किया गया है, जिसकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना (NLUM) के अन्तर्गत निम्न कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं-

1. शहरी गरीब महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उनके संघ बनाना तथा रिवाल्विंग फंड की सहायता प्रदान करना।
2. शहरी गरीब युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार एवं स्वरोजगार से जोडना।
3. शहरी गरीब परिवार व्यक्ति को स्वरोजगार हेतु रुपये 2 लाख तक का अनुदानित ऋण उपलब्ध करवाना।
4. शहरी क्षेत्र में बेघर व्यक्तियों को आश्रय स्थल की सुविधा उपलब्ध करवाना।
5. नगर निकायों में पथ विक्रेताओं को चिन्हित कर पहचान पत्र तथा विक्रय प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना। नगर निकायों में टाउन वेण्डिंग कमेटी के माध्यम से वेण्डिंग व नो वेण्डिंग जोन निर्धारित कर वेण्डिंग मार्केट में आधारभूत विकास करवाना।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी।)

जयपुर के सागर एनक्लेव (जोन-8) में अतिक्रमण

139. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के जोन-8 में स्थित सागर एनक्लेव कालोनी, ग्राम धौलाई में वर्ष 2019 में अवैध निर्माण के कुल कितने प्रकरण किस-किस भूखण्डधारी के विरुद्ध दर्ज किये गये थे तथा उक्त दर्ज प्रकरणों पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त दर्ज प्रकरणों में जविप्रा प्रशासन द्वारा अवैध निर्माण करने वाले भूखण्डधारियों को अवैध निर्माण के विरुद्ध नवम्बर, 2019 में जविप्रा अधिनियम, 1982 की धारा 32, 33 के नोटिस भी जारी किये गये थे? यदि हां, तो अवैध निर्माण के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त भूखण्डों पर अब तक अवैध निर्माण कायम है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध निर्माण हटाने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन-08 में स्थित सागर एनक्लेव कालोनी, ग्राम धौलाई में वर्ष 2019 में अवैध निर्माण के कुल 02 प्रकरण भूखण्ड संख्या 23 व 23ए के संबंध में दर्ज किये गये थे। दोनों भूखण्डों में निजी आवास का निर्माण किया गया है। उक्त भूखण्डों पर किये गये निर्माण के विरुद्ध दिनांक 13.11.2019 को जविप्रा अधिनियम की धारा 32, 33 के नोटिस जारी किये थे, जिनके चालान दिनांक 22.02.2021 को माननीय न्यायालय एसीजेएम क्रम-02 जविप्रा में प्रस्तुत किये जा चुके हैं, जो वर्तमान में माननीय न्यायालय में विचाराधीन हैं।

(2) जी हां। भूखण्ड संख्या 23 व 23ए के भूखण्डधारियों को जविप्रा अधिनियम की धारा 32, 33 के नोटिस जारी किये गये थे, जिनके चालान दिनांक 22.02.2021 को माननीय न्यायालय एसीजेएम क्रम-02 जविप्रा में प्रस्तुत किये जा चुके हैं। भूखण्ड संख्या 23ए के भू-स्वामी द्वारा माननीय अपीलीय अधिकरण जविप्रा, जयपुर में अपील संख्या 150/2020 प्रस्तुत किये जाने पर माननीय अपीलीय अधिकरण जविप्रा, जयपुर द्वारा स्थगन आदेश

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

जारी किये गये, जो वर्तमान में प्रभावी हैं तथा जिसमें आगामी तारीख 07.04.2022 नियत है।

(3) जी हां। माननीय न्यायालय के निर्णय उपरान्त विधिक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में पाण्डुपोल हनुमान मंदिर तक सड़क निर्माण

140. श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि टाइगर प्रोजेक्ट रणथम्भौर में स्थित गणेश मन्दिर तक सड़क बनी हुई है? यदि हां, तो क्या सरकार सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में स्थित आस्था केन्द्र पाण्डुपोल हनुमान मन्दिर के विकास हेतु सड़क निर्माण कराने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। टाइगर प्रोजेक्ट रणथम्भौर में स्थित गणेश मन्दिर जाने हेतु गणेश धाम गेट (शेरपुर) से जोगी महल गेट तक लगभग 5 किलोमीटर की सड़क पुराने समय से बनी हुई है।

सरिस्का अभयारण्य में स्थित पाण्डुपोल हनुमान मन्दिर तक लगभग 20 किलोमीटर की ग्रेवल रोड बनी हुई है।

जोधपुर में जोजरी नदी को प्रदूषण से मुक्त कराने की योजना

141. श्री पुखराज (भोपालगढ़): क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि जोधपुर की टैक्सटाइल मिलों से निकलने वाले गंदे पानी से जोजरी नदी प्रदूषित हो रही है? यदि हां, तो उक्त नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए क्या सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। जोधपुर के औद्योगिक क्षेत्रों में संचालित कपड़ा प्रसंस्करण के 302 एवं स्टील प्रसंस्करण के 86 उद्योग जल प्रदूषणकारी उद्योग की श्रेणी में शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा नदी को प्रदूषित होने से बचाने हेतु की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

मोतीपुरा बांध (नैनवां) की क्षतिग्रस्त पाल की मरम्मत

142. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला बून्दी की तहसील नैनवां में स्थित मोतीपुरा बांध की पाल वर्ष 2021 के वर्षाकाल में अधिक पानी आने से टूटने के कगार पर पहुंच गयी थी व प्रशासन द्वारा उक्त का अस्थायी समाधान करके टूटने से बचाया था? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त की पाल के निर्माण व मजबूती की क्या कार्ययोजना है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बांध से निकलने वाला नहरी तंत्र पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त को दुरुस्त कराने की क्या कार्ययोजना है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मानसून वर्ष 2021 में वर्षा के कारण मोतीपुरा बांध की पाल क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी, अपितु बांध की वेस्टवियर क्षतिग्रस्त हो गई थी जिसकी तत्काल मरम्मत कर दी गई थी। उक्त बांध एवं नहरी तंत्र के रेस्टोरेशन हेतु मुख्य मंत्री बजट घोषणा वर्ष 2021-22 की अनुपालना में बांध एवं नहरों के प्रस्ताव राशि रुपये 274.57 लाख के रिपेयर, रिनोवेशन एवं रेस्टोरेशन योजनान्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जा चुके हैं, जिनकी स्वीकृति उपरांत अग्रिम कारवाई की जानी प्रस्तावित है।

(2) बांध के नहरी तंत्र एवं बांध की आवश्यक मरम्मत हेतु केन्द्र सरकार की रिपेयर, रिनोवेशन एवं रेस्टोरेशन योजना अन्तर्गत राशि रुपये 274.57 लाख के प्रस्ताव तैयार कर केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली को प्रस्तुत किये गये हैं, स्वीकृति एवं संसाधन उपलब्धतानुसार कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।

नदियों को नदियों से जोड़ने की योजना

143. श्री प्रशान्त बैरवा (निवाई): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश की नदियों को जोड़ने

(श्री प्रशान्त बैरवा)

की कोई योजना बनाई है? यदि हां, तो क्या उक्त का क्रियान्वयन कर दिया गया हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार ने प्रदेश की नदियों को जोड़ने की योजना के तहत प्रदेश की कौन-कौनसी नदियों को परस्पर जोड़ने का निर्णय लिया था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में नदियों को जोड़ने के अन्तर्गत आधिक्य जल उपलब्धता वाले बेसिनों से कम जल उपलब्धता वाले बेसिनों में पानी हस्तानान्तरण करने के अन्तर्गत दो प्रस्तावित परियोजनाएं क्रमशः "पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना" तथा "साबरमती के अधिशेष जल को जवाई बांध पुर्नभरण योजना" अन्तर्गत कार्य हाथ में लिये गये हैं। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना अन्तर्गत नौनेरा (नवनेरा) बैराज का निर्माण कार्य स्वीकृत कर कार्य पर राशि रुपये 615.90 करोड़ का व्यय किया जा चुका है तथा मुख्य मंत्री बजट घोषणा वर्ष 2022-23 अंतर्गत नवनेरा-बीसलपुर-ईसरदा लिंक, महलपुर बैराज एवं रामगढ़ बैराज हेतु राशि रुपये 9,600 करोड़ के कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं। कार्य को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से करने हेतु पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम गठित किया जाना प्रस्तावित है।

साबरमती बेसिन के अधिशेष जल को जवाई बांध पुनर्भरण हेतु उपयोग में लिये जाने की पी.एफ.आर. केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली के पास अन्तरराज्जीय परिप्रेक्ष्य में स्वीकृति हेतु लम्बित है। सिरोही एवं पाली जिले में पेयजल उपलब्ध करवाये जाने हेतु मुख्य मंत्री बजट घोषणा वर्ष 2022-23 अन्तर्गत कोटड़ा तहसील में दों बांधों का निर्माण राशि रुपये 1,800 करोड़ तथा इन बांधों से पाइप लाइन द्वारा जवाई बांध में पानी लाये जाने हेतु राशि रुपये 1200 करोड़ के कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं।

(2) प्रस्तावित पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में चंबल नदी की सहायक नदी बेसिनों कुन्नू, कूल, पार्वती, कालीसिंध, मेज में उपलब्ध अधिशेष पानी को बनास, मोरेल, बाणगंगा, पार्वती, कालीसिल, गंभीर इत्यादि नदी बेसिनों में अपवर्तन किया जाना प्रस्तावित है। साबरमती बेसिन की सेई, साबरमती एवं वाकल नदी का पानी जवाई पुनर्भरण हेतु अपवर्तित किया जाना प्रस्तावित है।

सहकारी संस्थाओं के चुनाव

144. श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सहकारी संस्थाओं के चुनाव लम्बे समय से नहीं हुए हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों के अध्यक्षों के चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(3) सरकार सहकारी बैंकों के चुनाव शीघ्र करवाने के लिए क्या प्रयास कर रही है?

(4) क्या सरकार ग्राम सेवा सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों के अध्यक्षों के चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन एक सतत प्रक्रिया है, जो राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत मानव संसाधनों की उपलब्धता, सहकारी संस्था के प्रकार, कार्यक्षेत्र, सदस्य संख्या व सम्बन्धित संस्था के उपनियमों के परिप्रेक्ष्य में सम्पन्न करवाये जाते हैं।

(2) जी हां। राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 27(2) के चतुर्थ परन्तुक के अनुसार - "किसी भी सहकारी सोसाइटी की समिति, जो सदस्यों के रूप में व्यष्टियों से मिलकर बनी हो और जिनमें अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों अथवा स्त्रियों के वर्ग या प्रवर्ग से सदस्य हों, एक स्थान अनुसूचित जातियों के लिये, एक स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिये और दो स्थान स्त्रियों के लिये आरक्षित होंगे।"

उक्त प्रावधान के क्रम में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के उपनियम संख्या 11(2)(क) के अनुसार संचालक मण्डल में 12 निर्वाचित सदस्यों में से एक-एक पद क्रमश: अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए तथा दो पद स्त्रियों के लिये आरक्षित हैं। चूंकि सहकारी बैंकों के सदस्य मुख्य रूप से व्यक्तिगत सदस्य नहीं होकर संस्थाएं होती हैं, अत: सहकारी बैंकों पर अधिनियम की धारा 27(2) के चतुर्थ परन्तुक के अनुसार आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं होती है।

(सहकारिता मंत्री)

प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति में अध्यक्ष का केवल एक ही पद होता है। अत: एक ही पद होने के कारण उस पद को किसी वर्ग विशेष के लिए आरक्षित किया जाना न्यायोचित नहीं है। अध्यक्ष पद पर किसी भी वर्ग के सदस्य को निर्वाचन लड़ने का अधिकार है, जो उचित है।

(3) सहकारी बैंकों के निर्वाचनों से पूर्व सहकारी बैंकों की सदस्य ग्राम सेवा सहकारी समितियों के निर्वाचन करवाये जाने आवश्यक हैं। ग्राम सेवा सहकारी समितियों के निर्वाचन से पूर्व उनमें वार्ड गठन किये जाने के संबंध में उपनियम संशोधन अपेक्षित हैं, जो वर्तमान में मंत्री-मण्डलीय उपसमिति के समक्ष स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं। मंत्री-मण्डलीय उपसमिति द्वारा उपनियम संशोधन की स्वीकृति जारी होने के पश्चात् ग्राम सेवा सहकारी समितियों के उपनियमों में संशोधन कर वार्ड गठन किया जाकर उनके निर्वाचन सम्पन्न करवाये जावेंगे, जिसके पश्चात् शीघ्र ही सहकारी बैंकों के निर्वाचन सम्पन्न करवाये जावेंगे।

(4) जी नहीं। प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति में अध्यक्ष का केवल एक ही पद होता है। अत: एक ही पद होने के कारण उस पद को किसी वर्ग विशेष के लिए आरक्षित किया जाना न्यायोचित नहीं है। अध्यक्ष पद पर किसी भी वर्ग के सदस्य को निर्वाचन लड़ने का अधिकार है, जो उचित है।

आकाशीय बिजली दुर्घटना से पीड़ित परिवारों को सहायता

145. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विगत तीन वर्षों में प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने की दुर्घटनाएं घटित हुई हैं? यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में कितनी दुर्घटनाएं कहां-कहां घटित हुईं एवं उनमें कितने व्यक्ति घायल हुए व कितने व्यक्तियों की मौत हुई? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त हादसों में घायल व मृतक व्यक्तियों के परिवारों को सहायता राशि के रूप में कितनी-कितनी राशि किस-किस व्यक्ति को कहां-कहां दी गई? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार आकाशीय बिजली या आगजनी से घटित जनहानि पर सहायता राशि बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व कब से तथा नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विगत तीन वर्षों में आकाशीय बिजली गिरने की दुर्घटनाओं में घायल एवं मृतक व्यक्तियों की पंचायत समितिवार सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त हादसों में मृतकों एवं घायल व्यक्तियों के परिजनों/आवेदकों को दी गई सहायता राशि का पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) विभाग द्वारा आकाशीय बिजली एवं आगजनी की घटनाओं में जनहानि या अन्य हानि होने पर राज्य आपदा मोचन निधि के नोर्म्स के अनुसार सहायता प्रदान की जाती है।

राज्य आपदा मोचन निधि से प्रदान की जाने वाली सहायता राशि का निर्धारण भारत सरकार द्वारा ही किया जाता है।

(सूची एवं विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

डेगाना में बस स्टैण्ड का निर्माण

146. श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि उपखण्ड मुख्यालय डेगाना में बस स्टैण्ड का अभाव होने के कारण यात्रियों को वर्षों से असुविधा होती है?

(2) क्या सरकार उक्त उपखण्ड मुख्यालय पर नया बस स्टैण्ड निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उप खण्ड मुख्यालय डेगाना में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के स्वामित्व का बस स्टैण्ड नहीं है एवं न ही बस स्टैण्ड निर्माण हेतु निगम स्वामित्व की भूमि उपलब्ध है।

(2) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सीमित संसाधनों के कारण फिलहाल निगम का उपखण्ड मुख्यालय डेगाना में भूमि क्रय कर बस स्टैण्ड निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

रायपुर (पाली) में रोडवेज बसों का ठहराव

147. श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती शोभा चौहान)

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पथ परिवहन बसों का सचांलन किया जा रहा है? यदि हां, तो वीजागुड़ा वाया बगडी सोजत होते हुए जोधपुर तक चलने वाली बसों को क्यो बन्द किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विगत कुछ समय से रोडवेज की बसें रायपुर बस स्टैण्ड पर नहीं आकर सीधे बाईपास निकल जाती हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) बाईपास से गुजर रही बसों के सम्बन्ध में विभाग के अधिकारियों को क्या-क्या शिकायत मिली है तथा उक्त शिकायतों के सन्दर्भ में क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में पाली से बीजागुडा वाया बगडी, सोजत मार्ग पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा निम्नानुसार एक वाहन का संचालन किया जा रहा है:-

क्र. सं.	आगार	मार्ग मय वाया	समय
1.	पाली	पाली-बीजागुडा वाया सोजत, बगडी	16.50
2.		बीजागुडा-पाली वाया बगडी सोजत	07.30
3.		पाली-बीजागुडा वाया सोजत, बगडी	10.20
4.		बीजागुडा-पाली वाया बगडी सोजत	13.45

पूर्व में निगम द्वारा गुडा वीजा वाया बगडी सोजत होते हुए जोधपुर तक किसी निगम वाहन का संचालन नहीं किया गया है।

(2) पाली से ब्यावर मार्ग पर संचालित निगम की वातानुकूलित एवं लम्बी दूरी के वाहन, जिनका ठहराव रायपुर बस स्टैण्ड निर्धारित नहीं है, उनके अतिरिक्त निगम की अन्य वाहन रायपुर बस स्टैण्ड होकर संचालित होते हैं।

(3) बाईपास होकर जाने वाली बस की शिकायत प्राप्त होने पर दोषी चालक/परिचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है, जिसका विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

तिजारा क्षेत्र में रोडवेज बसों का संचालन

148. श्री संदीप कुमार (तिजारा): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री संदीप कुमार)

क्या सरकार तिजारा से कोटकासिम वाया खुशखेड़ा-भिवाड़ी तथा भिवाड़ी से कोटकासिम वाया तिजारा हेतु रोडवेज की बस के संचालन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सीमित संसाधनों के कारण तिजारा से कोटकासिम वाया खुशखेड़ा-भिवाड़ी तथा भिवाड़ी से कोटकासिम वाया तिजारा होकर निगम बस संचालन का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

वर्तमान में प्रश्नगत मार्गों पर निगम की कोई सीधी बस सेवा संचालित नहीं है किन्तु तिजारा से भिवाडी वाया गैलपुर, टपूकड़ा एवं भिवाड़ी से तिजारा वाया टपूकड़ा, गैलपुर मार्ग पर पर्याप्त संख्या में निगम की वाहनों का संचालन किया जा रहा है।

मावली में खेल मैदान

149. श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मावली में कुल कितने गांवों में खेल के मैदान हेतु भूमि आबंटित है? गांव एवं भूमि के क्षेत्रफल सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त भूमि पर कोई अतिक्रमण है? यदि हां, तो उसे हटाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में खेल मैदान से वंचित गांवों में भूमि कब तक आबंटित कर दी जायेगी?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मावली में कुल 178 राजस्व गांव हैं जिनमें से किसी भी गांव में खेल विभाग के नाम खेल मैदान की भूमि आबंटित नहीं है।

(2) खेल विभाग के नाम खेल मैदान की भूमि आबंटित नहीं होने के कारण अतिक्रमण से संबंधित सूचना शून्य है।

(3) खेल विभाग द्वारा भूमि आबंटन की कार्यवाही नहीं की जाती है।

वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है।

बेरोजगारी भत्ता योजना में संशोधन

150. श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में सरकार ने जन घोषणा पत्र में बेरोजगारों को भत्ता देने का वायदा किया था? यदि हां, तो अब तक कितने बेरोजगारों को भत्ता दिया गया है? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्रदेश के सभी रोजगार कार्यालयों में बेरोजगार अभ्यर्थी पंजीकृत हैं? यदि हां, तो कितने बेरोजगार पंजीकृत हैं? क्या पंजीकृत अभ्यर्थियों में से सभी को भत्ता दिया जा रहा है?

(3) क्या जनवरी, 2022 से बेरोजगारी भत्ता योजना में बदलाव किया गया है? यदि हां, तो क्या योजना में संशोधन के उपरान्त जनवरी, 2022 से कितने बेरोजगारों को भत्ता दिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि वर्तमान में सरकार ने जन घोषणा पत्र के बिन्दु संख्या 10.1 में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा किया था, जिसकी अनुपालना में 01 फरवरी, 2019 से मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना लागू की गई। इस योजना के अन्तर्गत शिक्षित स्नातक उत्तीर्ण पात्र बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। योजनान्तर्गत योजना प्रारम्भ से 31 जनवरी, 2022 तक 4,02,826 आशार्थियों को भत्ता स्वीकृत कर लाभान्वित किया गया है। जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। प्रदेश के सभी जिला रोजगार कार्यालयों में बेरोजगार अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। प्रदेश के सभी रोजगार कार्यालयों में कुल 16,54,106 बेरोजगार पंजीकृत हैं।

जी नहीं। पंजीकृत अभ्यर्थियों में से केवल मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के अन्तर्गत आवेदन किये जाने वाले पात्र स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है।

(3) जी हां। 01 जनवरी 2022 से मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना को रोजगार परक बनाने हेतु 3 माह का कौशल प्रशिक्षण एवं राजकीय विभागों में प्रतिदिन 4 घन्टे की इन्टर्नशिप का प्रावधान किया गया है। नवीन योजनानुसार पात्र पुरुष आशार्थियों को 4,000 रुपये प्रतिमाह व महिला, निःशक्तजन एवं

(राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता)

ट्रांसजेण्डर आशार्थियों को 4,500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जा रहा है।

नवीन योजना में लाभान्वितों की अधिकतम संख्या बढ़ाकर एक समय में 2 लाख कर दी गई है।

योजना में संशोधन के उपरान्त माह जनवरी 2022 में कुल 1,97,771 बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत कर लाभान्वित किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

उदयपुर ग्रामीण में पंजीकृत बेरोजगार

151. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में विगत दो वर्ष में कितने बेरोजगार पंजीकृत किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने बेरोजगार पुरुष एवं महिलाएं पंजीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा पंजीकृत बेरोजगारों में से कितनी महिलाओं तथा पुरुषों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया है तथा कितनों को देना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में विगत दो वर्ष में 31 जनवरी, 2022 तक कुल 15,445 बेरोजगार युवा जिला रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हुए हैं।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में 7,251 पुरुष एवं 8,194 महिला आशार्थी बेरोजगार पंजीकृत हुए है।

(3) सरकार द्वारा पंजीकृत बेरोजगारों में से योजनान्तर्गत 31 जनवरी, 2022 तक सम्पूर्ण प्रदेश में कुल 4,02,826 पात्र बेरोजगार युवाओं को लाभान्वित किया गया है, जिनमें 1,70,920 महिलाएं एवं 2,31,906 पुरुष आशार्थी हैं। योजना प्रारम्भ दिनांक 01 फरवरी, 2019 से 31 जनवरी, 2022 तक विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के कुल 2,140 आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया, जिनमें से 589 पुरुष एवं 1,551 महिलाएं हैं तथा 989 आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाना शेष है।

रतनगढ़ में सार्वजनिक स्थानों से विद्युत पोल हटाने की योजना

152. श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार आबादी, मंदिरों, चिकित्सालयों, विद्यालयों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर से गुजर रही बड़ी विद्युत लाइनों से होने वाली जनहानि की आशंका को देखते हुए उक्त स्थलों से विभाग स्तर पर विद्युत लाइन को हटवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विभाग द्वारा आमजन की सुविधार्थ सार्वजनिक स्थलों के आगे या आम रास्ते पर स्थित विद्युत पोल नि:शुल्क स्थानांतरित किये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में विभाग द्वारा बिना किसी शुल्क के दिसम्बर, 2018 से दिसम्बर, 2021 के बीच सार्वजनिक स्थलों व आम रास्ते से कितने व कहां-कहां से विद्युत पोल हटवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विद्युत लाइनें विद्युत विनियम में निर्धारित सुरक्षा मापदण्डों के अनुसार रिहायशी मकानों से निश्चित दूरी व ऊंचाई पर स्थापित की जाती हैं। तथापि विद्युत लाइनें खिंचने के बाद शहरी आबादी क्षेत्र का विस्तार होने के कारण लाइनों के समीप व नीचे नियम विपरीत स्थानीय निवासियों द्वारा अनधिकृत निर्माण कर लिया जाता है।

विद्युत वितरण निगमों की ऐसी विद्युत लाइनें जिनके नीचे सरकारी स्कूल का निर्माण कर लिया गया व जिनसे दुर्घटना होने की संभावना हो सकती है, वर्तमान में ऐसी लाइनों को वितरण निगमों द्वारा स्वयं के खर्चे पर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने का प्रावधान है। आदेश की प्रति परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

आबादी क्षेत्रों, मंदिरों, चिकित्सालयों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर से गुजरने वाली विद्युत लाइनों को विद्युत वितरण निगमों द्वारा अपने खर्चे पर हटाने का वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था मानव जीवन या सम्पत्ति के लिये घातक विद्युत लाइनों को हटवाना चाहते हैं तो लाइन को हटाने की तकमीना राशि की 50 प्रतिशत राशि आवेदक/संस्था द्वारा जमा करवाने तथा शेष 50 प्रतिशत राशि निगम द्वारा वहन कर लाइन को अन्यत्र शिफ्ट करने का प्रावधान है।

(राज्य मंत्री, ऊर्जा)

(2) जी नहीं। सार्वजनिक स्थानों अथवा आम रास्तों पर स्थित विद्युत पोलों को स्थानीय निकाय द्वारा शिफ्ट करवाये जाने का आवेदन किये जाने पर शिफ्टिंग में होने वाले समस्त व्यय की राशि स्थानीय निकाय द्वारा जमा किये जाने के पश्चात् पोलों को शिफ्ट किये जाने का प्रावधान है।

विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में माह दिसम्बर, 2018 से दिसम्बर, 2021 के मध्य सार्वजनिक स्थलों व आम रास्तों से कोई भी विद्युत पोल नि:शुल्क स्थानान्तरित या हटाये नहीं गये हैं।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी।)

डीडवाना में कुसुम योजना के लाभार्थी

153. श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला नागौर में विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में कुसुम योजना के तहत अब तक कितने किसानों को सोलर पम्प सैट उपलब्ध करवाये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के तहत सरकार द्वारा कितनी राशि उपलब्ध कराई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित)

जायल में कृषि कनेक्शन के ट्रांसफार्मर

154. श्रीमती मंजु देवी (जायल): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जायल में जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2021 तक की अवधि में विभाग ने किसानों के खेतों से कृषि कनेक्शन के ट्रांसफार्मर उतारे हैं? यदि हां, तो किन-किन कारणों से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में चोरी के अवैध विद्युत ट्रांसफार्मर पकड़े गये हैं? यदि हां, तो कितने? पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र जायल में जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2021 तक की अवधि में कुल 93 किसानों के खेतों से कृषि कनेक्शन के

(राज्य मंत्री, ऊर्जा)

ट्रांसफार्मर उतारे गये हैं। उक्त सभी ट्रांसफार्मर बकाया राशि होने के कारण उतारे गये हैं।

(2) जी हां। उक्त विधान सभा क्षेत्र में जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2021 तक की अवधि में कुल 10 अवैध विद्युत ट्रांसफार्मर पकडे़ गये हैं जिनका पंचायतवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

सूरतगढ़ में अपूर्ण जीएसएस

155. श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में वर्तमान में कुल कितने 11 के.वी.एफ.डी.आर. व कितने 33/11 के.वी. के जी.एस.एस. चालू हालत में हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में 33/11 के.वी./11 के.वी.एफ.डी.आर. के कितने जी.एस.एस. स्वीकृत हैं? स्वीकृत जी.एस.एस. में से कितने पूर्ण कर दिए गए हैं तथा कितने अपूर्ण हैं? उक्त अपूर्ण जी.एस.एस. कब तक पूर्ण कर दिए जाएंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में वर्तमान में 11 केवी के कुल 132 फीडर व 33/11 केवी के कुल 28 सब-स्टेशन चालू अवस्था में हैं जिनसे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। उक्त 11 केवी के फीडरों एवं 33/11 केवी सब-स्टेशनों का उपखण्डवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में 33/11 केवी के वर्तमान तक कुल 29 सब-स्टेशन स्वीकृत हैं जिनमें से 28 सब-स्टेशनों का कार्य पूर्ण कर विद्युत आपूर्ति की जा रही है एवं शेष एक 33/11 केवी सब-स्टेशन रंगमहल के निर्माण हेतु कार्यादेश जारी किया जा चुका है, जिसका कार्य वर्तमान में मार्ग विवाद होने के कारण लम्बित है। मार्ग विवाद का निस्तारण होने के पश्चात् उक्त सब-स्टेशन का निर्माण माह मई, 2022 तक पूर्ण किया जाना संभावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

नोखा में कन्या महाविद्यालय की स्थापना

156. श्री बिहारीलाल (नोखा): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा बजट 2021-22 में नोखा में कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या कन्या महाविद्यालय हेतु भवन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बजट घोषणा वर्ष 2021-22 की अनुपालना में नोखा में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोल दिया गया है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

वर्तमान में उक्त महाविद्यालय अस्थायी रूप से मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा की प्रथम मंजिल के 07 कक्षा-कक्षों में संचालित है तथा सत्र 2021-22 में कुल 201 छात्राएं प्रवेशित हैं जिनके लिए फर्नीचर व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवा दी गयी हैं। महाविद्यालय हेतु महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर से अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त कर ली गयी है।

(2) राजकीय कन्या महाविद्यालय, नोखा के भवन निर्माण हेतु मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा की 25 बीघा भूमि में से 05 एकड़ (20,235 वर्ग मीटर) भूमि कन्या महाविद्यालय के नाम दर्ज करने की कार्यवाही राजस्व विभाग स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

भवन निर्माण भामाशाह सेठ श्री जगदीश प्रसाद बागड़ी द्वारा करवाया जाना प्रस्तावित है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी।)

विश्वविद्यालयों में कुलपति के रिक्त पद

157. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्तमान में कितने सरकारी व निजी विश्वविद्यालय संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में कितने सरकारी विश्वविद्यालयों में कुलपति के पद रिक्त हैं एवं इस वर्ष कितने कुलपतियों का कार्यकाल पूरा हो जायेगा? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री वासुदेव देवनानी)

(3) विश्वविद्यालयों में सही व निश्चित अवधि में कुलपति की नियुक्ति हो, इस दिशा में सरकार क्या प्रयास कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्तमान में संचालित सरकारी विश्वविद्यालयों की सूची परिशिष्ट-1 पर एवं निजी विश्वविद्यालयों की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में एक विश्वविद्यालय राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर में कुलपति का पद रिक्त है एवं 10 विश्वविद्यालयों में कुलपति का कार्यकाल इस वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। विस्तृत सूचना परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) विश्वविद्यालयों में सही व निश्चित अवधि में कुलपति की नियुक्ति के संबंध में संबंधित विश्वविद्यालयों के अधिनियम में निहित प्रावधान के अनुसार समय पर अपेक्षित कार्यवाही की जाती है।

यदि किन्हीं कारणवश कुलपति के चयन में समय लगने की संभावना होती है तो विश्वविद्यालय अधिनियम में निहित प्रावधानानुसार STOP-GAP ARRANGEMENT के अंतर्गत अन्य विश्वविद्यालय के कुलपति को चार्ज दिया जाता है।

(सूची एवं सूचना पुस्तकालय में रखी गयी।)

परिशिष्ट-01

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव, जिसे पढ़ा हुआ माना गया

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा)

ट्रांसफार्मरों का नियम विरुद्ध बेचान

छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में किसानों के जब्त किए गए विद्युत ट्रांसफार्मरों को विद्युत निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा मिलीभगत कर नियम के खिलाफ जाकर अवैध तरीके से बेच दिया गया है। छबड़ा में विद्युत निगम के अधिकारियों ने बकाया वसूली के तहत किसानों के जब्त किए गए विभागीय व अवैध विद्युत ट्रांसफार्मर बेच दिए। जले हुए ट्रांसफार्मरों का सैकड़ों लीटर तेल भी कर्मचारियों द्वारा मिलीभगत कर चोरी-छिपे बेच दिया गया है। निगम के एमडी के निर्देश पर उक्त प्रकरण की जांच अधिशाषी अभियंता अटरू ने शुरू कर दी है। निगम के सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता द्वारा पिछले तीन माह से किसानों के बकाया बिलों की राशि वसूली की कार्यवाही की जा रही है, जिसमें बिल जमा नहीं कराने वाले किसानों के सिंगल फेज व थ्री फेज विद्युत ट्रांसफार्मर बड़ी संख्या में उतारे गये हैं। जांच के दौरान करीब 15 से 20 विद्युत ट्रांसफार्मर जब्त किये गये। निगम के कनिष्ठ अभियंता ने विद्युत ट्रांसफार्मरों को स्टोर में जमा कराने के स्थान पर अन्य कर्मचारियों के सहयोग से विद्युत ग्रिड कार्यालय से ही बेच दिए, जबकि अवैध ट्रांसफार्मरों का विभाग में कोई लेखा-जोखा नहीं है। किसानों के जले हुए ट्रांसफार्मरों से निकलने वाले तेल को भी स्टोर में जमा नहीं कराया गया। इस तरह से सैकड़ों लीटर तेल को भी कर्मचारी ने मिलीभगत कर षड्यंत्रपूर्वक चोरी -छिपे बेच रहे हैं। ग्राम भोजपुर निवासी मालमसिंह पुत्र सलमान सिंह पर बकाया राशि के चलते 16 नवम्बर, 2020 को 25 केवीए का विद्युत ट्रांसफार्मर जब्त किया गया और सेवनखेड़ी जीएसएस पर ले जाया गया। नियमानुसार जब्त किए गए ट्रांसफार्मर को स्टोर में जमा कराना चाहिए था, किन्तु उक्त ट्रांसफार्मर को स्टोर में जमा नहीं कराया गया और मिलीभगत कर जीएसएस से ही बेच दिया गया। इस प्रकरण में विद्युत निगम के कर्मचारियों ने नियमों को ताक में रखकर मिलीभगत व भ्रष्टाचार कर सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाने का कृत्य किया है।

निवेदन है कि छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में विद्युत निगम के

कर्मचारियों द्वारा नियम विरुद्ध बेचे गए विद्युत ट्रांसफार्मरों की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने हेतु विभाग को निर्देश प्रदान करने का श्रम करावें।

परिशिष्ट-02

श्री अशोक गहलोत माननीय मुख्य मंत्री की आय-व्ययक 2022-23 पर की गई घोषणा के पैरा संख्या 28 की सूची

क्र. सं.	सड़क	लागत
1	झुंझुनूं के ग्राम समसपुर एवं ग्राम इस्लामपुर में बाईपास सड़क निर्माण	6 करोड़ रुपये
2	खाटूश्यामजी से सालासर धाम को जोड़ने के लिए खूड़ से सेवद बड़ी 34 किलोमीटर सड़क का निर्माण	20 करोड़ रुपये
3	ऊंटोली-कोहराना-जखराना-जटगांवड़ा-नायसराना-अकलीमपुर हरियाणा सीमा तक (अलवर)	15 करोड़ 50 लाख रुपये
4	एनएच-8 से जैनपुरबास पहाड़ी अपटू बबेडी तक क्षतिग्रस्त सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य (अलवर)	12 करोड़ रुपये
5	लक्ष्मणगढ़ में खुड़ी रसीदपुरा से भुमा छोटा वाया खेरू मणासीया से बादुसर तक सड़क निर्माण (सीकर)	8 करोड़ रुपये
6	रामपुर मेवाडा (बिछीवाड़ा)-डूंगरपुर में कोडियागुण बांध के ओटे में पुलिया निर्माण	7 करोड़ 10 लाख रुपये
7	NH-52 से हु वालिया-पगारा-औधन्धा-काछोला-नरसिंहपुरा- टिच का बरडा-मेण्डी (NH-.148 डी) तक 31 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य (हिण्डौली)	31 करोड़ रुपये
8	खेरवाड़ा-उदयपुर में जवास सुवेरी मार्ग पर स्थित सोम नदी पर पुलिया निर्माण	6 करोड़ रुपये
9	करौली में बालाजी से बामनवास वाया टोडाभीम, दलपुरा-रायसना मेगा हाईवे निर्माण	140 करोड़ रुपये
10	पीपल्दा-कोटा में अन्थड़ा से बनकाखेड़ा सम्पर्क सड़क का निर्माण	2 करोड़ 97 लाख रुपये
11	मोनापुरा जिला सीमा से हु ड़ला सीमा एनएच-21 वाया गढ़हिम्मतसिंह सड़क का निर्माण (महवा)-दौसा	20 करोड़ रुपये

क्र. सं.	सड़क	लागत
12	टामटिया से मोरेन नदी पर पुलिया में सड़क झकड़ा गांव छवि तक (डूंगरपुर)	2 करोड़ 60 लाख रुपये
13	शाहपुरा जयपुर में बिशनगढ़ से नायन सड़क निर्माण व तीन वेंटेड कॉजवे निर्माण कार्य	2 करोड़ 80 लाख रुपये
14	विराटनगर कुहाड़ा मोड से वाया पापड़ा, बड़ा काकराणा, खाला की ढत्राणी, तालूकाबास की छींड, तालूकाबास, पांछूडाला की छींड, सितोपसिंहपुरा, भोजावास, भांकरी, चौबाला, पाथरेड़ी, चौकी राजनोता रोड, भालोजी मोड़ तक एमडीआर 251 (33 किमी.)	33 करोड़ रुपये
15	पिलानी-सूरजगढ़-बुहाना-पचेरी हरियाणा सीमा तक सड़क मरम्मत एवं उन्नयन कार्य (पिलानी-झुंझुनूं)	52 करोड़ 50 लाख रुपये
16	करौली के हिण्डौन शहर के रेलवे ओवरब्रिज से कोतवाली पुलिस थाना हिण्डौन सिटी तक सड़क निर्माण कार्य	19 करोड़ रुपये
17	लोरवाड़ा से महेशरा वाया दोबड़ा खुर्द सड़क निर्माण कार्य मय वेन्टेड कॉजवे (बनास नदी)-सवाई माधोपुर	28 करोड़ 40 लाख रुपये
18	अंता-सांगोद राज्य उच्च मार्ग 51ए (22 किमी.)	9 करोड़ 60 लाख रुपये
19	बबाई-हरडिया-सेफरागवार-कांकरिया-जोधपुरा-बागोली-पंचलगी-झड़ाया (खेतड़ी) सड़क चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य	23 करोड़ 40 लाख रुपये
20	सपोटरा-कैलादेवी की 16 किलोमीटर सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य	16 करोड़ रुपये
21	सपोटरा-मांगरोल-गोठरा-गेरई-सैमरदा-काशीपुरा-घुराकर 12 किलोमीटर सड़क का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाईकरण कार्य (करौली)	12 करोड़ रुपये

क्र. सं.	सड़क	लागत
22	खारडा-रानी से विजोवा-रानी की 15 किलोमीटर सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य (मारवाड़ जंक्शन-पाली)	15 करोड़ रुपये
23	अरनोद गोतमेश्वर मंदिर तक सड़क सुदृढ़ीकरण-प्रतापगढ़	4 करोड़ रुपये
24	जस्टाना, बौंली, निवाई रोड (स्टेट हाईवे-117) 32.40 किलोमीटर सड़क का निर्माण करवाया जायेगा (बामनवास-सवाई माधोपुर)	56 करोड़ 35 लाख रुपये
25	झील-मिलकपुर रोड से लहचोरा कलां (बयाना)-भरतपुर को जोड़ने वाली नोन पेचेबल सड़क का पुनर्निर्माण	37 लाख रुपये
26	सीकर शहर में स्थित आरओबी (नवलगढ़ पुलिया) की चौड़ाई दो लेन से बढ़ाकर 4 लेन करने का कार्य	45 करोड़ रुपये
27	भुसावर बाईपास का निर्माण (भुसावर-छौंकरवाड़ा सड़क एट कंचनपुरा से वैर-भुसावर सड़क वाया ईटामडा, मूसेपुर)-भरतपुर	33 करोड़ 50 लाख रुपये
28	बगड़ी-महारिया-खुर्रा-मण्डावरी कृषि मण्डी तक एवं रीको एरिया से जमात तक सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य (लालसोट)-दौसा	31 करोड़ रुपये
29	आगासडी से उनरोड तक सड़क निर्माण कार्य (शिव)-बाड़मेर	3 करोड़ 20 लाख रुपये
30	स्टेट हाईवे सवाई माधोपुर से होकर खण्डार से करणपुर (करौली) तक सड़क निर्माण कार्य (बहरावण्डा-खण्डार-बालेर-करणपुर सड़क एसएच 123 का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य)	60 करोड़ रुपये
31	सांभरिया बराला, हनुमानपुरा सड़क पर ढूंढ नदी में पुलिया निर्माण सहित सड़क निर्माण कार्य (बस्सी)-जयपुर	9 करोड़ 50 लाख रुपये

क्र. सं.	सड़क	लागत
32	डूण्डलोद से टिटनवाड रोड वाया कारी, जाखल रोड (जाखल बाईपास सहित) एमडीआर 312 का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य (नवलगढ़, उदयपुरवाटी)-झुंझुनूं	45 करोड़ रुपये
33	मेहंदीपुर बालाजी से बामनवास वाया रायसना, टोडाभीम, दलपुरा सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण (महवा, टोडाभीम, बामनवास)-दौसा	90 करोड़ रुपये
34	एसएच 29 ए बासड़ी मोड़ से अलवर सीमा तक लिंक रोड, सैंथल वाया बीनावाला सहित सड़क का सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण एवं एमडीआर-152, सींगवाड़ा से नांगल बैरसी वाया एनएच 121 सड़क का सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण (दौसा)	10 करोड़ रुपये
35	मिसिंग लिंक रोड सोप से पचाला (देवली-उनियारा)	2 करोड़ 40 लाख रुपये
36	धवा से हरसोलाव वाया नोखा चान्दावता-रोल चान्दावता मिसिंग लिंक की 20 किलोमीटर सड़क	6 करोड़ रुपये
37	भदाणा-झाड़ीसरा-जोधियासी-रोहिणी सड़क (28 किलोमीटर) (नोखा)-नागौर	28 करोड़ रुपये
38	चौमूं पुरोहितान से शाहपुरा ठिकरिया, होद से बरसिंगपुरा, अठबीघा से सुन्दरदास जी-सलबाड़ी,	6 करोड़ रुपये
39	महावा से जोरा मीणा की ढाणी (7 किलोमीटर) (नीम का थाना)-सीकर	7 करोड़ रुपये
40	एसएच-60 जायल-दूगोली-खाबडियाना (21 किलोमीटर) (जायल-नागौर)	21 करोड़ रुपये
41	रामगढ़ से कालापट्टा विलेज सड़क का सुदृढ़ीकरण कार्य मय पुलिया (बारां)	5 करोड़ 60 लाख रुपये
42	जालौर से बागौरा सड़क का निर्माण (सायला)-जालौर	25 करोड़ रुपये

क्र. सं.	सड़क	लागत
43	विराटनगर में जौधूला स्कूल से वाया राडावास होते हुए दौलाज तक 8 किलोमीटर सड़क का निर्माण	8 करोड़ रुपये
44	कुशालीपुरा में कमलेश्वर महादेव वाया टोडरा सड़क का निर्माण (खण्डार)-सवाई माधोपुर	50 करोड़ रुपये
45	भीम-राजसमंद में देवगढ़ से 40 मील चौराया एनएच-8 की 25 किलोमीटर सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	25 करोड़ रुपये
46	मेड़ता रोड से बूटाटी सड़क का सुदृढ़ीकरण-नागौर	12 करोड़ रुपये
47	झामरी से धाडका तक पुलिया निर्माण (कुशलगढ़)-बांसवाड़ा	8 करोड़ 50 लाख रुपये
48	राजा के नंगला से सालेपुर, बाड़ी रोड घटिया से चौराहा सैंपऊ तक व बाड़ी रोड सैंपऊ से बसेड़ी रोड तक सीसी सड़क कुल 6 किलोमीटर	10 करोड़ रुपये
49	बड़ी सादड़ी-छोटी सादड़ी-नीमच रोड एसएच-15 का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य (निम्बाहेड़ा)-चित्तौड़गढ़	25 करोड़ रुपये

परिशिष्ट 03

I. खो-नागोरियान-जयपुर हेतु बीसलपुर बांध आधारित पेयजल परियोजना फेज-द्वितीय का 133 करोड़ 24 लाख रुपये लागत से कार्य करवाया जायेगा।

II. जगतपुरा, प्रताप नगर एवं महल रोड, जयपुर के आस-पास के क्षेत्र हेतु बीसलपुर बांध आधारित पेयजल परियोजना फेज-द्वितीय का 184 करोड़ 89 लाख रुपये की लागत से कार्य करवाया जायेगा।

III. पृथ्वीराज नगर, जयपुर हेतु बीसलपुर बांध आधारित पेयजल परियोजना, फेज प्रथम, स्टेज-द्वितीय एवं फेज-द्वितीय का 600 करोड़ रुपये की लागत से कार्य करवाये जायेंगे।

IV. शहरी जल योजना, दौसा के संवर्धन हेतु 126 करोड़ 87 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे।

V. महवा शहरी जल योजना के संवर्धन हेतु 62 करोड़ 46 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे।

VI. नवगठित नगरपालिका थानागाजी-अलवर में ग्रामीण जलप्रदाय योजना को शहरी जलप्रदाय योजना में क्रमोन्नत किया जाकर पेयजल की समुचित व्यवस्था की जायेगी। इस पर 21 करोड़ 86 लाख रुपये की लागत आयेगी।

VII. ईसरदा बांध परियोजना से जमवारामगढ़ में पानी लाकर पेयजल उपलब्ध करवाया जायेगा।

VIII. बिलाड़ा-जोधपुर में दातीवाड़ा परियोजना के अन्तर्गत देवलिया ग्राम से जोलेजी फोजदारा तक बड़ी पाइप लाइन जोड़कर पेयजल उपलब्ध कराने की DPR बनायी जायेगी।

IX. बस्सी-जयपुर की ग्रामीण जलप्रदाय योजना को शहरी जलप्रदाय योजना में क्रमोन्नत किया जाकर पेयजल की समुचित व्यवस्था की जायेगी। इस पर लगभग 19 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

X. झोटवाड़ा-जयपुर के उद्योग नगर क्षेत्र में पेयजल हेतु 2 हजार किलोलीटर क्षमता की टंकी बनाकर जलप्रदाय की समुचित व्यवस्था की जायेगी। इस पर लगभग 10 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

XI. लक्ष्मण डूंगरी-जयपुर में पेयजल की समुचित व्यवस्था हेतु वर्तमान

जल प्रणाली में सुधार किया जायेगा। इस पर लगभग 20 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

XII. ब्लाक रोहट-पाली में पेयजल की व्यवस्था हेतु लगभग 28 करोड़ रुपये की लागत से जोधपुर से रोहट-पाली तक पाइप लाइन का कार्य किया जायेगा।

XIII. गुडामालानी एवं चौहटन-बाड़मेर के 7 ब्लाकों की 1 हजार 42 बस्तियों में 425 आर.ओ. प्लांट लगाये जाकर शुद्ध पीने योग्य जल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जायेगी। इस हेतु 120 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

XIV. शहरी जल योजना भिण्डर-उदयपुर का 25 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्गठन किया जायेगा।

XV. श्रीमाधोपुर-सीकर में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु कार्य हाथ में लिया जायेगा।

परिशिष्ट 04

इसमें आनासागर झील-अजमेर, चूहड़ सिद्ध घाटी-अलवर, सवाई माता-बांसवाड़ा, शाहबाद-बारां, जूनापत्रसार-बाड़मेर, माण्डेरा रून्ध-भरतपुर, भड़क, छत्रीखेड़ा-भीलवाड़ा, जोडबीड-बीकानेर, भीमलत-बून्दी, मोहर मगरी-चित्तौड़गढ़, श्याम पांडिया, तारानगर-चूरू, गोल (मेन)-दौसा, दमोह वाटरफाल-धौलपुर, रतनपुर, बिछीवाड़ा-डूंगरपुर, धन्नासार बरानी-हनुमानगढ़, नईनाथ बांसखोह-जयपुर, कनोई-जैसलमेर, सुन्धा माता-जालौर, बड़बेला तालाब-झालावाड़, मनसा माता-झुंझुनूं, माचिया-जोधपुर, कैलादेवी नेचर कैम्प-करौली, आवली रोजड़ी-कोटा, गोगेलाव-नागौर, खोबागुड़ा, देसूरी-पाली, गोतमेश्वर, लालगढ़-प्रतापगढ़, रूप नगर, झीलवाड़ा-राजसमन्द, विजयगढ़, बौंली-सवाई माधोपुर, हर्ष पर्वत-सीकर, राजल दाबेला-सिरोही, 3 एमएसडी डाबला-श्रीगंगानगर, बीसलपुर-टोंक एवं माछला मगरा-उदयपुर सम्मिलित किये जायेंगे।

परिशिष्ट 05

क्रम संख्या	जिला	शहर
1	अजमेर	सरवाड़
2	अलवर	खेरली, राजगढ़, किशनगढ़बास, तिजारा
3	बांसवाड़ा	परतापुर गढ़ी
4	बारां	मांगरोल
5	भरतपुर	भुसावर, कुम्हेर, नदबई, नगर, वैर, डीग, कामां
6	भीलवाड़ा	जहाजपुर, गंगापुर, शाहपुरा
7	बीकानेर	देशनोक
8	बूंदी	कापरेन, केशोरायपाटन, नैनवां, इन्द्रगढ़
9	चित्तौड़गढ़	बेगूं, कपासन
10	चूरू	छापर
11	धौलपुर	बाड़ी
12	दौसा	महवा, बांदीकुई, दौसा
13	हनुमानगढ़	पीलीबंगा
14	जयपुर	विराटनगर, चौमूं, जोबनेर, शाहपुरा
15	जालौर	जालौर
16	जैसलमेर	पोकरण
17	झालावाड़	अकलेरा
18	झुंझुनूं	बिसाऊ, मुकुन्दगढ़, सूरजगढ़
19	जोधपुर	फलौदी
20	करौली	टोडाभीम, करौली
21	कोटा	इटावा, कैथून, सांगोद
22	नागौर	कुचेरा, मण्डवा, नावां
23	पाली	बाली, फालना, तख्तगढ़
24	प्रतापगढ़	छोटी सादड़ी
25	राजसमन्द	आमेट, देवगढ़
26	सीकर	खाटूश्यामजी, रींगस, नीमकाथाना

क्रम संख्या	**जिला**	**शहर**
27	सिरोही	पिण्डवाड़ा
28	श्रीगंगानगर	पदमपुर, श्रीकरणपुर, श्रीविजयनगर, सूरतगढ़
29	टोंक	देवली, मालपुरा, टोडारायसिंह
30	उदयपुर	भीण्डर, कानौड़